ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

जून 2024
वर्ष : 06 | अंक : 08
मूल्य : ₹140

dhyeyaias.com

नेतृत्व शून्यता में ईरान का राजनीतिक भविष्य

मुख्य विशेषताएं

- राज्य समाचार
- ब्रेन बूस्टर
- पॉवर पैक्ड न्यूज
- वन लाइनर
- यूपीएससी प्री मॉक पेपर

विशेष

प्री लिम्स स्पेशल

रिवीजन स्पेशल

- चर्चित जनजातियाँ
- महत्वपूर्ण गणनायें
- भारत के प्राकृतिक संसाधन
- विभिन्न संगठनों द्वारा पहल

ध्येय LAW®

An enterprise of Dhyeya IAS

PCS-J & APO

न्यायिक सेवाओं में जाने का सुनहरा अवसर

NOW IN LUCKNOW

NEW BATCH STARTS

15TH JULY

03RD AUGUST

7800001572, 9319991061

टीम
परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध निदेशक	:	क्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	विवेक ओझा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	हरि ओम पाण्डेय
	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
समीक्षक एवं	:	नितिन अस्थाना
सलाहकार	:	शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
सोशल मीडिया	:	केशरी पाण्डेय
मार्केटिंग सहयोग	:	प्रियांक, अंकित
तकनीकी सहायक	:	वसीफ खान
कार्यालय सहायक	:	चंदन, गुड्डू
	:	अरूण, राहुल

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर व अन्य

Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
140	12	1680	1200

Half Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
140	6	840	600

*Postal charges exta

ध्येय IAS
most trusted since 2003

परफेक्ट

मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. राष्ट्रीय 06-18

- ☑ **भारतीय समाज और लोकतंत्र के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट की मुखर होती भूमिका**
- ☑ हिंदू विवाह पर सुप्रीम कोर्ट
- ☑ एगशेल स्कल नियम
- ☑ अनुच्छेद 361
- ☑ बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित
- ☑ सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र
- ☑ सर्वोच्च न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम को कड़ा किया
- ☑ उपभोक्ता संरक्षण कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- ☑ सुप्रीम कोर्ट ने शामलात देह भूमि अधिकारों पर फैसले की समीक्षा की दी अनुमति
- ☑ पीएमएलए आरोपियों की गिरफ्तारी के मामले में ईडी की शक्ति सीमित- सुप्रीम कोर्ट
- ☑ व्यक्तित्व/प्रचार अधिकार
- ☑ राज्य उचित प्रक्रिया के बिना निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगा
- ☑ गंभीर मामलों में भी उचित व नियत प्रक्रिया का पालन करना जरूरी- सुप्रीम कोर्ट
- ☑ सीबीआई में केंद्र सरकार की भूमिका

2. अन्तर्राष्ट्रीय 19-28

- ☑ **राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत के बाद कैसे होंगे ईरान में राजनीतिक और शक्ति समीकरण**
- ☑ वियतनाम को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा
- ☑ विश्व प्रवासन रिपोर्ट
- ☑ भारत इंडोनेशिया रक्षा संबंध
- ☑ भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नाइजीरिया दौरा
- ☑ 100 रुपये के नोट पर नेपाल का नया मानचित्र
- ☑ मालदीव के विदेश मंत्री की भारत यात्रा
- ☑ न्यू कैलेडोनिया में अशांति
- ☑ भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त समिति की बैठक
- ☑ आर्मेनिया व अजरबैजान के बीच शांति समझौता
- ☑ भारत-घाना संयुक्त व्यापार समिति की बैठक
- ☑ भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक

3. पर्यावरण 29-37

- ☑ **यूएनएफएफ की बैठक और भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हो रही कार्यवाही**
- ☑ हिंद महासागर तल की बाथमेट्री
- ☑ पृथ्वी का घूर्णन हुआ धीमा
- ☑ आइबेरियन लिंक्स
- ☑ भारतीय कृषि भूमि में बड़े पेड़ों की कमी: एक गंभीर चिंता
- ☑ जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित भारतीय
- ☑ विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट
- ☑ वेनेजुएला का आखिरी ग्लेशियर
- ☑ अफ्रीका उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन
- ☑ सी एनीमोन ब्लीचिंग
- ☑ चक्रवात रेमल

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 38-49

- ☑ **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में मजबूत हो रहा भारत का अंटार्कटिक अभियान**
- ☑ थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस)
- ☑ वेस्ट नाइल वायरस रोग
- ☑ भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023
- ☑ CRISPR: वंशानुगत अंधेपन के इलाज के लिए BRILLIANCE अध्ययन
- ☑ दिल्ली की डेयरियों में ऑक्सीटोसिन का उपयोग
- ☑ उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट
- ☑ कृत्रिम सामान्य बुद्धिमता (AGI)

- ☑ निसार द्वारा विवर्तनिक गतिविधियों की निगरानी
- ☑ बैक्टीरियल पैथोजेन्स प्राथमिकता सूची
- ☑ 3डी प्रिंटेड रॉकेट इंजन
- ☑ TAK-003 डेंगू वैक्सीन
- ☑ भू-चुम्बकीय उत्क्रमण

5. आर्थिकी 50-59

- ☑ भारत और दुनिया में पर्यटन की सुधरती स्थिति
- ☑ एसएफबी के लिए आरबीआई के दिशानिर्देश
- ☑ सहभागी नोट (P-Notes)
- ☑ विश्व की सेवा फैक्टरी बनता भारत
- ☑ चीन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार
- ☑ भारतीय ई-कॉमर्स बाजार
- ☑ सेबी में फ्रंट-रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग
- ☑ भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश प्रमुख चालक: आईएमएफ
- ☑ आर्थिक मूल्य पृथ्वी अवलोकन (ईओ) डेटा
- ☑ एफ एंड ओ व्यापार का सैशेटाइजेशन
- ☑ भारत में धन प्रेषण
- ☑ शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी पर रिपोर्ट

6. विविध 60-70

- ☑ नक्सलवाद पर भारत सरकार का निर्णायक प्रहार
- ☑ संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-विरोधी ट्रस्ट फंड
- ☑ इग्ला-एस: बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली
- ☑ स्वस्थ खानपान को बढ़ावा देने के लिए ICMR की नई गाइडलाइन
- ☑ भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन
- ☑ भारत में फिशिंग हमले
- ☑ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024
- ☑ मैतेई सागोल
- ☑ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- ☑ यूनेस्को का विश्व स्मृति एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर
- ☑ पर्यावरण संरक्षण के लिए बाजार आधारित प्रोत्साहन

7. क्विक लर्न 71-146

ब्रेन बूस्टर 71-82

- ☑ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी
- ☑ टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम
- ☑ भारतीय मसाला उद्योग
- ☑ प्लास्टिक संधि
- ☑ स्मार्ट (SMART) सिस्टम
- ☑ विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी
- ☑ भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
- ☑ एमएसटीबी वैक्सीन MTBVAC
- ☑ फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र सदस्यता
- ☑ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस
- ☑ दक्षिण अमेरिका की भौगोलिक विशेषताएँ

समाचार में स्थान 83-85

राज्य समाचार 86-93

पावर पैक्ड न्यूज 94-104

वन लाइनर्स 105-107

प्री स्पेशल 108-123

- ☑ भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया पहल
- ☑ रक्षा अनुसंधन एवं विकास संगठन की हालिया पहल
- ☑ इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मिशन
- ☑ हाल ही में चर्चा में रही प्रमुख जनजातियाँ
- ☑ जहाजरानी मंत्रालय की हालिया पहल
- ☑ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की हालिया पहल
- ☑ 2011 में भारत की जनगणना से संबंधित मुख्य तथ्य
- ☑ 10वीं कृषि जनगणना
- ☑ एशियाई शेरों की जनगणना-2020
- ☑ सतत विकास लक्ष्य
- ☑ भारत में प्राकृतिक संसाधन
- ☑ भारत में लघु खनिज
- ☑ भारत में प्रमुख कृषि फसलें
- ☑ वर्ष 2023 में विज्ञान क्षेत्र की प्रमुख पहलें
- ☑ भारत में विनियामक निकाय

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 124-131

प्रीलिम्स आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 132-146

भारतीय समाज और लोकतंत्र के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट की मुखर होती भूमिका

सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ समय से देश की संघीय शासन प्रणाली में अपेक्षित सुधार के लिए कठोर कार्यवाही में लगा है। साथ ही आम नागरिकों के अधिकारों से छेड़छाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ भी कार्यवाही जारी है। चाहे देश में भ्रामक विज्ञापनों का मामला हो, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने का मामला हो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सक्रियता दिखाई है। इस्लाम नहीं मानने वाले मुस्लिमों पर उत्तराधिकार कानून लागू होगा कि नहीं और क्या शरिया कानूनों के तहत मुस्लिम महिलाएं संपत्ति में एक तिहाई हिस्सेदारी की हकदार हैं। इसका निर्धारण भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाज, परिवार, अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने के लिए अहम फैसले एक के बाद एक लिए जा रहे हैं। इन फैसलों के जरिए सर्वोच्च न्यायालय की अति सक्रिय भूमिका भी नजर आई है। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ज्यूडिशियल एक्टिविज्म की राह पर चलता नजर आ रहा है। शासन प्रशासन के विभिन्न अंगों, तंत्रों द्वारा कुशल तरीके से काम न करने के चलते आम नागरिकों को होने वाले नुकसान पर सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान विशेष रूप से बढ़ा है और उसके निर्णयों में इस बात का साक्ष्य भी मिलता है।

पतंजलि भ्रामक प्रचार मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णयः

- किसी चीज का प्रचार प्रसार करना विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है जो कि एक मौलिक अधिकार है। लेकिन किसी उत्पाद का भ्रामक प्रचार विज्ञापन कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के तहत विचार और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार पर इसलिए कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन भी लगाए गए हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर अथॉरिटी की निष्क्रियता पर सवाल उठाया है।
- वहीं उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पतंजलि और उसकी इकाई दिव्या फार्मेसी के 14 मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से 15 अप्रैल को रद्द कर दिया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट देर से कार्यवाही करने की प्रवृत्ति से असंतुष्ट है।

हिंदू विवाह पद्धति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसलाः

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वैवाहिक पद्धति को लेकर अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और यह 'सॉन्ग-डांस', 'वाइनिंग-डायनिंग' का आयोजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अपेक्षित प्रथा एवं रीति रिवाजों का पालन नहीं किया गया तो वह हिंदू विवाह अमान्य है और हिंदू विवाह पंजीकरण इस तरह के विवाह को वैध नहीं बताता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया है। सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि हिंदू विवाह को वैध होने के लिए, इसे सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे के सात चरण) जैसे उचित संस्कार और समारोहों के साथ किया जाना चाहिए और विवादों के मामले में इन समारोह का प्रमाण भी मिलता है।
- जस्टिस बी. नागरत्ना ने अपने फैसले में कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्य की संस्था

के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने युवा पुरुषों और महिलाओं से आग्रह करते हुए कहा है कि वह विवाह की संस्था में प्रवेश करने से पहले इसके बारे में गहराई से सोचें और भारतीय समाज में उक्त संस्था कितनी पवित्र है, इस पर विचार करें।

आर्टिकल 39(बी) की व्याख्या पर सक्रिय हुआ सुप्रीम कोर्टः

- निजी संपत्ति पर अधिकार के सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 39(b) पर हाल में बहस हुई है। सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (MHADA) के चैप्टर VIII-A को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।
- 1986 में एक संशोधन के जरिए यह चैप्टर जोड़ा गया। महाराष्ट्र सरकार ने जर्जर हो चुकी इमारतों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए यह कानून बनाया गया। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 39(बी) का हवाला दिया गया था। 1991 में इस संशोधन को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने संशोधन को यह कहते हुए बरकरार रखा कि अनुच्छेद 39(बी) के तहत बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 31सी द्वारा सुरक्षा दी गई है।
- हाई कोर्ट के फैसले को 1992 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पहले सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने मामले को सुना फिर 1996 में मामला पांच जजों की बेंच के पास भेज दिया गया था।
- 2001 में यह केस सात जजों की संविधान पीठ के सामने स्थानांतरण हुआ था और जब वहां से भी सवाल का जवाब नहीं तय हो सका तो 2002 में केस नौ जजों की बेंच के पास गया। करीब 22 साल बाद, 23 अप्रैल 2024 से नौ जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की है। कोर्ट को तय करना है कि क्या निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत 'समाज का भौतिक संसाधन' माना जा सकता है?
- हाल में इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि इस मुद्दे के दो अलग-अलग नजरिए हैं:
  - » कोई भी निजी संपत्ति समुदाय की भौतिक संसाधन नहीं है।
  - » हर निजी संपत्ति समुदाय की भौतिक संसाधन है।
- कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रहित और निजीकरण को देखते हुए अनुच्छेद 39(बी) की समकालीन व्याख्या किए जाने की जरूरत है। अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार, 'समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि वह सर्वसामान्य हित के लिए सर्वोत्तम हो'।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल को स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी के बीच सख्त विरोधाभास नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "आज के समय में अनुच्छेद 39 की व्याख्या नहीं की जा सकती। समाजवाद और साम्यवाद के बेजोड़ एजेंडे को इन योजनाओं में पढ़ा जा सकता है। यह हमारा संविधान नहीं है। हम आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की रक्षा करते हैं। हम अभी भी व्यवसाय जारी रखने के अधिकार की रक्षा करते हैं।
- हम अभी भी इसे राष्ट्रीय एजेंडे के हिस्से के रूप में चाहते हैं। हम इसे सरकार का एजेंडा नहीं कहते। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, 1990 से निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने की नीति रही है। अब अगर वास्तव में हमें उत्पादन बढ़ाना है, तो निजी निवेश को प्रोत्साहित करना होगा।
- इसलिए भारत आज क्या है और भारत कल क्या आगे बढ़ रहा है, इसका ध्यान रखने के लिए हमारी व्याख्या नई होनी चाहिए। संविधान पीठ ने कहा है कि 1950 के दशक में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि विद्युत वितरण बड़े पैमाने पर निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। वे इस तथ्य के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि एक निजी कंपनी सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी।

कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट का मामला और सुप्रीम कोर्टः

- ग्लोबल फार्मास्युटिकल एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स की ओर से बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इससे खून के थक्के जम सकते हैं।
- एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट में वैक्सीन के नुकसान की बात कबूली है। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया है। भारत में भी कोविशील्ड नाम से यही वैक्सीन लगाई गई है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है और जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा के हित में निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
- देश के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में समिति गठित कर कोविशील्ड के दुष्प्रभावों के जांच की जाए। याचिका में कहा गया है कि कि समिति में एम्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली निदेशक और विशेषज्ञों को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाए।
- वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स और जोखिम की जांच तथा क्षति का निर्धारण करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इसके अलावा पीड़ित नागरिकों के लिए मुआवजा भुगतान की व्यवस्था की जाए।
- कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव के कारण गंभीर रूप से विकलांग हुए या जिनकी मृत्यु हो गई हो उनके आश्रितों को मुआवजा मुहैया कराने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि इस मुद्दे को कैसे दिशा दी जाए।
- उल्लेखनीय है कि भारत में कोविशील्ड को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर किया गया है। इसके 175 करोड़ डोज लगाए गए हैं। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की कोर्ट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) के साथ साइड इफेक्ट थ्रोम्बोसिस की बात

स्वीकार है। इस वैक्सीन से गंभीर नुकसान और मौत होने का आरोप लगा है, जिसका मामला ब्रिटेन के हाईकोर्ट में चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट और ईवीएम का मुद्दा:

- लोकसभा चुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं ओर राजनीतिक दलों में विश्वास जगाने के लिए व्यवस्था दी है कि ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो जांच कराई जाएगी। इसका आशय है कि अगर प्रत्याशियों को लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है तो ईवीएम की जांच की जा सकेगी।
- इसके बाद से कहा जा रहा है कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के इस व्यवस्था से जरूर संतुष्ट होगा फिर भी यह उम्मीद करनी बेमानी है कि आगामी लोकसभा चुनावों में हारने वाला यह नहीं कहेगा कि सरकार ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की क्योंकि हर बार चुनावों में जो पार्टी हारती है वही ईवीएम पर संदेह करती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 3 निर्देश दिए हैं:
  - » चुनाव आयोग को VVPAT पर बार कोड रखने की फीजीबिल्टी की जांच करनी चाहिए जिससे सभी पर्चियों की गिनती कंप्यूटराइज्ड तरीके से हो जाए।
  - » चुनाव के बाद चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और 45 दिनों तक उपलब्ध रखा जाना चाहिए।
  - » हारने वाले उम्मीदवार अपने खर्च पर किन्हीं 5 ईवीएम की 'बर्न मेमोरी' की जांच करा सकते हैं।

राष्ट्रीय संक्षिप्त मुद्दे

हिंदू विवाह पर सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित पारंपरिक अनुष्ठानों और समारोहों का सख्ती से और धार्मिक रूप से पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा विवाह अमान्य होगा।

न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

- ➢ अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा 7, जिनमें 'हिंदू विवाह के समारोहों' को सूचीबद्ध किया गया है, उनका विवाह की वैधता के लिए पालन किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो विवाह कानून की नजर में वैध नहीं माना जाएगा।
- ➢ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, एक हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जा सकता है।
- ➢ सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह एक 'संस्कार' के रूप में विस्तृत किया। उन्होंने कहा के विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसे भारतीय समाज में महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के बारे में:

- ➢ यह अधिनियम हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करता है। जन्म से या धर्म परिवर्तन से बने हिंदू विवाह अधिनियम के विषय है, इसके तहत हिंदू की परिभाषा में बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं।
- ➢ **विवाह योग्य आयु:** हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत, विवाह के लिए न्यूनतम आयु दूल्हे के लिए 21 वर्ष और दुल्हन के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। नाबालिगों से शादी करने पर तीन साल तक की कैद और/या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- ➢ **द्विविवाह:** अधिनियम की धारा 5 निर्दिष्ट करती है कि एक साथ दो पत्नियाँ (द्विविवाह) रखना अवैध है। यदि पति या पत्नी में से एक जीवित है और व्यक्ति पुनर्विवाह करता है, तो ऐसा विवाह न केवल आमान्य है, बल्कि वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 494 और 495 के तहत दंडनीय भी है।
- ➢ **तलाक के प्रावधान:** हिन्दू विवाह अधिनियम न केवल पंजीकरण प्रदान करता है बल्कि तलाक के संबंध में नियम भी निर्धारित करता है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक आपसी सहमति या न्यायिक अलगाव के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में यह शादी के एक वर्ष पूरा होने से पहले भी तलाक लेने कि अनुमति देता है। अधिनियम तलाक के लिए विभिन्न आधारों को निर्दिष्ट करता है, जिसमें ऐसे प्रावधान भी शामिल हैं जो पत्नियों को अपने पतियों से तलाक लेने की अनुमति देते हैं।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय के माध्यम से भारतीय समाज में विवाह संस्था के महत्व एवं इससे जुड़े पारंपरिक समारोहों व रीति-रिवाजों के

आवश्कता पर बल दिया। साथ में यह भी स्पष्ट किया की अपेक्षित समारोहों के अभाव में किसी संस्था द्वारा केवल प्रमाण-पत्र जारी करना वैध हिंदू विवाह नहीं माना जाता है। अत: हिंदू विवाह में संस्कारो का पालन किया जाना चाहिए।

एगशेल स्कल नियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्रीय उपभोक्ता अदालतों के फैसलों को पलट दिया, जिन्होंने वादी को दिए गए मुआवजे को कम करने के लिए एगशेल स्कल नियम लागू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा दिए गए 5 लाख रुपये के मूल मुआवजे को बहाल कर दिया, जिसने प्रतिवादी को चिकित्सा लापरवाही का दोषी पाया था और माना था कि इस केस में एगशेल स्कल नियम लागू नहीं होता है। एगशेल स्कल नियम, मेडिकल प्रैक्टिशनर को कुछ छूट प्रदान करता है।

एगशेल स्कल नियम क्या है?

- एगशेल स्कल नियम सिविल याचिका में लागू होने वाला एक सामान्य कानून सिद्धांत है जो वादी को हुए नुकसान की पूरी सीमा के लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी बनाता है, भले ही वादी के पास पहले से मौजूद भेद्यता या स्थिति हो उन्हें चोट लगने के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया अर्थात एगशेल स्कल नियम के तहत, जिस व्यक्ति ने चोट पहुंचाई, वह उसी गंभीर चोट के लिए जिम्मेदार होगा, न कि सिर्फ उतनी सी चोट के लिए जितनी एक स्वस्थ व्यक्ति को लगती।
- यह नियम अक्सर व्यक्तिगत चोट के मामलों में लागू किया जाता है, विशेषकर लापरवाही या अपकृत्य कानून से जुड़े मामलों में।
- इस सिद्धांत की अवधारणा पहली बार अमेरिका के विस्कॉन्सिन में 1891 के वोसबर्ग बनाम पुटनी मामले में विकसित हुई।
- एगशेल स्कल नियम को लागू करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
  - वादी के पास पहले से मौजूद भेद्यता या स्थिति।
  - प्रतिवादी के कार्यों के कारण वादी को चोट लगी जिसने पहले से मौजूद स्थिति को और खराब कर दिया।

कोर्ट ने क्या कहा?

- न्यायालय ने माना कि 'एगशेल स्कल नियम' इस मामले में लागू नहीं होता क्योंकि पहले से मौजूद कमजोरी या चिकित्सीय स्थिति का कोई सबूत नहीं था जो वादी को असामान्य क्षति के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता।

क्या था मामला?

- 2005 में, ज्योति देवी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक अस्पताल में अपना अपेंडिक्स निकलवाने गई थीं। हालाँकि सर्जरी योजना के अनुसार हुई थी, लेकिन उसके पेट का दर्द कम नहीं हुआ।
- अंतत:, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने पाया कि उसके पेट में '2.5 सेमी का (सुई)' रह गया था, जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा निकालने की आवश्यकता थी।
- जब ज्योति ने मुआवजे के लिए जिला उपभोक्ता फोरम का रुख किया, तो उसे मंडी के अस्पताल द्वारा चिकित्सा लापरवाही के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। हालाँकि, जब अस्पताल ने आदेश के खिलाफ अपील की, तो राज्य उपभोक्ता फोरम ने मुआवजे को घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया।

निष्कर्ष:

- यह निर्णय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एक कड़ा संदेश भेजता है कि उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा और चिकित्सा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करते हुए, यह निर्णय:
  - स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को रोगी की देखभाल और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  - चिकित्सीय लापरवाही के लिए मुआवजा मांगने के रोगियों के अधिकारों को मजबूत करता है।
  - स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
  - स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को मरीजों के इलाज में लापरवाही या लापरवाही बरतने से रोकता है।
  - चिकित्सा लापरवाही के पीड़ितों के लिए न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत का समर्थन करता है।

अनुच्छेद 361

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस के खिलाफ कोलकाता में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई है किन्तु अनुच्छेद 361 के तहत मिली संवैधानिक सुरक्षा पुलिस को राज्यपाल को आरोपी के रूप में नामित करने या यहां तक कि मामले की जांच करने से रोकती है।

संवैधानिक छूट क्या है?

- भारत में राज्यपाल की संवैधानिक प्रतिरक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत उन्हें दी गई सुरक्षा को संदर्भित करती है।

अनुच्छेद 361 के बारे में:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनकी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह होने से छूट प्रदान करता है।
- राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से जारी नहीं की जाएगी।

कानूनी व्याख्या:

- **कानूनी कार्यवाही से छूट:** राष्ट्रपति और राज्यपालों को नागरिक मुकदमों, आपराधिक मुकदमों और अदालती पूछताछ सहित कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा मिलती है।
- **अदालत कानूनी कार्यवाही पर विचार नहीं कर सकती:** सर्वोच्च न्यायालय सहित अन्य अदालतें राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर विचार नहीं कर सकती हैं।
- **केवल आधिकारिक कार्यों के लिए प्रतिरक्षा:** प्रतिरक्षा केवल उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों पर लागू होती है, न कि उनके व्यक्तिगत कार्यों पर। दो महीने का नोटिस देने के बाद, उनके कार्यकाल के दौरान उनके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में उनके खिलाफ नागरिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
- हालाँकि, यह छूट राज्यपाल के आधिकारिक कार्यों और अच्छे विश्वास में लिए गए निर्णयों तक ही सीमित है। यह उन्हें व्यक्तिगत कार्यों या उनके आधिकारिक कर्तव्यों से असंबंधित अवैध गतिविधियों के लिए आपराधिक जांच या अभियोजन से नहीं बचाता है।
- पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में, संवैधानिक छूट के कारण पुलिस उन्हें आरोपी के रूप में नामित करने या सीधे मामले की जांच करने में सक्षम नहीं हो सकती है। हालाँकि, अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं, जैसे:
  - राज्यपाल पर जांच और मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय या राष्ट्रपति से मंजूरी मांगना।
  - आरोपों की आंतरिक जांच या प्रशासनिक जांच करना।
  - शिकायत के समाधान के लिए कानूनी सलाह लेना और अन्य कानूनी विकल्प तलाशना।

निष्कर्ष:

राज्यपाल को प्रदान की गई प्रतिरक्षा का उद्देश्य इन उच्च कार्यालयों की स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करना है, जिससे उन्हें कानूनी उत्पीड़न या धमकी के डर के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि यह संवैधानिक सुरक्षा पूर्ण नहीं है और न्यायिक जांच और व्याख्या के अधीन है।

बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कीं।

मुख्य बिंदु:

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा एससीबीए को अपनी कार्यकारी समिति के चुनावों के लिए आरक्षण और दिशानिर्देश स्थापित करने होंगे।
- इसके साथ ही कोषाध्यक्ष सहित विभिन्न समिति पदों पर एक तिहाई सीटें महिला सदस्यों के लिए आरक्षित की जाएंगी।
- योग्य महिला सदस्य सभी पदों के लिए चुनाव लड़ सकती हैं।

आरक्षण के मानदंड:

- कार्यकारी समिति में न्यूनतम 1/3 सीटें अर्थात् 9 में से 3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों में से न्यूनतम 1/3 अर्थात् 6 में से 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।।
- पदाधिकारी का कम से कम एक पद विशेष रूप से बारी-बारी से और रोटेशन के आधार पर महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया जाएगा।
- 2024-2025 के आगामी चुनाव में कार्यकारी समिति के कोषाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है।

इस फैसले का महत्त्व:

- **लैंगिक प्रतिनिधित्व:** यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि SCBA की निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को निष्पक्ष और समान प्रतिनिधित्व मिले।
- **सशक्तीकरण:** यह महिला वकीलों को नेतृत्व की भूमिका निभाने और कानूनी पेशे के भविष्य को आकार देने में भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है।
- **विविधता:** यह आरक्षण विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देता है, जिससे समिति में विभिन्न दृष्टिकोण और विचार आते हैं।
- **भागीदारी को प्रोत्साहित करता है:** यह अधिक महिलाओं को कानूनी पेशे में भाग लेने और नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **रोल मॉडल:** नेतृत्व की स्थिति में महिलाएं रोल मॉडल के रूप में काम करती हैं, जो युवा महिला वकीलों को आत्मविश्वास के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं।
- **संतुलित निर्णय लेना:** यह आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय पुरुषों और महिलाओं दोनों के विचारों और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण से किए जाएं।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन:** यह निर्णय लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।
- **समाज पर प्रभाव:** यह निर्णय एक सकारात्मक मिसाल कायम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और समाज के अन्य व्यवसायों और क्षेत्रों में लिंग-आधारित भेदभाव को चुनौती देता है।

समिति के बारे में:

- बार एसोसिएशन कमेटी, जिसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों का एक पेशेवर संगठन है। समिति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है:

- वकीलों और कानूनी पेशे के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
- वकीलों के आचरण और नैतिकता को विनियमित करना।
- वकीलों को कानूनी मुद्दों और विकास पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
- कानूनी शिक्षा जारी रखने के लिए सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- कानून सुधार और नीतिगत मामलों पर न्यायपालिका और सरकार के साथ जुड़ना।
- न्याय प्रशासन और कानून के शासन का समर्थन करना।
- न्याय और मानवाधिकारों तक पहुंच को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

एससीबीए में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करके एक अधिक समावेशी और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जो अंततः न्यायसंगत समाज में योगदान देता है। इससे न्याय तंत्र में सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा मिलेगा।

सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत 14 नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए है। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 क्या है?

- यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के पीड़ित छह गैर-मुस्लिम समुदाय (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान करता हैं।
- नागरिकता के लिए नियत तारीख 31 दिसंबर 2014 है, जिसका अर्थ है कि आवेदक ने इस तारीख को या इससे पूर्व भारत में प्रवेश किया हो।
- यह अधिनियम संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, जोकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त आदिवासी बहुल क्षेत्रों से संबंधित है।
- इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम उन राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम) पर लागू नहीं होगा जहां इनर-लाइन परमिट व्यवस्था है।
- नागरिकता के लिए इन समूहों को छूट प्रदान की गयी हैं। यह छूट 11 साल की अवधि को घटाकर पाँच साल कर दी गयी हैं।

प्रक्रिया:

- **सीएए नियम 2024:** सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 बी के तहत बनाई गई है। आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपने मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तिथि और एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा। आवेदनों की जांच की जाएगी और उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।
- सीएए नियमों में उल्लिखित सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद लाभार्थियों को प्रमाण पत्र डाक द्वारा भेजे जाएंगे।

नागरिकता प्राप्त करने के परिणाम:

- अधिनियम में कहा गया है कि नागरिकता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप (i) ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा और (ii) उनके अवैध प्रवास के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाही बंद की जाएगी।

चिंताएं:

- अधिनियम में तीन देशों के पीड़ित छह धार्मिक अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अहमदिया और हजारा , म्यांमार में रोहिंग्या और श्रीलंका में तमिलों को शामिल नहीं किया गया हैं।
- **अनुच्छेद 14 का उल्लंघन:** यह कानून धार्मिक आधार पर भेदभाव करके, कानून समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

आगे की राह:

धार्मिक उत्पीड़ित व्यक्ति को नागरिकता प्रमाण पत्र की प्राप्ति उसके जीवन में गुणात्मक करेगा, तो वही देश में स्वतंत्र भाव से अपना जीवन यापन करेगा। साथ ही सरकार को इस अधिनियम को समावेशी बनाने की आवश्यकता हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम को कड़ा किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी और पॉक्सो (POCSO) के तहत बलात्कार और गलत तरीके से कारावास के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामले में एक अपील पर विचार के दौरान POSCO अधिनियम में महत्वपूर्ण खामियां देखीं। उन कमियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिए।

निर्णय:

- **अपील के लिए 30 दिन की समयसीमा:** सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिन की सख्त समयसीमा तय की है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना और न्याय देने में देरी को रोकना है।
- **विस्तृत आदेश अनिवार्य:** सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि किशोर न्याय बोर्डों या बाल न्यायालयों द्वारा पारित सभी आदेशों के साथ विस्तृत कारण और स्पष्टीकरण होने चाहिए। यह निर्णय

लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

किशोर न्याय अधिनियम के बारे में:

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना है। इस अधिनियम ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को प्रतिस्थापित कर दिया और प्रावधानों को और मजबूत करने के लिए 2021 में इसमें संशोधन किया गया।

पॉक्सों एक्ट की प्रमुख विशेषताऐं

- **बच्चे की परिभाषा:** बच्चे का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है।
- **किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी):** कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों से निपटने के लिए एक बोर्ड जिसमें एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक मनोवैज्ञानिक शामिल होता है।
- **कानून के साथ संघर्ष में बच्चे (सीसीएल):** जिन बच्चों पर अपराध करने का आरोप है। ऐसे मामले में, जिनमें बच्चों द्वारा किया गया अपराध छोटी प्रकृति का होता है और सजा के लिए पुनर्वास दृष्टिकोण अपनाया जाता है।
- **जघन्य अपराध की स्थिति में:** 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे पर जघन्य अपराध करने पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। जघन्य अपराधों को सात साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी):** सीएनसीपी बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक समिति है।
- **पुनर्वास:** अधिनियम बच्चे के सुधार और समाज में पुन: एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सजा से अधिक पुनर्वास पर जोर देता है।
- **आयु निर्धारण:** अधिनियम किसी व्यक्ति को बच्चा मानता है जब तक कि वयस्क साबित न हो।
- **जमानत:** बच्चे जमानत के हकदार हैं और यदि बच्चे द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है तो जेजेबी जमानत दे सकता है।
- **परामर्श:** बच्चों को सुधार और पुनर्वास के लिए परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
- **संस्थागत देखभाल:** बच्चों को देखभाल और सुरक्षा के लिए अवलोकन गृहों, विशेष घरों या उपयुक्त संस्थानों में भेजा जा सकता है।
- **दत्तक ग्रहण:** अधिनियम बच्चे के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देते हुए गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।
- **दंड:** बाल श्रम, बाल विवाह या बच्चों के प्रति क्रूरता होने पर दंड का प्रावधान है।

निष्कर्ष:

किशोर न्याय अधिनियम, 2015, भारत में बच्चों के अधिकारों और सम्मान को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ी चुनौतियों को संबोधित करने से जरूरतमंद बच्चों को देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करने में अधिनियम की सफलता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

उपभोक्ता संरक्षण कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अधिवक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

मुद्दे:

- क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवाओं में कमी के लिए अधिवक्ताओं को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है?
- क्या अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ उपभोक्ता संरक्षण अधि नियम 2019 की धारा 2(42) में निहित सेवा के दायरे में आती हैं?

निर्णय:

- यह निर्णय 2007 के राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के खिलाफ एक अपील के दौरान आया , जहां यह माना गया था कि अधिवक्ता (वकील) के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (सीपीए) की धारा 2 (ओ) के तहत दी गई परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यदि सेवा में कोई कमी है, तो एनसीडीआरसी ने माना कि सीपीए के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सेवाओं में कमी के लिए अधिवक्ताओं को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- कोर्ट ने कहा कि वकील किसी संविदात्मक दायित्व के तहत सेवाएं नहीं दे रहे हैं, बल्कि अदालत के अधिकारी के रूप में अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानूनी पेशा स्वाभाविक रूप से सेवा-उन्मुख और महान है, न कि व्यावसायिक लाभ से प्रेरित। वकीलों से अपेक्षा की जाती है कि वे नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखें और न्यायिक स्वतंत्रता और कानून के शासन को बनाए रखने में योगदान दें।
- यह फैसला चिकित्सा पेशेवरों से संबंधित 1996 के फैसले पर भी पुनर्विचार करने का संकेत देता है। शीर्ष अदालत के 1995 के फैसले में कहा गया था कि डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

प्रभाव:

- इस फैसले का कानूनी पेशे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि

यह स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवाओं में कमी के लिए अधिवक्ताओं को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

- यह निर्णय अधिवक्ताओं को उनके पेशेवर कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए बेवजह की शिकायतों और संभावित दायित्व से बचाता है।

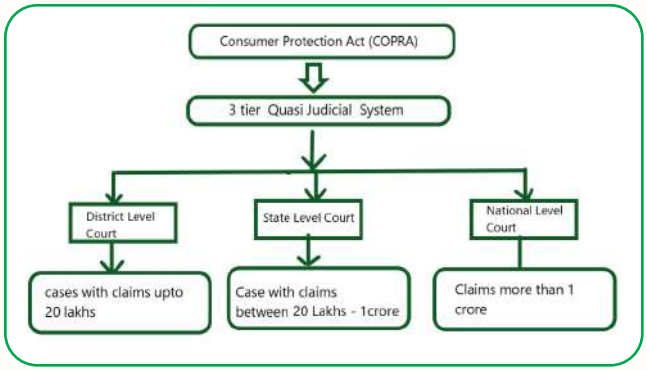

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में:

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एक संशोधित कानून है जो ग्राहकों को अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं, झूठे या भ्रामक विज्ञापनों और धोखे के अन्य रूपों से बचाने के लिए व्यापक लाभ और अधिकार प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु:

- यह अधिनियम उपभोक्ता की परिभाषा के दायरे को बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, टेलीशॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी-लेवल मार्केटिंग के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेनदेन को शामिल करता है।
- ई-कॉमर्स का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और इसे ऑनलाइन सामान/सेवाओं/डिजिटल उत्पादों की खरीद और बिक्री के रूप में परिभाषित किया गया है।

निष्कर्ष:

इस फैसले का कानूनी पेशे पर महत्वपूर्ण प्रभाव है क्योंकि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे और उनकी सेवाओं के संबंध में अधिवक्ताओं के दायित्व को स्पष्ट करता है। यह उपभोक्ता कानून और कानूनी नैतिकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सुप्रीम कोर्ट ने शामलात देह भूमि अधिकारों पर फैसले की समीक्षा की दी अनुमति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिकारों पर अपने 2022 के उस फैसले की समीक्षा की अनुमति दी, जिसमें ग्राम पंचायतों को 'शामलात देह' भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति दी गई थी।

मुख्य बिंदु:

- न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 2022 के उस फैसले की समीक्षा की अनुमति दी जिसमें दो सदस्यीय पीठ (न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम) ने एक बड़ी पांच सदस्यों वाली पीठ के फैसले के मामले में प्रासंगिक निर्णय (भगत राम बनाम पंजाब राज्य, 1967) की अवहेलना की थी।
- इस समीक्षा से हरियाणा में गांव के भूस्वामियों के अधिकारों की रक्षा हो सकती है। अर्थात इससे न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम पंचायतों द्वारा 'शामलात देह' भूमि के अधिग्रहण से भूस्वामियों के अधिकारों का हनन न हो।
- शामलात देह मूलत: गांव की आम जमीन है, जिसे कई भूस्वामियों द्वारा गांव के लोगों के "साझा उद्देश्यों" की पूर्ति के लिए अपनी व्यक्तिगत भूमि का बराबर हिस्सा देकर बनाया गया होता है।
- शीर्ष अदालत ने 2022 में पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 (इसके बाद से पंजाब एक्ट) में 1992 के संशोधन को बरकरार रखा था, जो ग्राम पंचायतों को शामलात देह भूमि को "गांव के साझा उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि" के रूप में प्रबंधित और नियंत्रित करने की अनुमति देता है।
- यह समीक्षा उस याचिका पर आधारित है जो गांव के भूस्वामियों के एक समूह द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि 2022 का फैसला उनकी शामलात देह भूमि पर उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है।

2022 के फैसले की समीक्षा की अनुमति क्यों?

- भगत राम बनाम पंजाब राज्य (1967) के मामले में पांच जजों की एक बेंच ने सुनाया कि अगर गांव के लोगों ने सामुदायिक इस्तेमाल के लिए किसी जमीन को चिह्नित किया है, तो उस जमीन का इस्तेमाल में न आने वाला हिस्सा उसके असल मालिकों के बीच बांट दिया जाएगा।
- वहीं 7 अप्रैल 2022 को जस्टिस गुप्ता और जस्टिस रामासुब्रमण्यिना की पीठ ने 1967 के फैसले के एकदम उलट फैसला सुनाया था और कहा था कि जमीन का कोई भी टुकड़ा उसके मालिकों में दोबारा से नहीं बांटा जा सकता।

भगत राम बनाम पंजाब राज्य (1967):

- 1967 में, पांच न्यायाधीशों की पीठ डोलिके सुंदरपुर गांव के लिए भूमि समेकन योजना की वैधता पर फैसला कर रही थी, जिसमें भूमि को "सामान्य उद्देश्यों के लिए" आरक्षित करने और इन जमीनों से होने वाली आय को पंचायत को देने का प्रस्ताव था।
- भूस्वामियों ने इस योजना को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह अनुच्छेद 31ए के दूसरे प्रावधान का उल्लंघन करता है जिसमे सरकार को किसी व्यक्ति से उस भूमि को अधिग्रहण करने से

रोकता है जो भूमि का आकार 'सीलिंग सीमा' (जो राज्य और लागू कानून के आधार पर बदलता है) से कम है तब उस भूमि को अधिग्रहण करने की स्थिति में राज्य भूमि के लिए 'बाजार मूल्य के बराबर' मुआवजा देना शामिल है।

- पंजाब राज्य ने तर्क दिया कि पंचायत की आय के लिए भूमि आरक्षित करना भूमि अधिग्रहण के रूप में योग्य नहीं है क्योंकि आय का उपयोग ग्राम समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। हालाँकि कोर्ट ने फैसला भूस्वामियों के पक्ष में दिया था।

निष्कर्ष:

न्यायालय के फैसले की समीक्षा की अनुमति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 'शामलात देह' भूमि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाए, लेकिन भूस्वामियों के अधिकारों का भी हनन न हो।

पीएमएलए आरोपियों की गिरफ्तारी के मामले में ईडी की शक्ति सीमित- सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विशेष अदालत द्वारा शिकायत का संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए की धारा 19 के तहत किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता।

फैसले की मुख्य बातें:

- **गिरफ्तारी की शक्ति को सीमित करता है:** अदालत में पेश होने के बाद ईडी को किसी व्यक्ति की हिरासत के लिए अलग से आवेदन करना होगा। केंद्रीय एजेंसी को विशिष्ट आधार दिखाने होंगे जिनके लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।
- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार:** पीएमएलए के तहत एक निर्दिष्ट विशेष अदालत द्वारा सम्मानित व्यक्ति को हिरासत में नहीं माना जाता है और उसे धन-शोधन विरोधी कानून द्वारा उत्पन्न कठोर शर्तों के तहत जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- **आरोपी को बांड भरने का निर्देश दिया जा सकता है:** विशेष अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के तहत आरोपी को बांड भरने का निर्देश दे सकती है। सीआरपीसी की धारा 88 के तहत प्रस्तुत किया गया बांड केवल एक उपक्रम है। धारा 88 के तहत बांड स्वीकार करने का आदेश जमानत देने के समान नहीं है और इसलिए पीएमएलए की धारा 45 की जुड़वां शर्तें इस पर लागू नहीं होती हैं।
- **अभियुक्त को राहत:** एक अभियुक्त जो समन के अनुसार विशेष अदालत में पेश होता है, उसे भविष्य में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सकती है। यदि कोई आरोपी समन जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं होता है, तो विशेष अदालत एक जमानती वारंट और उसके बाद एक गैर-जमानती वारंट जारी कर सकती है।
- **ईडी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसे आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है:** जब ईडी उसी अपराध के संबंध में आगे की जांच करना चाहता है, तो वह पहले से दर्ज शिकायत में आरोपी के रूप में नहीं दिखाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, बशर्ते कि धारा 19 की आवश्यकताएं पूरी हों।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के बारे में:

- मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002, भारत में एक विधायी अधिनियम है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और नियंत्रित करना है।

उद्देश्य:

- मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए और अपराध की आय को जब्त करने के लिए।

परिभाषाएँ:

- **मनी लॉन्ड्रिंग:** अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध धन या संपत्ति में परिवर्तित करने की प्रक्रिया।
- **अपराध से प्राप्त आय:** आपराधिक गतिविधि से प्राप्त की गई कोई भी धन या संपत्ति।

प्रमुख प्रावधान:

- **मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध (धारा 3):** जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का प्रयास करेगा, उसे कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
- **मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा (धारा 4):** कम से कम तीन साल की कैद, लेकिन इसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- **संपत्ति की कुर्की और जब्ती (धारा 5 और 8):** अधिकारियों को अपराध की आय को कुर्क करने और जब्त करने का अधिकार देता है।
- **जांच और तलाशी (धारा 11 और 17):** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जांच और तलाशी लेने के लिए अधिकृत करता है।
- **गिरफ्तारी और हिरासत (धारा 19):** ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का अधिकार देता है।

प्रवर्तन:

- **प्रवर्तन निदेशालय (ईडी):** मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार।
- **विशेष अदालतें:** पीएमएलए मामलों की सुनवाई के लिए नामित अदालतें।

निष्कर्ष:

निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि विशेष अदालत द्वारा बुलाए गए

व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत में नहीं लिया जाएगा। यह ऐतिहासिक निर्णय मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की आवश्यकता और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाता है।

व्यतित्व/प्रचार अधिकार

चर्चा में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं को उनके व्यक्तित्व/प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में शामिल हैं:

- विभिन्न संस्थाओं को उसके व्यक्तित्व/प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकना
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एआई चैटबॉट और सोशल मीडिया खातों को अभिनेता की सहमति के बिना किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उसका नाम, आवाज या छवि का उपयोग करने से रोकना।
- अगली सुनवाई तक संस्थाओं को जैकी श्रॉफ के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकना।
- उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सभी लिंक और वेबसाइटों को हटाने का आदेश।

व्यक्तित्व अधिकार के बारे में:

- व्यक्तित्व अधिकार, जिसे प्रचार अधिकार के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी व्यक्ति की पहचान की रक्षा करता है, जिसमें उनका नाम, छवि, आवाज, हस्ताक्षर और समानता शामिल है।
- ये अधिकार इस विचार पर आधारित हैं कि किसी व्यक्ति की पहचान का आर्थिक मूल्य है और उसे अनधिकृत उपयोग से बचाया जाना चाहिए।

कानूनी प्रावधान:

- **निजता का अधिकार (संविधान का अनुच्छेद 21):** इस मौलिक अधिकार में किसी की व्यक्तिगत जानकारी और पहचान को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है।
- **पासिंग ऑफ (ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 27):** यह प्रावधान किसी व्यक्ति के नाम, प्रतिष्ठा या छवि के अनधिकृत उपयोग से बचाता है।
- **मानहानि (भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499-502):** यह प्रावधान झूठे बयानों या अभ्यावेदन के माध्यम से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान से बचाता है।
- **कॉपीराइट कानून (कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 55):** यह प्रावधान लेखकों और कलाकारों को उनके कार्यों पर विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिसमें उनके उपयोग और अनुकूलन पर नियंत्रण भी शामिल है।
- **अनुबंध कानून (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872):** यह प्रावधान व्यक्तियों को ऐसे अनुबंधों में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है जो उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हैं।
- **टॉर्ट लॉ (सामान्य कानून):** यह प्रावधान व्यक्तियों को क्षति और निषेधाज्ञा सहित उनके व्यक्तित्व अधिकारों के अनधिकृत उपयोग के लिए उपाय खोजने की अनुमति देता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (धारा 43ए, 2000):** यह प्रावधान किसी व्यक्ति की पहचान सहित संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी की सुरक्षा करता है।

निष्कर्ष:

अदालत के फैसले में माना गया है कि जैकी श्रॉफ की पहचान का व्यावसायिक मूल्य है और उन्हें यह नियंत्रित करने का अधिकार है कि उनकी पहचान का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कैसे किया जाता है। यह निर्णय भारत में व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मिसाल कायम करता है, जो व्यावसायिक क्षेत्र में व्यक्तिगत पहचान और प्रतिष्ठा के महत्व पर जोर देता है।

राज्य उचित प्रक्रिया के बिना निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगा

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा कि राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता। खंडपीठ का कहना है कि निजी संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ एक मानवाधिकार भी है। यह संपत्ति के अधिग्रहण से पहले सरकार के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है।

फैसले के बारे में:

- 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, लेकिन संविधान में अनुच्छेद 300 ए को शामिल किया गया, बशर्ते कि 'कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा'।
- शीर्ष अदालत ने निजी संपत्ति को 'सार्वजनिक उद्देश्यों' के लिए राज्य के मनमाने अधिग्रहण से बचाने के लिए एक उल्लेखनीय कदम उठाया।
- यह माना गया कि मालिकों को मुआवजा देने के लिए अपनाई जाने वाली अनिवार्य प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वाला अनिवार्य अधिग्रहण इसे संवैधानिक नहीं बनाएगा।
- एक वैध अधिग्रहण के लिए उचित और निष्पक्ष मुआवजे का अनुदान सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
- यदि उचित प्रक्रिया स्थापित नहीं की गई है तो अनिवार्य अधिग्रहण असंवैधानिक है जो किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अधिकार से वंचित कर देगा।

नये कानून की आवश्यकता:

- इस फैसले ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कोलकाता नगर निगम द्वारा एक निजी भूमि के अधिग्रहण के बचाव में दायर अपील को खारिज कर दिया गया था।
- अदालत ने निगम को 60 दिनों के भीतर लागत के रूप में 5 लाख रूपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

अनुच्छेद 300A: प्रमुख बिंदु:

- अनुच्छेद 300A घोषित करता है कि 'कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा' और इसे संवैधानिक और मानव अधिकार दोनों के रूप में वर्णित किया गया है, इनका अनुपालन न करना अधिकार का उल्लंघन होगा।
- अदालत ने बताया कि अनुच्छेद 300A कानून के शासन के व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, और न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए।

भूमि अधिग्रहण के लिए संवैधानिक परीक्षण:

सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण के लिए 7 संवैधानिक परीक्षण निर्धारित किये हैं जो इस प्रकार हैं:

- **नोटिस का अधिकार:** राज्य का कर्तव्य व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित करना है। यह अनुच्छेद 19(1)(ए) में दिए गए जानने के अधिकार का एक विस्तारित संस्करण है।
- **सुनवाई का अधिकार:** अधिग्रहण की आपत्तियों को सुनना राज्य का कर्तव्य है।
- **नागरिक को तर्कसंगत निर्णय का अधिकार:** राज्य का कर्तव्य है कि वह संपत्ति अर्जित करने के अपने निर्णय की जानकारी व्यक्ति को दे।
- **केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण करने का कर्तव्य:** राज्य का यह सूचित करने का कर्तव्य है कि अधिग्रहण विशेष रूप से सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है।
- **क्षतिपूर्ति या उचित मुआवजे का अधिकार:** नागरिक को उचित मुआवजा पाने का अधिकार।
- **एक कुशल और शीघ्र प्रक्रिया का अधिकार:** अधिग्रहण की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक और समय के भीतर संचालित करना राज्य का कर्तव्य है।
- **निष्कर्ष का अधिकार:** कार्यवाही का निष्कर्ष या अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करना।

निष्कर्ष:

यह निर्णय कानून के शासन के सिद्धांत की पुष्टि करता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संपत्ति के अधिकारों के सम्मान के महत्व को रेखांकित करता है। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए एक मिसाल कायम करता है कि राज्य के कार्यों को संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और सरकार के मनमाने अतिक्रमण के खिलाफ व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

गंभीर मामलों में भी उचित व नियत प्रक्रिया का पालन करना जरूरी- सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को आतंकी मामले में गिरफ्तारी को अमान्य करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ का फैसला इस बात पर जोर देता है कि आतंकी मामलों में भी उचित और नियत प्रक्रिया मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा कवच है।

मुख्य बिंदु:

- न्यूजक्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ को 3 अक्टूबर 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था, जिसमे दिल्ली पुलिस ने

आरोप लगाया कि न्यूजक्लिक को चीन समर्थक प्रचार के लिए धन मिला था।

- एफआईआर में कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियां), धारा 16 (आतंकवादी अधि नियम), 17 (आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना), धारा 18 (साजिश), और धारा 22 (सी) (कंपनियों, ट्रस्टों द्वारा अपराध) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 120 बी (आपराधिक साजिश) जैसे गंभीर अपराधों का उल्लेख किया गया था।

गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल क्यों?

- न्यूजक्लिक के संस्थापक के अनुसार उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि इसमें उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
- संविधान का अनुच्छेद 22(1), जो गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा के बारे में है, जिसके अनुसार गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता और न ही उसे हिरासत में लिया जा सकता और न ही अपने कानूनी सलाहकार से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि संवैधानिक और वैधानिक जनादेशों को सही अर्थ देने के लिए आवश्यक है कि गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अपवाद के प्रदान किया जाना चाहिए।

क्षेत्र का अंतर	कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया	कानून की उचित प्रक्रिया
दायरा	इसका दायरा संकीर्ण है क्योंकि यह समता और न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने पर संबंधित कानून पर सवाल नहीं उठाता है।	यह सिद्धांत नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक दायरा प्रदान करता है।
व्युत्पत्ति	इस सिद्धांत की उत्पत्ति ब्रिटिश संविधान से हुई है।	इस सिद्धांत की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हुई है।
उद्देश्य	संबंधित विधायिका या निकाय द्वारा विधिवत अधि नियमित कानून वैध है यदि इसे स्थापित करने की प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया गया है।	यह जांच करता है कि कोई भी कानून मनमाना और अन्यायपूर्ण तो नहीं है।
संविधान	भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख किया गया है।	भारत के संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का महत्त्व:

- यह निर्णय भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों की पुष्टि करता है।
- इसके साथ ही यह निर्णय गंभीर आतंकवाद के मामलों में भी उचित प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है तथा मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संदेश देता है।

निष्कर्ष:

यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि न्यूजक्लिक के संस्थापक पर लगे आरोप अभी भी विचाराधीन हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह सुनिश्चित करता है कि उनको निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिले और उनके साथ उचित प्रक्रिया के तहत उचित व्यवहार किया जाए।

सीबीआई में केंद्र सरकार की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस दावे को स्वीकार करने से मना कर दिया है कि उसका केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर कोई नियंत्रण नहीं है, साथ में यह भी प्रश्न किया है कि मामलों की जांच के लिए प्रमुख जांच एजेंसी को राज्यों में और कौन भेज सकता है?

घटनाक्रम:

पश्चिम बंगाल सरकार का तर्क:

- पश्चिम बंगाल राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत एक मूल मुकदमा दायर किया, जिसमें केंद्र सरकार पर राज्य के अधिकार क्षेत्र के मामलों में सीबीआई को जांच के लिए अधिकृत करके हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया।
- पश्चिम बंगाल ने नवंबर 2018 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 (डीएसपीई अधिनियम, 1946) की धारा 6 के तहत अपने क्षेत्र के भीतर सीबीआई जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी। किंतु सीबीआई ने इस दौरान पश्चिम बंगाल में 15 से अधिक मामले दर्ज किए हैं।

केंद्र सरकार का तर्क:

- सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया है कि मुकदमा चलाने योग्य नहीं है और इसे शुरू में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल ने मुकदमे में गलत तरीके से संघ को प्रतिवादी बनाया था।
- याचिकाकर्ताओं द्वारा सीबीआई को 'संघ का पुलिस बल' कहना गलत है। सीबीआई ने कहां और कैसे जांच की, इसमें केंद्र की

कोई भूमिका नहीं है।

न्यायपालिका का प्रश्न:

- न्यायमूर्ति मेहता ने सॉलिसिटर जनरल का ध्यान दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 अधिनियम की धारा 5(1) की ओर आकर्षित करते हुए इस दावे पर सवाल उठाया, जो सीबीआई को नियंत्रित करता है।
- यह धारा केंद्र सरकार को अपराधों की जांच के लिए केंद्र शासित प्रदेश के अलावा राज्य के किसी भी क्षेत्र में सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अधिकृत करती है।
- सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि सीबीआई को प्रतिवादी बनाने के लिए मुकदमे में संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 131 के तहत एक 'राज्य' नहीं है। मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 131 के तहत मूल मुकदमे केवल केंद्र और राज्यों से जुड़े विवादों के लिए दायर किए जा सकते हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में:

- सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अधीन एक गैर-वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा की गई थी।
- इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों पर की गई थी, जिसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से शक्ति प्राप्त हुई थी।

सीबीआई के सामने चुनौतियाँ:

- सीबीआई पर प्रमुख राजनेताओं से जुड़े मामलों में जैसे बोफोर्स घोटाला, हवाला कांड, संत सिंह चटवाल मामला, भोपाल गैस त्रासदी और 2008 नोएडा दोहरे हत्याकांड (आरुषि-हेमराज हत्याकांड) जैसे संवेदनशील मामलों को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया गया है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी पहले भी अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सीबीआई की आलोचना करते हुए इसे 'पिंजरे में बंद तोता जो अपने मालिक की आवाज में बोल रहा है' करार दिया था।
- सरकारों द्वारा एजेंसी का इस्तेमाल गलत कामों को छुपाने, गठबंधन में सामंजस्य बनाए रखने और राजनीतिक विरोधियों को नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता रहा है।
- सीबीआई के पास सीमित शक्ति है क्योंकि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों से पूछताछ या जांच करने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो नौकरशाही के उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है।
- जांच के लिए सीबीआई की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार की सहमति पर निर्भर करते हैं, जो इसकी जांच की सीमा को सीमित करता है।

आगे की राह:

सीबीआई के कामकाज पर कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 24वीं रिपोर्ट में कई प्रमुख उपायों की सिफारिश की गई है। इसमे शामिल है:

- एजेंसी की ताकत बढ़ाकर मानव संसाधन को मजबूत करना।
- बुनियादी सुविधाओं में बेहतर निवेश करना।
- वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना और प्रशासनिक सशक्तिकरण प्रदान करना।
- संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची से सम्बन्धित विषयों पर सीबीआई को अधिक शक्तियां प्रदान करना।
- इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में डीएसपीई अधिनियम को बदलने के लिए 'केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो अधिनियम' नामक एक अलग कानून बनाने का सुझाव दिया गया है।

SUBSCRIBE TO OUR
YOUTUBE CHANNEL
DHYEYA TV QR
BATEN UP KI QR
Follow the below mentioned instructions :
Scan the above QR Code on your phone. | Click on the link. | Subscribe to our channel. | Get updated on Current Affairs & UP Specific News.

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे

राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत के बाद कैसे होंगे ईरान में राजनीतिक और शक्ति समीकरण

हाल ही में ईरान के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियन की मौत हो गई। इसके बाद ईरान के उप-राष्ट्रपति मुहम्मद मोखबर (जो भारत के लिए ईरान के विशेष दूत भी हैं) को अगले 50 दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। ईरान के संविधान के अनुसार अगले 50 दिनों के अंदर ईरान को अपना नया राष्ट्रपति चुनना होगा।

ईरान में हुई इस विमान दुर्घटना की जांच पड़ताल होनी शुरू हो गई है कि ये हादसा कहीं किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं था। ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद अब इस बात की चर्चा शुरू हो गयी है कि विश्व एवं मिडिल ईस्ट की राजनीति में ईरान किस तरीके से नेतृत्व करेगा। क्या इससे ईरान का शासन प्रभावित होगा और क्या ईरान का प्रभाव घटेगा। ये प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति ईरान के हितों के लिए कट्टरपंथी और आक्रामक सोच के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में ईरान ने कोई समझौतावादी रूख नहीं अपनाया बल्कि प्रतिशोध की राजनीति को ही बढ़ावा दिया। कुछ ही समय पहले इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान कहा था कि यदि इजरायल ईरानी धरती पर कोई हमला करता है तो उसे इसके गंभीर दुष्परिणाम झेलने होंगे।

हाल के समय में, ईरान ने जिस तरीके से यमन के हूतियों को समर्थन देकर सऊदी अरब को चुनौती दी और हमास को समर्थन देकर इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोला था उससे ईरान के मंसूबे साफ हो गये थे। ईरान पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि हुती विद्रोहियों को ईरान हथियार भी दे रहा है। यमन की अधिक आबादी हुती विद्रोहियों के नियंत्रण में रहती है। उनका संगठन देश के उत्तरी हिस्से में टैक्स वसूलता है और अपनी मुद्रा भी छापता है। अमेरिका और सऊदी अरब कहते हैं कि ईरान ने हुती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किया था, जिनका उपयोग 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमले के लिए किया गया था। इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया था। सऊदी अरब ने ईरान पर हुती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइल और ड्रोन देने का भी आरोप लगाया है, जिन्हें 2019 में सऊदी अरब के तेल कारखानों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था। हुती विद्रोही सऊदी अरब पर कम रेंज वाली हजारों मिसाइल दाग चुके हैं और उन्होंने यूएई को भी निशाना बनाया है। इस तरह के हथियारों की सप्लाई करने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र की ओर से हथियारों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करना, लेकिन ईरान इन सभी आरोपों को खारिज करता है।

ईरान के राजनीतिक समीकरण पर प्रभावः

- भले ही इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे किन्तु, देश की विदेश और क्षेत्रीय नीतियां मोटे तौर पर अयातुल्लाह खमेनी के निर्देश पर ही चलती थीं और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर इसमें मदद की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी।
- रिवोल्यूशनरी गार्ड और कुद्स फोर्स जैसी इसकी शाखाएं पूरे मध्य पूर्व में हथियारबंद लड़ाकों का वो मोर्चा खड़ा करने में कामयाब रही हैं, जिसे ईरान 'प्रतिरोध की धुरी' कहता है। इन संगठनों की मदद से ईरान काफी हद तक किसी भी घटना से अपना पल्ला झाड़ पाने में सफल रहता है।
- इसमें यमन में हूती, लेबनान में हिज्बुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास के अलावा, इराक, सीरिया और अन्य देशों में कई छोटे छोटे अन्य संगठन भी शामिल हैं। हो सकता है कि रईसी की मौत की वजह से होने वाले सत्ता परिवर्तन का उसकी भू-सामरिक योजनाओं पर बहुत व्यापक या सीधा असर न पड़े। अगर सारे नहीं, तो ज्यादातर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) की मदद से अयातुल्लाह ही निर्णय प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं।
- 1979 में अपनी स्थापना के बाद से अपनी तय भूमिका के चलते इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर न केवल एक सैन्य संगठन के

तौर पर खुद को बहुत मजबूत बना लिया है, बल्कि वो सियासी और आर्थिक तौर पर भी काफी ताकतवर हो गई है। यहां ईरान के भीतर सैन्य जिम्मेदारियों का विभाजन समझना भी बहुत जरूरी है।

- ईरान की सेना की जिम्मेदारी, देश की संप्रभुता की रक्षा करने की है। वहीं आईआरजीसी का उत्तरदायित्व इस्लामिक गणराज्य की अक्षुण्णता और ताकत के साथ-साथ अयातुल्लाह की हिफाजत करना है।
- उदाहरण के तौर पर पिछले महीने अमेरिका ने भारत की जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे, वह कंपनिया जो सामान ईरान को बेच रही थी, उनका इस्तेमाल आईआरजीसी के व्यापक ड्रोन कार्यक्रम में होना था, जो न केवल पूरे मध्य पूर्व में, बल्कि यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं।

ईरान की भू राजनीतिक सामरिक नीति कैसी होगी:

- अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के विश्लेषकों का मानना है कि रईसी की मौत के बाद जानकार कहते हैं कि ईरान की नीति में दीर्घकालिक कोई बदलाव नहीं दिखेगा। यह जरूर है कि रईसी के जाने से पश्चिम के सामने तात्कालिक तौर पर ईरान का वह रूढ़िवादी चेहरा हट गया है, जो अमेरिका और इजरायल के विरोध का प्रतीक बन गया था।
- 2021 में एक विवादित और नियंत्रित चुनाव में जीतने के बाद रईसी परमाणु बातचीत को लेकर सख्त रुख अपनाने को लेकर चर्चा में रहे। जिस साल उन्होंने चुनाव जीता यह वो साल था कि जब ईरान में ऐतिहासिक तौर पर सबसे कम वोटिंग हुई।
- रईसी घरेलू राजनीति में हार्डलाइनर और ताकतवर चेहरों में शुमार हो गए, जो हमेशा विवादों में ही रहे। ईरान की घरेलू राजनीति में तो उनकी छवि बेहद कट्टरपंथी नेता के तौर पर उभर कर आई थी। उनके चुनाव के एक साल बाद ही उनकी ओर से हिजाब कानून को और सख्ती से लागू करवाने से देश में आंदोलन खड़ा हो गया था।
- इस कानून का मकसद महिलाओं के कपड़े और व्यवहार पर अकुंश लगाना था। कुर्दिश इरानी महिला माशा अमीनी की मोरल पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई। इसके बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। आंदोलन को बेहद कठोरता के साथ दबाया गया। आंदोलनकारियों को फांसी दी गई।
- यूरोनियम का संवर्धन हो, या फिर ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में प्रवेश के जरिए डी-डॉलरीकरण की नीति को आगे बढ़ाना, ईरान दशकों से जिस विदेश नीति पर चल रहा था, उससे हटने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे।
- यूक्रेन में रूस के हमले के मामले में रूस का साथ देने, सऊदी अरब के साथ राजनयिक रिश्ते बहाल होने के बाद भी ईरान के हितों को गंभीरता से देखने की नीति जारी रहेगी।
- मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव के बीच रईसी की मौत से ईरान की शासन व्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि ईरान के सभी बड़े फैसले इस्लामिक देश के धर्मगुरु सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई लेते हैं।

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की भूमिका:

- ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं जो देश से जुड़े सभी मामलों पर अंतिम फैसला देते हैं। ईरान का सुप्रीम लीडर ही राष्ट्र प्रमुख होता है और 'कमांडर इन चीफ' भी होता है।
- सुप्रीम लीडर ही ईरान में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। 85 साल के खामेनेई 1989 में अपने पिता और इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के संस्थापक अयातुल्ला रुहोल्लाह खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता बने थे। उसके बाद से ही खामेनेई की ईरान की राजनीति और सेना पर मजबूत पकड़ बनी हुई है और उन्होंने सत्ता के सामने आने वाली चुनौतियों को कुचलने के लिए कई बार हिंसा तक का सहारा लिया है।
- अयातुल्ला खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति को एक्टिवेट करने वाले रणनीतिकार हैं इसलिए नए राष्ट्रपति के जरिए ईरान के हितों को ध्यान में रखकर काम कराने की युक्ति बनाने के लिए निगाहें ईरान के सुप्रीम लीडर पर हैं।
- ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध करने का तरीका वैसे ही जारी रहेगा। अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) के पर्यवेक्षकों को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स की जांच पड़ताल की कार्यवाही करने में पहले की तरह मुश्किलें जारी रहेंगी।

भारत-ईरान संबंध:

- भारत ने ईरान के साथ चाबहार स्थित शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए समझौता किया है। ईरान के साथ भारत के संबंध अभी भी समान स्तर पर बने हुए हैं।
- रईसी ने 2021 में राष्ट्रपति का पद संभाला था और इस दौरान दोनों नेताओं की कोई द्विपक्षीय यात्रा नहीं हुई थी लेकिन मोदी और रईसी ने ब्रिक्स और एससीओ शिखर सम्मेलनों के दौरान मुलाकात की

और व्यापार, संपर्क, आतंकवाद-रोधी और लोगों से लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी।

- मध्य-पूर्व में भारत के हितों के लिहाज से ईरान महत्वपूर्ण है। खाड़ी देशों से अच्छे संबंध रखते हुए भी भारत ईरान से अपने संबंधों को सामान्य रख पाता है ये भारत की कूटनीतिक उपलब्धि है। वहीं भारत ईरान संबंधों में चीन न आड़े आए, इसके लिए भी दोनों देश सहयोग को बढ़ा रहे हैं।
- भारत अमेरिका संबंध और अमेरिकी कैटसा कानून के प्रभावों के बाद भी भारत और ईरान के संबंध सामान्य हैं बल्कि रणनीतिक रूप से मजबूत ही होते पाए गए हैं।
- हमास, हुती विद्रोहियों को अपने क्षेत्रीय हितों की वजह से समर्थन देने वाले ईरान ने आतंकवाद निरोधक सहयोग हेतु भारत को समय -समय पर आश्वासन दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय संक्षिप्त मुद्दे

वियतनाम को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

चर्चा में क्यों?

दक्षिणपूर्वी देश से आयातित वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च करों से बचने के लिए, वियतनाम अमेरिकी प्रशासन पर अपनी 'गैर-बाजार अर्थव्यवस्था' वर्गीकरण को 'बाजार अर्थव्यवस्था' में बदलने के लिए दबाव डाल रहा है।

गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाएँ क्या हैं?

अमेरिका कई कारकों के आधार पर किसी देश को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नामित करता है। इसमे शामिल है:

- यदि देश की मुद्रा परिवर्तनीय है।
- यदि मजदूरी दरें श्रम और प्रबंधन के बीच मुक्त सौदेबाजी द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- यदि संयुक्त उद्यम या अन्य विदेशी निवेश की अनुमति हैं।
- यदि राज्य संसाधनों के आवंटन और मूल्य और उत्पादन निर्णयों को नियंत्रित करता है।
- मानवाधिकार जैसे अन्य कारकों पर भी विचार किया जाता है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति अमेरिका के साथ व्यापार को कैसे प्रभावित करती है:

- गैर-बाजार अर्थव्यवस्था लेबल अमेरिका को नामित देशों से आयातित वस्तुओं पर 'एंटी-डंपिंग' शुल्क लगाने की अनुमति देता है। एंटी-डंपिंग शुल्क अनिवार्य रूप से आयातित वस्तुओं के निर्यात मूल्य और उनके सामान्य मूल्य के बीच अंतर की भरपाई करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, डंपिंग तब होती है जब किसी देश की निर्यात कीमतों को जानबूझकर घरेलू कीमतों से नीचे निर्धारित किया जाता है, जिससे आयात करने वाले देश में उद्योगों को नुकसान होता है।
- एंटी-डंपिंग शुल्क का स्तर तीसरे देश, उदाहरण के लिए, बांग्लादेश, जो एक बाजार अर्थव्यवस्था है, के अनुकूल मान करके निर्धारित किया जाता है।
- अमेरिका वियतनाम जैसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था से आयात किए जाने वाले उत्पाद के मूल्य का आकलन इस आधार पर करता है कि बांग्लादेश में इसकी कीमत क्या है और फिर यह मान लेता है कि यह वियतनाम की कंपनी के लिए भी अनुमानित उत्पादन लागत है। लागत के बारे में कंपनी के अपने डेटा पर विचार नहीं किया जाता है।

निष्कर्ष:

बाजार अर्थव्यवस्था का लेबल प्राप्त करने की दिशा में वियतनाम की यात्रा में महत्त्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख कंपनी, जैसे यूएस स्टील निर्माता और अमेरिकन श्रिम्प प्रोसेसर्स एसोसिएशन, बाइडेन प्रशासन से वियतनाम की स्थिति में बदलाव के खिलाफ आग्रह कर रहे हैं। एसोसिएशन के तर्क अनुसार, वियतनाम के भूमि स्वामित्व प्रतिबंधों, कमजोर श्रम कानूनों उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी कांग्रेस में भी इसका विरोध हो रहा है, जहां आठ अमेरिकी सीनेटरों और 31 हाउस प्रतिनिधियों के एक समूह ने आशंका व्यक्त की है कि इस तरह के बदलाव से वियतनाम में भारी निवेश करने वाली चीनी फर्मों को फायदा होगा। उनका तर्क है कि यह परिवर्तन संभावित रूप से इन कंपनियों को अमेरिकी टैरिफ को अधिक आसानी से बायपास करने में सक्षम बना सकता है, जिससे भविष्य में जटिलता बढ़ जाएगी।

विश्व प्रवासन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की। यह रिपोर्ट वैश्विक प्रवासन पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलावों का खुलासा करती है।

रिपोर्ट की प्रमुख बातें:

- शीर्ष गंतव्य देशों में, खाड़ी देशों (जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत शामिल हैं) में महिला अप्रवासियों की तुलना में पुरुषों की हिस्सेदारी कहीं अधिक है।
- रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया एकमात्र गैर-खाड़ी देश है जहां पुरुष प्रवासियों का अनुपात महिलाओं की तुलना में काफी अधिक है।
- पाकिस्तान और बांग्लादेश छठे और आठवें स्थान पर हैं। यह देश अंतरराष्ट्रीय प्रेषण के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से थे, जिन्होंने लगभग $30 बिलियन और $21.5 बिलियन प्राप्त किए।
- अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की वैश्विक आबादी लगभग 281 मिलियन है तथा संघर्ष, हिंसा, आपदाओं और अन्य कारकों से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 117 मिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण, जिसमें 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण गिरावट का अनुभव हुआ था, जो कि अब फिर से बढ़ गया है। 2022 में, प्रवासियों ने वैश्विक स्तर पर अनुमानित $831 बिलियन का प्रेषण भेजा, जो कि 2021 के $791 बिलियन से 5% की वृद्धि और 2020 के $717 बिलियन से 16% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है।
- इसके अलावा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण प्राप्तियों में 8% की वृद्धि हुई है, जो 2021 में $599 बिलियन से बढ़कर 2022 में $647 बिलियन हो गई है।

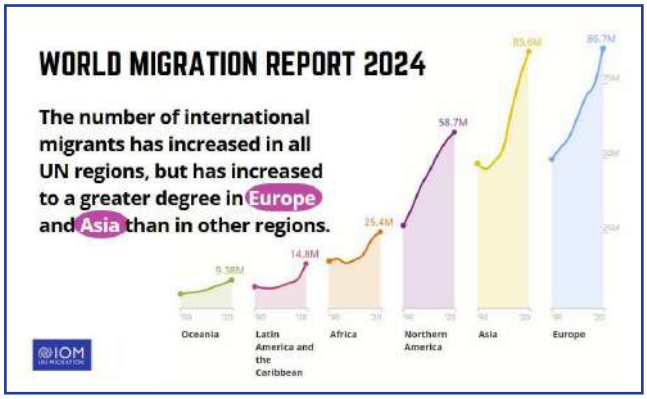

भारत में स्थिति:

- भारत, 2022 में 111 बिलियन डॉलर के साथ विदेश से सबसे अधिक धन प्राप्तकर्ता था। इसकी प्रेषण प्राप्तियां अपने निकटतम समकक्षों मेक्सिको ($61.1 बिलियन), चीन ($51 बिलियन), फिलीपींस ($38.05 बिलियन) और फ्रांस ($30.04 बिलियन) से कहीं आगे थीं।
- भारत दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों (लगभग 18 मिलियन) का उद्गम स्थल भी है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों में रहते हैं।
- रिपोर्ट के मुताबिक, 2010 से 2022 तक भारत की प्राप्तियां दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 2010 में देश को 53.48 अरब डॉलर, 2015 में 68.91 अरब डॉलर और 2020 में 83.15 अरब डॉलर मिले।
- भारत में पुरुषों की तुलना में महिला अप्रवासियों का अनुपात थोड़ा बड़ा था। इस बीच, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में पुरुष प्रवासियों का प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से उच्च है।

निष्कर्ष:

दक्षिण एशिया में कई लोगों के लिए प्रेषण एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में काम करता है, लेकिन इस क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों को कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इनमें वित्तीय शोषण, प्रवासन व्यय से बोझिल ऋण, विदेशी द्वेष और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार शामिल हैं। प्रेषण की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, प्रवासी श्रमिकों के सामने चुनौतियां बनी हुई हैं, जोकि बेहतर सुरक्षा और सहायता प्रणालियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

भारत इंडोनेशिया रक्षा संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के रक्षा सचिव और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के महासचिव ने नई दिल्ली में 7वीं भारत-इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के बढ़ते दायरे पर संतोष व्यक्त किया।
- रक्षा सहयोग और रक्षा उद्योगों पर कार्य समूहों की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा सह-अध्यक्षों द्वारा की गई।
- दोनों पक्षों ने सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को बढ़ाने के साधनों की पहचान की, विशेष रूप से रक्षा उद्योग संबंधों, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में।
- इंडोनेशिया के प्रतिनिधि ने भारत फोर्ज, महिंद्रा डिफेंस और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड जैसे अन्य भारतीय रक्षा उद्योग भागीदारों के साथ भी विचार-विमर्श किया और अनुसंधान और संयुक्त उत्पादन में सहयोग के माध्यम से रक्षा औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

भारत-इंडोनेशिया रक्षा संबंध:

- दोनों देशों की तीन सेनाओं के बीच परिचालन स्तर पर नियमित रूप से वार्ता की जाती रही हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा की जाती है।
- भारत और इंडोनेशिया के बीच 'गरुड़ शक्ति' नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है।

अन्य सम्बन्ध:

- आसियान (ASEAN) क्षेत्र में इंडोनेशिया भारत का दूसरा सबसे

बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बनकर उभरा है। भारत, इंडोनेशिया के कोयले और कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है।

- रामायण और महाभारत के महान महाकाव्यों की कहानियाँ इंडोनेशियाई लोक कला और नाटक को प्रेरित करती हैं।

इंडोनेशिया:

- इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसके पड़ोसी देश सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते और ऑस्ट्रेलिया हैं। बड़े द्वीप हैं: सुमात्रा, कालीमंतन, सुलावेसी, जावा और पापुआ। इन पांच द्वीपों के बीच, जावा सबसे छोटा द्वीप है, लेकिन लगभग दो तिहाई इंडोनेशियाई लोग जावा में रहते हैं।

निष्कर्ष:

भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है और वे इंडो-पैसिफिक के साझा दृष्टिकोण पर पहुंचे हैं। वर्तमान समय में, इस साझेदारी की विशेषता द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग है, जिसमें लगातार उच्च-स्तरीय बातचीत भी शामिल है। इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नाइजीरिया दौरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव, अमरदीप सिंह भाटिया के नेतृत्व में भारत के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नाइजीरिया का दौरा किया और अबूजा में नाइजीरियाई समकक्षों के साथ एक संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की बैठक की। बैठक के दौरान भारत और नाइजीरिया ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चर्चा हुई।

संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी):

- भारत और नाइजीरिया 2017 में चल रहे द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों की समीक्षा के लिए भारतीय पक्ष से वाणिज्य सचिव और नाइजीरियाई पक्ष से स्थायी सचिव (व्यापार) के स्तर पर एक संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) स्थापित की थी।

बैठक के मुख्य बिंदु:

- दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार के साथ-साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश को बढ़ाने के लिए फोकस के कई क्षेत्रों की पहचान की।
- इनमें दोनों पक्षों के बाजार तक पहुंचने के मुद्दों को हल करना और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, फार्मास्यूटिकल्स, यूपीआई, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, बिजली क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा, परिवहन, रेलवे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।
- वे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को शीघ्र संपन्न करने पर भी सहमत हुए।
- नाइजीरिया अफ्रीका क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- भारत और नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 11.8 बिलियन डॉलर से घटकर 2023-24 में 7.89 बिलियन डॉलर हो गया।
- 27 अरब डॉलर के कुल निवेश के साथ, लगभग 135 भारतीय कंपनियां नाइजीरिया में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। ये निवेश बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं सहित विविध क्षेत्रों में होते हैं।

भारत और नाइजीरिया संबंध:

- भारत और नाइजीरिया के बीच सम्बन्ध औपनिवेशिक काल के पहले से है। 1 अक्टूबर, 1960 को नाइजीरिया के स्वतंत्र होने से दो साल पहले, भारत ने नवंबर 1958 में लागोस में अपना डिप्लोमैटिक हाउस स्थापित किया था।
- **व्यापार समझौता:** 1983 में भारत सरकार और नाइजीरिया सरकार के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** दोनों देश दक्षिण-दक्षिण सहयोग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र, जी77 और एनएएम जैसे बहुपक्षीय संगठनों में।
- **लोकतंत्र:** दोनों देश बहु-धार्मिक, बहु-जातीय और बहुभाषी समाज वाले बड़े विकासशील और लोकतांत्रिक देश हैं।
- **क्षेत्रीय प्रभाव:** नाइजीरिया की अफ्रीका में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और महाद्वीप पर उच्चतम जीएनपी है, जो इसे क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाता है।
- **शांति स्थापना:** नाइजीरिया संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और भारत ने नाइजीरिया सहित अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भी सैनिकों का योगदान दिया है।

निष्कर्ष:

नाइजीरिया और भारत के बीच ऐतिहासिक रूप से सौहार्दपूर्ण और सुखद संबंध रहे हैं। वर्तमान में, भारत रियायती ऋण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के रूप में विकासात्मक सहायता प्रदान करके नाइजीरिया का विकास भागीदार बन रहा है।

100 रुपये के नोट पर नेपाल का नया मानचित्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेपाल ने 100 रुपये के नए नोट पर एक नया मानचित्र लगाने का फैसला किया जिस पर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी के विवादास्पद क्षेत्रों को दर्शाया गया है। इसके बाद नई दिल्ली और काठमांडू के बीच तनाव उत्पन्न हो गया।

हालिया दिनों में विवाद के घटनाक्रम:

- पिछले हफ्ते की कैबिनेट बैठक में नेपाल राष्ट्र बैंक को देश के नए नक्शे के साथ सौ रुपये के नोट छापने की मंजूरी देने का फैसला किया गया था।
- लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को भारत ने पूर्व में नवंबर 2019 के अपने नक्शे में शामिल किया था।
- नेपाल ने जून 2020 में देश के नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दी थी जिसमें नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे में लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा में दिखाया गया है।

- वर्ष 1997-1998 के दौरान प्रधानमंत्री आई. के. गुजराल ने वादा किया था कि यदि नेपाल अपने दावे के लिए सबूत पेश करने में सक्षम हो तो वे इन क्षेत्रों को छोड़ देंगे।

आगे की राह:

दोनों देशो को घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक संधि, दस्तावेजों, तथ्यों और नक्शों के आधार पर सीमा के मुद्दों का कूटनीतिक हल प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध होना चाहिए तथा सीमा विवाद सुलझाने के लिए 'गिव एंड टेक पॉलिसी' को यथार्थ करना चाहिए। जैसा कि भारत ने 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद को सुलझाया।

मालदीव के विदेश मंत्री की भारत यात्रा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री की भारत यात्रा राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है।

हालिया दिनों में दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध:

- मोहम्मद मुइज्जू ने अपने चुनाव अभियान के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया। जिससे दोनों देश के संबंधों में तनाव पैदा हो गया।
- भारत एवं मालदीव के मध्य तनाव का एक कारण मालदीव के साथ चीन की निकटता भी है। इस निकटता का मुख्य कारण चीन द्वारा मालदीव को भारत के विरूद्ध कर स्वयं के भू-राजनैतिक हितों की पूर्ति एवं आर्थिक संवृद्धि हेतु शिपिंग लेन का उपयोग शामिल है।
- लक्षद्वीप द्वीपों की प्रचार यात्रा के बाद भारतीय प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणियों से उत्पन्न राजनयिक विवाद के कारण मालदीव में पर्यटन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है।

मालदीव के विदेश मंत्री की भारत यात्रा का एजेंडा:

- 2023 के अंत तक मालदीव पर भारत का लगभग 400.9 मिलियन डॉलर बकाया है। उन्होंने नई दिल्ली से मालदीव को ऋण राहत प्रदान करने का आग्रह किया।
- मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर 50 मिलियन डॉलर के राजकोषीय बिल को एक और वर्ष के लिए आगे बढ़ाते हुए मालदीव को महत्वपूर्ण बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है।
- भारत और मालदीव ने भारतीय विमानन प्लेटफार्मों के निरंतर संचालन को सक्षम करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो मालदीव के लोगों को मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करते हैं।
- मालदीव द्वारा भारतीयों से द्वीपसमूह की अर्थव्यवस्था में योगदान देने का आग्रह किया। जो पर्यटन पर काफी हद तक निर्भर है।

भारत के लिए मालदीव का महत्त्व:

- **व्यापार मार्ग:** अदन की खाड़ी और मलक्का जलडमरूमध्य के बीच महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित, मालदीव भारत के लगभग आधे विदेशी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात के लिए 'टोल गेट' के रूप में कार्य करता है।
- **सामरिक महत्व:** मालदीव रणनीतिक रूप से हिंद महासागर में स्थित है और इसकी स्थिरता और सुरक्षा भारत के हित में है।

आगे की राह:

भारत-मालदीव संबंधों का विकास भू-राजनीतिक गतिशीलता, नेतृत्व में परिवर्तन और साझा क्षेत्रीय हितों के संयोजन को दर्शाता है। भारत मालदीव के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम है और संबंध बनाने की दिशा में हमेशा अतिरिक्त प्रयास करता रहा है। अत: भविष्य के लिए एक मजबूत, अधिक लचीली और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं।

न्यू कैलेडोनिया में अशांति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फ्रांस ने अपने प्रशांत द्वीपीय क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल की घोषणा कर दी है।

कारण:

- मई, 2024 में, पेरिस द्वारा एक संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी गयी।
- यह विधेयक फ्रांसीसी निवासियों को प्रांतीय चुनावों में वोट डालने की अनुमति देगा, जो न्यू कैलेडोनिया में 10 साल से अधिक समय से रह रहे हैं।
- कई स्वतंत्रता समर्थक कनक इसे अपने वोटों के महत्व के कमी के रूप में देखते हैं।
- दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में स्थित न्यू कैलेडोनिया में विविध आबादी है, जिसमें कनक स्वदेशी लोग और फ्रांसीसी निवासी शामिल हैं, जिससे न्यू केलेडोनिया में हिंसा भड़क उठी और तीन लोगों की मौत हुई।

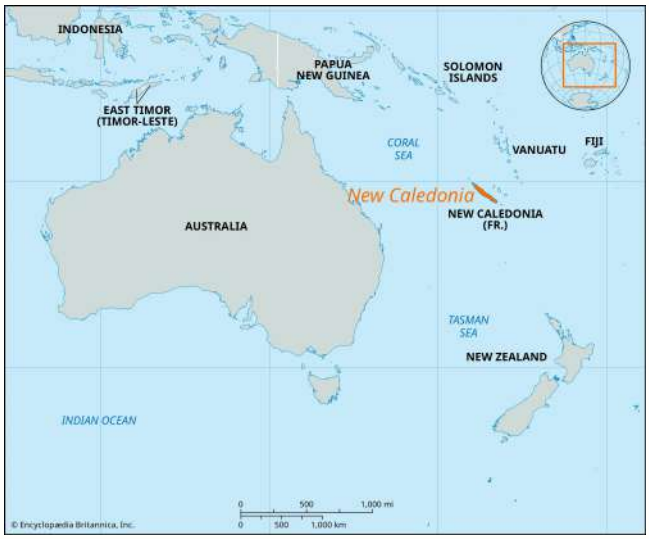

फ्रांस–न्यू कैलेडोनिया के बीच ऐतिहासिक सम्बंधः

- इस द्वीप में, जहाँ 41% मेलानेशियाई कनक और 24% यूरोपीय मूल के लोग हैं। कनक, आम तौर पर स्वतंत्रता के पक्षधर हैं जबकि यूरोपीय मूल के समूह और अन्य अप्रवासी चाहते हैं कि फ्रांसीसी शासन जारी रहे।
- 1998 में, द्वीप को सीमित स्वायत्तता प्रदान करने के लिए फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया के बीच नौमिया समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- इसके अलावा, तीन जनमत संग्रह- 2018, 2020 और 2021 में - स्वतंत्रता के प्रश्न पर आयोजित किए गए हैं। तीनों मामलों में, बहुमत ने स्वतंत्रता के खिलाफ मतदान किया।

न्यू कैलेडोनिया का महत्त्वः

- न्यू कैलेडोनिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने प्रशांत क्षेत्र में फ्रांस का प्रभाव बढ़ाने की जो योजना बनाई है, यह द्वीप उसके केंद्र में हैं।
- फ्रांस इस क्षेत्र में एक मजबूत उपस्थिति बनाए रखने के साथ-साथ महत्वपूर्ण शिपिंग लेन तक पहुंच में फ्रांसीसी कंपनियों के लिए लाभ देखता है।
- दुनिया में निकेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश न्यू कैलेडोनिया भूराजनीति के लिहाज से प्रशांत महासागर के बेहद जटिल समुद्री क्षेत्र में मौजूद है।

न्यू कैलेडोनियाः

- न्यू कैलेडोनिया ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1400 किमी पूर्व में प्रशांत महासागर के मेलानेशियन भाग में एक द्वीपसमूह है। इस प्रकार न्यू कैलेडोनिया ओशिनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है और दुनिया का 156वां सबसे बड़ा देश है।
- प्रति वर्ग किमी. 14 निवासियों के साथ यह पृथ्वी पर सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। नौमिया में हर तीसरे से अधिक निवासी रहते हैं।

आगे की राहः

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने न्यू कैलेडोनिया के बीच शांति और बातचीत का आह्वान किया है जिससे दोनों के संबंधो में स्थायित्व आ सके। फ्रांस को कनक समुदाय की चिंताओं को ध्यान में रखते ही हल निकालना होगा।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त समिति की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त समिति की पहली बैठक कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गयी हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच मौजूदा आर्थिक संबंधों की साझेदारी पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्य बिंदुः

- यह मुक्त व्यापार समझौते के लिए के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार उप सचिव जॉर्ज मीना ने भाग लिया।
- बैठक में भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) के कार्यान्वयन और दोनों देशों में व्यवसायों के सामने आने वाले बाजार पहुंच के मुद्दों के समाधान के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा हुई।
- बैठक में निवेश को बढ़ावा देने और नए क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई।
- Ind-Aus ECTA के तहत, दोनों पक्षों ने कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें जैविक उत्पादों जैसे भिंडी, अनार, अंगूर, पनीर, मैकाडामिया नट्स, दाल और एवोकैडो के लिए बाजार पहुंच शामिल है।
- बैठक में संयुक्त समिति के लिए प्रक्रिया के नियमों को भी अपनाया गया और मासिक आधार पर आयात डेटा के नियमित आदान-प्रदान के लिए एफटीए के लिए का पहला संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया।

- इसने कुछ महत्वपूर्ण सेवा मुद्दों को भी संबोधित किया, जिसमें सीमा पार ई-भुगतान की सुविधा के लिए और नर्सिंग और दंत चिकित्सा जैसे व्यवसायों में पारस्परिक मान्यता समझौतों पर विचार शामिल है।
- इसके अलावा, यूके-ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप लेबर मार्केट टेस्टिंग आवश्यकता को हटाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई, साथ ही दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य कर्मियों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने, टेली-मेडिसिन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की गई।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध:

- ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक व्यापार 2023-24 में लगभग 24 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाएगा।
- वित्त वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलिया को भारत का कुल निर्यात 8 बिलियन डॉलर के करीब रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। दोनों देश एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं।
- आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए), एक लघु व्यापार सौदा, पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के नेतृत्व वाली केंद्र-दक्षिणपंथी सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
- इस समझौते से ऑस्ट्रेलिया को भारतीय निर्यात के 96 प्रतिशत मूल्य पर शुल्क समाप्त हो गया, जिसमें कई श्रम-गहन क्षेत्रों के निर्यात शामिल थे। हालाँकि, यह समझौता ऑस्ट्रेलियाई संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट के साथ मेल खाता है जिसमें भारत में बाल श्रम पर चिंता जताई गई है।

निष्कर्ष:

संयुक्त समिति की बैठक ने मजबूत और पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक संबंधों के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिससे सहयोग और समृद्धि में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। बैठक में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए व्यवसायों और सरकारों की उत्सुकता पर प्रकाश डाला गया, जिससे दोनों देशों के व्यवसायों और नागरिकों को महत्वपूर्ण लाभ होगा।

आर्मेनिया व अजरबैजान के बीच शांति समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान सीमा के एक हिस्से पर एक समझौते पर पहुंचे, जिसके तहत आर्मेनिया तावुश प्रांत के चार गांवों को अजरबैजान को सौंप देगा।

वर्तमान स्थिति:

- नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र पर कड़े संघर्ष के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान ने पहला सीमा चिन्ह लगा दिया है। दोनों देशों के विशेषज्ञ शांति प्रक्रिया के तहत अपनी सीमाओं का सीमांकन करने पर काम कर रहे हैं।
- 1990 के दशक से अर्मेनियाई बलों के नियंत्रण में रहे नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र पर अजरबैजान द्वारा पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के बाद दोनों देश शांति संधि की दिशा में काम कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि:

- नागोर्नो-काराबाख जोकि अजरबैजान का एक क्षेत्र हैं। सोवियत संघ के पतन के बाद से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद का मुद्दा रहा है।
- इस क्षेत्र में मुख्यत: अर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं तथा इसने 1991 में अजरबैजान से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध हुआ जो 1994 तक चला।
- 1994 में युद्धविराम पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन वर्षों तक छिटपुट झड़पें जारी रहीं।
- 2020 में, छह सप्ताह के युद्ध के परिणामस्वरूप अजरबैजान ने क्षेत्र पर दोबारा कब्जा कर लिया।

संघर्ष के कारण:

ऐतिहासिक संदर्भ:

- नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र में अर्मेनियाई और अजरबैजानियों के बीच 20वीं शताब्दी की शुरुआत से जातीय और क्षेत्रीय विवादों का एक लंबा इतिहास है। सोवियत काल के दौरान, अर्मेनियाई बहुसंख्यक आबादी के बावजूद, नागोर्नो-काराबाख अजरबैजान सोवियत समाजवादी गणराज्य के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र था।

जातीय संघर्ष:

- यह क्षेत्र जातीय रूप से अर्मेनियाई है लेकिन अजरबैजान की सीमाओं के भीतर स्थित है। नतीजतन, अर्मेनियाई और अजरबैजानियों दोनों ने इस क्षेत्र पर अपना दावा किया है, जिससे तनाव और समय-समय पर हिंसा भड़कती है।

भारत का रुख क्या है?

- **कूटनीति:** 2020 के संघर्ष के बाद, भारत का मानना है कि संघर्ष का कोई भी स्थायी समाधान केवल कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से ही प्राप्त किया जा सकता है।
- **शांतिपूर्ण समाधान:** भारत आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए ओएससीई मिन्स्क समूह के निरंतर प्रयासों का समर्थन करता है।

अजरबैजान:

- अजरबैजान एशिया का एक देश है जिसकी सीमा रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और ईरान से लगती है।
- कैस्पियन सागर देश की पूर्व सीमा पर स्थित है।
- उत्तर और पश्चिम का अधिकांश भाग काकेशस पर्वत से ढका हुआ है।
- राजधानी शहर: बाकू

आर्मेनिया:

- इसके पश्चिम में तुर्की, उत्तर में जॉर्जिया और पूर्व में अजरबैजान है।
- राजधानी: येरेवान

निष्कर्ष:

देश के मध्य शांति समझौते से इस क्षेत्र में एक उम्मीद जगी है। किन्तु सफल मध्यस्थता प्रयासों के बिना, युद्ध विराम उल्लंघन और नए तनाव से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पूर्ण पैमाने पर संघर्ष फिर से भड़कने का खतरा है। इस क्षेत्र में संघर्ष दक्षिण काकेशस क्षेत्र को अस्थिर कर देगा। साथ ही इससे अजरबैजान से तेल और गैस के निर्यात घटेगा, जिससे विश्व नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।

भारत-घाना संयुक्त व्यापार समिति की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 2 से 3 मई, 2024 तक घाना की राजधानी अकरा में घाना समकक्षों के साथ संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के चौथे सत्र की बैठक की।

बैठक की मुख्य बातें:

- **द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध:** बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों की समीक्षा की। साथ ही भविष्य में व्यापार संबंधों के विकास पर चर्चा की।
- **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) का क्रियान्वयन:** इस दौरान घाना इंटरबैंक भुगतान और निपटान प्रणाली (GHIPSS) का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) को छह महीने के भीतर तुरंत चालू करने के लिए समझौता किया गया।
- **समझौता ज्ञापन (एमओयू) और अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौता (एएफसीएफटीए):** बैठक में डिजिटल परिवर्तन का समाधान और स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) की चर्चा शामिल रही। अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते (एएफसीएफटीए) में उपस्थिति सम्भावनाओं पर भी विमर्श हुआ।
- **सहयोग बढ़ाने के लिए फोकस के क्षेत्र:** दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की। इन क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल बुनियादी ढांचा, महत्वपूर्ण खनिज, कपड़ा और वस्त्र शामिल हैं।

–: प्रीलिम्स इनसाइट :–

घाना के बारे में:

- घाना एक महत्वपूर्ण अफ्रीकी देश है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में पश्चिम अफ्रीका में गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है।
- यह निम्न के साथ सीमाएँ साझा करता है:
  - बुर्किना फासो (उत्तर)
  - गिनी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर (दक्षिण)
  - टोगो (पूर्व)
  - आइवरी कोस्ट (पश्चिम)
- दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य घाना में एक वनाच्छादित पठारी क्षेत्र शामिल है, जिसमें अशंती ऊपरी भूमि और क्वाहू पठार शामिल हैं।
- इसे व्हाइट वोल्टा और ब्लैक वोल्टा जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ काटती हैं, जो दक्षिण की ओर बहती हैं और लेक वोल्टा बनाती हैं, जो आयतन के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है।
- ग्रीनविच घाना में पूर्वी क्षेत्र से गुजरती है, जो टेमा के निकट स्थित है।

भारत–घाना संबंध:

- 1957 में घाना को स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद भारत और घाना राजनयिक भागीदार बन गए। क्वामे नक्रूमा और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के बीच एक मजबूत व्यक्तिगत संबंध था, जिसने दोनों देशों के बीच सहयोग की नींव बनाने में मदद की।
- घाना अफ्रीका क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है और यहाँ भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। 2022-23 में भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2.87

बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

- भारत घाना में एक तीसरे बड़े निवेशक के रूप में उभरा है। ये निवेश फार्मास्यूटिकल्स, निर्माण, विनिर्माण, व्यापार सेवाएँ, कृषि, पर्यटन, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

निष्कर्ष:

भारत-घाना संयुक्त तकनीकी समिति (जेटीसी) के चौथे सत्र में सौहार्दपूर्ण और दूरदर्शी विचार-विमर्श हुआ, जो दोनों देशों के बीच सामंजस्य पूर्ण और विशेष संबंधों को दर्शाता है। दोनों पक्षों ने लंबित मुद्दों के समाधान, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए उत्साह दिखाया।

भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच 12वीं संयुक्त कार्य समूह (JWG) की बैठक 16-17 मई, 2024 को उलन बातोर में हुई।

बैठक की प्रमुख बातें:

- बैठक की सह-अध्यक्षता भारत से रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव और मंगोलिया से रक्षा मंत्रालय के राज्य सचिव ने की।
- संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और मंगोलिया के बीच चल रहे रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया।
- उन्होंने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की। इस दिशा में विकास हेतु भविष्य की रूपरेखा तैयार करते हुए इन क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने हेतु विचार विमर्श किया।
- इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारत-मंगोलिया संबंध:

कूटनीति:

- भारत ने दिसंबर 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए ,तब जनवरी 1956 में पहले मंगोलियाई राजदूत नई दिल्ली पहुंचे।
- भारत सोवियत गुट के बाहर मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश था।
- संयुक्त राष्ट्र सदस्य के रूप में भारत की भूमिका को मंगोलियाई लोगों ने स्वीकार किया है, जो 1991 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) में पूर्ण सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए भारत के समर्थन की भी सराहना करते हैं।
- मंगोलिया की राजधानी उलन बातोर में भारतीय निवासी मिशन फरवरी 1971 में खोला गया था। 1994 में, दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे उनके रिश्ते और मजबूत हुए।
- 2015 में, संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया, जिसमें रक्षा क्षेत्र द्विपक्षीय जुड़ाव का एक अनिवार्य तत्व था।

ऊर्जा सहयोग:

- भारत रूसी तेल आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए मंगोलिया के दक्षिण गोबी रेगिस्तान में एक ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का वित्तपोषण कर रहा है।
- इन रिफाइनरियों को 'ग्रीनफील्ड' कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण पहले से अविकसित भूमि पर किया गया है।
- भारत के एक्जिम बैंक द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना के 2026 तक चालू होने की उम्मीद है।
- इसके अतिरिक्त, भारत की सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मंगोलिया की पहली सौर ऊर्जा विद्युतीकरण परियोजना को पूरा किया, जिसे औपचारिक रूप से अप्रैल 2006 में दादल सौम में खोला गया।

रक्षा सहयोग:

- भारत और मंगोलिया 2004 से प्रतिवर्ष 'नोमेडिक एलीफैंट' सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं।
- भारतीय सशस्त्र बल पर्यवेक्षक नियमित रूप से मंगोलिया के वार्षिक बहुपक्षीय शांति अभ्यास 'खान क्वेस्ट' में भाग लेते हैं।

निष्कर्ष:

भारत और मंगोलिया के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। दोनों देश एक-दूसरे को 'आध्यात्मिक पड़ोसी' मानते हैं। आधुनिक समय में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और बाजार अर्थव्यवस्था जैसे मूल्य दोनों देशों को करीब ला रहे हैं।

यूएनएफएफ की बैठक और भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हो रही कार्यवाही

हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट को सूचित किया है कि पिछले 15 वर्षों में भारत ने वन आवरण में वृद्धि के क्षेत्र में और वन प्रबंधन में अच्छी उपलब्धि हासिल की है। 2010 से 2020 के बीच भारत, नेट गेन इन एवरेज फॉरेस्ट एरिया के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है और भारत सरकार का कहना है कि यह कुशल वन संरक्षण और प्रबंधन नीतियों के चलते हो पाया है।

भारत ने 6 मई से 10 मई को यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित यूएनएफएफ के 19वें सत्र में भाग लेते हुए अपने वन प्रबंधन नीतियों पर प्रकाश डाला। यूएनएफएफ-19 का समापन वनों की कटाई और वन क्षरण व भूमि अपरदन को रोकने के लिए तत्काल और त्वरित कार्रवाई करने की घोषणा के साथ हुआ। इनमें वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन और वैश्विक वन लक्ष्यों की उपलब्धि शामिल है। इस बैठक में भारत का कहना था कि उसने जैवविविधता और वन्य जीव संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जिसके चलते वन संरक्षण प्रयासों को और सार्थक परिणाम मिले।

इस सत्र में भारत के पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने कहा कि हाल में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे मनाया गया और उसके साथ ही प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हाथियों के संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन भी किया गया। बाघों और हाथियों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश भी दिए हैं जिससे कि प्राकृतिक आवासों का विखंडन किसी भी स्थिति में न किया जाए क्योंकि इससे इससे मानव पशु संघर्ष बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। यूएनएफएफ के 19 वें सत्र में भारत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत में हो रही कार्यवाही के बारे में दुनिया को अवगत कराया। इन कार्यवाहियों में शामिल हैं:

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम:

- यूएनएफएफ-19 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव और वन महानिदेशक द्वारा किया गया जिन्होंने यूएनएफफ को सूचित किया कि उसने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत की है जो एक मार्केट बेस्ड मेकेनिज्म है जिसके तहत व्यक्तियों, किन्हीं समुदायों या निजी क्षेत्र द्वारा की गई स्वैच्छिक पर्यावरण कार्यवाही के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए लोगों को ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा।
- इस ग्रीन क्रेडिट को बेचना संभव होगा। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के माध्यम से निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों के साथ-साथ अन्य लोगों को ऐसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित होता है।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस:

- यूएनएफएफ की 19वीं बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने यूएन को बताया कि भारत में कैट फैमिली के सभी प्रजातियों के बेहतर संरक्षण के लिए भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है। एलाएंस का मुख्यालय भारत में होगा और इसे 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये की एकमुश्त बजटीय सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना की शुरुआत:

- देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान (FRI) में आयोजित वनों पर

संयुक्त राष्ट्र फोरम (यूएनएफएफ) के कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भारत के पर्यावरण मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि जंगल की आग न केवल वनस्पतियों और जीवों को अपूरणीय क्षति पहुंचाती है, बल्कि वन क्षेत्र के आस-पास रहने वाले समुदायों की आजीविका को भी प्रभावित करती है। वनों के स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए वन प्रमाणन एक महत्वपूर्ण साधन है, जो विकासशील देशों में छोटे पैमाने के उत्पादकों के लिए विशेष रूप से कई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने बैठक में कहा कि भारत ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना शुरू की है।

- भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (यूएनएफएफ) की मेजबानी के लिए पहल की है। खाद्य और कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय वन अनुसंधान संगठन के साथ-साथ भारत के प्रतिनिधियों तथा संगठनों सहित 40 देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों रूप से कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज की थी।

पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत की वैश्विक वार्ता साझेदारी:

- यूएनएफएफ की 19वीं बैठक के दौरान ही भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने पुर्तगाल की एकीकृत ग्रामीण अग्नि प्रबंधन एजेंसी, कोरिया वन सेवा और इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल (आईटीटीओ) के साथ साझेदारी में 'सहयोगात्मक शासन के माध्यम से परिदृश्य एकीकृत अग्नि प्रबंधन के लिए सिद्धांत और रणनीतियां' पर न्यूयॉर्क में आयोजित यूएनएफएफ-19 के अधीन एक कार्यक्रम की भी मेजबानी की।

विश्व वन्यजीव दिवस 2024 और जागरूकता अभियान:

- विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का विषय 'लोगों और ग्रह को जोड़ना: वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज' है। यह थीम वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में डिजिटल नवाचार द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है।
- यह वन्यजीवों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने, उनकी आबादी की निगरानी करने और लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए नवीन समाधान विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डालता है।
- भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने भी ऐसे वैश्विक दिवसों पर वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी साक्षरता, जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इसमें वन्य जीव अपराधों, वन्य जीव तस्करी, जंगल की आग का प्रबंधन, जंगली जानवरों को होने वाली बीमारियों, वन संरक्षण और प्रबंधन में प्रौद्योगिकी और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका आदि पर जागरूकता बढ़ाई जा रही है।

भारत में प्रवाल भित्ति को बचाने में बायोडिग्रेडेबल स्ट्रा की संभावित भूमिका:

- विश्व के कई हिस्सों में शिकारी मछलियां शिशु मूंगों (कोरल्स) को अपना भोजन बना लेती हैं, जिसकी वजह से समुद्री प्रजातियों को नुकसान पहुंच रहा है। अगर इसे संरक्षित नहीं किया गया, तो समुद्री पारिस्थितकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। भारत में भी इस पर ध्यान देने का दबाव बढ़ गया है और भारत इस दिशा में अमेरिकी वैज्ञानिकों की उस नई तकनीक से काफी कुछ सीख सकता है जिसकी वजह से समुद्र में मूंगों को बचाया जा सकता है।
- दक्षिण फ्लोरिडा के शोधकर्ता, शिकारी मछलियों को प्रयोगशाला में उगाए गए मूंगों (कोरल) को खाने से रोकने के लिए अनूठा तरीका अपना रहे हैं। इसके लिए वे बायोडिग्रेडेबल स्ट्रा का सहारा ले रहे हैं। प्रवाल भित्तियों की आबादी में गिरावट को दूर करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक वर्षों से काम कर रहे हैं।
- पिछली गर्मियों में, दक्षिण फ्लोरिडा और फ्लोरिडा कीज में बचाव समूह समुद्र के बढ़ते तापमान से मूंगे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मौजूदा मूंगों को जीवित रखने के लिए काम करने के अलावा, शोधकर्ता प्रयोगशालाओं में नए मूंगे उगा रहे हैं और फिर उन्हें समुद्र में डाल रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल स्ट्रा से बनाया गया छोटा पिंजरा प्रत्यारोपित मूंगे की जीवित रहने की दर को 90% से अधिक तक बढ़ा देता है।
- कोरल पिंजरे में एक चूना पत्थर की डिस्क होती है जो अटलांटा स्थित विनकप इंक की ओर से बनाई गई आठ सीधी फेड ब्रांड स्ट्रॉ से घिरी होती है। इन स्ट्रा से बने पिंजरे के शुरुआती प्रोटोटाइप समुद्र में घुलने से पहले लगभग दो महीने तक मूंगे की रक्षा करने में सक्षम थे।

निष्कर्ष:

- विशेषज्ञों का कहना है कि मूंगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे दुनिया भर में समुद्र के 1% से भी कम हिस्से में मिलते हैं लेकिन लगभग 25 प्रतिशत समुद्री जीवन को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं।
- मूंगा तूफान के दौरान समुद्र तट के किनारे मनुष्यों और उनके घरों को तूफानी लहरों से बचाने में भी मदद करती हैं लेकिन पानी के नीचे के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना जो सभी समुद्री प्रजातियों के 25% से ऊपर को बनाए रखता है, आसान नहीं है।
- इससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण यह सुनिश्चित करना है कि प्रयोगशाला में उगाया गया और समुद्र में डाला गया मूंगा बड़ी मछलियों का भोजन न बन जाए। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों का पर्यटन और समुद्री जैवविविधता अगर बचानी है तो इस तरीके का अनुसंधान करना होगा क्योंकि आज इन क्षेत्रों में कोरल रीफ के सामने इन्वेजिव स्पिसीज का खतरा बढ़ गया है।

पर्यावरणीय संक्षिप्त मुद्दे

हिंद महासागर तल की बाथमेट्री

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा हिंद महासागर तल का एक अध्ययन किया गया।

अध्ययन की मुख्य बातें:

- अध्ययन से पता चला हैं की हिंद महासागर की धाराएं पूरी तरह से सतही प्रभावों से नियंत्रित नहीं होती हैं।
- इसमें सतही प्रवाह के विपरीत, 1,000 और 2,000 मीटर की गहराई पर पूर्वी भारत तटीय धारा (ईआईसीसी) के अधिक यथार्थवादी प्रवाह का अनुमान लगाया गया है।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट पर 2,000 मीटर की गहराई पर एक सीमा धारा की पहचान की गई।
- मालदीव द्वीप समूह की उपस्थिति इक्वेटोरियल अंडर करंट (ईयूसी) की पश्चिमी सीमा को प्रभावित करती पाई गई।
- यह विभिन्न समय सीमाओं में धाराओं तापमान और लवणता जैसे समुद्र संबंधी मापदंडों के सटीक पूर्वानुमान की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

–: प्रीलिम्स इनसाइट :–

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के बारे में:

- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) की स्थापना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन की इकाई है और हिंद महासागर वैश्विक महासागर अवलोकन प्रणाली (IOGOOS) और महासागरों के अवलोकन के लिए साझेदारी (POGO) का संस्थापक सदस्य है।
- यह यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान आयोग (IOC) का स्थायी सदस्य है।

बाथमेट्री:

- यह समुद्री स्थिति के साथ-साथ मौसम और जलवायु, (विशेष रूप से भारतीय रिम देशों और उपमहाद्वीप के) पूर्वानुमानों में सुधार के लिए प्रमुख कारकों को समझने में मदद करता है।
- बाथमेट्री एक ऐसी तकनीक है जो नदियों, समुद्रों और महासागरों जैसे जल निकायों की गहराई का मानचित्रण करने के लिए समर्पित है। यह पानी के नीचे की उच्चावच (Terrace/Reliefs) की भी पहचान करता है और समुद्र तल के त्रि-आयामी मानचित्र बनाने में मदद करता है।
- बाथमीट्रिक मानचित्र स्थलाकृतिक मानचित्रों की तरह दिखते हैं, जो भूमि की विशेषताओं के आकार और ऊंचाई को दिखाने के लिए रेखाओं का उपयोग करते हैं।
- बाथिमेट्रिक डेटा आमतौर पर सोनार, लिडार या अन्य रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके एकत्र किया जाता है और अक्सर इसे बाथिमेट्रिक मानचित्र या 3 डी मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये विजुअलाइजेशन समुद्र तल की जटिल और गतिशील प्रकृति में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष:

मौसम, जलवायु भविष्यवाणी और समुद्री उद्योग में महासागर महत्वपूर्ण हैं। सतह और उपसतह दोनों स्तरों पर और विभिन्न समय के पैमाने पर, धाराओं, तापमान और लवणता जैसे समुद्र संबंधी मापदंडों का सटीक पूर्वानुमान, उनके विशाल आर्थिक लाभों के कारण महत्वपूर्ण हैं। सटीक पूर्वानुमानों के लिए उन्नत अवलोकन और बेहतर मॉडल पर शोध और उनका अधिक उपयोग आवश्यक हैं।

पृथ्वी का घूर्णन हुआ धीमा

चर्चा में क्यों?

27 मार्च, 2024 को नेचर जर्नल में प्रकाशित एक शोधपत्र में बताया गया है कि मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी का घूर्णन की गति में कमी आयी हैं।

कारण:

- शोध में बताया गया हैं कि पृथ्वी के घूर्णन की गति में कमी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय बर्फ के पिघलने और पानी के भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने से हो सकता है।
- ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पृथ्वी की घूर्णन गति चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण लाखों वर्षों में धीरे-धीरे कम हुई है। तलछटों के विश्लेषण से पता चला कि 1.4 अरब साल पहले पृथ्वी एक दिन में केवल 19 घंटे में एक चक्कर पूरा करती थी, जबकि आज इसमें 24 घंटे लगते हैं। 370 मिलियन वर्ष पहले भी एक दिन केवल 22 घंटे का होता था।

प्रभाव:

- ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर पानी की आवाजाही ने पृथ्वी को कम गोलाकार और अधिक चपटी बना दिया है। इसके परिणामस्वरूप, पृथ्वी का जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया है, जो कि किसी पिंड के द्रव्यमान के फैलाव का माप है।
- सार्वभौमिक समय में समय-समय पर एक लीप सेकंड जोड़ा जाता है। पिछली बार लीप सेकंड 31 दिसंबर 2016 को जोड़ा गया था। 1970 के बाद से पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ रही थी, जिससे 2025

या 2026 में एक लीप सेकंड घटाया जाना था। लेकिन मानव-प्रेरित धीमी गति के कारण अब इसे 2028 या 2029 में घटाना होगा।

- एक लीप सेकंड का जोड़ या घटाव दूरसंचार और कंप्यूटिंग के लिए समस्याग्रस्त हो सकता है। हालाँकि, यह हमारे दैनिक जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं डालता है।

पृथ्वी का घूर्णन:

- पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती रहती है जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं। अत: इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं।

निष्कर्ष:

प्रमुख चिंता यह है कि मानव गतिविधियाँ पृथ्वी की गति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों को कैसे प्रभावित कर रही हैं? सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन से भी यह स्पष्ट होता है कि जलभृतों से पानी निकलने और महासागरों में इसके पुनर्वितरण के परिणामस्वरूप पृथ्वी का घूर्णन धीमा हुआ है। इससे पता चलता है कि मानव क्रियाओं के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं।

आइबेरियन लिंक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्पेन की सरकार के अनुसार, स्पेन और पुर्तगाल में जंगली आइबेरियन लिंक्स की संख्या 2020 से लगभग दोगुनी होकर पिछले साल 2000 से अधिक हो गई है।

आइबेरियन लिंक्स के बारे में:

- आइबेरियन लिंक्स यूरोप के दो स्थानिक मांसाहारी प्रजातियों में से एक है। (दूसरा यूरोपीय मिंक, मुस्तेला लुट्रेओला)
- इस प्रजाति में, अन्य बिल्ली प्रजातियों की तरह, लैंगिक द्विरूपता (एक ही प्रजाति में विभिन्न लिंगों के व्यक्तियों के बीच आकार में अंतर) होती है, जिसमें नर भारी और लंबा होता है।
- यह लिंक्स आम तौर पर रात में विरण करते हैं और इसका मुख्य शिकार खरगोश होता हैं।
- यह प्रजाति अपने नुकीले कान, लंबे पैर और तेंदुए जैसे धब्बेदार फर के लिए जानी जाती है।
- दो दशक पहले विलुप्त होने की कगार पर थी। इसका कारण था शिकार, सड़क दुर्घटनाएँ, और जंगली खरगोशों की संख्या में भारी गिरावट, जो लिंक्स का मुख्य शिकार हैं।
- 2002 में जब पहली बार धब्बेदार रात्रिचर बिल्ली की जनगणना की गई थी, तो यह संख्या आइबेरियन प्रायद्वीप में 100 से कम थी।

संरक्षण स्थिति:

- आईयूसीएन रेड लिस्ट: संकटग्रस्त
- साइट्स: परिशिष्ट II

आइबेरियन प्रायद्वीप के बारे में:

- आइबेरियन प्रायद्वीप, जिसे इबेरिया भी कहा जाता है, दक्षिण-पश्चिमी यूरोप में एक प्रायद्वीप है, जो यूरेशिया के पश्चिमी किनारे पर स्थित है।
- यह स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय प्रायद्वीप है। इसका नाम इसके प्राचीन निवासियों से लिया गया है, जिन्हें यूनानियों ने इबेरियन कहा था, संभवत: इबेरस (एब्रो) के कारण, जो प्रायद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी (टैगस के बाद) है।

निष्कर्ष:

आइबेरियन लिंक्स कई चुनौतियों का सामना कर रहा है जो इसके अस्तित्व को खतरे में डालते हैं, जिनमें कृषि और औद्योगिक विकास के कारण प्राकृतिक आवसों का विनाश शामिल हैं। इसके अलावा, मूल भूमध्यसागरीय जंगलों को बिना झाड़ियों के बागानों में परिवर्तित करना, प्रत्यक्ष उत्पीड़न, और ऑटोमोबाइल के कारण मृत्यु दर अन्य कारण हैं जो खतरे को बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने खतरे के स्तर को 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' से 'संकटग्रस्त' में घटा दिया है, फिर भी इस गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति की रक्षा और इसके प्राकृतिक आवास को बहाल करने के लिए समर्पित संरक्षण का प्रयास आवश्यक हैं।

भारतीय कृषि भूमि में बड़े पेड़ों की कमी: एक गंभीर चिंता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर सस्टेनेबिलिटी पत्रिका में प्रकाशित शोधपत्र के अनुसार पिछले एक दशक में भारतीय खेतों में लाखों बड़े पेड़ गायब हो गए हैं, जिससे पर्यावरण और कृषि पद्धतियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

शोध के महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- 2010 से 2018 के बीच, सैटेलाइट इमेजिंग से प्राप्त डाटा के अनुसार, कई क्षेत्रों में बड़े पेड़ों की संख्या में अधिक कमी आई है।
- इस शोध में मध्य भारत, विशेष रूप से महाराष्ट्र और तेलंगाना की वन स्थिति के बारे में बताया गया है। 2011 और 2018 के बीच, इन क्षेत्रों में लगभग 2.5 मिलियन पेड़ नष्ट हो गए।
- 2010 से 2022 के बीच भारतीय कृषि भूमि पर बड़ी संख्या में पेड़ो गिरावट दर्ज की गयी। 67 वर्ग मीटर से बड़े आकार वाले 5 मिलियन से अधिक पेड़ 2018 और 2022 के बीच खेत से गायब हो गए। यह घटना पूरे भारत में कृषि भूमि पर पेड़ कम होने की राष्ट्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है।

कारण:

- शोधकर्ताओं के अनुसार जंगल की आग, कवक, कीड़े और सूखे के कारण पेड़ों की मृत्यु दर 5-10 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
- मानवजनित जलवायु परिवर्तन और मानव कुप्रबंधन भी पेड़ों के नुकसान को बढ़ा रहे हैं।

- अध्ययन में पाया गया कि किसानों ने मुख्य रूप से पेड़ों से होने वाले कम लाभ की धारणा और फसल की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से पेड़ों को हटाया।
- किसानों ने अतिरिक्त जल आपूर्ति के लिए भूजल निष्कर्षण के लिए बोरवेल स्थापित करने और पैदावार बढ़ाने के लिए धान के खेतों का विस्तार करने के लिए पेड़ों को हटाया।

कृषि वनों का महत्त्व:

- कृषि वन सामाजिक पारिस्थितिक लाभ प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कार्बन सिंक के रूप में एक संभावित जलवायु समाधान हैं।
- शोधकर्ताओं ने बताया कि भारत में कृषि वन जो छाया प्रदान करते हैं, मृदा को उर्वर बनाते हैं तथा भूमि को अन्य लाभ प्रदान करते हैं।
- महुआ, नारियल, सांगरी, नीम, बबूल, शीशम, जामुन, हमिंगबर्ड, करोई और कटहल जैसे पेड़ कृषि भूमि में फल, ईंधन, रस, औषधि, गीली घास, फाइबर, पशुओं और मानव उपयोग के लिए चारा और लकड़ी प्रदान करते हैं।
- पेड़ किसानों की आजीविका में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष:

यह शोध बताता है कि 2010 और 2022 के बीच बड़ी कृषि भूमि पर पेड़ों का लुप्त होना भारतीय कृषि और पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता का विषय है। संरक्षण और पुनः वृक्षारोपण की आदतों को लागू करने की आवश्यकता है, ताकि कृषि और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखा जा सके।

जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित भारतीय

चर्चा में क्यों?

याले और सीवोटर के द्वारा किए गए तीसरे राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण में जलवायु परिवर्तन को लेकर देश की बढ़ती चिंता की स्पष्ट तस्वीर सामने आई है। 53 प्रतिशत भारतीयों का मानना है कि वे ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित हो रहे हैं।

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु:

- सितंबर-अक्टूबर 2023 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 91 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव वास्तविक है।
- सर्वेक्षण में शामिल 59 प्रतिशत लोगों ने इस मुद्दे के बारे में "बहुत चिंतित" को चुना।
- भारत में बहुत से लोग (52 प्रतिशत) मानते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं, जबकि 38 प्रतिशत मानते हैं कि इसका मुख्य कारण प्राकृतिक पर्यावरणीय परिवर्तन हैं।
- 53 प्रतिशत भारतीयों का मानना है कि वे पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित हो रहे हैं। लगभग एक तिहाई भारतीय (34 प्रतिशत) पहले से ही मौसम संबंधी आपदाओं जैसे अत्यधिक गर्मी, सूखा, समुद्र-स्तर में वृद्धि, बाढ़ या अन्य के कारण स्थानांतरित हो चुके हैं या ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं।
- 71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से स्थानीय मौसम पर असर पड़ा है और 76 प्रतिशत ने कहा कि इससे भारत में मानसून पर "बहुत अधिक" या "कुछ हद तक" असर पड़ा है।
- 78 प्रतिशत भारतीयों के अनुसार, भारत सरकार को ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए।

जलवायु परिवर्तन क्या होता है?

- जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य एक लम्बी अवधि में तापमान और मौसम की स्थिति में होने वाले स्थायी परिवर्तनों से है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:

- **वर्षा पैटर्न में परिवर्तन:** पिछले कुछ दशकों में बाढ़, सूखा और वर्षा आदि की अनियमितताएँ काफी बढ़ गई हैं। यह सब जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप हो रहा है। कुछ जगहों पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि कुछ जगहों पर पानी की कमी के कारण सूखे की संभावना बनी रहती है।
- **समुद्र स्तर में वृद्धि:** वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के दौरान ग्लेशियर पिघलते हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, जिससे समुद्र के आसपास के द्वीपों के डूबने का खतरा भी बढ़ जाता है। मालदीव जैसे छोटे द्वीपीय देशों में रहने वाले लोग पहले से ही वैकल्पिक गंतव्यों की तलाश कर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय:

- जीवाश्म ईंधन का प्रयोग/उपयोग यथासंभव कम किया जाना चाहिए।
- ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों को अपनाया जाना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि।
- जंगलों और पेड़ों को कटने से बचाया जाना चाहिए तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए।
- प्लास्टिक जैसी ऐसी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जिसका विघटन कठिन और असंभव हो।
- ऊर्जा के प्राकृतिक एवं नवीकरणीय स्रोतों को अधिकाधिक संख्या एवं मात्रा में अपनाया जाना चाहिए जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि।

भारत के प्रयास:

- **पंचामृत:** भारत ने भारत की जलवायु के निम्नलिखित पाँच अमृत तत्वों (पंचामृत) को प्रस्तुत किया है:
  - 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुँचना।
  - 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना।
  - अभी से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक

बिलियन टन की कमी।
  - 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत की कमी।
  - 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व।
- पेरिस समझौते का क्रियान्वयन।

निष्कर्ष:

जलवायु परिवर्तन अपने प्रतिकूल प्रभावों के साथ हमारे मुहाने तक पहुँच चुका है। अब समय आ गया है कि मनुष्य समझदारी से काम लें, ताकि मनुष्य परिवर्तनों का सामना कर सकें और भविष्य में आपदाओं से बचने और पर्यावरण को बचाने के लिए सावधानी बरतें।

विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र औषधि एवं अपराध नियंत्रण कार्यालय (यूएनओडीसी) ने विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में जंगली जीवों और वनस्पतियों की संरक्षित प्रजातियों की अवैध तस्करी का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान किया है तथा 2015 से 2021 तक वैश्विक स्तर पर व्यापार में संबंधित अपराध के कारणों और निहितार्थों के बारे में बताया गया है।

रिपोर्ट की प्रमुख बातें:

- रिपोर्ट में सबसे अधिक प्रभावित पशु प्रजाति गैंडे को और देवदार (अन्य सैपिंडेल्स प्रजातियों के साथ) को सबसे अधिक प्रभावित पौधों की प्रजाति के रूप में पहचाना गया है।
- अवैध वन्यजीव व्यापार में गैंडे के सींग का हिस्सा 29% था, जबकि देवदार और अन्य सैपिंडेल्स में पौधों के व्यापार का 47% हिस्सा था।
- मात्रा के संदर्भ में, पशु प्रजातियों में पैंगोलिन स्केल (28%) और हाथी दांत (15%) गैंडे के सींग का व्यापार होता हैं। पौधों में, देवदार के बाद शीशम (35%) और अगरवुड (13%) महत्वपूर्ण बाजार हैं।
- इस अवधि के दौरान जैव विविधता उत्पादों की जब्ती हुई, जिसमें सभी जब्तियो में 16% मूंगे शामिल थे, इसके बाद मगरमच्छ (9%), और हाथी (6%) शामिल थे।

चुनौतियाँ:

- **अवैध व्यापार प्रवाह:** वैश्विक जब्ती डेटा विश्लेषण को यदि कीमत और बाजार अवलोकनों के साथ त्रिकोणित किया जाए तो यह अवैध व्यापार प्रवाह में गिरावट को दर्शाता है, एवं अवैध कटाई में कमी को दर्शाना अधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वन्यजीव तस्करी के अधीन अधिकांश प्रजातियों के लिए प्रासंगिक डेटा एकत्र नहीं किया जाता है।
- **वन्यजीव जनसंख्या स्तर की निगरानी:** अधिकांश प्रभावित वन्यजीव की जनसंख्या में परिवर्तन की व्यवस्थित रूप से निगरानी नहीं की जाती है, जिससे संरक्षण प्रयासों के प्रभाव का आकलन करना मुश्किल हो जाता है।
- **तस्करों की बदली रणनीति:** तस्करों के खिलाफ भले ही सकारात्मक रुझान देखे जा रहे हैं, किन्तु संभावना है कि तस्कर, बाजार के दबाव के अन्य वन्यजीव वस्तुओं में व्यापार करने के लिए स्थानांतरित हो सकते हैं।
- रिपोर्ट में दी गयी केस स्टडी में हाथीदांत और पैंगोलिन के अवैध व्यापार श्रृंखालाओ के बीच संबंधों को देखा गया है साथ ही तस्करों द्वारा विभिन्न प्रजातियों और नए देशों (अवैध व्यापार के लिए) पर ध्यान स्थानांतरित करने के उदाहरणों पर भी प्रकाश डाला गया है।

निहितार्थ:

- विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट के पिछले संस्करणों के उपचारात्मक दृष्टिकोण अभी भी प्रासंगिक हैं, जिनमें सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि, जब्ती के लिए जांच त्वरित कार्रवाई, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, उपभोक्ता मांग में कमी, अंतर-एजेंसी समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं।
- पिछले दशक में हाथी दांत और गैंडे के सींग के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को कम करने में प्रगति से पता चलता है कि बहुआयामी हस्तक्षेप प्रभावी हो सकते हैं।
- सफल कार्यवाहियों से मिले सबक समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें बहुपक्षीय जांच, प्रमुख तस्करों पर मुकदमा चलाना, कानूनी निषेधों को सुसंगत बनाना और प्रभाव संकेतकों पर नजर रखने में निवेश करना शामिल है।
- वन्यजीव तस्करी को कम करने के प्रयास में बढ़ोत्तरी हुई है, साथ ही प्रभाव को अधिकतम करने के लिए सरकार, बहुपक्षीय एजेंसियों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि दो दशकों के प्रयासों के बावजूद वन्यजीव तस्करी एक वैश्विक मुद्दा बनी हुई है। साथ ही उपचारात्मक कार्यक्रम एवं सभी के संयुक्त प्रयासों के कारण हाथियों और गैंडों की तस्करी को कम करने में प्रगति देखी गई है।

वेनेजुएला का आखिरी ग्लेशियर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वेनेजुएला संभवत: अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बनने जा रहा है, इसका आखिरी हम्बोल्ट ग्लेशियर अनुमान से कहीं अधिक तेजी से पिघल रहा है। एक समय वेनेजुएला की प्राकृतिक सुंदरता का गौरवपूर्ण प्रतीक रहे ग्लेशियर के लुप्त होने का पर्यावरण, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

ग्लेशियर क्षति के कारण:

- **ग्लोबल वार्मिंग:** वेनेजुएला का आखिरी ग्लेशियर, हम्बोल्ट, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अपेक्षा से अधिक तेज गति से पिघल

रहा है।

- **तापमान में वृद्धि:** पिछले सात दशकों में एंडीज पर्वत शृंखला के तापमान में कम से कम 0.10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है, जिसने हम्बोल्ट ग्लेशियर के पिघलने में योगदान दिया है।
- **अल नीनो:** अल नीनो, एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, जिसने सतह के पानी में असामान्य गर्मी पैदा करके हम्बोल्ट ग्लेशियर के पिघलने को तेज कर दिया है।
- **ग्रीनहाउस गैसें:** जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं।
- **हीट ट्रैपिंग:** ग्रीनहाउस गैसें वातावरण में गर्मी को रोकती हैं, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है।
- **तापमान वृद्धि के परिणाम:** तापमान वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक बार और तीव्र गर्मी की लहरें, बाढ़, सूखा और समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई है।
- **तेजी से पिघलना:** ग्लेशियर, गर्मी के संपर्क में आने वाले बर्फ के टुकड़ों की तरह, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते तापमान के कारण त्वरित गति से पिघल रहे हैं।

ग्लेशियर क्षति का प्रभाव:

- **मीठे पानी का स्रोत:** ग्लेशियर मीठे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, विशेष रूप से गर्म और शुष्क अवधि के दौरान, स्थानीय समुदायों, पौधों और जानवरों के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। ग्लेशियर क्षति से इस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
- **तापमान विनियमन:** हिमनद अपवाह डाउनस्ट्रीम पानी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, विशेष रूप से उन्हें ठंडा रखता है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:** ग्लेशियर के नष्ट होने से सीधे तौर पर जलीय प्रजातियां प्रभावित होती हैं, खाद्य जाल बाधित होता है और संभावित रूप से जैव विविधता में गिरावट आती है।
- **समुद्र के स्तर में वृद्धि में योगदान:** पिघलते ग्लेशियर समुद्र के स्तर में वृद्धि में योगदान करते हैं।
- **सांस्कृतिक प्रभाव:** ग्लेशियरों के नष्ट होने से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भी प्रभाव पड़ते हैं, विशेषकर उन समुदायों पर जहां ग्लेशियर उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। पर्वतारोहण और पर्यटन जैसी गतिविधियाँ, जो ग्लेशियरों पर निर्भर हैं, प्रभावित होंगी।

निष्कर्ष:

वेनेजुएला का आखिरी ग्लेशियर, हम्बोल्ट, बहुत तेजी से नष्ट हो रहा है और अपने पीछे पर्यावरणीय क्षरण और सांस्कृतिक क्षति की विरासत छोड़ रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने और हमारे ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

अफ्रीका उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

अफ्रीकी राष्ट्रपतियों ने उर्वरक और मिट्टी के स्वास्थ्य पर नैरोबी घोषणा का समर्थन किया है, जिसमें घरेलू उर्वरक उत्पादन को प्राथमिकता देने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अगले 10 वर्षों में इसे तीन गुना करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। अफ्रीका उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन (एएफएसएच) 7 से 9 मई 2024 तक नैरोबी, केन्या में 'भूमि की बात सुनो' विषय के तहत आयोजित किया गया था। तथा इसमें अफ्रीका में कृषि विकास के लिए उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीकी नेताओं की पिछली प्रतिबद्धताओं की प्रगति की समीक्षा करने की मांग भी की गई।

शिखर सम्मेलन की प्रमुख बातें:

- शिखर सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब पूरे महाद्वीप में लाखों अफ्रीकी भोजन और पोषण की कमी का सामना कर रहे हैं।
- इसके तहत नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, किसानों, निजी क्षेत्र, विकास एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों को इसके तहत अवसर एवं वातावरण प्रदान किया जा रहा है और विद्वान बढ़ती अफ्रीकी आबादी तक भोजन की पहुच के लिए नवीन तरीकों की दीर्घकालिक और टिकाऊ रणनीतियों पर विचार करेंगे।
- विभिन्न हितधारकों द्वारा की गई चर्चाओं में मिट्टी के पोषक तत्वों, मिट्टी की नमी, आवश्यक खनिजों, मिट्टी के जीवों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में भूमि की जरूरतों पर ध्यान देने की तात्कालिकता पर जोर दिया गया है और ऐसी प्रथाओं, नीतियों और दृष्टिकोणों को अपनाना जो किसानों के लिए एक महत्त्वपूर्ण संपत्ति के रूप में भूमि के दीर्घकालिक मूल्य में सुधार करेगा।
- हितधारकों ने महाद्वीप पर मिट्टी की उर्वरता को सुधारने और बनाए रखने के लिए प्रभावी मिट्टी प्रबंधन प्रणाली के लिए मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और संस्थागत संरचनाओं का मूल्यांकन किया।

नैरोबी घोषणा के बारे में:

- नैरोबी, केन्या में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आठवें अफ्रीका क्षेत्रीय मंच पर नैरोबी घोषणा को अपनाया गया।

- इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एसएफडीआरआर), 2015-2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए कार्य योजनाएं शामिल हैं।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए भारत की पहल:

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल:** यह मृदा नमूना संग्रह, प्रयोगशाला परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्माण पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है। इसमें वास्तविक समय की स्थिति और भू-निर्देशांक मानचित्रण के साथ मृदा प्रयोगशालाओं की रजिस्ट्री शामिल है।
- **स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम:** कृषि और किसान कल्याण विभाग ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सहयोग से एक पायलट परियोजना शुरू की। इस परियोजना में ग्रामीण केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय स्कूलों में 20 मृदा प्रयोगशालाओं की स्थापना शामिल थी।
- **कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम (केएससीपी):** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन ने केएससीपी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य कृषि सखी के सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत को बदलना है। कार्यक्रम में 70,000 कृषि सखियों को 'पैरा-एक्सटेंशन वर्कर्स' के रूप में प्रमाणित करने के लिए एक कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है।
- कृषि सखी कृषक और प्रशिक्षित पेशेवर हैं। वे किसानों के मित्र के रूप में कार्य करते हैं, प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का मार्गदर्शन करते हैं।

निष्कर्ष:

हालाँकि फसल की पैदावार में उर्वरकों का योगदान 30% से अधिक होने का अनुमान है, लेकिन भारत में कृषक अकेले उर्वरक के माध्यम से कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि को कायम नहीं रख सकते हैं। एकीकृत मृदा प्रबंधन की आवश्यकता को मान्यता देते हुए, सरकार ने अन्य हितधारकों के सहयोग से राष्ट्रीय मृदा प्रबंधन नीति विकसित की है। इस नीति में टिकाऊ कृषि मिट्टी और जल प्रबंधन, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी विकास, इसके प्रसार और उपयोग, उर्वरक विकास और निवेश पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश शामिल हैं।

सी एनीमोन ब्लीचिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लक्षद्वीप द्वीप समूह में समुद्री एनीमोन पर काम कर रहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (एनबीएफजीआर) के वैज्ञानिकों ने अगत्ती द्वीप पर बड़े पैमाने पर एनीमोन के विरंजन की घटना देखी गई।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (एनबीएफजीआर) के वैज्ञानिक पिछले कुछ वर्षों से समुद्री एनीमोन पर बंद परिस्थितियों में उनके विकास की संभावना पर काम कर रहे हैं क्योंकि मछलीघर व्यापार में इस प्रजाति की काफी मांग है।
- यह शोध समुद्री जीवन संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र द्वारा किया जा रहा है तथा यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित द्वीप महिलाओं की आजीविका संवर्धन के लिए चल रही परियोजना का हिस्सा है।

ब्लीचिंग संबंधी चिंताएँ और पारिस्थितिक प्रभाव:

- द्वीपों के समूह में पहली बार सी एनीमोन ब्लीचिंग देखी गई है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- ब्लीचिंग की यह घटना समुद्री एनीमोन को बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है और मृत्यु दर को बढ़ाती है।
- वैज्ञानिको ने पाया की सहजीवी शैवाल की हानि समुद्री एनीमोन को उनके प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से वंचित कर देती है, जिससे उनका दीर्घकालिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।

प्रजनन में चुनौतियाँ:

- कई प्रयासों के बावजूद, समुद्री एनीमोनों में यौन प्रजनन नहीं देखा गया है, यही लक्षण स्वदेशी जलीय कृषि प्रणालियों में ढाई साल से अधिक समय तक रखे गए स्वस्थ जानवरों में भी देखे गये है।
- इसमें सुधार हेतु प्रसार द्विभाजन विधि का उपयोग करके किया जा रहा है, जिसे कैप्टिव स्थितियों में मानकीकृत किया गया।

-: प्रीलिम्स इनसाइट :-

सी एनीमोन्स के बारे में:

- समुद्री एनीमोन नरम शरीर वाले समुद्री जानवर हैं जो फूलों के समान होते हैं। वे फाइलम निडारिया के अकशेरुकी क्रम एक्टिनियारिया से संबंधित हैं और मुख्य रूप से गतिहीन हैं।
- वे सभी महासागरों के ज्वारीय क्षेत्र से लेकर 10,000 मीटर (लगभग 33,000 फीट) से अधिक गहराई तक पाए जा सकते हैं। कुछ प्रजातियाँ खारे पानी के वातावरण में निवास करती हैं।
- आम तौर पर, समुद्री एनीमोन सबसे बड़े, सबसे अधिक संख्या में और सबसे अधिक रंगीन गर्म समुद्रों में होते हैं, जीवंत टीलिया प्रजातियाँ आमतौर पर समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

प्रभावी समाधान की आवश्यकता:

- समुद्री एनीमोन ब्लीचिंग के मुद्दे को संबोधित करने के लिए समुद्री आवासों की पारिस्थितिक अखंडता की रक्षा के लिए वैश्विक और स्थानीय दोनों तरह की कार्रवाई की आवश्यकता है।
- समुद्र की सतह का बढ़ता तापमान समुद्री एनीमोन और उनके सहजीवी शैवाल के बीच संतुलन को बाधित करता है, जिससे शैवाल का निष्कासन शुरू हो जाता है और परिणामस्वरूप जानवर

सफेद हो जाते हैं।

निष्कर्ष:

नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (एनबीएफजीआर) एनबीएफजीआर के वैज्ञानिकों का समूह समुद्री एनीमोन की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर लक्षद्वीप में व्यापक संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। वे वैश्विक उत्सर्जन में कटौती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करने के महत्व पर जोर देते हैं क्योंकि अगत्ती द्वीप में समुद्र का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जिससे एनीमोन का बड़े पैमाने पर विरंजन देखा गया है।

चक्रवात रेमल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चक्रवात रेमल ने 26 मई, 2024 को तटीय पश्चिम बंगाल में दस्तक दी, जिससे भारी बारिश हुई और इस क्षेत्र में बाढ़ आ गई। चक्रवात से कम से कम 84 लोग मारे गए, जिनमें भारत में 65 और बांग्लादेश में 19 लोग शामिल हैं। चक्रवात रेमल ने कोलकाता और दक्षिणी बंगाल के अन्य हिस्सों में हवाई, रेल और सड़क परिवहन में भी महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा किया। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा एक गंभीर चक्रवाती तूफान माना गया है।

पिछले चक्रवात:

- चक्रवात का डर पिछले विनाशकारी चक्रवातों, जैसे यास (2021), अम्फान (2020), चक्रवात फानी (2019), और आइला (2009) की वर्षगांठ के करीब आता है, जिसने सुंदरबन और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में भारी नुकसान पहुंचाया।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ:

- 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह।
- चक्रवाती भंवर बनाने के लिए पर्याप्त कोरिओलिस बल की उपस्थिति।
- ऊर्ध्वाधर हवा की गति में छोटे बदलाव।
- पहले से मौजूद कमजोर निम्न दबाव वाला क्षेत्र या निम्न-स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण।
- समुद्र तल प्रणाली के ऊपर ऊपरी विचलन।

चक्रवाती तूफान रेमल का नाम कैसे रखा गया?

- चक्रवाती तूफान रेमल का नाम ओमान ने इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार रखा था। अरबी में, रेमल का मतलब रेत होता है।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों (RSMC) और पाँच उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों (TCWC) द्वारा रखा जाता है, जिसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) RSMC में से एक है।
- बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण का निर्णय 2000 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों (PTC) पर WMO/ESCAP पैनल के सत्ताईसवें सत्र द्वारा किया गया था।
- पैनल में भारत, बांग्लादेश, ईरान, म्यांमार, पाकिस्तान और सऊदी अरब, थाईलैंड, यमन, श्रीलंका, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ओमान, कतर सहित 13 सदस्य देश हैं। बाद में, आईएमडी ने WMO/ESCAP PTC द्वारा अंतिम रूप दिए जाने और उन्हें अपनाने के बाद चक्रवात के नामों की एक नई सूची जारी की। सूची में 169 नाम शामिल थे, जिनमें से 13 नाम पैनल के 13 सदस्य देशों द्वारा सुझाए गए थे।

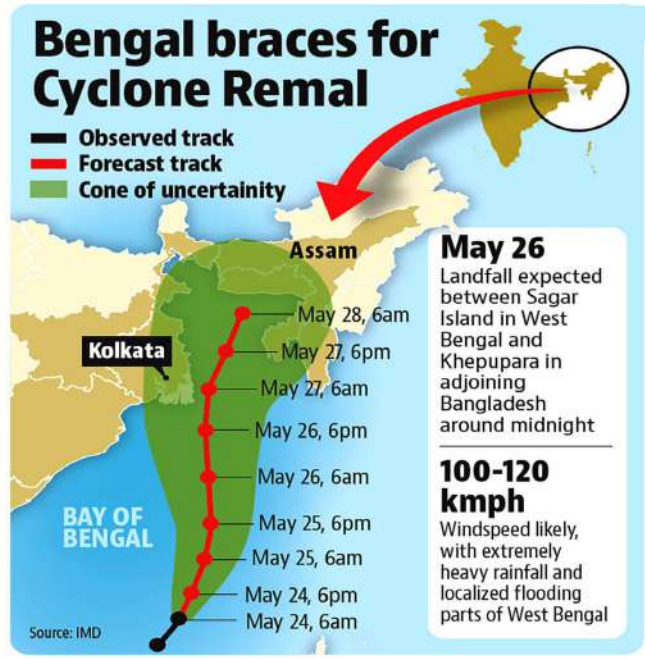

पृष्ठभूमि:

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) 185 सदस्यों वाली एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र (अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों को मिलाकर) में एक प्रभावी चक्रवात चेतावनी और आपदा न्यूनीकरण के महत्व को समझते हुए, WMO ने 1972 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर पैनल (PTC) की स्थापना की।

आगे की राह:

सरकार को चक्रवात से निपटने के लिए प्रभावित समुदायों को सहायता, आश्रय, भोजन और चिकित्सा देखभाल प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नुकसान का अनुमान लगाने और पुनर्निर्माण के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए गहन आकलन करना चाहिए, साथ ही सड़कों, पुलों और उपयोगिताओं सहित क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को बहाल करना चाहिए।

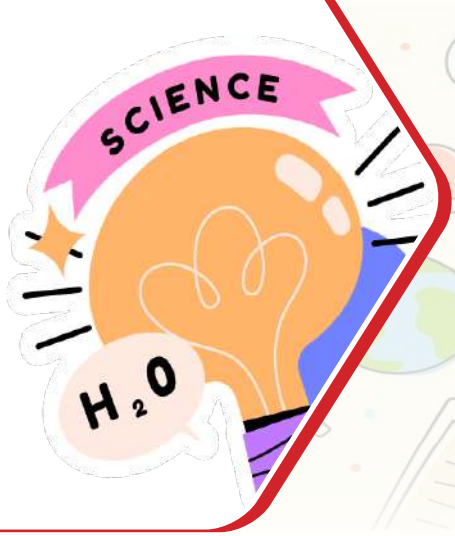

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में मजबूत हो रहा भारत का अंटार्कटिक अभियान

हाल ही में भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के द्वारा केरल के कोच्चि में 20 से 30 मई, 2024 तक 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी की गई। पर्यावरण संरक्षण समिति (सीईपी) की स्थापना 1991 में अंटार्कटिक संधि (मैड्रिड प्रोटोकॉल) के पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल के तहत की गई थी।

सीईपी अंटार्कटिका में पर्यावरण संरक्षण पर अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक को सलाह देता है। अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक को अंटार्कटिक संसद भी कहा जाता है जिसमें कुल 56 सदस्य देश भाग लेते हैं और अंटार्कटिक द्वीप से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा करते हैं। अंटार्कटिक को विज्ञान और अनुसंधान के प्रति समर्पित द्वीप भी कहा जाता है और इस बात को अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक जैसे मंचों की चर्चा अधिक सार्थक रूप प्रदान करती है। इस बैठक में ग्लेशियर्स के पिघलने की दर पर चिंता व्यक्त की गई है। ग्लेशियर संरक्षण के लिए देशों को सामूहिक स्तर पर मिलकर कार्य करने की जरूरत पर बल दिया गया है।

- अंटार्कटिक क्षेत्र की जैवविवधता के सामने आई चुनौतियों से निपटने के लिए एक ब्लू प्रिंट भी तैयार करने पर चर्चा हुई। ध्रुवीय भालूओ, पेंगुइन, क्रिल, वालरस और अन्य ध्रुवीय जीव जंतुओं को संरक्षित करने की दिशा में कार्यवाही करने पर बल दिया गया है। इसके साथ ही 26वां सीईपी (पर्यावरण संरक्षण समिति) एजेंडा अंटार्कटिक पर्यावरण मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन, प्रबंधन तथा रिपोर्टिंग, जलवायु परिवर्तन को लेकर सतर्कता, समुद्री स्थानिक संरक्षण सहित क्षेत्र संरक्षण, प्रबंधन योजनाएं और अंटार्कटिक जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित रहा। ये बैठकें अंटार्कटिका में पर्यावरणीय प्रबंधन, वैज्ञानिक सहकार्य और सहयोग पर रचनात्मक वैश्विक संवाद को सुविधाजनक बनाने की भारत की इच्छा के अनुरूप हैं। 46वीं एटीसीएम और 26वीं सीईपी बैठक की मेजबानी भावी पीढ़ियों के लिए अंटार्कटिका को संरक्षित करने के प्रयासों में एक जिम्मेदार वैश्विक हितधारक के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। भारत अंटार्कटिक संधि के सिद्धांतों को खुली बातचीत, सहयोग और सर्वसम्मति निर्माण के माध्यम से बनाए रखने और पृथ्वी के अंतिम प्राचीन जंगली क्षेत्रों में से एक के स्थायी प्रबंधन में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- उल्लेखनीय है कि अंटार्कटिक संधि सचिवालय (एटीएस) अंटार्कटिक संधि प्रणाली के लिए प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। 2004 में स्थापित एटीएस, एटीसीएम और सीईपी बैठकों का समन्वय करता है, सूचनाओं को पुनः प्रस्तुत और प्रसारित करता है और अंटार्कटिक शासन तथा प्रबंधन से संबंधित राजनयिक संचार, आदान-प्रदान और वार्ता की सुविधा प्रदान करता है। यह अंटार्कटिक संधि प्रावधानों और समझौतों के अनुपालन की निगरानी भी करता है तथा संधि कार्यान्वयन और प्रवर्तन मामलों पर अंटार्कटिक संधि सदस्यों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

अंटार्कटिक संधि, 1959 की मूल बातें:

- 1959 में हस्ताक्षरित और 1961 में लागू हुई अंटार्कटिक संधि ने अंटार्कटिका को शांतिपूर्ण उद्देश्यों, वैज्ञानिक सहयोग व पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया।
- पिछले कुछ वर्षों में इस संधि को व्यापक समर्थन मिला है और वर्तमान में 56 देश इसमें शामिल हैं। साल 1957-58 के बीच 12 देश साथ आए और तय किया कि अपने मतभेदों की वजह से अंटार्कटिका को तबाह नहीं होने देंगे। साथ ही ये भी निर्धारित हुआ कि वहां सामूहिक तौर पर रिसर्च चलते रहेंगे।

- दिसंबर 1959 में इन्हीं देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर करने वालों में ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान, नॉर्वे, यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और अर्जेंटीना शामिल थे।
- 1980 के शुरुआत में और भी देश इससे जुड़े, जिनमें भारत भी शामिल था। उल्लेखनीय है कि अंटार्कटिक संधि में शामिल 56 देशों में से 29 के पास कंसल्टेटिव पार्टी का अधिकार है, यानी ये फैसला लेने का काम करते हैं। भारत ने भले ही अस्सी के दशक में संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उसके पास भी ये अधिकार है।

अंटार्कटिक संधि की मुख्य बातें:

- अंटार्कटिका संधि में 14 अनुच्छेद मुख्य हैं, जो अलग-अलग हिस्सों पर फोकस करते हैं।
- यहां किसी भी तरह की मिलिट्री प्रैक्टिस या बेस बनाने की मनाही है।
- इस महाद्वीप पर न्यूक्लियर वेस्ट का निपटान नहीं हो सकता, न ही न्यूक्लियर टेस्ट हो सकेंगे।
- यहां हो रही वैज्ञानिक खोजें या रिसर्च आपस में साझा किए जाएंगे, और जरूरत पड़ने पर आपसी मदद की जाएगी।

अंटार्कटिक को लेकर भारत की सक्रियता:

- भारत 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकार सदस्य रहा है। यह आज तक अंटार्कटिक संधि के अन्य 28 सलाहकार सदस्यों के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेता है।
- भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र, दक्षिण गंगोत्री, 1983 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में, भारत दो अनुसंधान केंद्र मैत्री (1989) और भारती (2012) संचालित करता है।
- स्थायी अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अभियानों की सुविधा प्रदान करते हैं, जो 1981 से प्रतिवर्ष चल रहे हैं। वर्ष 2022 में, भारत ने अंटार्कटिक संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अंटार्कटिक अधिनियम लागू किया।
- अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत अंटार्कटिका में पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सहयोग और शांतिपूर्ण संचालन के लिए समर्पित है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने 2024 में भारत द्वारा एटीसीएम और सीईपी बैठकों की मेजबानी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "एक देश के रूप में हम अंटार्कटिक क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान के साझे लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता के सार्थक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए तत्पर हैं।"
- दक्षिणी महासागर में भारत के वैज्ञानिक और रणनीतिक प्रयास गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) के अधीन हैं।
- एनसीपीओआर भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के तहत एक प्रतिष्ठित स्वायत्त संस्थान है। एमओईएस ने कार्यक्रम के सफल समन्वय और आयोजन के लिए एमओईएस मुख्यालय में प्रमुख के रूप में डॉ. विजय कुमार, वैज्ञानिक (जी) और सलाहकार के साथ एक मेजबान कंट्री सेक्रिटेरीअट की स्थापना की है।
- भारत ने 46वें एटीसीएम की अध्यक्षता के लिए पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे प्रतिष्ठित राजदूत पंकज सरन का नाम प्रस्तावित किया है।
- एटीसीएम और सीईपी बैठकों में भागीदारी इसके सदस्यों, पर्यवेक्षकों और आमंत्रित विशेषज्ञों द्वारा नामित प्रतिनिधियों तक ही सीमित है। इस वर्ष 46वें एटीसीएम और 26वें सीईपी में 60 से अधिक देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इसका आयोजन भारत के कोच्चि में लुलु बोलगट्टी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एलबीआईसीसी) में एनसीपीओआर, एमओईएस करेगा।

भारत का अंटार्कटिक अभियान:

- भारतीय अंटार्कटिक अभियान 1981 में शुरू हुआ था। पहला अभियान दल डॉ. एस जेड कासिम के नेतृत्व में गया था जिसमें 21 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों की एक टीम शामिल थी।
- भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम ने अब अंटार्कटिका में तीन स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाने का श्रेय हासिल कर लिया है, जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है। अब तक अंटार्कटिका में भारत के दो अनुसंधान स्टेशन कार्यशील हैं जिनका नाम मैत्री और भारती है।
- नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (एनसीपीओआर), गोवा, संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। इससे पहले अंटार्कटिका के लिए 39वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान की शुरूआत नवंबर 2019 में हुई थी।
- इसने 27 वैज्ञानिक परियोजनाओं को शुरू किया, जो जलवायु संबंधी प्रक्रिया और उसका जलवायु परिवर्तन से संबंध, क्रस्टल एवोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रक्रियाओं और संरक्षण, स्थल और समुद्र तट के निकटवर्ती क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यवेक्षण अनुसंधान और ध्रुवीय टेक्नोलॉजी पर केन्द्रित हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोलर रिसर्च, जापान के साथ दो अतिरिक्त सहयोगी परियोजनाएं भी शुरू की गई।

अंटार्कटिक से जुड़ी चुनौतियां:

- अंटार्कटिक बैठक में पहली बार अंटार्कटिक के पर्यटन पर बात हुई। इस महाद्वीप पर टूरिज्म भी तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि पहले से ग्लोबल वार्मिंग की जद में रहते इस हिस्से पर पर्यटन का बुरा असर होगा।
- बाकी मुद्दों के साथ पर्यटन को विनियमित करना आवश्यक है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 से एक साल के भीतर 74 हजार से ज्यादा टूरिस्ट अंटार्कटिका घूमने जा चुके हैं।
- नेचर कम्युनिकेशन्स जर्नल में छपी एक रिसर्च में 100 से ज्यादा शोध के बाद ये माना गया कि अंटार्कटिका पर जाने वाले हर एक टूरिस्ट की वजह से 83 टन से ज्यादा बर्फ पिघलती है। ऐसे में हजारों पर्यटकों का वहां पहुंचना कितना खतरनाक हो रहा होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता।
- दक्षिण ध्रुवीय महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं,

उसे लेकर नई चिंता जताई जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहां की बर्फ तेजी से पिघल रही है, ये बात तो कई बार कही जा चुकी लेकिन अब जो चेतावनी आ रही है, वो डराने वाली है। बर्फ इतनी तेजी से पिघल रही है कि इससे महासागर के भीतर स्लोडाउन के हालात बन रहे हैं।

- समुद्र के भीतर का बहाव हल्का पड़ता जा रहा है। इससे दुनियाभर के पानी के स्त्रोतों में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के शोधकर्ताओं ने स्टडी में बताया कि कैसे अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने का असर डीप ओशन करंट्स पर पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने उस डेटा की मदद ली, जिसमें 35 मिलियन कंप्यूटिंग घंटों और कई तरीकों से अंटार्कटिका पर नजर रखी गई। अनुसंधान में कहा गया है कि हर रोज और लगातार अंटार्कटिका में बर्फ का अंबार, जो नमक और ऑक्सीजन से भरपूर होता है, पिघलता है।
- इससे जो वॉटर करंट बनती है, वो प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर तक पहुंचती है। ये करंट सतह से और भी न्यूट्रिएंट्स लेकर ऊपर की तरफ आती है और प्रवाह बंट जाता है। जब बर्फ ज्यादा पिघलेगी तो अंटार्कटिका का पानी पतला और कम नमक वाला हो जाएगा। इससे गहरे समुद्र के भीतर का बहाव धीमा पड़ जाएगा।

ध्रुवीय फूड चेन पर प्रभाव:

- गहरे समुद्र का भीतरी प्रवाह कम होते ही 4 हजार मीटर से ज्यादा गहराई वाले हिस्सों में पानी का बहना ही रुक जाएगा। इससे दलदल का निर्माण होगा, जहां पानी एक निश्चित दायरे में जम जाता है।
- धाराओं के जरिए ही मछलियों और बाकी समुद्री जीवों तक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचता है। इसमें कमी आने से पोषण में भी कमी आने लगेगी। इससे फूड चेन बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाएगी। सबसे बड़ी बात कि इससे पानी में ऑक्सीजन सप्लाई पर असर होगा, जो समुद्र के भीतर उठापटक मचा देगा।
- इसका असर बाहर भी पड़ेगा। चूंकि समुद्र के ऊपर की परतें कमजोर पड़ जाएंगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित नहीं कर पाएंगी, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाएगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संक्षिप्त मुद्दे

थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस)

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 महामारी के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि टीकाकरण के संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। लंदन में उच्च न्यायालय के समक्ष एक कानूनी दस्तावेज में कंपनी ने स्वीकार किया है कि कोविड वैक्सीन अत्यंत दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) के साथ थ्रोम्बोसिस को प्रेरित कर सकती है।

थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) क्या है?

- थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) के साथ थ्रोम्बोसिस एक दुर्लभ स्थिति है, जिसमें शरीर में असामान्य स्थानों पर रक्त के थक्के बन जाते हैं और रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट्स छोटी कोशिकाएं होती हैं, जो रक्त को जमने में मदद करती हैं।
- इसे कुछ कोविड-19 टीकों से जुड़े एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिकूल प्रभाव के रूप में देखा गया है, विशेष रूप से वे जो कोविशील्ड जैसे एडेनोवायरस वैक्टर का उपयोग करते हैं।
- एडेनोवायरस वैक्टर गैर-आवरण वाले, डबल-स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हैं जो आमतौर पर जीन थेरेपी, टीकाकरण और कैंसर जीन थेरेपी के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- उनकी सुरक्षा प्रोफाइल और अभिव्यक्ति के कारण उन्हें सबसे कुशल जीन वितरण वाहन माना जाता है।
- 2023 yalemedicine.org की रिपोर्ट के अनुसार, रक्त का थक्का रक्त का एक जेल जैसा द्रव्यमान होता है जो आपकी त्वचा पर चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने के लिए स्वाभाविक रूप से बनता है।
- हालाँकि, जब ये थक्के रक्त वाहिकाओं के अंदर विकसित होते हैं, तो रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं और कई मौतों के लिए जिम्मेदार स्थिति पैदा कर सकते हैं।
- ऐसे थक्के आमतौर पर उन लोगों में होते हैं जो गतिहीन हैं, अस्पताल में भर्ती हैं या सूजन, संक्रमण या कैंसर से जुड़ी चिकित्सीय स्थितियों से पीड़ित हैं।

टीटीएस के लक्षण:

- गंभीर या लगातार सिरदर्द
- धुंधली दृष्टि

- सांस लेने में कठिनाई
- छाती में दर्द
- पैर में सूजन
- लगातार पेट दर्द रहना
- इंजेक्शन लगने वाली त्वचा के नीचे आसानी से नीला पड़ना या छोटे रक्त के धब्बे दिखाई देना

जोखिम में कौन हैं?

- कुछ कारक व्यक्तियों को इस स्थिति के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जैसे उम्र, युवा महिला और संभवत: आनुवंशिक कारक।

उपाय:

- जिन व्यक्तियों को टीटीएस से जुड़े टीके मिले हैं, उनके लिए लक्षणों के बारे में जागरूक रहना और टीकाकरण के कुछ हफ्तों के भीतर उनमें से किसी का भी अनुभव होने पर चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है। टीटीएस को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रारंभिक पहचान और उपचार महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष:

ब्रिटेन की अदालत में एस्ट्राजेनेका के दस्तावेजों में यह स्वीकार करने के बाद कि उसके कोविड-19 टीके में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) के साथ थ्रोम्बोसिस पैदा करने की क्षमता है जिसने जनता में परेशानी का स्थिति पैदा की है। हालांकि भारत में डॉक्टरों ने कहा है कि यह जानकारी नई नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे 'चेतावनी से अच्छी तरह वाकिफ हैं'। इसके अलावा, उन्होंने ध्यान दिलाया कि टीके से जुड़ी कोई भी प्रतिकूल घटना पहली खुराक के 21 दिनों से एक महीने के भीतर घटित हुई होगी।

वेस्ट नाइल वायरस रोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल राज्य के तीन जिले 'त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड' में वेस्ट नाइल बुखार के मामले सामने आए हैं।

वेस्ट नाइल वायरस रोग क्या है?

- वेस्ट नाइल वायरस (डब्ल्यूएनवी) एक मच्छर जनित, सिंगल स्ट्रेडेड आरएनए वायरस है। यह एक फ्लेविवायरस है और उन वायरस से संबंधित है जो जापानी एन्सेफलाइटिस और पीले बुखार का कारण बनते है।
- क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर इसके संचरण के प्रमुख वाहक के रूप में कार्य करते हैं। संक्रमित मच्छर पक्षियों सहित मनुष्यों और जानवरों के बीच बीमारी फैलाते हैं।
- मच्छर अपने रक्त प्रवाह में वायरस ले जाने वाले पक्षियों को खाने से संक्रमित हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वायरस मच्छर की लार ग्रंथियों तक पहुंच जाता है।
- जब मच्छर फिर से काटता है, तो यह वायरस को मनुष्यों और जानवरों में इंजेक्ट कर सकता है, जिससे संभावित रूप से बीमारी हो सकती है क्योंकि यह मच्छरों के शरीर में भी मल्टीप्लाई होता है।
- डब्ल्यूएनवी रक्त आधान के माध्यम से, संक्रमित मां से उसके बच्चे में या प्रयोगशालाओं में वायरस के संपर्क में आने से भी फैल सकता है।
- हालांकि यह अभी ज्ञात नहीं किया जा सका है कि यह संक्रमित मनुष्यों या जानवरों के संपर्क में आने से फैलता है कि नहीं। यह पक्षियों सहित संक्रमित जानवरों को खाने से नहीं फैलता है।

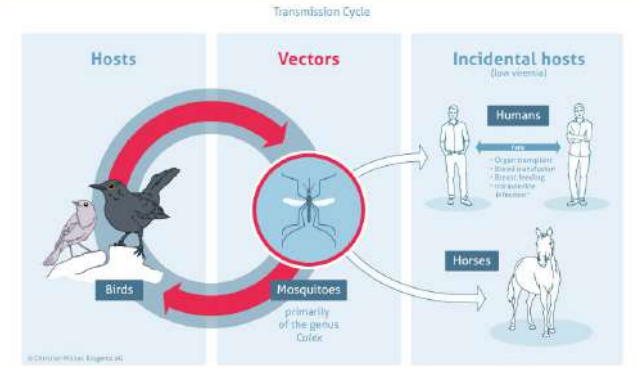

नाइल वायरस नाम क्यों?

- यह वायरस सबसे पहले 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में एक महिला में पाया गया था। इसकी पहचान 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों (कौवे और कोलंबिफॉर्म जैसे कबूतर) में की गई थी।
- 1997 से पहले, डब्ल्यूएनवी को पक्षियों के लिए रोगजनक नहीं माना जाता था, लेकिन फिर, एक अधिक विषैले स्ट्रेन के कारण इजराइल में विभिन्न पक्षी प्रजातियों की मृत्यु हो गई, जिससे एन्सेफलाइटिस और पक्षाघात के लक्षण दिखाई दिए। फिर इसे रोगजनक की श्रेणी में रखा गया।

भारत में वायरस:

- भारत में, डब्ल्यूएनवी के खिलाफ एंटीबॉडी पहली बार 1952 में मुंबई में मनुष्यों में पाई गई थी और तब से दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी भारत में वायरस गतिविधि की सूचना मिली है।
- डब्ल्यूएनवी को भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्यूलेक्स विष्णुई मच्छरों से, महाराष्ट्र में क्यूलेक्स क्विनक्यूफैसियाटस मच्छरों से और कर्नाटक में मनुष्यों से अलग किया गया है।

निष्कर्ष:

वर्तमान में, वेस्ट नाइल वायरस (डब्ल्यूएनवी) का कोई इलाज या टीका नहीं है। न्यूरोइनवेसिव डब्ल्यूएनवी वाले रोगियों के लिए सहायक देखभाल ही एकमात्र विकल्प है। पक्षियों और घोड़ों में नए मामलों का पता लगाने के लिए एक सक्रिय पशु स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित करना महत्वपूर्ण है। चूंकि जानवरों में डब्ल्यूएनवी का प्रकोप अक्सर मानव मामलों से पहले होता है, इसलिए यह प्रणाली पशु चिकित्सा और मानव सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों दोनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी

प्रदान कर सकती है।

भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023

चर्चा में क्यों?

इसरो ने वर्ष 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति मूल्यांकन रिपोर्ट (आईएसएसएआर) जारी की। यह रिपोर्ट, सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष संचालन हेतु अंतरिक्ष संपत्तियों की स्थिति एवं अंतरिक्ष के संभावित खतरों का आकलन करती है।

रिपोर्ट में बताई गयी प्रमुख बातें:

वैश्विक परिदृश्य:

- रिपोर्ट के अनुसार 2023 में, अंतरिक्ष वस्तु (ऑब्जेक्ट) आबादी में वृद्धि जारी रही, जो अंतरिक्ष तक बढ़ती पहुंच और दैनिक जीवन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बढ़ते अनुप्रयोगों को दर्शाता है।
- वर्ष 2022 की तुलना में ऑर्बिट में स्थापित अंतरिक्ष वस्तुओं की संख्या में वृद्धि देखी गई, जिसमें 212 प्रक्षेपणों और ऑन-ऑर्बिट ब्रेक-उप घटनाओं से कुल 3143 ऑब्जेक्ट्स शामिल किऐ गए।
- भारत ने दिसंबर वर्ष 2023 के अंतर्गत 127 उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ इसमें योगदान दिया।
- प्रगति के बावजूद, 2023 में ऑन-ऑर्बिट ब्रेक उप की पांच प्रमुख घटनाएं हुई। जहां एक वर्ष के भीतर ही कुछ टुकड़े नष्ट हो गए, 2023 के अंत तक अंतरिक्ष मलबे की आबादी में 69 खंडित ऑब्जेक्ट्स शामिल हो गए।

भारतीय परिदृश्य:

- 31 दिसंबर 2023 तक निजी ऑपरेटरों/शैक्षणिक संस्थानों सहित कुल 127 भारतीय उपग्रह लॉन्च किए गए हैं।
- 2023 में इसरो के सभी प्रक्षेपण सफल रहे।
- 31 दिसंबर, 2023 तक, भारत सरकार के पास लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में 22 और जियो-सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट (GEO) में 29 परिचालन उपग्रह थे।
- इसके अलावा 2023 के अंत तक तीन भारतीय गहन अंतरिक्ष मिशन भी सक्रिय थे: चंद्रयान-2 ऑर्बिटर, आदित्य-एल1, और चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल।
- 2023 के अंत तक, 21 भारतीय उपग्रह वायुमंडल में पुन: प्रवेश कर चुके थे, जिनमें से 8 उपग्रह अकेले 2023 में पुन: प्रवेश कर चुके थे।
- भारतीय प्रक्षेपणों ने 2023 तक 82 रॉकेट को ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। 2001 में पीएसएलवी-सी3 के ऊपरी चरण के आकस्मिक टूटने से 371 मलबे के टुकड़े उत्पन्न हुए, जिनमें से 2023 के अंत तक 52 अभी भी ऑर्बिट में हैं।

अंतरिक्ष स्थिति आकलन 2023:

- इसरो की एसएसए गतिविधियों में उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों का मूल्यांकन, वायुमंडलीय पुन: प्रवेश की भविष्यवाणी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष वस्तु (ऑब्जेक्ट) आबादी के विकास का अध्ययन और बाहरी अंतरिक्ष में संचालन करते समय जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना शामिल है।
- **इसरो:** इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का एक प्रमुख घटक हैं।
- **गठन:** वर्ष 1969
- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय हितों की पूर्ति एवं मानवीय विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास सुनिश्चित करना।

भारत द्वारा अंतरिक्ष मलबे को कम करने की पहल:

- **NETRA परियोजना:** अंतरिक्ष वस्तु ट्रैकिंग और विश्लेषण के लिए नेटवर्क
- **SOPA:** ISTRAC के माध्यम से निकट दृष्टिकोण की भविष्यवाणी के लिए अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण
- **COLA:** लॉन्च वाहनों के लिए टकराव बचाव विश्लेषण

निष्कर्ष:

किसी भी अंतरिक्ष वस्तु के निकट आने की स्थिति में परिचालन संपत्तियों की सुरक्षा के लिए टकराव बचाव युद्धाभ्यास (सीएएम) का चलन बढ़ रहा है। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय मलबे को कम करने के लिए वैश्विक अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बहुचर्चित गगनयान प्रोजेक्ट के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की भारत की योजना को अंतरिक्ष मलबे के मुद्दों से खतरा हो सकता है, ऐसे मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन की विशेष आवश्यकता है।

CRISPR: वंशानुगत अंधेपन के इलाज के लिए BRILLIANCE अध्ययन

चर्चा में क्यों?

जन्मजात अंधेपन से पीड़ित 14 व्यक्तियों में CRISPR जीन एडिटिंग के अभूतपूर्व चिकित्सकीय परीक्षण के परिणाम सकारात्मक हैं। एक विशेष शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के माध्यम से पीड़ितों की आंख में CRISPR/Cas9 जीनोम आधारित EDIT-101 का एक इंजेक्शन लगाया गया जिसके अच्छे परिणाम दिखे हैं।

अध्ययन के प्रमुख अंश:

- **BRILLIANCE:** इस परीक्षण को "BRILLIANCE" कहा गया। 14 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया, जिन्हें जन्मजात मे अंधपन का एक दुर्लभ रूप था, जिसे लेबर कंजेनिटल अमोरोसिस (एलसीए) के रूप में जाना जाता है। इन प्रतिभागियों में 12 वयस्क और दो बच्चे शामिल थे।
- यह अध्ययन उन बच्चों के इलाज के लिए जीन थेरेपी का उपयोग करने वाला पहला अध्ययन था जो एक प्रकार के अंधेपन के साथ पैदा हुए थे। अध्ययन में भाग लेने वालों को EDIT-101 नामक

CRISPR जीन थेरेपी की एक खुराक मिली।

- अध्ययन में परीक्षण किया गया कि प्रतिभागी कितनी अच्छी तरह रंगीन रोशनी देख सकते हैं, अलग-अलग मात्रा में प्रकाश में एक छोटी वस्तुओं को देख सकते हैं और उपचार प्राप्त करने के बाद एक चार्ट से पढ़ सकते हैं।

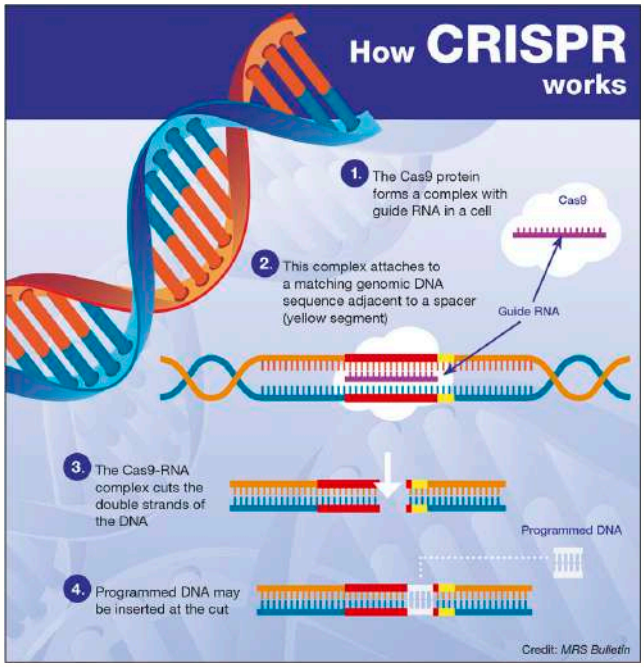

EDIT-101 के बारे में:

- यह प्रोटीन CEP290 के सामान्य कार्य को पुनर्स्थापित करता है, जिससे रेटिना, प्रकाश का पता लगाने में सक्षम हो पाती है।
- इससे प्रतिभागियों पर कोई गंभीर प्रतिकूल दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। हालाँकि कुछ रोगियों ने हल्के प्रतिकूल प्रभाव की सूचना दी, हालाँकि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान कर लिया गया।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, क्लिनिकल परीक्षण में 14 में से 11 लोगों की दृष्टि में सुधार हुआ, बिना किसी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव के।

लेबर जन्मजात अमोरोसिस के बारे में:

- लेबर जन्मजात अमोरोसिस (Leber Congenital Amaurosis) जन्मजात रेटिनल डिस्ट्रोफी का एक समूह है जिसके परिणामस्वरूप कम उम्र में दृष्टि कमजोर होती है। यह 40,000 लोगों में से एक को प्रभावित करता है
- यह अंधापन एक जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है जो CEP290 नामक प्रोटीन को ठीक से काम करने से रोकता है। यह प्रोटीन दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है।

सीआरआईएसपीआर के बारे में:

- CRISPR/Cas9 डीएनए को बदलने का एक सटीक तरीका है। यह डीएनए के विशिष्ट स्ट्रैंड को काट देता है और उन्हें नए स्ट्रैंड से बदल देता है।
- 2020 में, इमैनुएल चार्पेंटियर और जेनिफर ए डौडना को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।यह पुरस्कार जीन प्रौद्योगिकी के सबसे तेज उपकरणों में से एक CRISPR/Cas9 आनुवंशिक कैंची की खोज के लिए दिया गया है।

निष्कर्ष:

- प्रायोगिक सीआरआईएसपीआर प्रौद्योगिकियों से 200 से अधिक लोगों का इलाज किया गया है। लेकिन अब तक, केवल एक सीआरआईएसपीआर उपचार को नैदानिक उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। कैसगेवी (जिससे सिकल सेल रोग का उपचार किया गया हैं) दिसंबर 2023 से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में उपलब्ध है।
- चल रहे अन्य नैदानिक परीक्षण एचआईवी/एड्स, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोगों और एंटीबायोटिक प्रतिरोध के लिए अन्य सीआरआईएसपीआर उपचारों का परीक्षण कर रहे हैं।
- वैज्ञानिकों का कहना हैं के हम जीनोम संपादन प्रौद्योगिकियों में एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके द्वारा न कि केवल इलाज कर सकते हैं बल्कि कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रोगियों की सुरक्षित रूप से मदद कर सकते हैं।

दिल्ली की डेयरियों में ऑक्सीटोसिन का उपयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को दिल्ली में डेयरी कॉलोनियों में मवेशियों पर ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश एक याचिका की सुनवाई के दौरान आया है।

ऑक्सीटोसिन का उपयोग प्रतिबंधित क्यों?

- केंद्र सरकार ने अप्रैल 2018 में ऑक्सीटोसिन पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए दुधारू मवेशियों पर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे न केवल मवेशियों के स्वास्थ्य पर बल्कि दूध का सेवन करने वाले मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है।
- केंद्र ने निर्णय लिया था कि पूरे देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (KAPL) को ऑक्सीटोसिन का उत्पादन करने की अनुमति दी जाएगी। ऑक्सीटोसिन मवेशियों में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है।

न्यायालय के निर्देश:

- पीठ ने कहा कि चूंकि ऑक्सीटोसिन देना पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है, यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 12 के तहत एक संज्ञेय अपराध है।

- न्यायलय ने औषधि नियंत्रण विभाग, जीएनसीटीडी को साप्ताहिक निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नकली ऑक्सीटोसिन के उपयोग या कब्जे के सभी मामले, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 12 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम की धारा 18 (ए) के तहत दर्ज किए जाएं।
- न्यायालय ने आगे कहा कि इन अपराधों की जांच क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशनों द्वारा की जाएगी जहां डेयरी कॉलोनियां स्थित हैं।

डेयरी स्थल को लेकर न्यायालय की प्रतिक्रिया:

- न्यायालय का विचार था कि डेयरियों को उचित सीवेज, जल निकासी, बायोगैस संयंत्र, मवेशियों के घूमने के लिए पर्याप्त खुली जगह और पर्याप्त चारागाह क्षेत्र वाले क्षेत्रों में 'स्थानांतरित' किया जाना चाहिए।
- न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि लैंडफिल साइटों के बगल में स्थित डेयरियों में मवेशी खतरनाक अपशिष्टों को खाते हैं और यदि उनका दूध मनुष्यों, विशेषकर बच्चों द्वारा पिया जाता है, (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि लैंडफिल साइटों के बगल में डेयरियां बीमारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, इसलिए इन डेयरियों को तुरंत स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर न्यायालय ने जोर दिया।

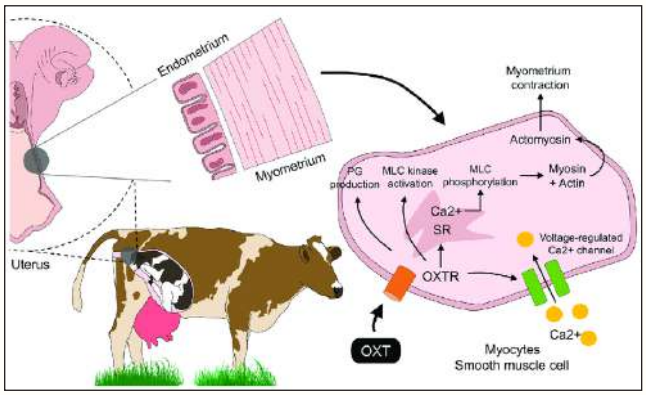

ऑक्सीटोसिन क्या है?

- ऑक्सीटोसिन स्तनधारियों की पिट्यूटरी ग्रंथियों द्वारा, प्रसव, स्तनपान आदि के दौरान स्रावित होता है। इस हार्मोन को "लव हार्मोन" भी कहा जाता है।
- इसे प्रसव के दौरान उपयोग के लिए फार्मा कंपनियों द्वारा रासायनिक रूप से निर्मित किया जाता है और बेचा जाता है और इसे या तो इंजेक्शन या नाक से घोल के रूप में दिया जाता है।

निष्कर्ष:

ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग को रोकने के लिए, मादक और मनोदैहिक दवाओं या एंटीबायोटिक दवाओं के समान, मानव और पशु चिकित्सा उपयोग के लिए इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अवैध आयातकों और बिना लाइसेंस वाले उत्पादकों पर छापे मारकर और निगरानी में तकनीक का प्रयोग कर इसके दुरुपयोग से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिल सकती है।

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (एनटीडी) 2024 पर अपनी वैश्विक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट की प्रमुख बातें:

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग का वैश्विक बोझ:

- रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में 1.62 बिलियन लोगों को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (एनटीडी) के खिलाफ उपचार की आवश्यकता थी। हालांकि यह 2010 से 26% की कमी को दर्शाता है, लेकिन यह सतत विकास लक्ष्य 2030 रोड मैप के 90% की कमी के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गति प्रदान नहीं करता है।
- 2023 में, डब्ल्यूएचओ द्वारा पांच देशों को एक एनटीडी को खत्म करने के लिए और एक देश को दो एनटीडी को खत्म करने के लिए मान्यता दी गई थी। दिसंबर 2023 तक, कुल 50 देशों ने कम से कम एक एनटीडी को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है, जो 100 देशों के 2030 लक्ष्य की ओर आधा रास्ता है।
- 2022 में, लगभग 848 मिलियन लोगों ने निवारक कीमोथेरेपी उपचारों के माध्यम से कम से कम एक एनटीडी के लिए उपचार प्राप्त किया, 2021 की तुलना में 49 मिलियन कम लेकिन 2020 की तुलना में 50 मिलियन अधिक।
- 2022 के अंत तक, वेक्टर-जनित एनटीडी से होने वाली मौतों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है (2016 की तुलना में)।
- 2023 में, नोमा (कैन्क्रम ऑरिस, गैंग्रीनस स्टामाटाइटिस) को एनटीडी की सूची में जोड़ा गया था।

एनटीडी रणनीतियों में प्रगति:

- एकीकृत त्वचा-एनटीडी रणनीतियों (11 देशों) को अपनाने और कार्यान्वयन और एनटीडी से संबंधित (19 देशों) के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन के विकास में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।
- एनटीडी को 28 देशों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में एकीकृत किया गया है और एनटीडी हस्तक्षेपों को 6 देशों की आवश्यक सेवाओं के पैकेज में शामिल किया गया है।
- 32 देश एनटीडी पर डेटा रिपोर्टिंग करते हैं, जबकि 17 देश लिंग-विभाजित डेटा एकत्र और रिपोर्ट कर रहे हैं।
- एनटीडी-स्थानिक देशों में जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वच्छता तक पहुंच कुल मिलाकर 85.8% है और एनटीडी के खिलाफ उपचार

की आवश्यकता वाली आबादी का प्रतिशत 63% है।
- एनटीडी के कारण भयावह स्वास्थ्य आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय से सुरक्षित होने वाली आबादी का हिस्सा 87.4% है।

वित्तीय सहायता:
- एनटीडी दवा दान कार्यक्रमों ने 2023 में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किए, 2.1 बिलियन टैबलेट और शीशियाँ वितरित कीं, जो 2022 की तुलना में 200 मिलियन अधिक हैं। उनमें से, 994 मिलियन का प्रबंधन डब्ल्यूएचओ द्वारा किया गया और 112 सदस्य राज्यों को मुफ्त में उपलब्ध कराया गया।
- 2023 में, एनटीडी कार्यक्रमों को लागू करने, निगरानी करने और मूल्यांकन करने के लिए सदस्य राज्यों और भागीदारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मानक मार्गदर्शन, क्षमता सुदृढ़ीकरण उपकरण और डेटा संग्रह तंत्र की पेशकश को व्यापक बनाया गया था।
- 2023 में किए गए प्रमुख कार्यक्रमों में ग्लोबल एनटीडी प्रोग्राम पार्टनर्स की बैठक और रीचिंग द लास्ट माइल फोरम शामिल थे, जिसने वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे में एनटीडी की दृश्यता बढ़ाई और संसाधन जुटाना बढ़ाया।

निष्कर्ष:
27 मई से 1 जून 2024 तक जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA77) के 77वें सत्र से पहले जारी की गई रिपोर्ट, सदस्य राज्यों और वैश्विक भागीदारों को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए रोडमैप 2021-2030 को लागू करने की दिशा में 2023 में प्रगति पर अपडेट प्रदान करती है। यह दुनिया भर में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों (एनटीडी) से निपटने में प्रगति और चुनौतियों का एक व्यापक विवरण प्रदान करता है।

कृत्रिम सामान्य बुद्धिमता (AGI)

चर्चा में क्यों?
हाल ही में ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआई) के विकास के लिए अरबों डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता का परिचय:
- आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस ऐसा सिस्टम होता हैं जिनके सॉफ्टवेयर में सामान्य मानव संज्ञानात्मक क्षमता होती हैं जो इंसानों की तरह समझ कर वातावरण के मुताबिक प्रतिक्रिया करने के लिए फैसले करते हैं।
- यह तर्क करने और नए वातावरण और विभिन्न प्रकार के डेटा के प्रति अनुकूल होने में सक्षम है। यह कार्य करने के लिए पूर्व निर्धारित नियमों पर निर्भर रहने के बजाय, मनुष्यों के समान समस्या-समाधान और सीखने के दृष्टिकोण को अपनाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता में अंतर:
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे संकीर्ण AI भी कहा जाता है, एक विशिष्ट कार्य करने में सक्षम है, जिसे करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। दूसरी ओर, कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता इंसानों की तरह सीखने, सोचने और अनुकूलन करने एवं विविध कार्यों को करने में सक्षम है।

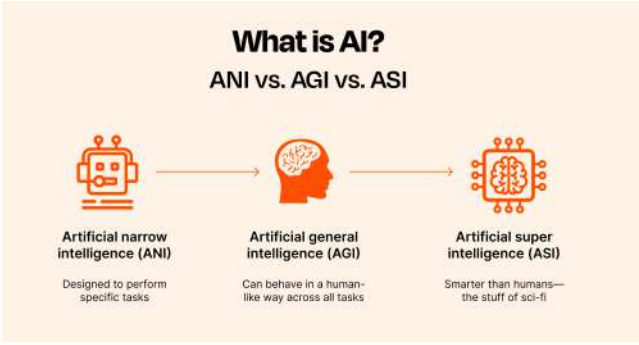

लाभ:
- **सैन्य क्षेत्र में:** AGI का विशिष्ट उपयोग निगरानी, सैन्य भागीदारी, वास्तविक समय की रणनीतियों और युद्ध प्रणालियों को बढ़ाने में होगा।
- **व्यवसाय के क्षेत्र में:** एजीआई से विभिन्न व्यवसायों उच्च तकनीक से स्वचालित किया जा सकता है और निर्णय लेने की क्षमता में गति में तेजी लायी जा सकती हैं।
- **शिक्षा:** एजीआई ग्रेडिंग को स्वचालित करता है, सीखने को वैयक्तिकृत करता है और छात्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकता है। एआई उपकरण शिक्षकों को पाठ्यक्रम सामग्री बनाने और छात्रों को नए तरीकों से संलग्न करने में मदद कर सकते हैं।

चिंतायें:
- **बेरोजगारी में वृद्धि:** इससे समाज में बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था भारत जैसे श्रम की अति उपलब्धता वाले देश के लिए उचित नहीं है।
- **रचनात्मक कौशल में कमी:** कल्पना आधारित तकनीक मनुष्य के रचनात्मक कौशल में कमी ला सकती है। वह कम समय में मानव से बेहतर एवं सृजन का कार्य कर सकती है।

निष्कर्ष:
एजीआई अभी भी काफी दूर है, लेकिन एआई क्षेत्र में तेजी से प्रगति ने प्रौद्योगिकी को एजीआई हासिल करने के करीब ला दिया है। कुछ भविष्यवाणियों में तो यह भी बताया गया है कि कंप्यूटर 2029 की शुरुआत में ही मानव बुद्धि के स्तर तक पहुंच जाएंगे। एजीआई की प्राप्ति का मतलब एआई होगा जो अमूर्त सोच, सामान्य ज्ञान, पृष्ठभूमि ज्ञान, स्थानांतरण शिक्षा और कारण और प्रभाव पर कार्य कर सकता है। इससे कई उद्योगों के लिए संभावनाएं खुलेंगी।

निसार द्वारा विवर्तनिक गतिविधियों की निगरानी

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) नासा के साथ मिलकर निसार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए तैयार है, NISAR देश और विश्व में आने वाले भूकंपों की पहले ही भविष्यवाणी कर सकेगा क्योंकि यह टेक्टोनिक प्लेट्स की गति का अध्ययन करेगा।

निसार के बारे में:

- नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) एक उपग्रह है जिसे नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) के लिए विकसित किया गया है ताकि पृथ्वी की सतह में सूक्ष्म बदलावों को ट्रैक किया जा सके। उपग्रह को अक्टूबर 2024 में लॉन्च करने की योजना है।
- यह एक द्वि-आवृत्ति उपग्रह है। जिसमें एल-बैंड और एस-बैंड हैं। नासा ने एल-बैंड रडार, जीपीएस, सॉलिड-स्टेट रिकॉर्डर और पेलोड डेटा सबसिस्टम पर जबकि इसरो एस-बैंड रडार, जीएसएलवी लॉन्च सिस्टम और अंतरिक्ष यान पर काम कर रहा है।

एंटीना रिफ्लेक्टर:

- उपग्रह का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा इसका बड़ा 39-फुट स्थिर एंटीना रिफ्लेक्टर है जो लगभग 14 से 15 दिनों में पृथ्वी को पूरी तरह से कवर कर सकता है।
- यह उपकरण संरचना पर ऊपर की ओर संकेत देने वाले फीड द्वारा उत्सर्जित और प्राप्त रडार संकेतों को केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

-: प्रीलिम्स इनसाइट :-

स्पाडेक्स:

- स्पाडेक्स भारत की क्षमता का परीक्षण करेगा कि वह अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को डॉक करने के लिए स्वायत्त युद्धाभ्यास कर सकता है, जैसे कि स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल का आईएसएस के साथ डॉकिंग।
- स्पेस डॉकिंग एक तकनीक है जो एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान में मनुष्यों को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है।

एनआईएसएआर की क्षमताएं:

- सेंटीमीटर सटीकता के साथ विवर्तनिक गतिविधियों की निगरानी।
- जल निकायों का सटीक मापन और जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल तनाव का आकलन।
- कुछ गहराई तक भूमि की परतों को भेदना और वनस्पति आवरण और हिमावरण की निगरानी करना।

सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR):

- सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) एक उपग्रह इमेजिंग तकनीक है जो पृथ्वी की सतह की मैपिंग करने के लिए रडार तरंगों का उपयोग करती है।
- ऑप्टिकल इमेजरी के विपरीत, जो पृथ्वी की सतह से परावर्तित प्रकाश को एक तस्वीर की तरह कैप्चर करती है, SAR सेंसर से सतह पर विद्युतचुंबकीय तरंगों को प्रसारित करके काम करता है।
- ये तरंगें सतह से वापस (बैकस्कैटर) सेंसर पर लौटती हैं, जो सतह की विशेषताओं और सेंसर और वस्तु के बीच की दूरी के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं।
- SAR एक सक्रिय डेटा संग्रहण विधि है। यह सेंसर अपने ऊर्जा के लिए प्रसारण उत्पन्न करता है।

निष्कर्ष:

निसार मिशन पृथ्वी की सतह के विस्तृत अवलोकन प्रदान करेगा, बर्फ की चादरों, भूमि विकृति, और पारिस्थितिक तंत्रों में बदलावों को ट्रैक करेगा। ये डेटा पृथ्वी की प्रक्रियाओं की हमारी समझ को बढ़ाएगा और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा। यह भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा, प्रतिक्रिया समय और जोखिम आकलन में सुधार करेगा। यह पृथ्वी की भूमि सतह पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी और समझ में मदद करेगा, जिसमें ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि और कार्बन भंडारण में परिवर्तन शामिल हैं।

बैक्टीरियल पैथोजेन्स प्राथमिकता सूची

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस (AMR) के खिलाफ लड़ाई में बैक्टीरियल प्रायोरिटी पैथोजेन्स लिस्ट (BPPL) का नवीनीकरण कर महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

बैक्टीरियल प्रायोरिटी पैथोजेन्स लिस्ट क्या है?

- 2024 की WHO बैक्टीरियल प्रायोरिटी पैथोजेन्स लिस्ट (BPPL) एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 2017 से एंटीबायोटिक -प्रतिरोधी बैक्टीरियल पैथोजेन्स की प्राथमिकता सूची को सुधारता है ताकि एंटीबायोटिक प्रतिरोध की बदलती चुनौतियों का सामना किया जा सके।
- यह सूची इन पैथोजेन्स को महत्वपूर्ण, उच्च और मध्यम प्राथमिकता समूहों के तीन प्राथमिकता समूहों में वर्गीकृत करती है, ताकि अनुसंधान और विकास (R-D) और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके।

- महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले पैथोजेन्स में उच्च भार और उपचार का प्रतिरोध करने और अन्य बैक्टीरिया में प्रतिरोध फैलाने की क्षमता के कारण प्रमुख वैश्विक खतरे होते हैं।
- अपडेट की गई सूची 15 परिवारों के एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया को तीन प्राथमिकता समूहों में वर्गीकृत करती है:
  - **महत्वपूर्ण प्राथमिकता समूह:** इसमें ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया (वे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। जैसे एसिनेटोबैक्टर शामिल हैं, जो आसानी से प्रतिरोध विकसित और फैला सकते हैं) और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर्क्युलोसिस रोग जो रिफाम्पिसिन के प्रतिरोधी होते हैं, जो तपेदिक के उपचार के लिए एक चिंता का विषय है।
  - **उच्च प्राथमिकता समूह:** इसमें वानकोमाइसिन-प्रतिरोधी पैथोजेन्स शामिल हैं, जो अस्पताल में होने वाले संक्रमण हैं और मेथिसिलिन-प्रतिरोधी स्टैफिलोकोकस ऑरियस (एमआरएसए), जो सामान्य एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी संक्रमण है।
  - **मध्यम प्राथमिकता समूह:** इसमें ऐसे पैथोजेन्स शामिल हैं जो विशेष रूप से कमजोर आबादी में उच्च रोग बोझ का कारण बनते हैं। 2024 सूची में नए जोड़े गए ग्रुप A और B स्ट्रेप्टोकोकाई शामिल हैं।

AMR से निपटने के लिए निवारक उपाय:

- **एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप:** व्यक्तियों को केवल डॉक्टर द्वारा परामर्श दिए जाने पर एंटीबायोटिक लेना चाहिए और पूरा कोर्स पूरा करना चाहिए, भले ही वे बेहतर महसूस करने लगें। उन्हें वायरल बीमारियों जैसे सामान्य सर्दी के लिए एंटीबायोटिक के लिए अपने डॉक्टर पर दबाव नहीं डालना चाहिए।
- **स्वच्छता प्रथाएं:** लोगों को अक्सर हाथ धोना चाहिए, विशेष रूप से खाने या भोजन तैयार करने से पहले, और बाथरूम का उपयोग करने के बाद। उन्हें मांस को अच्छी तरह पकाना चाहिए, संक्रमण से बचना चाहिए और अपने घरों को साफ रखना चाहिए।
- **टीकाकरण:** टीके कुछ बैक्टीरियल संक्रमणों को रोक सकते हैं, जैसे कि न्यूमोकोकस के कारण होने वाले संक्रमण।
- **जागरूकता:** लोगों को एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस (AMR) के बारे में स्वयं और दूसरों को शिक्षित करना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में संक्रमण रोकथाम और जिम्मेदार एंटीबायोटिक उपयोग को बढ़ावा देने वाली नीतियों के लिए जागरूकता को बढ़ाना चाहिए।

निष्कर्ष:

2024 की WHO बैक्टीरियल प्रायोरिटी पैथोजेन्स लिस्ट (BPPL) ड्रग -प्रतिरोधी बैक्टीरिया के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 2017 की पहली सूची के बाद से एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस का खतरा बढ़ गया है, जिससे कई एंटीबायोटिक्स की प्रभावशीलता कम हो गई है और आधुनिक चिकित्सा की प्रगति को खतरे में डाल दिया है।

3डी प्रिंटेड रॉकेट इंजन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (जिसे 3डी प्रिंटिंग भी कहा जाता है) तकनीक का उपयोग करके बनाए गए लिक्विड-फ्यूल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक हॉट-फायर परीक्षण किया।

3डी प्रिंटेड इंजन के बारे में:

- पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) के चौथे चरण में PS4 इंजन का उपयोग किया जाता है। इसरो ने इसे पुन: डिजाइन किया और यह एक लिक्विड रॉकेट इंजन है जो हाइपरगोलिक मिश्रण नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड और मोनोमेथिल हाइड्राजीन के द्वि-प्रणोदक संयोजन का उपयोग करता है। 145 फुट ऊँचा (44 मीटर) पीएसएलवी, भारत के मुख्य लॉन्चरों में से एक है, साथ ही एलवीएम-3 भी है।
- यह रॉकेट 370 मील (600 किमी) ऊंची सूर्य-सिंक्रोनस ध्रुवीय कक्षाओं में 3,860 पाउंड (1,750 किलोग्राम) तक का पेलोड वितरित कर सकता है।

-: प्रीलिम्स इनसाइट :-

- **सिलेक्टिव लेजर सिन्टरिंग (SLS):** यह पाउडर आधारित 3डी प्रिंटिंग तकनीक है, जो सामग्री परतों को अंतिम भाग में जोड़ने के लिए लेजर का उपयोग करती है।
- **फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग (FDM):** यह तकनीक थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट को बाहर निकालती है ताकि परत दर परत मॉडल बनाया जा सके।
- **स्टीरियोलिथोग्राफी (SLA):** इस फोटोसेंसिटिव तरल पदार्थ को अल्ट्रावायलेट लेजर के तहत ठोस किया जाता है।
- **पॉलीजेट:** यह तरल फोटोपॉलिमर का उपयोग करता है और इस तकनीक के माध्यम से इन तरल फोटोपॉलिमर की सूक्ष्म बूंदों को एक निर्माण केंद्र पर जमा करके भागों का निर्माण करता है।

एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है?

- एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक प्रक्रिया है जो कंप्यूटर-जनित डिजाइनों का उपयोग करके तीन-आयामी वस्तुओं को परत दर परत बनाने के लिए उपयोग की जाती है।
- यह एडिटिव विधि प्लास्टिक, कंपोजिट्स, या बायो-मटेरियल्स जैसी सामग्रियों की परतों को बनाकर विभिन्न आकार, आकार, कठोरता और रंगों की वस्तुओं का निर्माण करती है।
- इसरो ने पारंपरिक रूप से निर्मित पीएस4 इंजन को पुन: डिजाइन

किया ताकि इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के अनुकूल बनाया जा सके, जिसे डिजाइन फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (DfAM) कहा जाता है।

इसरो के अनुसार:

- नये लेजर पाउडर बेड फ्यूजन तकनीक का उपयोग करके बनाए गए इंजन में इंजन के हिस्सों की संख्या को 14 से घटाकर एक कर दिया है।
- नई प्रक्रिया 30.2 पाउंड (13.7 किलोग्राम) धातु पाउडर का उपयोग करती है, जबकि पारंपरिक तकनीक में 1,245 पाउंड (565 किलोग्राम) फोर्जिंग्स और शीट्स की आवश्यकता होती थी। इस नई प्रक्रिया ने समग्र उत्पादन समय को 60% तक कम कर दिया है।

निष्कर्ष:

3डी-प्रिंटेड पीएस4 इंजन का सफलतापूर्वक हॉट परीक्षण भविष्य के रॉकेट इंजनों के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मील का पत्थर भारत के परीक्षण दर को बढ़ावा देने और मानव अंतरिक्ष उड़ान में अपने संभावित योजनाओं का समर्थन करने में मदद करेगा, जिसमें 2047 तक अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतारना शामिल है। यह उपलब्धि नियमित पीएसएलवी कार्यक्रम में एडिटिवली मैन्युफैक्चर्ड पीएस4 इंजन के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे भारत के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए उन्नत निर्माण तकनीकों का एक नया युग शुरू होता है।

TAK-003 डेंगू वैक्सीन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में TAK-003 WHO द्वारा प्रीक्वालिफाइड होने वाला दूसरा डेंगू वैक्सीन बन गया है। इस वैक्सीन को जापान के टाकेडा फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित किया गया है।

वैक्सीन के बारे में मुख्य तथ्य:

- यह एक जीवित-क्षीण टीका है जिसमें डेंगू का कारण बनने वाले वायरस के चार सीरोटाइप के कमजोर संस्करण शामिल हैं।
- WHO उच्च डेंगू बोझ और संचरण तीव्रता वाले क्षेत्रों में 6-16 वर्ष की आयु के बच्चों में TAK-003 के उपयोग की सिफारिश करता है।
- वैक्सीन को 2-खुराक अनुसूची में खुराक के बीच 3 महीने के अंतराल के साथ प्रशासित किया जाना चाहिए।
- TAK-003 डेंगू बीमारी को रोकने में मदद कर सकता है, जो एक मच्छर जनित बीमारी है जो कई मामलों में जीवन के लिए खतरा है।

लाइव-एटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में:

- लाइव-एटेन्यूएटेड वैक्सीन एक प्रकार की वैक्सीन है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए वायरस या बैक्टीरिया जैसे जीवित रोगजनक के कमजोर रूप का उपयोग करता है।
- रोगजनक को उसकी उग्रता और बीमारी पैदा करने की क्षमता को कम करने के लिए बदल दिया जाता है, लेकिन फिर भी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त विशेषताएं बरकरार रहती हैं।

जीवित-क्षीण टीकों के कई फायदे हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया:** वैक्सीन बी और टी कोशिकाओं को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान की जा सकती है।
- **प्राकृतिक संक्रमण की नकल:** वैक्सीन प्राकृतिक संक्रमण प्रक्रिया की नकल करते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली को वास्तविक संक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया करने की अनुमति मिलती है।
- **एकल खुराक:** अक्सर, दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए केवल एक खुराक की आवश्यकता होती है।
- **लागत-प्रभावी:** अन्य प्रकार के टीकों की तुलना में इनका उत्पादन कम महंगा होता है।

डेंगू के बारे में:

- डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो चार संबंधित वायरस में से किसी एक के कारण होती है: डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4।
- यह डेंगू वायरस के कारण होने वाली मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है, जो अक्सर स्पर्शोन्मुख होती है; यदि लक्षण प्रकट होते हैं तो वे आमतौर पर संक्रमण के 3 से 14 दिन बाद शुरू होते हैं।

डेंगू के लक्षण:

- डेंगू का सबसे आम लक्षण बुखार है:
- दर्द (आंखों में दर्द, आमतौर पर आंखों के पीछे, मांसपेशियों, जोड़ों या हड्डियों में दर्द)
- मतली उल्टी

डेंगू कैसे फैलता है?

- डेंगू वायरस मुख्य रूप से संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है।

इलाज:

- डेंगू के इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा अभी उपलब्ध नहीं है।
- जितना हो सके तरल पदार्थ व आराम करने की सलाह दी जाती है।
- चिकित्सक बुखार को नियंत्रित करने और दर्द से राहत पाने के लिए एसिटामिनोफेन लेने की सलाह देते हैं।

निष्कर्ष:

जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण के कारण भौगोलिक रूप से डेंगू के मामलों में वृद्धि और विस्तार होने की संभावना बढ़ गई है। अनुमान है कि हर साल दुनिया भर में डेंगू के 100-400 मिलियन से अधिक मामले आते हैं और 3.8 बिलियन लोग डेंगू प्रभावित देशों में रहते हैं, जिनमें से अधिकांश एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में हैं। इस वैक्सीन से डेंगू के मामलों में कमी आने की संभावना है।

भू-चुम्बकीय उत्क्रमण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बीबीसी विज्ञान फोकस रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तरी ध्रुव लगभग 'प्रति वर्ष 15 किमी' की दर से स्थानांतरित हो रहा है। 1990 के दशक के बाद से यह गति तेज हो गई है, जो साइबेरिया की ओर लगभग '55 किमी प्रति वर्ष' तक पहुँच गई है

डायनमो सिद्धान्त:

- 1900 के दशक के मध्य में भौतिकविद वाल्टर एम. एल्सेसर और एडवर्ड बुलार्ड द्वारा प्रस्तावित डायनेमो सिद्धांत, पृथ्वी के भू-चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रचलित व्याख्या है।
- यह क्षेत्र ग्रह के बाहरी कोर में पिघले हुए धातु पदार्थ के जटिल प्रवाह से उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी के घूमने और कोर में ठोस लोह की उपस्थिति से प्रभावित होता है। परिणामी द्विध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र मोटे तौर पर पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के साथ संरेखित होता है।
- इस डायनेमो क्षेत्र में, बाहरी कोर में द्रव की गति मौजूदा कमजोर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाह हुई सामग्री (तरल लोहा) को स्थानांतरित करती है, जिससे विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है।
- कोर में रेडियोधर्मी क्षय से निकलने वाली गर्मी इस प्रवाह की गति को प्रेरित करता है। विद्युत धारा तब एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जो द्रव के साथ संपर्क करके एक द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है।

पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में:

- पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से एक भू-अक्षीय द्विध्रुवीय है, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों के पास स्थित हैं, जो एक द्विध्रुव चुंबक की तरह कार्य करते हैं।
- यह सौर हवा को रोकता है और पृथ्वी को सौर ज्वालाओं और हानिकारक गामा किरणों से बचाता है। पृथ्वी की सतह से लगभग 60,000 किमी ऊपर तक चुंबकीय प्रभाव महसूस किया जाता है।

भू-चुम्बकीय उत्क्रमण क्या है?

- भू-चुंबकीय उत्क्रमण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक परिवर्तन है जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्तर और दक्षिण आपस में बदल जाते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्मित चट्टानों में चुंबकत्व के अध्ययन से पता चलता है कि पिछले 20 मिलियन वर्षों में, ये खिसकाव लगभग हर 200,000 से 300,000 वर्षों में हुआ है।
- सूर्य के आवधिक 11-वर्षीय उत्क्रमण के विपरीत, पृथ्वी का उत्क्रमण अनियमित है, 10,000 वर्ष से लेकर 25 मिलियन वर्ष तक और इसे पूरा होने में कुछ सौ से लेकर कुछ हजार वर्ष लग सकते हैं।
- पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन (पोलर शिफ्ट थ्योरी) के कारण उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव खिसक जाते हैं। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव (86° उत्तर, 172° पश्चिम), जो वर्तमान में कनाडा में एलेस्मेरे द्वीप के उत्तर में है, तेजी से साइबेरिया की ओर बढ़ रहा है।
- दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव अंटार्कटिका के तट पर, अंटार्कटिक वृत्त के बाहर है। चूँकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सममित (symmetrical) नहीं है, जिससे उनके बीच एक सीधी रेखा पृथ्वी के केंद्र से नहीं गुजरती है।

बदलाव का कारण और प्रभाव:

- उपग्रह अवलोकनों ने हाल ही में पृथ्वी के अंदर तीव्र चुंबकीय क्षेत्र की 'बूँदों' का पता लगाया है, जो वर्तमान परिवर्तनों में योगदान दे रहे हैं।
- उत्तरी ध्रुव की गति 1990 के दशक में 15 किलोमीटर प्रति वर्ष से बढ़कर साइबेरिया की ओर 55 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई है, जो संभवत: आगामी चुंबकीय उत्क्रमण का संकेत दे रही है, हालांकि समय और परिणाम अनिश्चित हैं।
- ये उत्क्रमण कई कारणों से हो सकता है, जिनमें सूर्य भी शामिल है। एक विशाल चुंबक, जो उच्च सनस्पॉट गतिविधि के दौरान पृथ्वी के चुंबकीय ढाल को प्रभावित कर सकता है यदि पृथ्वी का चुंबकत्व कम हो रहा है।
- उल्कापिंड या धूमकेतु का प्रभाव पृथ्वी की ध्रुवीयता को भी उत्क्रमित कर सकता है। ऐसी टक्करें चुंबकत्व को बाधित करती हैं, और जब यह पुनर्गठित होता है, तो चुंबकीय ध्रुव पलट सकते हैं।
- ध्रुव उत्क्रमण के दौरान, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है। यह कमजोर स्थिति ग्रह को सौर विकिरण के अधिक संपर्क में ला सकती है, जिससे पर्यावरण और जीवित जीवों के स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ सकता है।
- **प्रौद्योगिकी पर प्रभाव:** एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र हमारे प्रौद्योगिकी-निर्भर समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। पावर ग्रिड और उपग्रह संचार बाधित हो सकते हैं, जिससे व्यापक तकनीकी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
- **स्वास्थ्य जोखिम:** कमजोर चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी पर बढ़ा हुआ विकिरण जीवित कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है, जिससे जानवरों में कैंसर की दर बढ़ सकती है।
- **पशु नेविगेशन में व्यवधान:** पक्षी और समुद्री कछुए जैसे जानवर नेविगेशन के लिए चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। ध्रुव उत्क्रमण से उनके प्रवासी पैटर्न में बाधा आ सकती है, जिससे उनका अस्तित्व और पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो सकता है।

निष्कर्ष:

हालाँकि ध्रुव उत्क्रमण का विचार चिंताजनक लग सकता है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हजारों वर्षों में सामने आती है। हालाँकि यह घटना ध्यान देने और अध्ययन करने लायक है, लेकिन यह चिंता का तत्काल कारण नहीं है। यह प्रक्रिया क्रमिक है और पृथ्वी के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। वैज्ञानिक हमारे ग्रह और निवासियों पर प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए चुंबकीय क्षेत्र और उसके परिवर्तनों की निगरानी करना जारी रखते हैं।

भारत और दुनिया में पर्यटन की सुधरती स्थिति

कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन, इजरायल-फिलिस्तीन, हीट वेव जैसे तमाम कठिनाइयों के बीच वैश्विक पर्यटन में उछाल देखने को मिला है। इस बात की पुष्टि विश्व आर्थिक मंच ने की जिसने अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत सहित दुनिया के अन्य देशों में पर्यटन की स्थिति के बारे में आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों ने अपनी क्रय शक्ति का इस्तेमाल पर्यटन उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर किया है जिससे देशों व राज्यों को अच्छी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हुई है। पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय सरकारों ने टूरिस्ट स्पॉटो के विकास के लिए निवेश किए हैं और पर्यटकों की सुख सुविधाओं का ध्यान भी रखा है।

हाल ही में भारत वैश्विक यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक-2024 में 15 स्थान की छलांग लगाकर 39वें स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में भारत 54वें पायदान पर था। विश्व आर्थिक मंच की ओर से जारी इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है। वहीं, दक्षिण एशिया और निम्न-मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे आगे है। सरे विश्वविद्यालय की मदद से तैयार सूचकांक से पता चलता है कि भारत अत्यधिक मूल्य प्रतिस्पर्धा के मामले में दुनिया में 18वें स्थान एवं प्रतिस्पर्धी हवाई परिवहन में 26वें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के दर्शनीय प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन विदेशी यात्रियों को यहां आकर्षित करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक पर्यटन गतिविधियां महामारी से पहले के स्तर पर लौट आई हैं।

सूचकांक में अमेरिका पहले, स्पेन दूसरे, जापान तीसरे, फ्रांस चौथे और ऑस्ट्रेलिया पांचवें स्थान पर है। वहीं, जर्मनी छठे, यूनाइटेड किंगडम सातवें, चीन आठवें और इटली नौवें स्थान पर काबिज हैं। स्विट्जरलैंड 10वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने कहा, ये तथ्य इस बात को रेखांकित करते हैं कि उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में यात्रा और पर्यटन विकास के अधिक अनुकूल हालात बने हैं। इसे अनुकूल कारोबारी माहौल, गतिशील श्रम बाजार, खुली यात्रा नीतियों, मजबूत परिवहन व पर्यटन बुनियादी ढांचे और अच्छी तरह से विकसित प्राकृतिक, सांस्कृतिक स्थानों से मदद मिली है।

वैश्विक यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक-2024 में देशों की लिस्टिंग के लिए उन कारकों और नीतियों को ध्यान में रखा गया है जो यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देते हैं, जो परिणामस्वरूप में देश के विकास में योगदान देते है। वर्ष 2024 के लिए इस इंडेक्स में 119 देशों को शामिल किया गया है और बताया गया है शीर्ष 10 देश दुनियाभर से सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं।

भारत में पर्यटन स्थलों का विकासः

- पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन' (प्रसाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के अंतर्गत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/केंद्र-शासित प्रदेशों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कुल 5294.11 करोड़ रुपये की 76 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रसाद योजना के अंतर्गत 1629.17 करोड़ रुपये की कुल 46 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के अंतर्गत 2014-15 से 2023-24 (अब तक) की अवधि के दौरान 780.92 करोड़ रुपये की कुल 54 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है।
- पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए सतत और जिम्मेदारीपूर्ण गंतव्य-स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी

2.0) के रूप में नया रूप प्रदान किया है। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के परामर्श से स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत विकास के लिए अब तक 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 55 गंतव्य-स्थलों की पहचान की गई है।

- पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मौसम संबंधी बाधाओं को दूर करने और देश को 365 दिनों के पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट पर्यटन उत्पादों की पहचान की है: क्रूज, एडवेंचर, चिकित्सा और कल्याण, गोल्फ, पोलो, बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां (एमआईसीई), इको-टूरिज्म, फिल्म पर्यटन, चिरस्थायी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन आदि।
- विशिष्ट पर्यटन उत्पादों की पहचान एवं संवर्धन के माध्यम से विशेष रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने और उन अद्वितीय उत्पादों के लिए बार -बार यात्रा सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है, जिनमें भारत को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ज्यादा लाभ प्राप्त होता है।
- पर्यटन मंत्रालय ने सतत पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है, जिससे भारत को सतत एवं जिम्मेदार पर्यटन के लिए एक पसंदीदा वैश्विक गंतव्य-स्थल के रूप में स्थापित किया जा सके। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने ट्रैवल फॉर लाइफ अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पर्यटन संसाधनों की खपत में पर्यटकों और पर्यटन व्यवसायों के प्रति सहयोगात्मक रवैये के माध्यम से सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- पर्यटन मंत्रालय वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न भारतीय उत्पादों और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सृजन बाजारों में भारत को एक समग्र गंतव्य-स्थल के रूप में बढ़ावा देता है।
- उपर्युक्त उद्देश्यों को एक एकीकृत विपणन और संवर्धनात्मक कार्यनीति एवं यात्रा व्यापार, राज्य सरकारों और भारतीय मिशनों के सहयोग से एक समन्वित अभियान द्वारा पूरा किया जाता है। सरकार देश के विभिन्न पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विशेषज्ञों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ उनके सुझाव और प्रतिक्रिया लेने के लिए लगातार बातचीत कर रही है। पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने 'अतुल्य भारत! विजिट इंडिया ईयर 2023' घोषित किया है।
- पर्यटन मंत्रालय के अनुरोध पर विदेश मंत्रालय ने इन महत्वपूर्ण बाजारों में भारत को पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए विदेशों में स्थित 20 भारतीय मिशनों में पर्यटन अधिकारियों को मनोनीत किया है।

पर्यटन से जुड़ी चुनौतियां:

- पर्यावरण संबंधी गिरावट, अत्यंत भीड़-भाड, स्थानीय लोगों की बेदखली, सामाजिक रूप से अस्वीकृत गतिविधियां, स्थानीय लोगों की दुश्मनी, विदेशी नियंत्रण और स्थानीय संसाधनों का प्रयोग जैसे कारक पर्यटन को प्रभावित करते हैं। कई इलाकों में बेहतर कानून व्यवस्था का अभाव भी पर्यटन को प्रभावित करता है। विदेशी महिला पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार की भी घटनाएं सामने आती रही हैं। पर्यटक स्थलों पर कूड़ा, कचरा, अपशिष्ट प्रबंधन भी कई बार एक चुनौती के रूप में देखा गया है। खासकर माउंटेन टूरिज्म के दौरान ये समस्या भारत में देखी गई है।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** हवाई अड्डों, राजमार्गों और सार्वजनिक परिवहन के रूप में भारत का बुनियादी ढाँचा अपर्याप्त और कमजोर रहा है।कई पर्यटन स्थलों पर साफ पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है।
- इसके अतिरिक्त अच्छी तरह से लगाए गए साइनबोर्ड और पर्यटक सूचना केंद्रों जैसे पर्यटक-अनुकूल बुनियादी ढाँचे के अभाव से पर्यटकों को घूमने और भारत के पर्यटन स्थलों का पता लगाने में चुनौती का सामना करना पड़ता है।
- भारत में पर्यटन क्षेत्र के समक्ष एक और बड़ी चुनौती, कुशल जनशक्ति का अभाव होना है। इस उद्योग में टूर गाइडिंग, आतिथ्य और यात्रा प्रबंधन सहित विभिन्न आयामों में कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होती है।
- इस क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों की भारी कमी होने से पर्यटकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। भारत के पर्यटन उद्योग में अपार संभावनाएँ हैं लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं जो इसके विकास में बाधक हैं। इस उद्योग से संबंधित चुनौतियाँ बहुआयामी हैं और उन्हें दूर करने के लिये व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

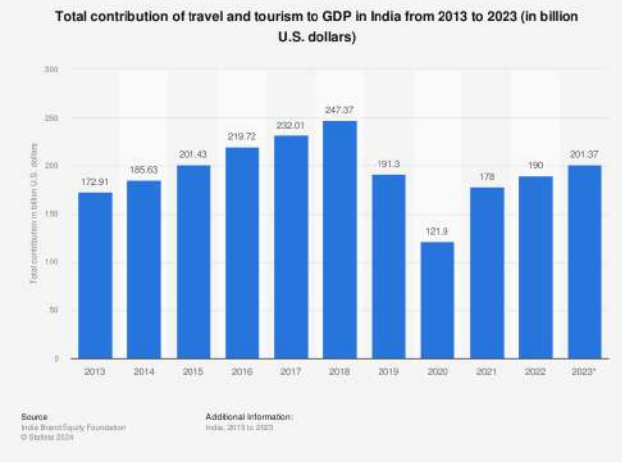

भारत में ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम:

- 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र के लिए 'ट्रैवल फॉर लाइफ' कार्यक्रम का वैश्विक शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य स्थायी पर्यटन के बारे में जागरूकता पैदा करना और पर्यटकों और पर्यटन व्यवसायों को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने वाले स्थायी अभ्यासों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता को मुख्यधारा में

लाना है, ताकि एक स्थायी, जिम्मेदार और लचीला पर्यटन क्षेत्र विकसित किया जा सके। यह पर्यावरण के संसाधनों को संरक्षित करने के लिए बिना सोचे-समझे और विनाशकारी उपभोग के बजाय संसाधनों के विचारशील और जानबूझकर उपयोग की विशेषता वाली 'उपयोग-और-निपटान' अर्थव्यवस्था से एक परिपत्र अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) में परिवर्तन का आह्वान करता है।

भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासः

- पर्यटन मंत्रालय ने देश में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी में पर्यटन स्थलों के एकीकृत विकास के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करने के मिशन के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में अपनी स्वदेश दर्शन योजना को नया रूप दिया है। यह योजना विभिन्न परियोजनाओं और पहलों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को लागू करेगी और पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता सहित टिकाऊ पर्यटन के सिद्धांतों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगी। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत एक उप-योजना 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। एसडी 1.0 के तहत, मंत्रालय ने 76 परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 5294.11 करोड़ रूपये मंजूर किए हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं, अमृत धरोहर का कार्यान्वयन, रामसर स्थलों पर प्राकृतिक पर्यटन को मजबूत करना, स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत मंत्रालय स्थानीय पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण दे रहा है।
- इसका उद्देश्य प्राकृतिक पर्यटन को मजबूत करने के लिए सुविधादाताओं/गाइडों/अन्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना है। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स हैं, जिन्हें वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड्स के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया गया है, जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्थानीय स्तर पर मानव संसाधनों के कौशल, अपस्किलिंग, ज्ञान प्रबंधन से संबंधित हस्तक्षेप पर पर्यटन मंत्रालय से समर्थन मांगा है।

आर्थिक संक्षिप्त मुद्दे

एसएफबी के लिए आरबीआई के दिशानिर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लघु वित्त बैंकों (SFB) को सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये है।

महत्त्वपूर्ण बिंदुः

- **स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग:** यूनिवर्सल बैंक बनने की इच्छुक एसएफबी को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए।
- **न्यूनतम नेट वर्थ:** छोटे वित्त बैंकों की न्यूनतम नेट वर्थ 1,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
- **सीआरएआर आवश्यकताएँ:** एसएफबी को 15% की निर्धारित पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
- **ट्रैक रिकॉर्ड:** छोटे वित्त बैंकों के पास कम से कम पांच वर्षों के प्रदर्शन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।
- **शेयरहोल्डिंग पैटर्न:** हालांकि किसी पहचाने गए प्रमोटर के लिए कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, मौजूदा प्रमोटरों को परिवर्तन के दौरान प्रमोटर के रूप में बने रहना चाहिए। परिवर्तन के दौरान प्रवर्तकों को जोड़ने या बदलने की अनुमति नहीं है।
- **प्रमोटर आवश्यकतायें:** आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार पात्र एसएफबी को अनिवार्य रूप से पहचान के प्रमोटर की आवश्यकता नहीं है।
- **उचित तर्क:** एसएफबी को एक सार्वभौमिक बैंक में परिवर्तन के लिए एक विस्तृत तर्क प्रदान करना होगा।

लघु वित्त बैंकों के बारे में:

- केंद्रीय बजट 2014-15 में लघु वित्त बैंकों की घोषणा की गई थी, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लाइसेंस प्राप्त और शासित हैं और संचालन के स्थान पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- ये बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं।
- उन्हें 200 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश (कुछ एसएफबी के लिए अपवाद) और अपने एएनबीसी (समायोजित नेट बैंक क्रेडिट) का 75% प्राथमिकता क्षेत्र में विस्तारित करना आवश्यक है।

यूनिवर्सल बैंकः

- यूनिवर्सल बैंक ऐसे बैंक हैं जो वाणिज्यिक बैंकिंग और निवेश

बैंकिंग से अलग वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे छोटे वित्त बैंक (एसएफबी) बढ़ते हैं, कुछ यूनिवर्सल बैंक बनने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे एसएफबी के रूप में बने रहना चुन सकते हैं क्योंकि वे पहले से ही अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं। एक यूनिवर्सल बैंक बनने का मतलब यह नहीं है कि वे स्वचालित रूप से अधिक जमा आकर्षित करेंगे या बेहतर उधारकर्ताओं को उधार देने में सक्षम होंगे। एसएफबी संभवत: तभी यूनिवर्सल बैंक बनने के बारे में सोचेंगे जब वे ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला को सेवा देने के लिए पर्याप्त विकसित हो जाएंगे।

सहभागी नोट (P-Notes)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने कहा है कि भारत के बाजार नियामक के साथ पंजीकृत विदेशी निधि दाता और GIFT सिटी में स्थापित इकाइयां भी सहभागी नोट जारी कर सकते हैं।

पी-नोट्स क्या हैं?

- पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो खुद को सीधे पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं।
- पी-नोट्स में वृद्धि आम तौर पर एफपीआई प्रवाह की प्रवृत्ति के अनुरूप होती है। यह भारतीय प्रतिभूतियों जैसे शेयर, सरकारी बॉण्ड, कॉरपोरेट बॉण्ड आदि में निवेश करने के लिए जारी किए जाते हैं।
- पी- नोट्स धारकों को पंजीकरण आवश्यकताओं के लिए भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (SEBI) की उचित त्वरित प्रक्रिया से गुजरना होता है।
- अपनी अपारदर्शी प्रकृति के कारण, पी-नोट्स को लंबे समय से भारत से कड़ी जांच और सख्त अनुपालन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इन संरचनाओं को विदेशी अधिकार क्षेत्र से जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

भारत में पी-नोट्स निवेश की वर्तमान स्थिति:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर, फरवरी के अंत तक भारतीय बाजारों में पी-नोट निवेश का मूल्य 1,49,517 करोड़ रुपये था, जो जनवरी के अंत में 1,43,011 करोड़ रुपये था।
- इस मार्ग से निवेश किए गए कुल 1.5 लाख करोड़ रुपये में से 1.27 लाख करोड़ रुपये इक्विटी में, 21,303 करोड़ रुपये ऋण में और 541 करोड़ रुपये हाइब्रिड सिक्योरिटीज में निवेश किए गए।
- पी-नोट के निवेश में वृद्धि के साथ-साथ, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की संपत्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो पिछले महीने के 66.96 लाख करोड़ रुपये से फरवरी के अंत तक बढ़कर 68.55 लाख करोड़ रुपये हो गई।

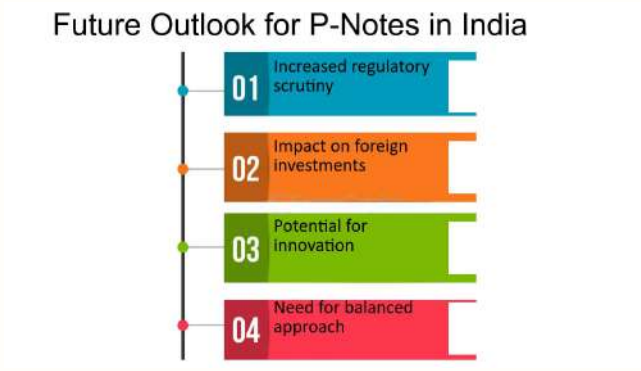

योगदान देने वाले कारक:

- पी-नोट निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले आकर्षक निवेश अवसरों और देश के मजबूत नियामक ढांचे सहित विभिन्न कारकों को दिया जा सकता है।
- इसके अलावा, भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों का बढ़ता विश्वास इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। चूंकि भारत के पूंजी बाजार वैश्विक रुचि को आकर्षित करना जारी रखते हैं, इसलिए पी-नोट निवेश में वृद्धि देश की आर्थिक ताकत और आशाजनक विकास क्षमता को रेखांकित करती है। यह एक आकर्षक निवेश केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करता है।

निष्कर्ष:

पिछले दशक में, भारत में विनियामक कार्रवाई के कारण पी-नोट्स बाजार का बड़ा हिस्सा विदेश चला गया है। पी-नोट्स ग्राहकों के लिए कर एक बड़ा जोखिम है क्योंकि कर विभाग ने अतीत में लाभार्थियों को संधि लाभ देने से मना कर दिया है। दोहरे कर बचाव समझौतों (डीटीएए) के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए, गैर-निवासी को कर विभाग द्वारा निर्धारित कई मानदंडों को पूरा करना होगा। विदित हैं,ऐसे उपकरण किसी देश के लिए विदेशी निवेशकों के व्यापक पूल को आकर्षित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

विश्व की सेवा फैक्टरी बनता भारत

चर्चा में क्यों?

वैश्विक निवेश बैंक, गोल्डमैन साच्स ने 'दुनिया की उभरती सेवा फैक्ट्री के रूप में भारत का उदय' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट वैश्विक सेवाएं प्रदान करने में भारत की हालिया सफलता पर प्रकाश डालती है और मध्यम अवधि में इसकी विकास संभावनाओं और जोखिमों का अवलोकन करती है।

रिपोर्ट द्वारा बताई गई मुख्य बातें:

- **सेवा निर्यात वृद्धि:** भारत के सेवा निर्यात में पिछले 18 वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जहाँ पेशेवर परामर्श सबसे तेजी से बढ़ रहा है, वही यात्रा सेवाएं सबसे धीमी गति से बढ़ रही हैं।
- **वैश्विक तुलना:** वैश्विक सेवाओं का निर्यात 18 वर्षों में तीन गुना हो गया है। 2005 के बाद से भारत की निर्यात वृद्धि वैश्विक स्तर पर सिंगापुर और आयरलैंड के बाद तीसरी सबसे तेज रही है।
- **वैश्विक सेवाओं में हिस्सेदारी:** वैश्विक सेवाओं के बहिर्प्रवाह में भारत की हिस्सेदारी 2005 में 2% से बढ़कर 2023 में 4.6% हो गई है, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। इसकी तुलना में, इसी अवधि के दौरान माल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 1.8% हो गई।
- **बाहरी संतुलन पर प्रभाव:** सेवा व्यापार में वृद्धि ने महंगे तेल आयात जैसे वित्तीय झटकों के प्रभाव को सीमित कर भारत के बाहरी खाते के संतुलन को कम करने में मदद की है। गोल्डमैन साच्स को उम्मीद है कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी, 2030 तक सेवा निर्यात बढ़कर 800 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है।
- **सरकारी लक्ष्य बनाम प्रक्षेपण:** 2030 तक 800 बिलियन डॉलर का अनुमानित सेवा निर्यात, सेवाओं और व्यापारिक निर्यात दोनों के लिए सरकार के 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य से थोड़ा कम है। रिपोर्ट बताती है कि उच्च-मूल्य सेवाओं में वृद्धि से रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ सकती है।

अन्य अवलोकन:

- **तत्काल दृष्टिकोण:** अल्पावधि में भारत के सेवा निर्यात की स्थिति अनिश्चित है। आईटी सेवाओं में शीर्ष कंपनियां एवं देश का प्रमुख निर्यात केंद्रों ने पिछले वर्ष में अपने कार्यबल में कमी की है।
- **चिंताएँ और बाधाएँ:** विश्लेषकों ने भारत की सेवा वृद्धि में बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इनमें स्नातकों को नौकरी के लिए तैयार करने की चुनौती और उन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर संकट शामिल है जहां विकास केंद्रित है, जैसे कि बेंगलुरु में जल संकट।
- **बाहरी जोखिम:** भारत के सेवा निर्यात में बाहरी जोखिम हैं, जिनमें गंतव्य देशों में संरक्षणवाद में वृद्धि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, घरेलू नीतिगत हस्तक्षेप जो निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे आईटी हार्डवेयर आयात को प्रबंधित करने के प्रयास चिंता का विषय हैं।

निष्कर्ष:

भारत को सेवाओं में अपनी सफलता बरकरार रखने के लिए सावधानीपूर्वक अपनी रणनीति बनाने की जरूरत है। इसमें वैश्विक बाजार पहुंच और पेशेवर सेवाओं में अवसरों के लिए एक उचित प्रोत्साहन नीति शामिल होना चाहिए। इसमें एक नियामक दृष्टिकोण भी शामिल होना चाहिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विनिर्माण-लिंक्ड सेवाओं और ब्लॉक श्रृंखला अनुप्रयोगों जैसे क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करने में सक्षम हो।

चीन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में चीन के साथ भारत का व्यापार 100 बिलियन डॉलर को पार कर गया, जिससे दो वर्षों के बाद चीन, अमेरिका को पीछे कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया।

भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार:

- भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में भारत और चीन के बीच वस्तु व्यापार 118.41 बिलियन डॉलर रहा।
- चीन का भारत से निर्यात मामूली रूप से 0.6% घटकर 16.75 बिलियन डॉलर से 16.66 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि चीन से आयात 44.7% बढ़कर 70.32 बिलियन डॉलर से 101.75 बिलियन डॉलर हो गया।
- आयात में इस वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ा है, जो वित्त वर्ष 2019 में 53.57 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 85.09 बिलियन डॉलर हो गया है।
- फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, साथ ही चीन से लोहा और इस्पात के आयात में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, मोबाइल पार्ट्स, लैपटॉप और लिथियम बैटरी के आयात में वृद्धि हुई है।

भारत की व्यापार गतिशीलता:

- ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार, वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 तक अपने शीर्ष 15 व्यापारिक साझेदारों के साथ भारत की व्यापार गतिशीलता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसने आयात और निर्यात दोनों को प्रभावित किया है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार अधिशेष या घाटे की स्थिति को भी प्रभावित किया है।
- वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चीन 2013-14 से 2017-18 तक और 2020-21 में भी भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था। चीन से पहले, संयुक्त अरब अमीरात देश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। 2021-22 और 2022-23 में अमेरिका सबसे बड़ा साझेदार था।
- 2023-24 में, 83.6 बिलियन डॉलर के साथ यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। इसके बाद रूस ($65.7 बिलियन), सऊदी अरब ($43.4 बिलियन) और सिंगापुर ($35.6 बिलियन) का स्थान था।

निर्भरता के रणनीतिक निहितार्थ:

- अध्ययन में कहा गया है कि इस निर्भरता के रणनीतिक निहितार्थ श्गहरेश् हैं और यह न केवल आर्थिक बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा आयामों को भी प्रभावित करते हैं।

- इसमें कहा गया है, ष्यह न केवल आर्थिक जोखिमों को कम करने के लिए बल्कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और एकल-देश के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए भी जरूरी है, खासकर चीन जैसे भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धी से।"

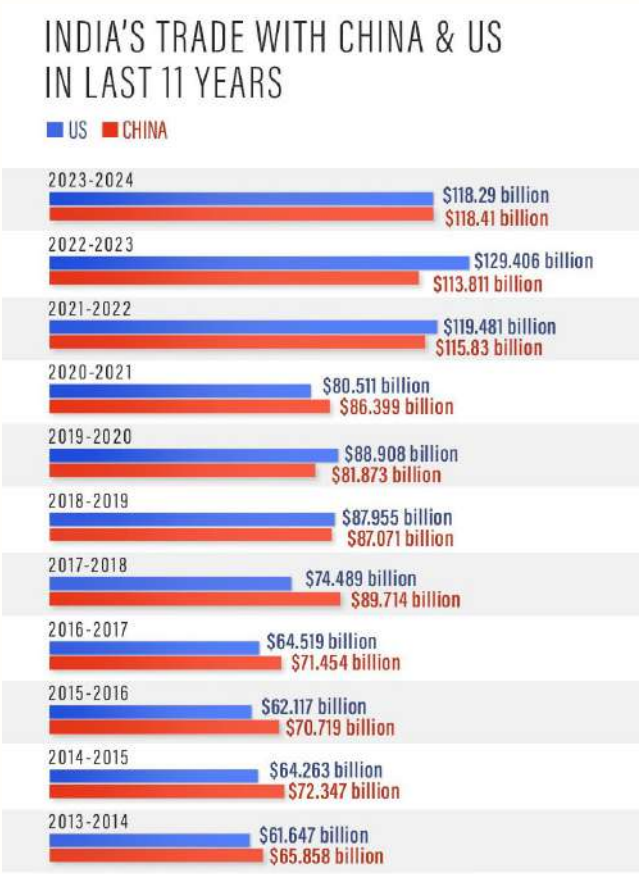

आगे की राहः

चीन से भारत का बढ़ता आयात चिंता का विषय है, जो प्रमुख वस्तुओं के लिए निरंतर निर्भरता को दर्शाता है। भारत, चीनी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पीएलआई योजनाएं, डंपिंग रोधी शुल्क और गुणवत्ता नियंत्रण, बहिष्कार एवं लेबलिंग आदेश लागू कर रहा है। जिससे व्यापार घाटे को संतुलित किया जा सके।

भारतीय ई-कॉमर्स बाजार

चर्चा में क्यों?

इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार, भारतीय ई-कॉमर्स बाजार का आकार 2030 तक 325 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। इस बढ़ोतरी से भारत 2030 तक, वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन खुदरा उद्योग में तीसरे स्थान पर पहुंचने की उम्मीद है।

भारतीय ई-कॉमर्स बाजार की स्थितिः

- वर्तमान में भारत में ई-कॉमर्स बाजार का मूल्य 70 बिलियन डॉलर है, जो देश के समग्र खुदरा बाजार का लगभग 7% है।
- इंटरनेट की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, 2022 में भारतीय आबादी का 52%, यानी लगभग 759 मिलियन लोग, इंटरनेट का उपयोग करेंगे।
- वर्ष 2025 तक लगभग 87% भारतीय घरों में इंटरनेट कनेक्शन होने की उम्मीद है। हालांकि, मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस की अवधि में 2019 की तुलना में 21% की वृद्धि देखी गई है।
- भारत में ऑनलाइन खरीदारों की संख्या 2019 और 2026 के बीच ग्रामीण भारत में 22% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर 88 मिलियन और शहरी भारत में 15% बढ़कर 263 मिलियन होने का अनुमान है।

सरकारी पहलें:

- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने खुदरा विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) का उपयोग करने की योजना बना रहा है।
- भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 2011 बिलियन अमरीकी डॉलर का अपना अब तक का सर्वोच्च सकल व्यापारिक मूल्य हासिल किया।
- राष्ट्रीय खुदरा नीति, जो कारोबार करने में आसानी, लाइसेंस प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने, खुदरा क्षेत्र का डिजिटलीकरण और सुधारों पर ध्यान केंद्रित करती है।
- सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए उमंग, स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल, भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) आदि जैसी कई पहल शुरू की हैं।
- भारत सरकार ने ई-कॉमर्स में विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया है।
- 5जी सेवाओं का विकास एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान भी चलाया है।

आगे की राहः

इन्वेस्ट इंडिया की रिपोर्ट 2030 तक भारत को वैश्विक ई-कॉमर्स का पावरहाउस में बनने का एक आकर्षक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसके लिए अत्याधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए नियामक संस्थाओं का विकास, सरल भुगतान प्रणाली के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे।

सेबी में फ्रंट-रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंडों में फ्रंट-रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ये निर्णय सेबी द्वारा एलआईसी में फ्रंट-रनिंग के मामलों का खुलासा किए जाने के बाद लिए गए हैं।

हालिया घटनाक्रम:

- एक्सिस एएमसी मामले में, ब्रोकर-डीलरों, कुछ कर्मचारियों और संबंधित संस्थाओं को एएमसी के कारोबार को आगे बढ़ाने में शामिल पाया गया था।
- एलआईसी के मामले में, एक सूचीबद्ध बीमा कंपनी के कर्मचारी को कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाने में शामिल पाया गया था।

इनसाइडर ट्रेडिंग व फ्रंट रनिंग क्या है?

- **इनसाइडर ट्रेडिंग:** जब कंपनी का कोई एग्जिक्यूटिव या उसके मैनेजमेंट से जुड़ा कोई आदमी उसकी (कंपनी की) अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयर खरीद या बेचकर गलत ढंग से मुनाफा कमाता है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। इसे भेदिया कारोबार भी कहा जाता है।
- **फ्रंट-रनिंग:** जब कोई व्यक्ति आगामी ट्रेडों के बारे में विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी का उपयोग करके ग्राहकों के सामने व्यक्तिगत ट्रेड करता है और अनुचित लाभ कमाता है।

सेबी द्वारा सुधार हेतु मजबूत संस्थागत तंत्र को लागू करना:

- **उन्नत निगरानी तंत्र:** संदिग्ध पैटर्न के लिए ट्रेडिंग गतिविधि की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण का उपयोग करना।
- **आंतरिक नियंत्रण तंत्र:** कर्मचारियों, डीलरों और संबंधित संस्थाओं को कदाचार में लिप्त होने से रोकने के लिए सख्त आंतरिक प्रक्रियाएं विकसित करना।
- **उन्नयन प्रक्रियाएं तंत्र:** संदिग्ध उल्लंघनों की रिपोर्टिंग और जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करना।
- **बढ़ी हुई जवाबदेही:** सेबी संस्थागत तंत्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए एएमसी प्रबंधन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- **व्हिसलब्लोअर तंत्र:** सेबी के अनुसार एएमसी को एक ऐसी प्रणाली लागू करनी होगी, जिससे कर्मचारी कंपनी के भीतर संदिग्ध कदाचार की गुमनाम रूप से रिपोर्ट कर सकें।

सेबी द्वारा नियमो में संशोधन:

- बोर्ड ने मौजूदा नियामक ढांचे को बढ़ाने के लिए सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
- सेबी ने निष्क्रिय योजनाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों में संशोधन किया है।

आगे की राह:

वर्तमान में, म्यूचुअल फंड अपनी परिसंपत्तियों का 25% से अधिक हिस्सा फंड मैनेजर के समान समूह से संबंधित कंपनियों में निवेश नहीं कर सकते हैं। सेबी ने अब निष्क्रिय फंडों में निवेश करने की अनुमति दी है, जिसकी कुल सीमा 35% है। यह सूचकांक की अधिक सटीक व्यवस्था बनाने की अनुमति देता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश प्रमुख चालक: आईएमएफ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए के लिए आर्थिक परिदृश्य जारी किया है, जिसमे कहा गया की भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक निवेश एक महत्वपूर्ण कारक है।

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र की कई अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा की कम कीमतों के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में और कमी देखी जा सकती है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया।
- वैश्विक संघर्ष से व्यापार जोखिम बढ़ता है, जिसे समस्त हित धारकों के लाभ प्रभावित होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया हैं कि नीति निर्माताओं को व्यापार संबंधी विवादों को कम करना चाहिए।
- दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की विकास दर 2023 में 5.2 प्रतिशत से घटकर इस साल 2024 में 4.6 प्रतिशत और 2025 में 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- सार्वजनिक निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक हैं।
- एशियाई केंद्रीय बैंकों को घरेलू मूल्य स्थिरता पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा प्रत्याशित ब्याज दर पर नीतिगत निर्णयों को अत्यधिक निर्भर करने से बचना चाहिए।

अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश:

- सार्वजनिक निवेश केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक कल्याण के लिए किया गया निवेश है। करों से प्राप्त राजस्व द्वारा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश किया जाता है।
- भारत में सार्वजनिक निवेश मुख्यत: कृषि, बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में किया जाता है।
- सार्वजनिक निवेश में किसी राष्ट्र के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की क्षमता होती है और इस प्रकार अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित होता है।
- बेरोजगारी कम करने और नई नौकरियाँ पैदा करने में सार्वजनिक निवेश की अहम भूमिका होती है।
- औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश से भारत की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और इस प्रकार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक निवेश बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में निवेश से गरीबी कम करने, कृषि-व्यवसाय को बढ़ावा देने और देश की वार्षिक कृषि उपज बढ़ाने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष:

IMF द्वारा जारी यह रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश की भूमिका पर बल देती है। समय की मांग है कि भारत के नीति निर्माता निवेश का विविधीकरण कर नये रोजगार, बुनियादी संरचना एवं मानव पूंजी का विकास कर अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करें।

आर्थिक मूल्य पृथ्वी अवलोकन (ईओ) डेटा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पृथ्वी अवलोकन (ईओ) डेटा में 2030 तक वैश्विक स्तर पर $3 ट्रिलियन से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता है। रिपोर्ट पृथ्वी अवलोकन डेटा के दोहरे आर्थिक और पर्यावरणीय मूल्य पर प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- **छह प्रमुख क्षेत्र:** रिपोर्ट छह प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करती है जो पृथ्वी अवलोकन डाटा के अनुमानित आर्थिक मूल्य का 94% प्राप्त करने के लिए प्रमुख हैं, जिनमें शामिल हैं:
- कृषि
- तेल और गैस
- सरकार
- बिजली
- आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन
- बीमा और वित्तीय सेवाएँ
- **आर्थिक क्षमता:** 2023 और 2030 के बीच वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में संचयी $3.8 ट्रिलियन योगदान के साथ, ईओ डेटा का वैश्विक मूल्य छह वर्षों में $266 बिलियन से बढ़कर $700 बिलियन से अधिक हो सकता है।
- **पर्यावरणीय लाभ:** पृथ्वी अवलोकन(ईओ) डेटा में हर साल 2 गीगाटन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को खत्म करने की क्षमता है, जो 476 मिलियन गैसोलीन-संचालित कारों के अनुमानित संयुक्त वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है।
- **क्षेत्रीय विकास:** एशिया प्रशांत क्षेत्र 2030 तक पृथ्वी अवलोकन (ईओ) के मूल्य का सबसे बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए तैयार है, जो 315 अरब डॉलर के संभावित मूल्य तक पहुंच जाएगा, जबकि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सबसे बड़े प्रतिशत विकास के लिए तैयार हैं।
- **सुशासन को बढ़ावा:** रिपोर्ट बताती है कि पृथ्वी अवलोकन (ईओ) डेटा को अपनाने से नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है, दक्षता बढ़ सकती है और जोखिमों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है।

पृथ्वी अवलोकन डेटा का आर्थिक मूल्य इसकी क्षमता से संचालित होता है:

- **निर्णय लेने में सुधार:** पृथ्वी अवलोकन डेटा सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करता है, जिससे विभिन्न उद्योगों में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।
- **दक्षता बढ़ाना:** पृथ्वी अवलोकन डेटा संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने, लागत कम करने और उत्पादकता में सुधार करने में मदद करता है।
- **स्थिरता बढ़ाना:** यह डेटा पर्यावरण निगरानी, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है।
- **नवाचार का समर्थन:** ईओ डेटा नए उत्पादों और सेवाओं के विकास, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के बारे में:

- WEF एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए व्यापार, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य हित धारक को शामिल करके स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- 1971 में एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन के रूप में स्थापित, और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह फोरम किसी भी राजनीतिक, पक्षपातपूर्ण या राष्ट्रीय हितों से जुड़ा नहीं है।

प्रमुख रिपोर्टें:

WEF विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिनमें शामिल हैं:

- **वैश्विक जोखिम रिपोर्ट:** अगले दशक में आने वाले गंभीर जोखिमों की पड़ताल करती है।
- **यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक (टीटीडीआई):** एक प्रमुख सूचकांक जो 2007 से उत्पादन में है।
- **रोजगार का भविष्य रिपोर्ट:** यह बताती है कि अगले पांच वर्षों में नौकरियां और कौशल कैसे विकसित होंगे।

निष्कर्ष:

पृथ्वी अवलोकन डेटा की बढ़ती मांग, उपग्रह प्रौद्योगिकी में प्रगति, डेटा तक बढ़ती पहुंच और सतत विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन की आवश्यकता से प्रेरित है।

एफ एंड ओ व्यापार का सैशेटाइजेशन

चर्चा में क्यों?

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने घरेलू बचत की सुरक्षा के लिए एफ एंड ओ (Future and Option) व्यापार के सैशेटाइजेशन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि एफ एंड ओ में व्यापार के लिए आवश्यक वित्तीय साक्षरता स्टॉक के व्यापार से

अलग है।

एफ एंड ओ व्यापार के सैशेटाइजेशन के पीछे कारण:

- **घरेलू बचत जोखिम:** बहुत से नये निवेशक एफ एंड ओ व्यापार को नहीं समझते हैं और एफ एंड ओ में बिना जानकारी के व्यापार घरेलू बचत के लिए जोखिम पैदा करता है, जिससे उत्पादक निवेश पर प्रभाव पड़ता है।
- **घरेलू बचत में गिरावट:** वित्त वर्ष 2023 में शुद्ध वित्तीय घरेलू बचत पांच साल के निचले स्तर पर आ गई, तीन साल में 9 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई।
- **निवेश में बदलाव:** 2020-21 से 2022-23 तक म्यूचुअल फंड निवेश में तीन गुना वृद्धि और शेयरों और डिबेंचर में घरेलू निवेश दोगुना होने के बावजूद, इन निवेशों की स्थिरता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

एफ एंड ओ के सैशेटाइजेशन के बारे में:

- एफ एंड ओ (वायदा और विकल्प) व्यापार का सचेतीकरण जटिल वित्तीय उत्पादों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय पैकेटों में तोड़ने की प्रथा को संदर्भित करता है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत निवेशकों के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाया जा सके। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य एफ एंड ओ बाजार में भागीदारी बढ़ाना है, खासकर खुदरा निवेशकों के बीच।
- एफ एंड ओ व्यापार के संदर्भ में, सैशेटाइजेशन में आम तौर पर शामिल होते हैं:
  - **छोटे अनुबंध आकार:** व्यक्तिगत निवेशकों के लिए इसे अधिक किफायती बनाने के लिए एफ एंड ओ का न्यूनतम अनुबंध करना शामिल होता है।
  - **कम मार्जिन आवश्यकताएं:** एफ एंड ओ अनुबंधों का व्यापार करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक मार्जिन को कम करना, जिससे व्यक्तियों के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान हो सके।
  - **सरलीकृत उत्पाद:** जटिलता को कम करने और खुदरा निवेशकों के लिए उन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए साप्ताहिक या मासिक समाप्ति जैसे सरल एफ एंड ओ उत्पादों की पेशकश करना।

सैशेटाइजेशन के बारे में चिंताएँ:

- **अत्यधिक जोखिम:** छोटे अनुबंध आकार और कम मार्जिन आवश्यकताओं के साथ व्यापार में आसानी के कारण निवेशक अत्यधिक जोखिम उठा सकते हैं।
- **वित्तीय साक्षरता का अभाव:** खुदरा निवेशक एफएंडओ ट्रेडिंग से जुड़ी जटिलताओं और जोखिमों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, जिससे संभावित रूप से महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है।
- **बाजार में अस्थिरता:** खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी बाजार में अस्थिरता में योगदान कर सकती है, जो संभावित रूप से समग्र बाजार स्थिरता को प्रभावित कर सकती है।

निष्कर्ष:

निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए मजबूत अनुपालन और नियामक मानकों की आवश्यकता है। साथ ही, एफएंडओ में व्यापार के लिए वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है, और निवेशकों को इसमें शामिल जोखिमों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है।

भारत में धन प्रेषण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि भारत वार्षिक धन प्रेषण में $100 बिलियन को पार करने वाला पहला देश है, जिसमें 2022 में कुल $111 बिलियन प्राप्त हुए।

मुख्य पहलू:

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी:** भारत सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का मूल स्थान है, जिसमें लगभग 18 मिलियन भारतीय देश से बाहर रहते हैं, और पुरुषों की तुलना में महिला प्रवासियों की हिस्सेदारी थोड़ी अधिक है।
- **जीसीसी गंतव्य:** खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देश, विशेष रूप से यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब, निर्माण, आतिथ्य, सुरक्षा, घरेलू काम और खुदरा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत भारत के प्रवासी श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य बने हुए हैं।
- **धन प्रेषण रुझान:** भारत 2010 ($53.48 बिलियन), 2015 ($68.91 बिलियन) और 2020 ($83.15 बिलियन) में धन प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष देश था, और यह 2022 में +111.22 बिलियन तक पहुँच गया।
- **वैश्विक रैंकिंग:** मेक्सिको ने 2022 में चीन को पीछे छोड़ते हुए धन प्रेषण के दूसरे सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में अपना स्थान बनाए रखा। जी7 देश फ्रांस और जर्मनी 2022 में वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण प्राप्त करने वाले शीर्ष 10 देशों में बने रहे।
- **दक्षिणी एशिया से धन प्रेषण:** दक्षिण एशिया के तीन देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दुनिया में अंतरराष्ट्रीय धन प्रेषण के शीर्ष दस प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं।

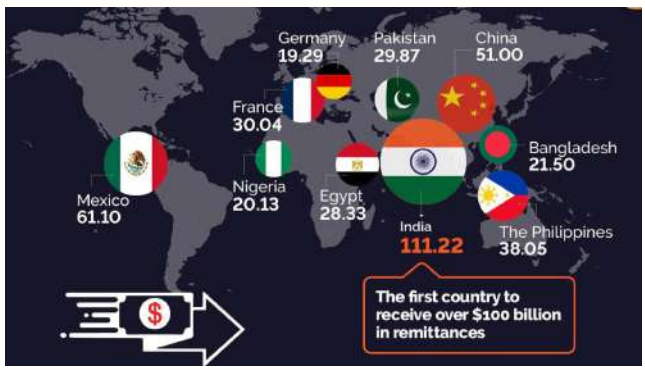

धन प्रेषण क्या है?

- धन प्रेषण व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा एक देश से दूसरे देश में भेजे जाने वाले धन को संदर्भित करता है, अक्सर प्रवासी श्रमिकों या प्रवासियों द्वारा अपने देश में अपने परिवारों, दोस्तों या व्यवसाय के संबंध में धन भेजा जाता है।

प्रेषण के लाभ:

- **विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा देना:** प्रेषण किसी देश की विदेशी मुद्रा आय में योगदान कर सकते हैं, मुद्रा को स्थिर करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं।
- **आर्थिक विकास का समर्थन करना:** प्रेषण का उपयोग विकास परियोजनाओं, जैसे कि बुनियादी ढाँचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को निधि देने के लिए किया जा सकता है, जो किसी देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकते हैं।
- **गरीबी कम करना:** प्रेषण कम आय वाले परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान कर सकते हैं, गरीबी को कम करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
- **उपभोग बढ़ाना:** प्रेषण का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जा सकता है, जो उपभोग को बढ़ावा दे सकता है और आर्थिक विकास का समर्थन कर सकता है।
- **उद्यमिता का समर्थन करना:** प्रेषण का उपयोग उद्यमशील उपक्रमों को निधि देने, नौकरियाँ पैदा करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है।
- **मुद्रा को स्थिर करना:** प्रेषण किसी देश की मुद्रा को स्थिर करने, मुद्रा में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करने में मदद कर सकता है।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य:** प्रेषण का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को निधि देने, मानव विकास का समर्थन करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।
- **बचत:** प्रेषण का उपयोग बचत बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता का समर्थन करने और ऋण पर निर्भरता को कम करने के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

विश्व भर में लाखों लोगों की आजीविका को सहारा देने में धन प्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका है, तथा यह कई देशों के लिए विदेशी मुद्रा आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कुल मिलाकर, धन प्रेषण वैश्विक वित्तीय प्रवाह का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तथा यह कई देशों में आर्थिक विकास और गरीबी में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, शहर में रहने वाले 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर में गिरावट आई है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- भारत में शहरी बेरोजगारी दर पिछले साल की इसी तिमाही में 6.8% से घटकर 2024 की जनवरी-मार्च तिमाही में 6.7% हो गई।
- शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में बेरोजगारी दर एक साल पहले इसी तिमाही में 9.2% से घटकर जनवरी-मार्च 2024 में 8.5% हो गई। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में श्रम बल भागीदारी दर जनवरी-मार्च 2024 में बढ़कर 50.2% हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 48.5% थी।
- 22 में से 12 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बेरोजगारी दर थी। जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 11% थी, उसके बाद केरल में 10.7% और राजस्थान में 9.6% थी। दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी दर 1.8% थी, उसके बाद कर्नाटक में 4.1% थी। बेरोजगारी दर में सुधार का श्रेय श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि को जाता है।
- हालाँकि, नौकरियों की गुणवत्ता को लेकर चिंता बनी हुई है, क्योंकि अवैतनिक रोजगार की हिस्सेदारी बढ़ी है, दिसंबर तिमाही में 6.7% कर्मचारी घरेलू उद्यमों में अवैतनिक सहायक थे। नियमित वेतन या वेतनभोगी रोजगार में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन यह महामारी से पहले के स्तर से कम है।

श्रम बल के बारे में:

श्रम बल, किसी देश या क्षेत्र में कुल लोगों की संख्या को संदर्भित करता है जिसमें शामिल होते है:

- **रोजगार प्राप्तकर्ता:** वेतन के लिए काम कर रहे हैं, या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक।
- **बेरोजगार:** काम करने में सक्षम और इच्छुक, लेकिन वर्तमान में बिना नौकरी के।
- **अल्प-रोजगार प्राप्तकर्ता:** अंशकालिक या कम-कुशल नौकरियों में काम करना।

श्रम बल में शामिल हैं:

- 15-64 वर्ष की आयु के लोग (कामकाजी आयु वर्ग की आबादी)।
- वे लोग जो सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं या वर्तमान में काम कर रहे हैं।
- स्व-रोजगार वाले व्यक्ति, जैसे उद्यमी, फ्रीलांसर या छोटे व्यवसाय के मालिक। पूर्णकालिक, अंशकालिक और अस्थायी कर्मचारियों सहित वेतनभोगी कर्मचारी।

विविध मुद्दे

नक्सलवाद पर भारत सरकार का निर्णायक प्रहार

हाल ही में छत्तीसगढ़ में मतदान से पहले सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की। इस दौरान सुरक्षाबलों ने नारायणपुर–बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के बॉर्डर पर 7 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षाबलों को नंबर 16 और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन सूर्य शक्ति पॉइंट 5 शुरू किया गया था। यह ऑपरेशन करना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियाँ सर्वाधिक है जिसके चलते भारत में नक्सलवाद जीवित है।

इसी साल छत्तीसगढ़ के सुकमा-बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र टेकलगुड़ेम गांव में सीआरपीएफ कैंप पर नक्सलियों ने बड़ा हमला किया था जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। सुकमा के जगरगुण्डा इलाके में नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाने और इलाके के लोगों को सहायता देने के लिए जनवरी माह में सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया था। सिक्योरिटी कैंप के बाद सीआरपीएफ के कोबरा जवान जोनागुड़ा-अलीगुड़ा क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और उसी दौरान जवानों के ऊपर माओवादियों द्वारा फायरिंग की गई थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर एक डेटा जारी किया। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक कम से कम 80 नक्सली मारे गए हैं और 125 से अधिक गिरफ्तार किए गए हैं जबकि 150 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा स्थिति की विस्तृत समीक्षा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया था। उनके निर्देश पर एक हाई पॉवर कमेटी का गठन किया गया था।

भारत सरकार का मानना है कि वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सफाया करना जरूरी हो गया है। हाल ही में, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों और सुरक्षा बल के जवानों की मुठभेड़ हुई थी जिसमें नक्सलियों के टॉप कमांडर सहित 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था। इस समय भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट के तर्ज पर ही नक्सलियों को निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने में इंडियन आर्मी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। अब वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में निर्णायक कार्यवाही शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, ब्लैक पैंथर फोर्स, कोया कमांडोज, बस्तरिया बटालियन सहित अलग अलग श्रेणी के सुरक्षाकर्मी शांति और सुरक्षा के लिए पूरी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं और अब नक्सलियों का ग्रॉसरूट नेटवर्क पूर्ण रूप से तोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है।

भारत में नक्सल और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति:

- केंद्र सरकार के नवीनतम अपडेट के अनुसार 1 अप्रैल, 2024 से भारत के 10 राज्यों के 38 जिले वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले हैं। इनमें भी सर्वाधिक प्रभावित जिलों की सूची में अब 12 जिले शामिल हैं।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वामपंथी चरमपंथ की घटनाएं 2004-14 के दशक में 14,862 से घटकर 2014-23 में 7,128 हो गई हैं।
- वामपंथी उग्रवाद के कारण सुरक्षा बलों की मौतों की संख्या 2004-14 में 1750 से 72 प्रतिशत घटकर 2014-23 के दशक के दौरान 485 हो गई है और उक्त अवधि में नागरिकों की मौत की संख्या 4285 से 68 प्रतिशत घटकर 1383 हो गई है। साल 2010 में हिंसा वाले जिलों की संख्या 96 थी, जो 2022 में 53 प्रतिशत घटकर 45 हो गई।
- इसके साथ ही, हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की

संख्या 2010 में 465 से घटकर 2022 में 176 हो गई। पिछले पांच वर्षों में 90 जिलों में 5,000 से अधिक डाकघर स्थापित किए गए हैं, जहां माओवादियों की उपस्थिति है या जहां अतीत में चरमपंथियों की उपस्थिति थी।

- केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का कहना है कि अब झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश नक्सलियों से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से पूरा मुक्त नहीं हो पाया है और वहां के कुछ हिस्सों में अब भी नक्सली सक्रिय हैं।

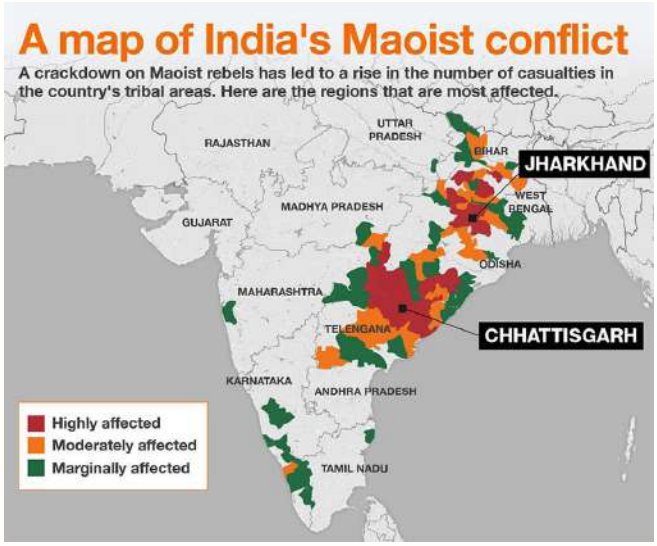

नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा:

- वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर की जाने वाली नक्सली और माओवादी हिंसक गतिविधियां भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक बड़ा खतरा हैं।
- शासन तंत्र, पूंजीपति और उद्योगपतियों को संदेह की नजर से देखने वाले नक्सली और माओवादी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के खिलाफ अपनी समानांतर सरकार चलाने में विश्वास रखते हैं।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों और जिलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, विकास के लाभों का समतामूलक वितरण ना होना, गरीबी और बेरोजगारी आदि के चलते उग्रवाद का प्रसार हुआ है।
- जनजातीय समुदाय में अत्यंत रक्ताल्पता और अन्य बीमारियों से होने वाली मौत, जीविका के साधनों का अभाव, लघु वन उत्पादों के स्वामित्व को छीनने और भूमि स्वामित्व और अधिग्रहण के मामलों के फलस्वरूप उत्पन्न विस्थापन और सामाजिक आर्थिक बहिष्करण आदि आधारों पर वामपंथी उग्रवादी सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न खड़े करते हैं।

समाधान की राहें:

- भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए इन क्षेत्रों में समावेशी विकास की रणनीति अपनाई है। सबसे पहले इन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन पर बल दिया गया है। इन क्षेत्रों में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने वित्तीय समावेशन के लिए 32 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में प्रथम चरण में 1788 ब्रांच पोस्ट ऑफिस (142 महाराष्ट्र में) की स्वीकृति दी है जिसमें से 1484 ब्रांच पोस्ट ऑफिस कार्यशील हो चुके हैं।
- महाराष्ट्र में सभी स्वीकृत ऑफिस भी प्रचालनीय हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने वर्ष 2015 से 2018 के अंत तक 30 सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 604 नई बैंक शाखाओं को और 987 एटीएम स्थापित किए हैं जिससे इन क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं और सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा सके।
- इसके अलावा इन क्षेत्रों में रूपे डेबिट कार्ड का प्रयोग और बैंक मित्रों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की गई है। नाबार्ड ने भी भारत के अनुसूचित बैंकों को ऐसे क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने में मदद करने और सौर शक्ति वाले वीसैट कनेक्टिविटी देने का भी प्रस्ताव किया है।
- सामाजिक समावेशन की बात करें तो इन क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के लिए 2013 में रोशनी नामक स्कीम चलाई गई थी और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 2017 में समाधान नामक रणनीति बनाई है जिसमें कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण, कारगर खुफियातंत्र, कार्ययोजना के मानक, कारगर प्रोद्यौगिकी, प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना और नक्सलियों के वित्तपोषण को विफल करने की रणनीति को शामिल किया गया है।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने का भारत सरकार का दृष्टिकोण:

- भारत सरकार का दृष्टिकोण, सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चत करने, शासन प्रणाली में सुधार तथा जन केन्द्रित प्रबंधन के क्षेत्रों में समग्र तरीके से वामपंथी उग्रवाद से निपटना है।
- इस दशकों पुरानी समस्या से निपटने के लिए, संबंधित राज्य सरकारों के साथ विभिन्न उच्चस्तरीय विचार-विमर्श और बातचीतों के बाद यह उपयुक्त समझा गया है कि तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावी क्षेत्रों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण से ही परिणाम मिलेंगे।
- इसे ध्यान में रखते हुए वामपंथी उग्रवादी हिंसा के संबंध में इसके विस्तार और प्रवृत्तियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है और योजना तैयार करने, विभिन्न उपायों के कार्यान्वायन और उनकी निगरानी के संबंध में विशेष ध्यान देने के लिए ग्यारह राज्यों में 90 सर्वाधिक प्रभावित जिलों को लिया गया है।
- चूंकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई मुख्यत: राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। केन्द्र सरकार स्थिति की गहन रूप से निगरानी करती है तथा अनेक तरीकों से उनके प्रयासों में सहायता और समन्वय करती है।
- इनमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रदान करना, इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति, विद्रोह प्रतिरोधी तथा आतंकवादरोधी

विद्यालयों की स्थापना, राज्य पुलिस तथा उनके सूचना तंत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, नक्सलरोधी अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कराना, रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता करना सूचना का आदान-प्रदान अन्तर-राज्य समन्वय को सुगम बनाना, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा सिविक एक्शन कार्यक्रमों में सहायता करना आदि शामिल हैं। इसके पीछे सोच माओवादी खतरे से एक ठोस तरीके से निपटने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि करने की है।

- सरकार ने नक्सली समस्या से निबटने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है जिसके तहत एक ओर जहां वह नक्सल प्रभावित राज्यों को उनके प्रयासों में मदद कर रही है तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति और कार्ययोजना भी तैयार की है।
- इस योजना में सुरक्षा से जुड़े उपायों के साथ ही स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके विकास से जुड़े कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। विकास योजनाओं से जुड़ी पहल में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क बनाने, मोबाइल टॉवर लगाने,कौशल विकास बैंकों और डाकघरों का नेटवर्क सुधारने तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने जैसे काम शामिल हैं। इन उपायों ने स्थानीय लोगों को नक्सलियों से दूर कर सरकार पर उनका विश्वास बढ़ाया है।

विविध संक्षिप्त मुद्दे

संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-विरोधी ट्रस्ट फंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 7 मई को संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में पांच लाख डॉलर के स्वैच्छिक वित्तीय योगदान की राशि सौंपी।

पृष्ठभूमि:

- 2022 में अक्तूबर में विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति को संबोधित किया था। तब उन्होंने कहा था कि वैश्विक स्तर पर आंतकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है।
- इस दौरान उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। साथ ही वादा किया था कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में 500,000 डॉलर का योगदान देगा।

उद्देश्य:

- भारत यूएनओसीटी के वैश्विक कार्यक्रमों मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) और आतंकवाद यात्रा कार्यक्रम (सीटीटीपी) का मुकाबला करने में मदद करेगा।
- इसका उद्देश्य पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के सदस्य देशों की क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे आतंकवाद के वित्तपोषण के महत्वपूर्ण मुद्दों से निपट सकें और आतंकवादियों की आवाजाही एवं यात्रा को रोक सकें।

फण्ड की स्थिति:

- पांच लाख डॉलर के योगदान के साथ ही ट्रस्ट फंड में भारत का अब वित्तीय समर्थन 25.5 लाख डॉलर हो गया है।

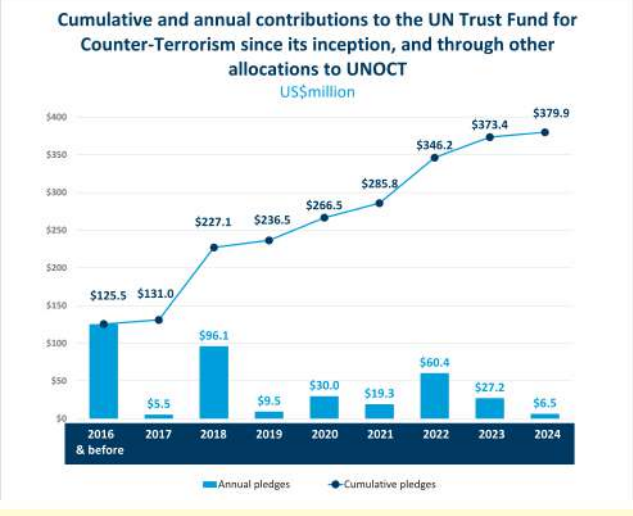

-: प्रीलिम्स इनसाइट :-

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संयुक्त राष्ट्र के पांच प्रमुख अंगों में से एक है, जिसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के साथ-साथ नए सदस्यों को जोड़ने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में

किसी भी संशोधन को मंजूरी देने का काम सौंपा गया है।

- **मुख्यालय:** न्यूयॉर्क
- **स्थापित:** 1945
- **पहला सत्र:** 17 जनवरी 1947, लंदन
- **कुल सदस्य:** 15 (5 स्थायी और 10 अस्थाई)
- **स्थायी सदस्य:** चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

निष्कर्ष:

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद के वित्तपोषण को प्रभावी ढंग से रोकना होगा। भारत आतंकवाद के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सदस्य देशों की क्षमता के निर्माण में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी कार्यालय द्वारा किए गए कार्यों और जनादेश को बहुत महत्व देता है। नवीनतम योगदान आतंकवाद के संकट के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले बहुपक्षीय प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

इग्ला-एस: बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय सेना को रूस द्वारा विकसित मानव-पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली (MANPADS) इग्ला-एस की 24 मिसाइल प्राप्त हुई।

विकास:

- सिस्टम को भारत में अदानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एडीएसटीएल) द्वारा असेंबल किया जा रहा है, जिसमें रूस के रोसोबोरोनएक्सपोर्ट से हस्तांतरित तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
- समझौते के तहत मिसाइलों का आयात किया जाएगा। साइट्स, लॉन्चर और बैटरी जैसे घटकों को अदानी डिफेंस द्वारा स्थानीय रूप से इकट्ठा या निर्मित किया जा रहा है।

क्या है इग्ला-एस वायु रक्षा प्रणाली?

- यह एक अत्यधिक कुशल 'मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम' (MANPADS) व वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) के रूप में जाना जाता हैं।
- **कार्य:** कम उड़ान वाले विमानों को रोकना एवं क्रूज मिसाइलों तथा ड्रोन जैसे हवाई खतरों का भी पता लगाना एवं उनका मुकाबला करना।
- इग्ला-एस प्रणाली, जिसमें 9एम342 मिसाइल, 9पी522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म, 9वी866-2 मोबाइल परीक्षण स्टेशन और 9एफ719-2 परीक्षण सेट शामिल है, एक बहुमुखी और व्यापक वायु रक्षा समाधान प्रदान करता हैं।
- **रेंज:** इसकी रेंज 500 मीटर से 6 किलोमीटर तक है और यह 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य पर हमला करती है। मिसाइल की गति 400 मीटर प्रति सेकंड है और तैनाती का समय 13 सेकंड है।
- यह एक हस्त-संचालित रक्षा प्रणाली है जिसे किसी व्यक्ति या चालक दल द्वारा संचालित किया जा सकता है।
- **महत्त्व:** इग्ला-एस जैसे MANPADS पैदल सेना इकाइयों को स्वतंत्र रूप से हवाई खतरों से बचाव करने की क्षमता प्रदान करके आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

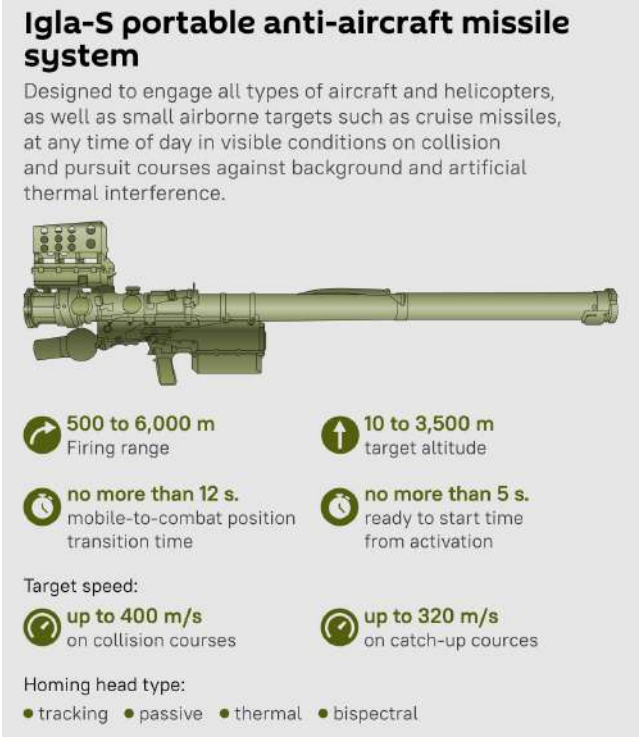

बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली या VSHORADS:

- यह हैदराबाद में स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के तहत एक अनुसंधान प्रयोगशाला, रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) द्वारा विकसित चौथी पीढ़ी की मानव-पोर्टेबल वायु-रक्षा प्रणाली (MANPADS) है।
- इसे विमान रोधी युद्ध तथा कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- SHORAD बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क में दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और यूएवी के खिलाफ सैनिकों की अंतिम रक्षा पंक्ति हैं।

निष्कर्ष:

यह रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की व्यापक पहल का हिस्सा है। इसकी पोर्टेबिलिटी, जवाबी कार्रवाई प्रतिरोध और हर मौसम में काम करने की क्षमताएं इसे आधुनिक सैन्य अभियानों में एक महत्त्वपूर्ण साधन बनाती हैं।

स्वस्थ खानपान को बढ़ावा देने के लिए ICMR की नई गाइडलाइन

चर्चा में क्यों?

भारत में बदलती जीवनशैली, खान-पान की आदतों और स्वस्थ और टिकाऊ भोजन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और सुझाव दिए है।

अध्ययन के महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- नए अनुमान से पता चलता है कि देश में कुल बीमारियों का 56.4 प्रतिशत हिस्सा अस्वास्थ्यकर आहार के कारण है।
- एक तिहाई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के के लिए खाद्य प्रणालियाँ भी जिम्मेदार हैं।

दिशा निर्देश:

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पोषण संस्थान (ICMR-NIN) ने 17 आहार संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें निम्नलिखित सिफारिशें शामिल हैं:
  - कम से कम आठ खाद्य समूहों से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने चाहिए।
  - दैनिक भोजन का आधा हिस्सा सब्जियों, फलों, जड़ों और कंदों से बनाएं। शेष हिस्सा अनाज, बाजरा, दालें, मांस, अंडे, नट्स, तिलहन, दूध या दही से बनाएं।
  - शाकाहारियों को अलसी, चिया बीज जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए।
  - **चीनी का सेवन:** चीनी का सेवन प्रतिदिन 30 ग्राम तक सीमित रखें, खासकर दो साल से छोटे बच्चों के लिए। चीनी के विकल्प भी मोटापा और अन्य बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
  - **प्रोटीन का सेवन:** प्रोटीन पूरक पाउडर का अधिक सेवन न करें क्योंकि इससे गुर्दे की क्षति, निर्जलीकरण और पोषक तत्वों का असंतुलन हो सकता है।
  - **टिकाऊ भोजन:** खाद्य पदार्थों का उपभोग इस प्रकार करें कि वे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिम्मेदार हों। इसका अर्थ है कि भोजन की उत्पत्ति, उत्पादन, वितरण और उपभोग के प्रत्येक चरण में पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाया जाए। इस प्रकार, टिकाऊ भोजन न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारत के बदलते खाद्य परिदृश्य में स्वस्थ और टिकाऊ आहार की आवश्यकता आज पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ICMR-NIN के दिशा-निर्देश स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देते हुए गैर-संचारी बीमारियों को रोकने में सहायक हैं। टिकाऊ भोजन की आदतें न केवल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी सुनिश्चित करती हैं। अत: स्वस्थ और टिकाऊ आहार अपनाकर हम एक स्वस्थ और स्थिर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं।

भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन

चर्चा में क्यों?

कीप इट ऑन संस्था (इंटरनेट नाकाबंदी के खिलाफ वकालत करने वाले नागरिक समाज निकायों का एक समूह) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2023 में दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन देखा गया, यह लगातार छठे वर्ष के लिए एक रिकॉर्ड है।

भारत में वर्तमान स्थिति:

- रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल भारत में 116 बार इंटरनेट बंद किया गया। इंटरनेट शटडाउन आदेश लागू करने के कुछ प्रमुख कारण सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और अन्य कारण थे।
- भारत में सामूहिक रूप से इंटरनेट शटडाउन के 500 से अधिक मामले सामने आए हैं।
- 2023 में कुल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शटडाउन लगाया, जिनमें से सात ने पांच या अधिक बार इंटरनेट सेवाओं को बाधित किया तथा पांच दिनों या उससे अधिक समय के लिए शटडाउन 2022 में सभी शटडाउन के 15% से बढ़कर 2023 में 41% से अधिक हो गया।
- 64 शटडाउन एक ही राज्य, प्रांत या क्षेत्र के एक से अधिक जिलों को प्रभावित करते हैं। इसे मणिपुर में 47 बंद और मार्च में पंजाब में राज्यव्यापी बंद से देखा जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार इंटरनेट शटडाउन आदेशों का प्रकाशन लगातार नहीं किया गया।
- 37 आदेशों के साथ, म्यांमार, जहां सेना ने 2021 में तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया, इंटरनेट शटडाउन की दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की गई, इसके बाद ईरान (34), फिलिस्तीन (16), और यूक्रेन (8) हैं।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुराधा भसीन फैसले में कहा कि इंटरनेट तक पहुंच भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंटरनेट पहुंच पर कोई भी सरकारी प्रतिबंध अस्थायी, वैध, आवश्यक और आनुपातिक होना चाहिए।
- **संशोधन दूरसंचार निलंबन नियम, 2017:** सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, भारतीय संसद ने दूरसंचार निलंबन नियम, 2017 में संशोधन किया। इस संशोधन ने इंटरनेट निलंबन आदेश को अधिकतम 15 दिनों तक सीमित कर दिया।
- हालाँकि, संशोधन में निलंबन आदेशों के प्रकाशन को अनिवार्य नहीं किया गया था, न ही इसमें इन आदेशों की आवधिक समीक्षा के

लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को शामिल किया गया था।

- सरकार ने अनुराधा भसीन फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को वैधानिक मान्यता नहीं दी है, जिससे अधिकारियों में जागरूकता और अनुपालन की कमी है।

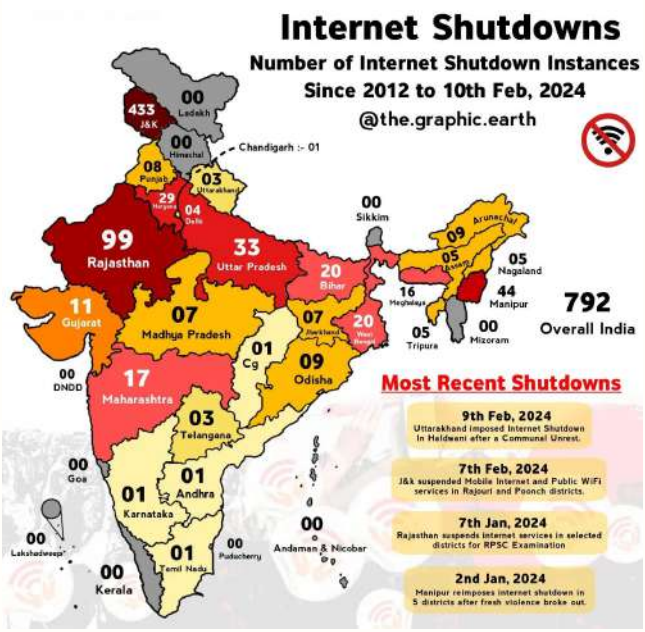

इंटरनेट निलंबन से जुड़े मुद्दे:

- **सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन:** अनुराधा भसीन के ऐतिहासिक फैसले में इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित करने के बावजूद, सरकार इंटरनेट शटडाउन का प्रयोग करती रहती हैं।
- **निलंबन आदेशों में पारदर्शिता का अभाव:** इंटरनेट शटडाउन के कारणों को प्रकाशित करने में सरकार की विफलता कानूनी प्रक्रियाओं और सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करती है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निलंबन आदेशों के बिना, नागरिकों को शटडाउन को अदालत में चुनौती देना दुष्कर लगता है।
- **गैर-अनुपालन:** अनुराधा भसीन फैसले का पालन कम किया जा रहा है। सिर्फ जम्मू-कश्मीर ही नहीं, मणिपुर में भी जातीय हिंसा के दौरान हुए अत्याचारों का दस्तावेजीकरण करने वाले फुटेज घटनाओं के वास्तविक घटित होने के कई सप्ताह बाद वायरल हो गए हैं।
- खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश के दौरान पूरे पंजाब में और राज्य में चल रही जातीय हिंसा के दौरान पूरे मणिपुर में कई बार इंटरनेट बंद किया गया था।

इंटरनेट निलंबन के प्रभाव:

- **दैनिक जीवन में व्यवधान:** आज के डिजिटल युग में, इंटरनेट निलंबन प्रभावी रूप से समग्र आर्थिक गतिविधि को रोक देता है, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और नौकरी के अवसरों तक पहुंच में बाधा आती है। इंटरनेट शटडाउन से मनोवैज्ञानिक तनाव भी होता है और सामाजिक और पत्रकारिता गतिविधियाँ भी बाधित होती हैं।
- **असमानता की खाई को बढ़ाता है:** ट्राई की एक रिपोर्ट के अनुसार, 936.16 मिलियन इंटरनेट ग्राहकों में से 38.57 मिलियन वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करते हैं, जबकि 897.59 मिलियन वायरलेस कनेक्शन का उपयोग करते हैं। कॉर्पोरेट जगत और गिग अर्थव्यवस्था डिजिटल पहुंच पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
- **लोकतंत्र पर प्रभाव:** विरोध प्रदर्शन जैसी लोकतांत्रिक गतिविधियों को दबाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच को सीमित करने के लिए इंटरनेट शटडाउन का अक्सर उपयोग किया जाता है।

निष्कर्ष:

इंटरनेट वरदान और अभिशाप दोनों है, यह सही प्रकार के विनियमन पर निर्भर करता है। प्रभावी विनियमन आर्थिक नुकसान को कम कर सकता है और डिजिटल इंडिया की क्षमता को पूरा करते हुए, दुनिया की 'इंटरनेट शटडाउन राजधानी' के रूप में भारत के टैग को हटा सकता है। निलंबन आदेश जारी करने और प्रकाशित करने में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कार्यकारी सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन आवश्यक है, जो मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में फिशिंग हमले

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यू जर्सी स्थित साइबर सुरक्षा समाधान और उत्पाद प्रदाता वेरिजॉन बिजनेस के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत फिशिंग हमलों से प्रभावित प्रमुख देशों में से एक है।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कर्मचारी अक्सर वैध स्रोतों से आने वाले दुर्भावनापूर्ण लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करते हैं, जिससे अक्सर गंभीर वित्तीय नुकसान होता है।
- रिपोर्ट, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 2023 में 30,458 सुरक्षा घटनाओं और 10,626 उल्लंघनों (2022 से दोगुनी वृद्धि) का विश्लेषण करने के बाद तैयार की गई थी।
- रिपोर्ट बताती है कि जासूसी हमले भारत सहित एशिया-प्रशांत के साइबर सुरक्षा परिदृश्य पर हावी हैं। लगभग 25% साइबर हमले जासूसी से प्रेरित हैं तथा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी वृधि देखी गई।
- सिस्टम में घुसपैठ, सोशल इंजीनियरिंग और बुनियादी वेब एप्लिकेशन हमले एशिया-प्रशांत में 95% उल्लंघनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्ययन के अनुसार, समझौता किए गए डेटा के सबसे आम प्रकार क्रेडेंशियल्स (69%), आंतरिक (37%), और रहस्य (24%) हैं।
- हालाँकि, वेरिजॉन बिजनेस ने कहा, जहां तक भारत का सवाल है, एक उम्मीद की किरण है क्योंकि रिपोर्टिंग प्रथाओं में सुधार हुआ

है, 20% उपयोगकर्ता अब परीक्षणों के दौरान फिशिंग की पहचान करते हैं और रिपोर्ट करते हैं।

–: प्रीलिम्स इनसाइट :–

- **स्पीयर फिशिंग:** स्पीयर फिशिंग किसी समूह के बजाय विशिष्ट व्यक्तियों को लक्षित करती है। हमलावर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या तो लक्ष्य के बारे में जानकारी रखते हैं या उसके बारे में जानकारी चाहते हैं।
- **व्हेलिंग:** स्पीयर फिशिंग का उप-प्रकार लेकिन आमतौर पर और भी अधिक लक्षित। व्हेलिंग विशिष्ट व्यक्तियों को लक्षित करती है, जैसे व्यावसायिक अधिकारी, मशहूर हस्तियाँ और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति।
- **स्मेशिंग:** एसएमएस के माध्यम से भेजा जाता है।
- **विशिंग:** फोन कॉल के माध्यम से किया जाता है, हमलावर पीड़ित को आमतौर पर पहले से रिकॉर्ड

फिशिंग क्या है?

- फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां वैध संस्था होने का दिखावा करके किसी व्यक्ति द्वारा ईमेल, फोन या टेक्स्ट के माध्यम से व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है। उनका लक्ष्य व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी, बैंकिंग विवरण और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्रदान करने के लिए धोखा देना है।
- फिशिंग हमले में, प्रेषक प्राप्तकर्ता के किसी भरोसेमंद व्यक्ति का रूप धारण करता है, जैसे परिवार का कोई सदस्य, उनकी कंपनी का सीईओ, या उपहार देने वाला कोई प्रसिद्ध व्यक्ति। संदेश तात्कालिकता की भावना पैदा करता है, और प्राप्तकर्ता को एक वैध वेबसाइट से मिलती-जुलती नकली वेबसाइट की ओर निर्देशित करता है।
- फिर उन्हें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने के लिए कहा जाता है, जिसे हमलावर पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, या व्यक्तिगत जानकारी बेचने के लिए चुरा लेता है। फिशिंग ईमेल का URL बिल्कुल वैध URL की नकल करता है।

निष्कर्ष:

साइबर जागरूकता एक महत्वपूर्ण कदम है। संस्थान बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाकर साइबर सुरक्षा में मानवीय त्रुटि को और कम कर सकते हैं। इसमें मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करना, नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित करना और पूरे संगठन में साइबर सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। ये कदम उठाकर, व्यवसाय फिशिंग हमलों और अन्य साइबर खतरों से बेहतर ढंग से अपनी रक्षा कर सकते हैं।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 का 21वां संस्करण विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (3 मई,2024) के अवसर पर प्रकाशित किया गया। यह रिपोर्ट वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- प्रेस स्वतंत्रता प्रश्नावली में पाँच श्रेणियां शामिल हैं- राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा।
- सूचकांक के अनुसार, पत्रकारिता के वर्तमान स्थिति को 31 देशों में स्थिति 'बहुत गंभीर', 42 में 'मुश्किल', 55 में 'समस्याग्रस्त' और 52 देशों में 'अच्छी' या 'संतोषजनक' है। नॉर्वे और डेनमार्क जहां तालिका में शीर्ष पर हैं वहीं इरिट्रिया सबसे नीचे है।
- सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका (45वां) का स्थान तीन पायदान नीचे गिर गया है। हालांकि एशिया में, सरकारों में बदलाव से मीडिया के लिए स्थिति में सुधार हुआ है और सूचकांक में ऑस्ट्रेलिया (12वें स्थान पर 27वें स्थान पर) और मलेशिया (40वें स्थान पर 73वें स्थान पर) के रूप में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- सूचकांक के अनुसार, पर्यावरण पत्रकार के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि हुई है। 15 वर्षों में 44 पत्रकारों की हत्या हुई।
- ब्रिक्स देशों में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भारत से ऊंचे स्थान पर है जबकि चीन और रूस नीचे हैं।

भारत में स्थिति:

- भारत की रैंक 2023 में 161 से सुधरकर 2024 में 159 हो गई, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट

आई हैं।

- भारत की रैंक तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे हैं जो क्रमश 158, 152 और 150 है।
- भारत 2003 से लगातार 100 से अधिक स्थान पर है, जो सीमित प्रेस स्वतंत्रता की दीर्घकालिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। हाल के वर्षों में देश के प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति तेजी से खराब हुई है।

निष्कर्ष:

सूचकांक प्रेस की स्वतंत्रता पर डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के नकली सामग्री उद्योग के तेज प्रभाव को भी उजागर करता है। यह सूचना के अधिकार को खतरे में डालता है, गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को कमजोर करता है इसके अतिरिक्त, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म सूचना के लिए एक मनमाना, भुगतान-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो यह दिखाता है कि कैसे यह प्लेटफॉर्म पत्रकारिता के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

मैतेई सागोल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मणिपुर सरकार ने मणिपुरी पोनी या मैतेई सागोल को विलुप्त होने से बचाने के लिए नागरिक समाज और निजी संगठनों के साथ मिलकर एक संयुक्त बैठक आयोजित की।

बैठक की प्रमुख बातें:

संयुक्त बैठक के निर्णयों में शामिल हैं:

- सागोल को चराने और उनके चरागाहों और स्थायी आवासों का सर्वेक्षण करना।
- जानवरों को अस्थायी रूप से रखने और सागोल के स्वामित्व के लिए एक क्षेत्र का सीमांकन एवं रखरखाव और देखभाल।
- परामर्श आयोजित करने, एक टास्क फोर्स के गठन और सागोल प्रबंधन के लिए बजट तैयार करने के संबंध में प्रमुख निर्णय लिए गए।
- सागोल पंजीकरण के लिए स्टडी बुक को अंतिम रूप देना और हितधारकों के माध्यम से टट्टूओं की जनगणना को औपचारिक बनाना।

मैतेई सागोल के बारे में:

- यह भारत की सात मान्यता प्राप्त घोड़े और टट्टू नस्लों में से एक है। अन्य में मारवाड़ी घोड़ा, काठियावाड़ी घोड़ा, जांस्करी घोड़ा, स्पीति घोड़ा, भूटिया घोड़ा और कच्छी-सिंधी घोड़ा शामिल हैं।
- यह अपनी अद्वितीय सहनशक्ति, चपलता, बुद्धिमत्ता, गति, गतिशीलता और कठोर भू-जलवायु परिस्थितियों के प्रति महान अनुकूलन क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
- नस्ल के संरक्षण के लिये वर्ष 2016 में मणिपुरी पोनी संरक्षण और विकास नीति (Manipuri Pony Conservation and Development Policy- MPCDP) बनाई गई थी।

-: प्रीलिम्स इनसाइट :-

- **अश्व नस्लें:** अश्व, इक्विडे (ऑर्डर पेरिसोडैक्टाइला) के स्तनपायी परिवारों में से एक है जिसमें आधुनिक घोड़े, जेबरा और गधे शामिल हैं, साथ ही 60 से अधिक प्रजातियां है,जो केवल जीवाश्मों से ज्ञात हैं।
- सागोल कांगजेई मणिपुर में खेले जाने वाले पोलो का पारंपरिक नाम है। 'सागोल' का तात्पर्य टट्टू या घोड़े से है, 'कांग' का अर्थ गेंद से है, और 'जेई' का तात्पर्य मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छड़ी से है। यह खेल प्रत्येक तरफ सात खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है, जो सभी टट्टुओं पर सवार होते हैं।

उनकी जनसंख्या में गिरावट का कारण:

- तेजी से शहरीकरण और अतिक्रमण के कारण मणिपुरी टट्टू के प्राकृतिक आवास आर्द्रभूमि का सिकुड़ना।
- ग्रामीण मणिपुर में पोलो मैदानों/पोलो खेल क्षेत्रों की कमी, पोलो के खेल को छोड़कर टट्टू के उपयोग पर प्रतिबंध व अनियंत्रित रोग।
- पड़ोसी राज्यों और देशों में टट्टुओं का पलायन राज्य में टट्टूओं की संख्या में गिरावट का कारण हैं।

निष्कर्ष:

मणिपुरी टट्टू मणिपुरी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनका उपयोग लाई हराओबा जैसे पारंपरिक आयोजनों के साथ-साथ पोलो और घुड़दौड़ जैसे खेलों में भी किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से, वे मणिपुर साम्राज्य की घुड़सवार सेना के लिए घुड़सवार के रूप में काम करते थे। हालाँकि, मणिपुरी टट्टू की आबादी तेजी से घट रही है, 2003 में 17वीं पशुधन जनगणना में 1,898 जानवरों से लेकर 2012 में 19वीं जनगणना में 1,101 हो गई है। इस गिरावट को संबोधित करने के लिए, मणिपुरी टट्टू संरक्षण और विकास नीति (एमपीसीडीपी) की स्थापना की गई थी। इन प्रयासों के बावजूद, 2019 में नवीनतम पशुधन जनगणना में 1,089 टट्टुओं की और गिरावट दर्ज की गई।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अग्रणी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (जीएएनएचआरआई) ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की मान्यता को स्थगित कर दिया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में:

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पेरिस सिद्धांतों के अनुसार स्थापित किया गया है।

- **कार्य:** मानवाधिकारों का प्रचार और संरक्षण।
- इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया।
- **संशोधन:** मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और मानवाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित।

भूमिका और कार्य:

- इसके पास स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है तथा इसके पास एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ हैं। इसकी कार्यवाही प्रकृति में न्यायिक है और यह केंद्र या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी से जानकारी या रिपोर्ट मांग सकती है।
- इसे मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों या जांच एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार है।
- इसके कार्य मुख्यत: अनुशंसात्मक प्रकृति के हैं।

–: प्रीलिम्स इनसाइट :–

- **राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (GANHRI):** 1993 में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (ICC) के रूप में स्थापित, इसे 2016 से राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (GANHRI) के रूप में जाना जाता है।
- GANHRI एक सदस्य-आधारित नेटवर्क है जो दुनिया भर से NHRI को एकजुट करता है। यह संयुक्त राष्ट्र का मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय भागीदार है।
- सदस्यों की संख्या-120
- भारत भी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन का सदस्य है।

एनएचआरसी की वर्तमान सीमाएँ क्या हैं?

- **सीमित जांच तंत्र:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के पास जांच के लिए एक समर्पित तंत्र का अभाव है और वह ऐसे तंत्रों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर है। यह घटना के एक वर्ष से अधिक समय बाद दर्ज की गई शिकायतों पर विचार नहीं करता है, जिसके कारण कई शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता है।
- **प्रवर्तन शक्ति का अभाव:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) केवल सिफारिशें कर सकता है और उसके पास प्रवर्तन शक्ति का अभाव है। एनएचआरसी को राजनीतिक रूप से संबद्ध न्यायाधीशों और नौकरशाहों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के गंतव्य के रूप में देखे जाने को लेकर चिंताएं हैं और अपर्याप्त फंडिंग इसकी प्रभावशीलता में बाधा डालती है।
- **सरकार पर निर्भरता:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की संरचना सरकारी नियुक्तियों पर निर्भर करती है, जिससे राजनीतिक प्रभाव से पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जो इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।
- राज्य मानवाधिकार आयोगों के पास राष्ट्रीय सरकार से जानकारी का अनुरोध करने का अधिकार नहीं है, जिससे राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **सीमित क्षेत्राधिकार:** सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अधिकार क्षेत्र सीमित है। सैन्य कर्मियों से जुड़े मामले अक्सर इसके दायरे से बाहर हो जाते हैं, जिससे व्यापक जवाबदेही में बाधा आती है।

निष्कर्ष:

एआई, डीप फेक और जलवायु परिवर्तन जैसी उभरती चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया जाना चाहिए। एनएचआरसी को दंडात्मक शक्तियों से सशक्त बनाने से जवाबदेही और अनुपालन में वृद्धि होगी। नागरिक समाज, कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों से सदस्यों की नियुक्ति करके विविधता बढ़ाने से एक समग्र दृष्टिकोण मिलेगा। एनएचआरसी को नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में सशक्त बनाने के लिए सक्रिय वकालत, जागरूकता अभियान और शिक्षा में संलग्न होना चाहिए। सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और अपनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों के साथ सहयोग करने से एनएचआरसी की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को और मजबूत किया जा सकता है।

यूनेस्को का विश्व स्मृति एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर

चर्चा में क्यों?

रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोक-लोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। यह निर्णय 7-8 मई को मंगोलिया के उलनबटोर में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (MOWCAP) की 10वीं आम बैठक के दौरान किया गया।

विश्व एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर की स्मृति के बारे में:

- यह रजिस्टर एशिया/प्रशांत क्षेत्र में उन 'प्रभाव की वृत्तचित्र विरासत' की एक सूची है जिसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (MOWCAP) द्वारा शामिल करने के लिए अनुमोदित किया गया है।
- यह मानवता की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992

में यूनेस्को द्वारा शुरू की गई 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम (एमओडब्ल्यू)' नामक एक अंतरराष्ट्रीय पहल का हिस्सा है।

- मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (MOWCAP) की स्थापना 1998 में की गई थी और वर्तमान में इसमें 43 देश शामिल हैं, जो यूनेस्को के पांच क्षेत्रीय कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासत को उसी तरह से पहचानना है जैसे यूनेस्को की विश्व विरासत सम्मेलन और विश्व विरासत सूची महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों को पहचानती है।

रचनाएः

- 'रामचरितमानस', 'पंचतंत्र' और 'सहृदयालोक-लोकन' ऐसी कालजयी रचनाएँ हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है, देश के नैतिक ताने-बाने और कलात्मक अभिव्यक्तियों को आकार दिया है।

रामचरितमानसः

- 16वीं सदी के भारतीय कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित, 'रामचरितमानस' भगवान राम के जीवन का वर्णन करने वाला एक महाकाव्य है। यह संस्कृत महाकाव्य रामायण पर आधारित हिंदी की अवधी बोली में लिखा गया है।
- यह भक्ति आंदोलन के समय भक्ति पर जोर देने और भगवान राम के चरित्र को जन मानस के लिए सुलभ बनाने हेतु लिखा गया।
- यह ग्रंथ, जिसे तुलसीकृत रामायण (तुलसीदास की रामचरित मानस) भी कहा जाता है, सात अध्यायों या कांडों में विभाजित है, जो भगवान राम के जन्म से लेकर अयोध्या के राजा बनने तक की कहानी बताती हैं।

पंचतंत्रः

- माना जाता है कि पंचतंत्र 2,500 साल पहले विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, जो लोक कथाओं और दंतकथाओं का संग्रह है।
- यह नीति, या बुद्धिमान आचरण की एक पुस्तक है, जिसे सरल कहानियों की एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमे नैतिक और दार्शनिक विषय है। कहानियों का उद्देश्य पाठकों के मानव स्वभाव को समझकर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करना है।

सहृदयलोक – लोकनः

- यह आचार्य आनंदवर्धन द्वारा लिखित एक संस्कृत ग्रंथ है। यह ध्वनिलोक पर एक संस्कृत भाष्य है।

निष्कर्षः

यह समावेशन भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, जो इसकी समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि करता है। यह वैश्विक सांस्कृतिक संरक्षण की ओर एक सार्थक कदम है, जिसमें विविध आख्यानों और कलात्मक अभिव्यक्तियों को पहचानने और उनकी सुरक्षा करने के महत्व पर जोर दिया गया है। इन साहित्यिक उत्कृष्ट कृतियों का सम्मान करके, समाज न केवल उनके रचनाकारों की रचनात्मक प्रतिभा को श्रद्धांजलि देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि उनका गहन ज्ञान और कालातीत शिक्षाएँ भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।

पर्यावरण संरक्षण के लिए बाजार आधारित प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (आईयूएफआरओ) द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वन संरक्षण एवं गरीबी कम करने के लिए बाजार आधारित प्रोत्साहन सफल नहीं रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण के लिए बाजार आधारित प्रोत्साहन क्या है?

- पर्यावरण प्रबंधन के लिए बाजार-आधारित प्रोत्साहन नीतिगत हस्तक्षेप हैं जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं को संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करने और उनके नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
- व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि में कार्बन क्रेडिट शामिल है, जहां संगठन या सरकारें कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करती हैं, जैसे कि पुनर्वनीकरण या वन संरक्षण।

लाभः

- **सुगमताः** कंपनियां प्रदूषण को कम करने के लिए लागत प्रभावी तकनीकी और प्रबंधन के अवसरों का लाभ नहीं उठा पाती हैं। यह दृष्टिकोण पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान बनाता है।
- **लचीलापनः** यह तंत्र संसाधन उपयोग और पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार के लिए समाधान खोजने में लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं और साथ ही पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की लागत को कम करने के लिए प्रोत्साहन भी देते हैं।
- **नवप्रवर्तन को बढावाः** वे नवप्रवर्तन को भी बढ़ावा देते हैं, सकारात्मक दबाव बनाते हैं जो समय के साथ पर्यावरणीय स्थिरता के लिए सुधारों को लागू करना सस्ता बनाता है।
- **व्यवहार्यताः** यदि अच्छी तरह से डिजाइन और कार्यान्वित किया जाए, तो ये दृष्टिकोण समाज के लिए सबसे कम लागत पर प्रदूषण को कम कर सकते हैं और संभावित रूप से कमांड-एंड-कंट्रोल नियमों की तुलना में उत्सर्जन में और भी अधिक कटौती प्राप्त कर सकते हैं।
- **सरकार के लिए राजस्व सृजनः** बाजार-आधारित उपकरण, जैसे पर्यावरण कर और व्यापार योग्य परमिट बाजार, सरकारी राजस्व बढ़ाने के अवसर पैदा करते हैं। यह बाजारों के बारे में जानकारी

का खुलासा करके और अपने कार्यों के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाकर निर्णय लेने में सुधार कर सकते हैं।

रिपोर्ट द्वारा बताई गई प्रमुख बातें:

- वैश्विक अध्ययन में पाया गया कि व्यापार और वित्त-संचालित पहलों ने वनों की कटाई को रोकने में सीमित प्रगति की है और, कुछ मामलों में, आर्थिक असमानता बढ़ गई है।
- विशेषज्ञो ने बाजार-आधारित दृष्टिकोणों पर आमूल-चूल पुनर्विचार करने का आह्वान किया, जिन्हें अक्सर जंगलों को बचाने, ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाने और विकासशील देशों में जीवन स्तर को बढ़ाने में प्रभावी माना जाता है।

-: प्रीलिम्स इनसाइट :-

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी):

- इसका कार्य पर्यावरणीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करना हैं।
- 13 अक्टूबर, 2023 को अधिसूचित ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) एक अभिनव बाजार-आधारित तंत्र है जिसे व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने के लिए मसौदा पद्धतियां विकसित की गई हैं जो प्रत्येक गतिविधि/प्रक्रिया के लिए मानक निर्धारित करती हैं, ताकि सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभाव और प्रतिस्थापना सुनिश्चित की जा सके।
- जीसीपी दो प्रमुख गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है: जल संरक्षण और वनीकरण।

बाजार-आधारित योजनाओं की जटिलता:

- 2010 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (आईयूएफआरओ) के अंतिम मूल्यांकन के बाद से, जटिल और अतिव्यापी बाजार-आधारित योजनाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें वित्तीय निवेशक और शेयरधारक दीर्घकालिक टिकाऊ वन प्रशासन की तुलना में अल्पकालिक मुनाफे में अधिक रुचि रखते हैं।
- उदाहरण के लिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना ने शक्तिशाली व्यवसायों द्वारा लॉगिंग जंगलों तक स्थानीय पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया।
- **स्वदेशी समूहों पर प्रभाव:** मलेशिया में, स्वदेशी समूहों से अपनी पारंपरिक भूमि पर विदेशी समर्थित वृक्षारोपण उद्यम से बेहतर आजीविका का वादा किया लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। घाना में, स्थायी कोको मानकों, कॉर्पोरेट गतिविधि और कार्बन ऑफसेट परियोजनाओं के बावजूद वनों की कटाई की दर में वृद्धि हुई है, जबकि किसान आज दशकों पहले की तुलना में कम कमाते हैं।

हरित व्यापार नीतियों की सीमाएँ:

- **कार्बन बाजारों का विकास:** हालिया उथल-पुथल के बावजूद, कार्बन बाजारों के अरब डॉलर के उद्योग में विकसित होने की उम्मीद है क्योंकि निगम अपने शुद्ध-शून्य जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्रेडिट का उपयोग करते हैं। ये क्रेडिट अक्सर विकासशील देशों में परियोजनाओं से खरीदे जाते हैं जो कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं या उससे बचते हैं, जैसे कि CO_2-अवशोषित वर्षावनों या पीट दलदलों की रक्षा करना।

राजस्व वितरण के बारे में चिंताएँ:

- केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अफ्रीका के कार्बन सिंक को एक अद्वितीय आर्थिक सोने की खान कहा है जो सालाना अरबों डॉलर उत्पन्न कर सकती है। हालाँकि, इस बात को लेकर चिंताएँ हैं कि गरीब समुदायों को वास्तव में कितना राजस्व प्राप्त होगा।
- **व्यापक समाधान की आवश्यकता:** रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि हालांकि बाजार-आधारित दृष्टिकोण नीति निर्माताओं के लिए आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन वे पूर्ण समाधान नहीं हो सकते हैं और वन प्रबंधन व्यापक आर्थिक और शासन सुधारों के साथ होना चाहिए।

निष्कर्ष:

भारत विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदारियों को साझा करने में समानता के महत्व पर प्रकाश देते हुए सीबीडीआर (सामान्य किन्तु विभेदित जिम्मेदारी) के सिद्धांत पर जोर देता है। हालाँकि, चिंता यह है कि गरीब देश अक्सर पर्यावरणीय चुनौतियों का खामियाजा भुगतते हैं, डंपिंग ग्राउंड बन जाते हैं, जबकि अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाएँ सख्त पर्यावरण मानकों पर जोर देती हैं, जिससे विकास का अंतर बढ़ जाता है।

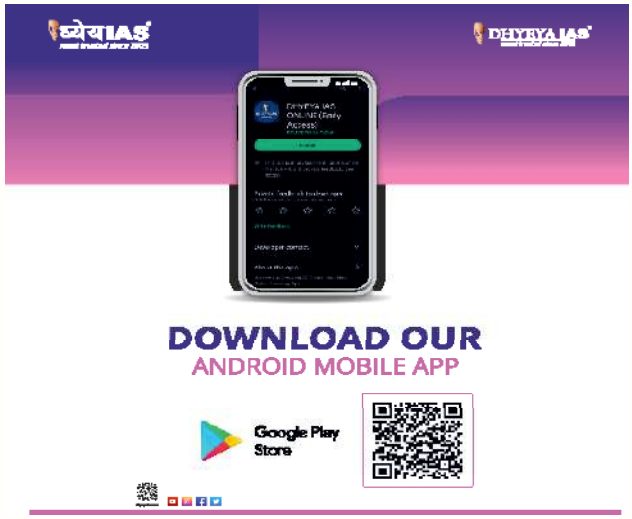

ब्रेन बूस्टर

वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी

चर्चा में क्यों?

वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (डब्ल्यूसीसीआई) ने इस वर्ष भारत से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी (डब्ल्यूसीसी) के रूप में अपने अंतिम नामांकन से पहले शिल्प समूहों के मानचित्रण के लिए श्रीनगर को चुना है। डब्ल्यूसीसीआई की तीन सदस्यीय टीम शिल्प समूहों, इसमें शामिल प्रक्रियाओं और कारीगरों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए श्रीनगर में थी।

1. विश्व शिल्प परिषद के बारे में

- विश्व शिल्प परिषद एआईएसबीएल की स्थापना सुश्री एलीन ओसबोर्न वेंडरबिल्ट वेब, सुश्री मार्गरेट एम. पैच एवं श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने की थी।
- नवंबर 2012 में, संगठन विश्व शिल्प परिषद एआईएसबीएल को औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में गठित किया गया था।
- 2021-2024 की वर्तमान अवधि के लिए मुख्यालय कुवैत में स्थित है।

2. विश्व शिल्प परिषद का उद्देश्य

- **संरक्षण एवं संवर्धन:** कारीगरों के लिए संसाधन, सहायता और मंच प्रदान करके विश्व स्तर पर पारंपरिक शिल्प के संरक्षण, प्रचार और उन्नति को बढ़ावा देना।
- **कारीगरों का सशक्तिकरण:** प्रोत्साहन, सहायता और मार्गदर्शन के माध्यम से कारीगरों को सशक्त बनाना, उनके कौशल, आजीविका और समग्र कल्याण को बढ़ाना।
- **सांस्कृतिक विनियमन:** सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय दौरों, अनुसंधान अध्ययनों, व्याख्यानों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और अन्य सहयोगी गतिविधियों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना जो अंतर-सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देते हैं।
- **पहचान और ज्ञान:** सदस्यों की विविध सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पृष्ठभूमियों और परंपराओं को स्वीकार करते हुए, शिल्पकारों के काम की व्यापक मान्यता और ज्ञान की दिशा में काम करना।
- **परामर्श एवं सहयोग:** सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में शिल्प की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकारों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, समाजों और व्यक्तियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना।
- **सतत विकास:** पारंपरिक शिल्प को समसामयिक संदर्भों में एकीकृत करके, सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर सतत विकास में योगदान करना।
- **मुख्यालय रोटेशन:** संगठनात्मक उपनियमों का पालन करते हुए, प्रत्येक चार वर्ष में राष्ट्रपति पद के सुचारू रोटेशन को सुनिश्चित करना, जिससे नेतृत्व में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा मिले।

3. डब्ल्यूसीसी के अंतर्गत भारतीय शहर

- मामल्लापुरम, भारत
- जयपुर, भारत
- मैसूर, भारत

4. वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के उद्देश्य

- **वैश्विक पहचान:** विशिष्ट शिल्प विषयों, कच्चे माल अथवा विभिन्न प्रकार के शिल्पों में विशेषज्ञता वाले रचनात्मक शहरों/क्षेत्रों की प्रतिष्ठा और संपत्तियों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना।
- **सरकारी समर्थन:** निर्दिष्ट शहरों/क्षेत्रों में शिल्प के विकास के लिए सरकारी समर्थन और भविष्य की प्रतिबद्धताओं को प्रोत्साहित करना।
- **स्थानीय नवाचार:** नवाचार के लिए स्थानीय क्षमता को मजबूत करना और रचनात्मक पर्यटन के विकास को बढ़ावा देना।
- **ज्ञान का आदान-प्रदान:** राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शिल्प क्षेत्रों में जानकारी, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
- **सहयोगात्मक अवसर:** नामित शिल्प शहरों के बीच सहयोग और साझेदारी के नए अवसर पैदा करना।

ब्रेन बूस्टर

टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

विश्व, टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम (EPI- Expanded Programme on Immunization) के शुभारंभ का 50वाँ वर्ष मना रहा है, जिसे डब्ल्यूएचओ द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य चेचक उन्मूलन की गति को आगे बढ़ाते हुए दुनिया भर के बच्चों के लिए जीवन रक्षक टीकों तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना था।

1. ईपीआई का इतिहास

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 1974 में टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम शुरू किया गया था।

2. ईपीआई का प्रभाव

- पिछले 50 वर्षों में अनुमानित 154 मिलियन लोगों की जान बचाई गई।
- शिशु मृत्यु दर में 40% से अधिक की कमी आई।
- लाखों लोगों को विकलांगता से बचाया गया।
- लाखों अनावश्यक मौतों को रोका गया, खासकर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में।
- स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत किया गया और बीमारियों को रोका गया, जिससे आर्थिक लाभ हुआ।

3. प्रमुख उपलब्धियाँ

- 1980 में चेचक का उन्मूलन।
- बाल टीकाकरण कार्यक्रमों का वैश्विक विस्तार।
- एक मजबूत टीका आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना।
- पोलियो में 99% से अधिक की कमी।
- हिब, न्यूमोकोकल, रोटावायरस, एचपीवी, मेनिन्जाइटिस ए, जापानी इंसेफेलाइटिस और मलेरिया के टीकों सहित नए टीकों की शुरूआत।

4. वर्तमान स्थिति

- प्रत्येक देश में एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम होता है।
- टीकों को सबसे सुरक्षित, सबसे अधिक लागत प्रभावी और सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में से एक माना जाता है।
- डब्ल्यूएचओ राष्ट्रीय ईपीआई कार्यक्रमों के लिए जीवन भर में 13 टीकों की सिफारिश करता है।

5. ईपीआई और भारत

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 1974 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम (ईपीआई) शुरू किया गया था और भारत में इसे 1978 में शुरू किया गया था।
- यूआईपी: सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) 1985 में शुरू किया गया था, जो ईपीआई का विस्तार था।

6. यूआईपी की मुख्य विशेषताएं

- यूआईपी का उद्देश्य छह वैक्सीन-निवारणीय रोगों से होने वाली मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना है।
- इसमें स्थानीय वैक्सीन उत्पादन क्षमता में सुधार, कोल्ड चेन की स्थापना, निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली और अन्य पहल शामिल हैं।
- यूआईपी 2005 में अपनी स्थापना के बाद से भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभिन्न अंग रहा है।
- यूआईपी सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है, जिसका लक्ष्य सालाना 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचाना है।

7. यूआईपी के तहत प्रदान किए जाने वाले टीके

- यूआईपी 12 टीका-निवारक रोगों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है: डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, और मेनिनजाइटिस और निमोनिया जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होता है।
- उप-राष्ट्रीय स्तर पर, यह रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करता है।

ब्रेन बूस्टर

भारतीय मसाला उद्योग

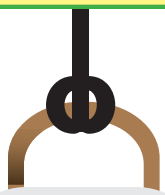

चर्चा में क्यों?

भारतीय मसालों में एथिलीन ऑक्साइड (ETO) की उच्च मात्रा पाई गई है, जो एक जहरीला रसायन है जिसका उपयोग खाद्य स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। इसके उपयोग के कारण सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका सहित कई देशों में जांच प्रक्रिया कर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ETO की मौजूदगी ने भारतीय मसालों (एमडीएच, एवरेस्ट) में संदूषण के बारे में चिंता जताई है, जिससे कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

1. एथिलीन ऑक्साइड क्या है?

यह एक कैंसर पैदा करने वाला कीटनाशक है जिसका उपयोग खाद्य स्टेबलाइजर और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।

2. उठाए गए कदम

- केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने सिंगापुर और हांगकांग स्थित भारतीय दूतावासों को तकनीकी विवरण, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और उन निर्यातकों का विवरण भेजने का निर्देश दिया है, जिनकी खेपें खारिज कर दी गई हैं।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत मसाला क्षेत्र के लिए नोडल निकाय, भारतीय मसाला बोर्ड, प्रतिबंध के कारणों का अलग से पता लगा रहा है।
- सिंगापुर और हांगकांग को भेजे जाने वाले मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की अनिवार्य जांच के मुद्दे पर चर्चा के लिए उद्योग परामर्श निर्धारित किया गया है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के मद्देनजर देश भर से सभी ब्रांडों के पाउडर के रूप में मसालों के नमूने लेना शुरू कर दिया है।

3. निहितार्थ

- वैश्विक मसाला महाशक्ति के रूप में भारत की प्रतिष्ठा जांच के दायरे में है।
- निर्यात में अभी कमी नहीं आई है, लेकिन निर्यात पर जांच का प्रभाव अभी भी देखा जाना बाकी है।
- छोटे और मध्यम आकार के किसानों को मांग में उतार-चढ़ाव और नए सुरक्षा उपायों को लागू करने से जुड़ी लागतों के कारण आय में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है।
- भारतीय मसालों की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे उपभोक्ता का विश्वास और ब्रांड निष्ठा प्रभावित हो सकती है।

4. विभाजन

उत्पाद विभाजन:

- शुद्ध मसाले (65% बाजार हिस्सेदारी)
- मिश्रित मसाले (30% बाजार हिस्सेदारी)
- मसाला अर्क और सुगंध (5% बाजार हिस्सेदारी)

अनुप्रयोग विभाजन:

- खाद्य और पेय पदार्थ (80% बाजार हिस्सेदारी)
- सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल (10% बाजार हिस्सेदारी)
- फार्मास्यूटिकल्स (5% बाजार हिस्सेदारी)
- अन्य (5% बाजार हिस्सेदारी)

5. रुझान और चालक

- जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की बढ़ती मांग।
- ऑनलाइन शॉपिंग की बढ़ती लोकप्रियता।
- मसालों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से बढ़ती मांग।

6. चुनौतियाँ

- कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव
- गुणवत्ता नियंत्रण के मुद्दे
- तीव्र प्रतिस्पर्धा
- मिलावट और संदूषण
- विनियामक चुनौतियाँ

ब्रेन बूस्टर

प्लास्टिक संधि

चर्चा में क्यों?

वैश्विक प्लास्टिक संधि की दिशा में वार्ता का चौथा सत्र, जो 23-29 अप्रैल, 2024 को कनाडा के ओटावा में हुआ, मिश्रित परिणामों के साथ समाप्त हुआ। वार्ता के द्वारा निर्णायक संधि का मसौदा नहीं बन पाया, और देश एक ऐसे मसौदा के साथ जा रहे हैं जो वर्ष के अंत में अंतिम वार्ता के लिए अभी तैयार नहीं है।

1. प्लास्टिक संधि के बारे में

- **वैश्विक प्लास्टिक संधि:** 175 देशों ने 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते का उद्देश्य प्लास्टिक उत्पादन, उपयोग और निपटान से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।
- **अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC):** INC ने 2022 की दूसरी छमाही के दौरान अपना काम शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2024 के अंत तक वार्ता पूरी करना है। पाँचवाँ सत्र (INC-5) 25 नवंबर से 1 दिसंबर, 2024 तक कोरिया गणराज्य के बुसान में निर्धारित है।
- **ऐतिहासिक संकल्प:** मार्च 2022 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-5) के फिर से शुरू हुए पाँचवें सत्र में, समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यवस्था विकसित करने के लिए एक ऐतिहासिक संकल्प अपनाया गया था।
- **प्लास्टिक प्रदूषण संकट:** प्लास्टिक प्रदूषण का तेजी से बढ़ता स्तर एक गंभीर वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे का प्रतिनिधित्व करता है जो सतत विकास के पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य आयामों पर नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।
- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA):** UNEA वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।

2. प्लास्टिक संधि का महत्व

- **वैश्विक प्रयासों को एकीकृत करना:** यह प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए देशों, संगठनों और हितधारकों को एक साझा ढांचे के तहत साथ लाता है।
- **वैश्विक लक्ष्य और मानक निर्धारित करना:** यह संधि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने, प्लास्टिक के सतत उपयोग को बढ़ावा देने और रीसाइक्लिंग को बढ़ाने के लिए साझा लक्ष्य, लक्ष्य और दिशा-निर्देश स्थापित करती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना:** यह प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने के लिए देशों के बीच सहयोग, ज्ञान साझाकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देता है।
- **विकासशील देशों का समर्थन करना:** यह संधि विकासशील देशों को प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रीसाइक्लिंग प्रणाली लागू करने में मदद करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
- **सतत विकास को बढ़ावा देना:** प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करके, संधि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेष रूप से एसडीजी 14 (पानी के नीचे जीवन) और एसडीजी 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन) को प्राप्त करने में योगदान देती है।

- **जागरूकता और शिक्षा को बढ़ाना:** संधि के कार्यान्वयन से प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ेगी और प्लास्टिक के सतत उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- **नवाचार और परिपत्र अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना:** संधि का ध्यान प्लास्टिक के सतत उपयोग और पुनर्चक्रण पर है, जो नवाचार और परिपत्र अर्थव्यवस्था प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देगा।
- **मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना:** यह मानव स्वास्थ्य, समुद्री जीवन और पर्यावरण पर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा।
- **वैश्विक शासन और नीति समन्वय का समर्थन करना:** संधि अंतर्राष्ट्रीय नीति समन्वय की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट के लिए अधिक प्रभावी और एकजुट प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी।
- **अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों के लिए एक मिसाल कायम करना:** प्लास्टिक संधि की सफलता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से अन्य दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है।

ब्रेन बूस्टर

3. संधि के निहितार्थ

- संधि में दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण को काफी हद तक कम करने की क्षमता है।
- संधि सतत प्लास्टिक उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है, जिससे कचरे को कम करने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है।
- संधि पुनर्चक्रण और सतत प्लास्टिक उद्योगों में नए आर्थिक अवसर पैदा कर सकती है।
- प्लास्टिक संधि वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

4. प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में

- प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे का संचय और वितरण है, जिसमें महासागर, जलमार्ग, भूमि और जीवित जीव शामिल हैं।
- प्लास्टिक प्रदूषण तब होता है जब प्लास्टिक सामग्री, जैसे बैग, बोतलें, माइक्रोबीड्स और अन्य सिंथेटिक सामग्री का उचित तरीके से निपटान नहीं किया जाता है और वे पर्यावरण में समा जाते हैं।
- यह प्रदूषण पर्यावरण, वन्यजीवों और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है और इसके महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रभाव होते हैं।

5. प्लास्टिक प्रदूषण के प्रकार

- **समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण:** महासागरों और जलमार्गों में प्लास्टिक अपशिष्ट, समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाता है।
- **भूमि-आधारित प्लास्टिक प्रदूषण:** भूमि पर प्लास्टिक अपशिष्ट, जिसमें कूड़ा, माइक्रोप्लास्टिक और प्लास्टिक का मलबा शामिल है।
- **माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण:** छोटे प्लास्टिक कण (5 मिमी से कम) जो छोटे समुद्री जानवरों द्वारा निगले जाते हैं और खाद्य श्रृंखला में अपना रास्ता बनाते हैं।
- **प्लास्टिक मलबा:** बड़ी प्लास्टिक वस्तुएँ, जैसे बोतलें, बैग और अन्य डिस्पोजेबल प्लास्टिक, जो पर्यावरण में जमा हो जाती हैं।

6. प्लास्टिक प्रदूषण के कारण

- एकल-उपयोग प्लास्टिक
- उचित अपशिष्ट प्रबंधन का अभाव
- कूड़ा-कचरा और खराब निपटान की आदतें
- औद्योगिक गतिविधियाँ, जैसे प्लास्टिक उत्पादन और विनिर्माण
- कृषि प्लास्टिक का उपयोग, जैसे मल्च और सिंचाई पाइप

7. समाधान

- **कम करें (Reduce):** प्लास्टिक उत्पादन और खपत को कम करें, विशेष रूप से एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को।
- **पुन: उपयोग (Reuse):** बैग, कंटेनर और पानी की बोतलों जैसे पुन: प्रयोज्य उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करें।
- **पुनर्चक्रण (Recycle):** प्लास्टिक रीसाइक्लिंग दरों को बढ़ाने के लिए रीसाइक्लिंग बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकियों में सुधार करें।
- **शिक्षा और जागरूकता:** प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभावों और टिकाऊ प्रथाओं की आवश्यकता के बारे में व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को शिक्षित करें।
- **सहयोग और भागीदारी:** वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए सरकारों, व्यवसायों और संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा दें।

8. 2023 में भारत में प्लास्टिक प्रदूषण

- **157 दिनों में प्लास्टिक ओवरशूट:** वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में भारत को 2023 में 157 दिनों तक प्लास्टिक ओवरशूट का सामना करना पड़ा।
- **कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक (MWI):** भारत का MWI 98.55% है, जो प्लास्टिक अपशिष्ट कुप्रबंधन के उच्च स्तर को दर्शाता है।
- **अपेक्षित कुप्रबंधित अपशिष्ट:** 2023 में अपेक्षित कुप्रबंधित अपशिष्ट लगभग 7,300,752 टन प्लास्टिक था।
- **कुल प्लास्टिक खपत:** भारत की कुल प्लास्टिक खपत 7,408,124 टन प्लास्टिक अपशिष्ट है।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट निर्यात और आयात:** भारत निर्यात के माध्यम से 59,260 टन प्लास्टिक अपशिष्ट का योगदान देता है, जो इसके कुल अपशिष्ट का 0.8% है, और 98,860 टन आयात करता है, जो इसके कुल अपशिष्ट का 1.33% है।
- **उत्सर्जित माइक्रोप्लास्टिक:** भारत जलमार्गों में 330,764 टन माइक्रोप्लास्टिक छोड़ता है।
- **रासायनिक योजक प्रदूषण:** अपशिष्ट प्रबंधन के कुप्रबंधन के कारण रासायनिक योजकों से 44,535 टन प्रदूषण होता है।
- **वैश्विक रैंकिंग:** भारत उन 12 देशों में शामिल है जो दुनिया के कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के 52% के लिए जिम्मेदार हैं।

स्मार्ट (SMART) सिस्टम

चर्चा में क्यों?

1 मई, 2024 को भारत ने ओडिशा के तट से दूर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल-असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो (SMART-स्मार्ट) का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल-आधारित हल्के वजन वाली टॉरपीडो डिलीवरी प्रणाली है, जिसे डीआरडीओ द्वारा भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को हल्के वजन वाले टॉरपीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है।

1. स्मार्ट के बारे में

स्मार्ट एक कैनिस्टर-आधारित मिसाइल प्रणाली है जिसमें कई उन्नत उप-प्रणालियाँ शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:

- दो-चरणीय ठोस प्रणोदन प्रणाली
- इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्ट्यूएटर प्रणाली
- सटीक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली

2. मुख्य विशेषताएं

- लंबी दूरी की मिसाइल वाहक जो सुपरसोनिक गति से यात्रा कर सकती है।
- पेलोड के रूप में हल्का टारपीडो।
- डेटालिंक के माध्यम से मध्य-पाठ्यक्रम अपडेट के साथ जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली।
- ध्वनिक होमिंग (सक्रिय/निष्क्रिय)।
- मिसाइल की रेंज 643 किमी (400 मील) है, जो 50 किलोग्राम उच्च विस्फोटक वारहेड के साथ 20 किमी (12.5 मील) की रेंज का हल्का टारपीडो ले जाती है।

3. कार्य

- युद्धपोत या ट्रक-आधारित तटीय बैटरी से लॉन्च किए जाने पर SMART, एक नियमित सुपरसोनिक मिसाइल की तरह उड़ान भरता है।
- हवाई या युद्धपोत पनडुब्बी लक्ष्य पहचान प्रणाली से दो-तरफा डेटा लिंक के द्वारा कम ऊंचाई पर हवा में अपनी अधिकांश उड़ान को कवर करता है।
- दुश्मन पनडुब्बी की सटीक अवस्थिति प्रदान करता है ताकि बीच में ही उसके उड़ान पथ को सही किया जा सके।
- जैसे ही यह डूबी हुई पनडुब्बी के काफी करीब पहुंचती है, मिसाइल टॉरपीडो प्रणाली को पानी में फेंक देगा है और स्वायत्त टॉरपीडो पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर देगा।

4. लाभ

- **लंबी दूरी की क्षमता:** स्मार्ट भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं का विस्तार करता है, जिससे पारंपरिक टारपीडो रेंज से अधिक दूरी पर पनडुब्बियों को निशाना बनाना संभव हो जाता है।
- **सुपरसोनिक गति:** मिसाइल की गति तैनाती के समय को कम करती है, जिससे पनडुब्बियों के लिए बच निकलना मुश्किल हो जाता है।
- **उन्नत मार्गदर्शन:** सिस्टम की मार्गदर्शन प्रणाली सटीक लक्ष्यीकरण और तैनाती को सक्षम बनाती है।
- **हैवीवेट टारपीडो:** शायना टारपीडो को पनडुब्बियों को निशाना बनाने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है।

5. चुनौतियाँ और सीमाएँ

- **विकास संबंधी जटिलताएँ:** सुपरसोनिक मिसाइल को टारपीडो के साथ एकीकृत करना महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- **लागत:** जटिलता और उन्नत प्रौद्योगिकी को देखते हुए यह प्रणाली महंगी होने की संभावना है।

6. निहितार्थ और महत्व

- **पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं में वृद्धि:** SMART भारत की नौसेना क्षमताओं को मजबूत करता है, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में।
- **प्रतिरोध:** प्रणाली की लंबी दूरी की क्षमता और सुपरसोनिक गति पनडुब्बी आधारित खतरों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध प्रदान करती है।
- **तकनीकी उन्नति:** स्मार्ट उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है।

ब्रेन बूस्टर

विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी

चर्चा में क्यों?

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया है कि भारत की गन्ना सब्सिडी उत्पादन के मूल्य के 10% के अनुमेय स्तर से अधिक हो गई है तथा अनुमान है कि वे लगातार चार वर्षों (2018-2022) के लिए उत्पादन के कुल मूल्य के 90% को पार कर गए हैं।

1. मुख्य चिंताएँ

- **घरेलू समर्थन:** भारत के उपायों को कृषि पर डब्ल्यूटीओ के समझौते, विशेष रूप से अनुच्छेद 7.2 (बी) के साथ असंगत माना गया, जो घरेलू समर्थन के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है।
- **बाजार मूल्य समर्थन:** चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान किए जाने वाले उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य-सलाह मूल्य (एसएपी) को डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा 'बाजार मूल्य समर्थन' माना जाता था, जो अतिरिक्त सब्सिडी में योगदान देता है।
- **निर्यात सब्सिडी:** भारत की निर्यात सब्सिडी भी डब्ल्यूटीओ के नियमों के साथ असंगत पाई गई, जो कृषि पर समझौते और सब्सिडी और प्रतिपूरक उपायों पर समझौते दोनों का उल्लंघन करती है।
- **पारदर्शिता की कमी:** यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने 1995-96 से घरेलू समर्थन अधिसूचनाओं में गन्ना या इसके डेरिवेटिव की रिपोर्टिंग में भारत की चूक को उजागर किया है, जिससे वैश्विक व्यापार विनियमों के साथ भारत के अनुपालन का आकलन करने की डब्ल्यूटीओ की क्षमता में बाधा आ रही है।

2. कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते के बारे में

- विश्व व्यापार संगठन के कृषि पर समझौते, विशेष रूप से अनुच्छेद 7.2 (बी), घरेलू समर्थन के लिए एक न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है, जो किसानों को व्यापार-विकृत किए बिना प्रदान की जा सकने वाली सहायता की राशि के लिए एक सीमा है।
- **न्यूनतम सीमा:** भारत सहित विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% पर न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है।
- विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान: विश्व व्यापार संगठन का विवाद निपटान तंत्र देशों को घरेलू समर्थन उपायों सहित एक-दूसरे की व्यापार प्रथाओं को चुनौती देने की अनुमति देता है।
- **व्यापार पर प्रभाव:** न्यूनतम सीमा का उद्देश्य घरेलू समर्थन उपायों द्वारा व्यापार को विकृत करने और अन्य देशों के कृषि क्षेत्रों को प्रभावित करने से रोकना है।
- **तीन बॉक्स:** विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते में घरेलू समर्थन को व्यापार को विकृत करने की उनकी क्षमता के आधार पर तीन बॉक्स हरे, नीले और एम्बर में वर्गीकृत किया गया है।

3. ग्रीन बॉक्स (गैर-व्यापार विकृत)

इसमें ऐसे समर्थन उपाय शामिल हैं जिन्हें गैर-व्यापार विकृत माना जाता है, जैसे:

- अनुसंधान और विकास
- कीट और रोग नियंत्रण
- खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम
- पर्यावरण कार्यक्रम
- पृथक आय समर्थन (उत्पादन या कीमतों से संबंधित नहीं)
- प्रदान की जाने वाली सहायता की मात्रा पर कोई सीमा नहीं

4. ब्लू बॉक्स (उत्पादन सीमित करने वाले)

इसमें ऐसे समर्थन उपाय शामिल हैं जिन्हें व्यापार-विकृत माना जाता है, लेकिन वे उत्पादन सीमाओं के अधीन हैं, जैसे:

- उत्पादन कोटा
- आपूर्ति प्रबंधन कार्यक्रम
- फसल चक्रण और विविधीकरण कार्यक्रम
- कृषि उत्पादन के मूल्य के 5% तक सीमित

5. एम्बर बॉक्स (व्यापार विकृत)

इसमें ऐसे समर्थन उपाय शामिल हैं जिन्हें व्यापार-विकृत माना जाता है, जैसे:

- मूल्य समर्थन
- आउटपुट सब्सिडी
- इनपुट सब्सिडी (जैसे, उर्वरक, बीज)
- विपणन सब्सिडी
- कटौती के अधीन प्रतिबद्धताएं और सीमाएं (उदाहरणार्थ, न्यूनतम सीमाएं)

ब्रेन बूस्टर

भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

चर्चा में क्यों?

आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार, चीन वित्त वर्ष 2023-24 में 118.4 बिलियन डॉलर के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है, जो अमेरिका से थोड़ा ही आगे है। 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 118.3 बिलियन डॉलर था।

1. मुख्य आँकड़े

- **भारत का माल निर्यात:** 2023 में $432 बिलियन, पिछले वर्ष की तुलना में 5% कम।
- **भारत का माल आयात:** 2023 में $673 बिलियन, पिछले वर्ष की तुलना में 7% कम।
- **वैश्विक माल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी:** 2023 में 1.8%।
- **वैश्विक माल आयात में भारत की हिस्सेदारी:** 2023 में 2.8%।
- **वैश्विक डिजिटल सेवाओं में भारत की हिस्सेदारी:** 2023 में 6%, 2019 में 4.4% था।
- **भारत का वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात:** 2023 में 4.4%, पिछले वर्ष की तुलना में 11% बढ़कर $344 बिलियन।
- **भारत का वैश्विक वाणिज्यिक सेवा आयात:** 2023 में $247 बिलियन पर स्थिर।

2. भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार

चीन:

- वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, जिसका दोतरफा व्यापार 118.4 बिलियन डॉलर रहा।
- वित्त वर्ष 2024 में चीन से आयात 3.24% बढ़कर 101.7 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि निर्यात 8.7% बढ़कर 16.67 बिलियन डॉलर हो गया।
- वित्त वर्ष 2019 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 53.57 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 85.09 बिलियन डॉलर हो गया।

संयुक्त राज्य अमेरिका:

- वित्त वर्ष 2024 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, जिसका दोतरफा व्यापार 118.3 बिलियन डॉलर रहा।
- वित्त वर्ष 2024 में अमेरिका को निर्यात 1.32% घटकर 77.5 बिलियन डॉलर रह गया, जबकि आयात 20% घटकर 40.8 बिलियन डॉलर रह गया।
- वित्त वर्ष 2019 में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 16.86 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 36.74 बिलियन डॉलर हो गया।

अन्य व्यापारिक साझेदार:

- यूएई: वित्त वर्ष 24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, जिसका दोतरफा वाणिज्य 83.6 बिलियन डॉलर है।

3. भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने की पहल

- **नई विदेश व्यापार नीति:** 2023 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और निर्यातकों के लिए व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। यह छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन, व्यापार करने में आसानी और उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित है।

- **ब्याज समानीकरण योजना:** यह योजना निर्यातकों को शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात ऋण प्रदान करती है। इसे 2500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के साथ 30 जून, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
- **निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना:** यह योजना व्यापार अवसंरचना विकसित करके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करती है।
- **बाजार पहुंच पहल योजना:** इस योजना का उद्देश्य निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देना है। यह बाजार अध्ययन और सर्वेक्षण के माध्यम से एक विशिष्ट बाजार और उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **राज्य और केंद्रीय शुल्क तथा करों की छूट योजना:** इस योजना का उद्देश्य श्रम-उन्मुख क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देना है।
- **निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट योजना:** इस योजना का उद्देश्य निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट देकर निर्यात को बढ़ावा देना है।

एमएसटीबी वैक्सीन MTBVAC

चर्चा में क्यों?

टीबी वैक्सीन MTBVAC को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति से चरण II नैदानिक परीक्षण करने की मंजूरी मिल गई है। यह वैक्सीन भारत में वयस्कों में नैदानिक परीक्षण शुरू करने वाली टीबी के खिलाफ मानव स्रोत से प्राप्त पहली वैक्सीन है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के सहयोग से बायोफैब्री द्वारा परीक्षण किया जाएगा।

1. MTBVAC के बारे में

MTBVAC मनुष्यों में क्षय रोग के खिलाफ एक टीका है, जो वर्तमान में अनुसंधान परीक्षण चरण में है। यह मनुष्यों से पृथक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रोगजनक के आनुवंशिक रूप से संशोधित रूप पर आधारित है।

2. विकास और विनिर्माण

- वैक्सीन का निर्माण पेरिस के पाश्चर इंस्टीट्यूट की डॉ. ब्रिगिट गिक्वेल के सहयोग से माइकोबैक्टीरियल जेनेटिक्स समूह की प्रयोगशाला में जरागोजा विश्वविद्यालय में किया गया था।
- वर्तमान में, जरागोजा विश्वविद्यालय के औद्योगिक साझेदार है: स्पेनिश जैव प्रौद्योगिकी कंपनी BIOFABRI, जो ZENDAL समूह से संबंधित है, MTBVAC के औद्योगिक और नैदानिक विकास के लिए जिम्मेदार है।

3. लाभ

- बीसीजी वैक्सीन का अधिक प्रभावी और लंबे समय तक चलने वाला विकल्प।
- मनुष्यों से पृथक रोगजनक के आनुवंशिक रूप से संशोधित रूप पर आधारित नैदानिक परीक्षणों में तपेदिक के खिलाफ एकमात्र टीका।

4. वित्तपोषण

- वैश्विक सार्वजनिक-निजी भागीदारी।
- यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल (IAVI) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान जैसे अमेरिकी संस्थानों द्वारा वित्त पोषित।

5. क्षय रोग के बारे में

- क्षय रोग (टीबी) एक संक्रामक रोग है जो अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करता है और एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होता है।
- यह संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने या थूकने से हवा के माध्यम से फैलता है।

6. लक्षण

टीबी के कई तरह के लक्षण हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- लंबे समय तक खांसी (कभी-कभी खून के साथ)
- सीने में दर्द
- कमजोरी
- थकान
- वजन कम होना
- बुखार
- रात में पसीना आना

7. उपचार

टीबी रोग का उपचार एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। टीबी संक्रमण और बीमारी दोनों के लिए उपचार की सिफारिश की जाती है। जिन आम एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है, वे निम्न हैं:

- आइसोनियाजिड
- रिफैम्पिन
- पाइराजिनामाइड
- एथमब्यूटोल
- स्ट्रेप्टोमाइसिन

8. भारत सरकार की पहल

- राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान
- निक्षय मित्र पहल
- संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र सदस्यता

चर्चा में क्यों?

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव के मसौदे के पक्ष में मतदान किया जिसमें कहा गया था कि फिलिस्तीन योग्य है और उसे संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और सिफारिश की कि सुरक्षा परिषद को इस मामले पर अनुकूल रूप से पुनर्विचार करना चाहिए।

1. मुख्य बिंदु

- प्रस्ताव को भारी समर्थन मिला, जिसमें भारत सहित 143 मत पक्ष में थे, जबकि 9 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया और 25 ने मतदान में भाग नहीं लिया।
- प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन की योग्यता को स्वीकार किया गया है और सुरक्षा परिषद से ष्इस मामले पर अनुकूल तरीके से पुनर्विचार करनेष् की सिफारिश की गई है।
- फिलिस्तीन के लिए भारत का ऐतिहासिक समर्थन 1974 से शुरू होता है, जब यह फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब राज्य बन गया था।
- भारत 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था और 1996 में गाजा में एक प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया, बाद में इसे 2003 में रामल्लाह में स्थानांतरित कर दिया।
- भारत ने फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया है और उचित समय पर इसके समर्थन की उम्मीद जताई है।

2. कोई देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कैसे बनता है?

- **सदस्यता:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कहा गया है कि सदस्यता उन सभी शांतिप्रिय राज्यों के लिए खुली है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित दायित्वों को स्वीकार करते हैं और संगठन के निर्णय के अनुसार इन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हैं।
- **आवेदन:** सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय द्वारा राज्यों को संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए भर्ती किया जाता है।
- **सुरक्षा परिषद:** प्रवेश के लिए किसी भी सिफारिश को परिषद के 15 सदस्यों में से 9 के सकारात्मक वोट प्राप्त होने चाहिए, बशर्ते कि इसके पांच स्थायी सदस्यों में से किसी ने भी आवेदन के खिलाफ मतदान न किया हो।
- **आम सभा:** किसी नए राज्य के प्रवेश के लिए विधानसभा में दो-तिहाई बहुमत का वोट आवश्यक है।
- **सदस्यता प्रभावी:** सदस्यता उस तिथि से प्रभावी हो जाती है जिस दिन प्रवेश के लिए प्रस्ताव अपनाया जाता है।

3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के संकल्प

प्रक्रियात्मक संकल्प: ये संकल्प परिषद के कार्य संचालन से संबंधित हैं, जैसे एजेंडा सेटिंग, बैठक कार्यक्रम और प्रक्रियात्मक मामले।

मूल संकल्प: ये संकल्प विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करते हैं, जैसे:

- **अध्याय VI:** विवादों का शांतिपूर्ण समाधान (जैसे, युद्ध विराम, वार्ता)।
- **अध्याय VII:** शांति के लिए खतरों, शांति के उल्लंघन और आक्रामकता के कृत्यों (जैसे, प्रतिबंध, बल के प्राधिकरण) के संबंध में कार्रवाई।
- **अध्याय VIII:** शांति और सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय व्यवस्था।
- अध्याय VII के तहत पारित प्रस्तावों को सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी माना जाता है, जबकि अध्याय VI के तहत पारित किए गए गैर-बाध्यकारी होते हैं।

प्रक्रियात्मक मामलों पर निर्णय

- प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय नौ सदस्यों के सकारात्मक वोट द्वारा किए जाएंगे।

अन्य मामलों पर निर्णय

- अन्य सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों के सहमति मतों सहित नौ सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिए जाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 मई 2024 को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थीम: 'योजना का हिस्सा बनें'

1. उद्देश्य

जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सभी हितधारकों को कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना।

2. इतिहास

- अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की स्थापना 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति द्वारा की गई थी।
- प्रारंभ में, यह 29 दिसंबर को मनाया जाता था, जिस दिन जैव विविधता पर कन्वेंशन लागू हुआ था।
- हालांकि, 20 दिसंबर, 2000 को, 1992 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कन्वेंशन को अपनाने के उपलक्ष्य में तिथि बदलकर 22 मई कर दी गई।

3. महत्व

- जैव विविधता सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है और वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करती है।
- यह महासागरों, समुद्रों, जंगलों, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, सतत विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ज्ञान-साझाकरण, क्षमता निर्माण, शहरी लचीलापन, सतत परिवहन, मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखा और जल एवं स्वच्छता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

4. अभियान

- जैव विविधता योजना अभियान 19 दिसंबर, 2023 को कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के 4 लक्ष्य और 23 टारगेट को दुनिया तक पहुँचाने और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
- अभियान का उद्देश्य सरकार और समाज के समग्र दृष्टिकोण को सहमति से कार्रवाई की ओर ले जाना है।

5. कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जीबीएफ के बारे में

- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा (जीबीएफ) दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के 15वें सम्मेलन (सीओपी15) में अपनाया गया एक वैश्विक समझौता है।
- इस ढांचे का उद्देश्य वैश्विक जैव विविधता संकट का समाधान करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है।

6. जीबीएफ के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं

चार लक्ष्य:

- **लक्ष्य ए:** पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बनाए रखना और बहाल करना
- **लक्ष्य बी:** सतत उपयोग और न्यायसंगत लाभ सुनिश्चित करना
- **लक्ष्य सी:** जैव विविधता हानि के कारणों को संबोधित करना
- **लक्ष्य डी:** कार्यान्वयन और समर्थन को बढ़ाना

23 टारगेट्स, जिनमें शामिल हैं:

- 2030 तक दुनिया की 30% भूमि, महासागर और जल की सुरक्षा करना। जैव विविधता पर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना।
- टिकाऊ कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन प्रथाओं को सुनिश्चित करना। टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देना

7. जैव विविधता क्या है?

- जैव विविधता पौधों, जानवरों, सूक्ष्मजीवों और पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न प्रजातियों की विविधता को संदर्भित करता है जो एक पर्यावरण के भीतर या पूरी पृथ्वी पर मौजूद हैं।
- इसमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता और विभिन्न प्रजातियों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया भी शामिल है।

ब्रेन बूस्टर

दक्षिण अमेरिका की भौगोलिक विशेषताएँ

दक्षिण अमेरिका एक विशाल और विविधतापूर्ण महाद्वीप है, जो 17.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं को मोटे तौर पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. पहाड़

- **एंडीज पर्वत श्रृंखला:** पश्चिमी किनारे पर वेनेजुएला से चिली तक फैली हुई है।
- **ब्राजील के हाइलैंड्स:** ब्राजील के अधिकांश भाग को कवर करते हैं।
- सिएरा नेवादा डी सांता मार्टा (कोलंबिया)।
- कॉर्डिलेरा ओरिएंटल (कोलंबिया, वेनेजुएला और इक्वाडोर)।

2. पठार

- **अल्टीप्लानो:** एंडीज में एक उच्च पठार, जो पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर और चिली के कुछ हिस्सों को कवर करता है।
- **गुयाना शील्ड:** उत्तरी दक्षिण अमेरिका में, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना को कवर करता है।

3. तराई

- **अमेजन बेसिन:** दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो दक्षिण अमेरिका के 40% से अधिक क्षेत्र को कवर करता है।
- **पराना-पैराग्वे बेसिन:** दक्षिणी ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना में।

4. तटरेखाएँ

- **प्रशांत तट:** एंडीज के साथ, ऊबड़-खाबड़ तटों और सुंदर समुद्र तटों की विशेषता।
- **अटलांटिक तट:** पूर्वी समुद्र तट के साथ, रेतीले समुद्र तटों और तटीय मैदानों के साथ।

5. नदियां

- **अमेजन नदी:** डिस्चार्ज वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी, जो ब्राजील, पेरू और अन्य देशों से होकर बहती है।
- **पराना नदी:** ब्राजील और पैराग्वे के बीच की सीमा का हिस्सा बनती है।
- **साओ फ्रांसिस्को नदी:** पूर्वी ब्राजील में।

6. द्वीप

- **गैलापागोस द्वीप:** इक्वाडोर के तट से दूर, अनोखे वन्यजीवों के लिए जाना जाता है।
- **फॉकलैंड द्वीप (माल्विनास):** दक्षिण अटलांटिक में विवादित क्षेत्र।

7. जलवायु क्षेत्र

- **उष्णकटिबंधीय:** भूमध्य रेखा के पास, अमेजॅन बेसिन और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भागों को कवर करते हुए।
- **समशीतोष्ण:** दक्षिणी क्षेत्रों में, जिसमें चिली, अर्जेंटीना और दक्षिणी ब्राजील शामिल हैं।
- **रेगिस्तान:** पश्चिमी पेरू और चिली (अटाकामा रेगिस्तान) में।

8. प्राकृतिक संसाधन

- **खनिज:** लौह अयस्क, तांबा, सोना, चांदी और टिन।
- **ऊर्जा:** तेल, प्राकृतिक गैस और जलविद्युत शक्ति।

9. झरने

- इगुआजू फॉल्स (अर्जेंटीना और ब्राजील)
- एंजेल फॉल्स (वेनेजुएला)

10. रेगिस्तान

- अटाकामा रेगिस्तान (चिली)
- पैटागोनिया रेगिस्तान (अर्जेंटीना और चिली)

11. मैदान

- पम्पास (अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील)
- लानोस (कोलंबिया और वेनेजुएला)

12. दक्षिण अमेरिका की कुछ उल्लेखनीय भौगोलिक विशेषताओं में शामिल हैं

- एंडीज पर्वत श्रृंखला, दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है।
- अमेजन वर्षावन, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है।
- इगाजु फॉल्स, दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक हैं।
- अटाकामा रेगिस्तान, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थानों में से एक माना जाता है।
- गैलापागोस द्वीप समूह, एक अद्वितीय और जैव विविधता वाला द्वीपसमूह है।
- इस विविध भूगोल ने महाद्वीप की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र को आकार दिया है, जिसमें कई देश विकास के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं।

चर्चा में रहे प्रमुख स्थल

इरीट्रिया

हाल ही में, भारत और इरिट्रिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श (FOC) का दूसरा दौर नई दिल्ली में हुआ।

- इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है। यह देश पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इरिट्रिया को लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद 1993 में इथियोपिया से स्वतंत्रता मिली।
- इरिट्रिया की सीमाएँ लाल सागर (उत्तर-पूर्व और पूर्व), सूडान (पश्चिम), इथियोपिया (दक्षिण) और जिबूती (दक्षिण-पूर्व) के साथ साझा होती है।

भौतिक विशेषताऐं:

- इरिट्रिया का सबसे ऊँचा स्थान माउंट सोइरा है, जिसे सोइरा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है।
- इरिट्रिया में कुछ मौसमी नदियाँ और धाराएँ हैं जो बरसात के मौसम में बहती हैं, जिनमें एंसेबा नदी और बरका नदी शामिल हैं।
- इरिट्रिया खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें सोना, तांबा, जस्ता, पोटाश और अन्य खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार हैं।
- देश की कुछ उल्लेखनीय खनिज परियोजनाओं में बिशा खदान शामिल है, जो दुनिया में उच्चतम श्रेणी की खुली खदान वाली तांबे की खदानों में से एक है।

ताम जा ब्लू होल

शोधकर्ताओं ने मेक्सिको के चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है, जिसका नाम ताम जा ब्लू होल (TJBH) है।

ताम जा ब्लू होल (TJBH) के बारे में:

- ताम जा ब्लू होल (TJBH) नामक स्थान को अब दुनिया में सबसे गहरे ज्ञात पानी के नीचे के सिंकहोल के रूप में पहचाना जाता है।
- मापों से पता चलता है कि ताम जा ब्लू होल समुद्र तल से कम से कम 1,380 फीट (420 मीटर) नीचे तक फैला हुआ है, जिसके तल तक अभी पहुँचा नहीं जा सका है।
- नया पाया गया सबसे गहरा ब्लू होल युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी तट से दूर चेतुमल खाड़ी में स्थित है।

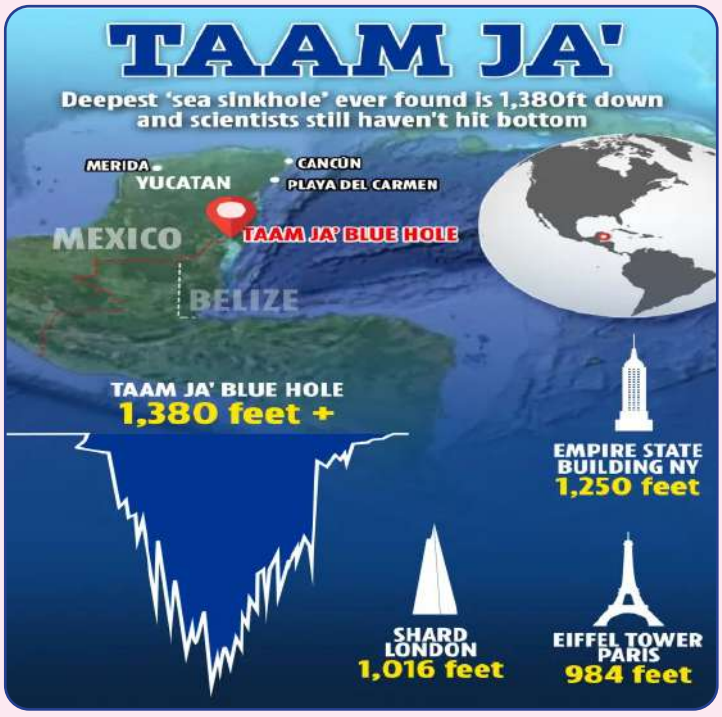

ब्लू होल के बारे में:

- ब्लू होल तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पानी से भरे ऊर्ध्वाधर गुफाएँ हैं जहाँ आधारशिला में चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसी घुलनशील सामग्री होती है।

बटागाइका क्रेटर

वैज्ञानिकों ने हाल ही में पाया है कि बटागाइका क्रेटर हर साल सक्रिय रूप से बढ़ रहा है।

बटागाइका क्रेटर के बारे में:

- बटागाइका क्रेटर रूस के सुदूर पूर्व में सखा गणराज्य में स्थित चेर्स्की रेंज क्षेत्र में एक थर्मोकार्स्ट अवसाद है, जो 100 मीटर तक की गहराई तक पहुँचता है।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर है, जो एक किलोमीटर लंबा है।
- इस संरचना का नाम पास के बटागाइका के नाम पर रखा गया है, जो याना नदी की एक दाहिनी सहायक नदी है।
- 1960 के दशक में आसपास के जंगल साफ होने के बाद पिघलते पर्माफ्रॉस्ट के कारण भूमि डूबने लगी थी।

शक्सगाम घाटी

हाल ही में, भारत ने शक्सगाम घाटी में चीन के द्वारा सड़क निर्माण गतिविधियों को लेकर चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है, इसे भारत ने जमीनी स्तर पर स्थिति को बदलने का 'अवैध' प्रयास माना है।

शक्सगाम घाटी के बारे में:

- शक्सगाम घाटी (कंकड़ का सूखा हुआ ढेर), जिसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट के रूप में भी जाना जाता है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के हुंजा-गिलगित क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
- यह एक विवादित क्षेत्र है जिस पर भारत का दावा है लेकिन पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित है।
- इसे पाकिस्तान ने 1963 के सीमा समझौते में इसे चीन को सौंप दिया था।
- शक्सगाम घाटी उत्तर में चीन के झिंजियांग प्रांत, दक्षिण और पश्चिम में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उत्तरी क्षेत्रों और पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र (भारतीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा) से लगती है।
- चीन ने शक्सगाम के माध्यम से गिलगित को होटन से जोड़ने वाली फीडर सड़कों का निर्माण किया है, जहाँ पर तिब्बत-झिंजियांग और होटन-गोलमुद राजमार्गों के चौराहे पर एक महत्त्वपूर्ण सैन्य मुख्यालय है।

मोल्दोवा

भारत और मोल्दोवा ने हाल ही में राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

मोल्दोवा के बारे में:

- मोल्दोवा यूरोप के बाल्कन क्षेत्र के उत्तरपूर्वी क्षेत्र और कार्पेथियन पर्वत के पूर्व में स्थित एक भूमि से घिरा हुआ देश है। इसकी राजधानी चिसीनाउ है जोकि देश के दक्षिण-मध्य भाग में है।
- सीमावर्ती देश: यूक्रेन (उत्तर, पूर्व और दक्षिण) और रोमानिया (पश्चिम)।
- उत्तर में, मोल्दोवा के परिदृश्य में समतल बाल्टी स्टेपी और वैसोकाया हिल पर समाप्त होने वाली ऊंची भूमि शामिल हैं।
- इस ऊपरी भूमि में मेडोबोरी-टोल्ट्री नामक चूना पत्थर की चोटियां हैं, जो प्रुत नदी के साथ बहती हैं, जोकि डेन्यूब नदी की एक सहायक नदी है। यह देश के अंतिम दक्षिणी सिरे पर मिलती है।

प्रमुख नदियाँ:

- मोल्दोवा में नदियों और धाराओं का एक सुविकसित नेटवर्क है, जिसका जल दक्षिण में ब्लैक सागर में बहता हैं।
- इयालपग, कोगलनिक और अन्य छोटी दक्षिणी नदियाँ बड़े पैमाने पर यूक्रेन के पास के डेन्यूब के मुहाने में बहती हैं।
- मोल्दोवा की मुख्य जल नदी नीस्टर नदी, दक्षिण-पश्चिमी यूक्रेन और मोल्दोवा से होकर बहती है। यह दक्षिण और पूर्व में काला सागर में बहती है।
- इसका उदगम कार्पेथियन पर्वत के उत्तर में हैं।

कांकेसंथुराई बंदरगाह

हाल ही में श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने उत्तरी प्रांत में कांकेसंथुराई बंदरगाह के नवीनीकरण को मंजूरी दी, जिसमें भारत ने परियोजना को 61.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की निधि देने पर सहमति व्यक्त की।

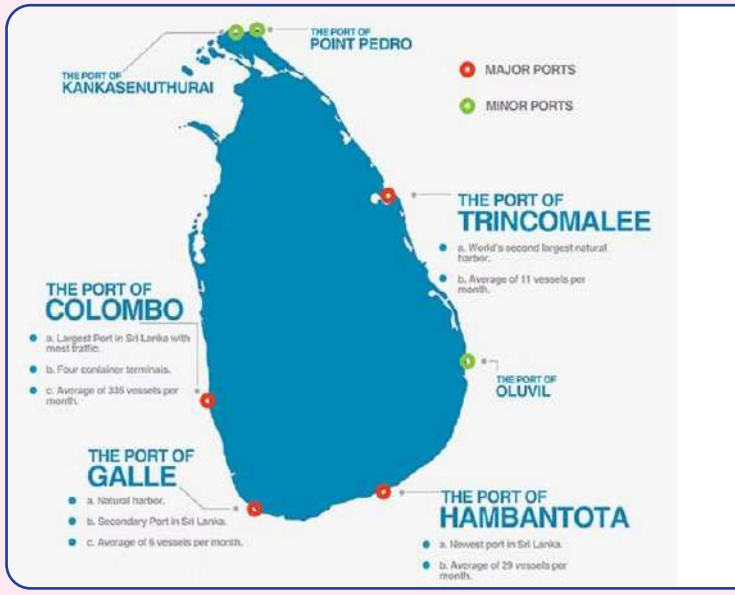

कांकेसंथुराई बंदरगाह के बारे में:

- कांकेसंथुराई बंदरगाह, जिसे केकेएस बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है।
- यह लगभग 16 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और पांडिचेरी के कराईकल बंदरगाह से 104 किलोमीटर (56 समुद्री मील) की दूरी पर स्थित है।
- तमिलनाडु के नागपट्टिनम को जाफना के पास कांकेसंथुराई बंदरगाह से जोड़ने वाली सीधी यात्री जहाज सेवा लगभग साढ़े तीन घंटे में 111 किलोमीटर (60 समुद्री मील) की दूरी तय करती है।
- यह बंदरगाह जाफना प्रायद्वीप के उत्तरी तट पर, प्वाइंट पेड्रो के करीब स्थित है, जो श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु है।
- बंदरगाह की दिशा उत्तर की ओर होने के कारण हिन्द महासागर में स्थित बंगाल की खाड़ी को देखा जा सकता हैं।

राज्य आधारित करेंट अफेयर्स

बिहार करेंट अफेयर्स

काँवर झील

हाल के दिनों में एशिया की सबसे बड़ी अलवण जल युक्त गोखुर झील और बिहार की एकमात्र रामसर स्थल काँवर धीरे-धीरे लुप्त हो रही है।

मुख्य बिंदु:

- गोखुर झील (Oxbow Lake) एक वक्राकार झील है जो समय के साथ क्षरण और अवसादों के निक्षेपण के परिणामस्वरूप विसर्पी नदी के किनारे बनती है।
- गोखुर झीलें सामान्यत: अर्द्धचंद्राकार होती हैं जो नदियों के पास बाढ़ के मैदानों एवं निचले इलाकों में पाई जाने वाली भू-स्थलाकृतियाँ हैं।
- कभी लोकप्रिय पर्यटन स्थल रही काँवर झील अतिक्रमण का शिकार हो गई है और जिसका अस्तित्त्व संकट में है।
- भूमि के अनियंत्रित विस्तार और निकटवर्ती बूढ़ी गंडक नदी के किनारे तटबंधों के निर्माण ने आर्द्रभूमि में मुख्य जल प्रवेश बिंदु को अवरुद्ध कर दिया है।
- एक साझा धारणा है कि झील के पुनर्भरण करने की सरकारी पहल के साथ, इसमें अपनी पिछली भव्यता को पुन: प्राप्त करने और एक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल में बदलने की क्षमता है, जो स्थानीय निवासियों के लिये नए रोजगार की संभावनाएँ प्रदान करता है।

जकार्ता फ्यूचर्स फोरम में बिहार पर्यावरण सचिव का संबोधन

हाल ही में भारत और बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग (DoEFCC) की सचिव बंदना प्रेयाशी ने इंडोनेशिया में प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम में संबोधित किया।

मुख्य बिंदु:

- 'न्यायसंगत और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन की सुविधा के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' शीर्षक वाली पैनल चर्चा में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) के महासचिव इंद्र मणि पांडे तथा इंडोनेशिया के ऊर्जा व खनिज संसाधन मंत्रालय के तहत नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण महानिदेशक प्रोफेसर एनिया लिस्टियानी डेवी शामिल थे।
- अपने संबोधन में सचिव ने भारत द्वारा अपनी विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिये गैर-जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर 40% का लक्ष्य हासिल करना और 'जलवायु सहनीय एवं निम्न कार्बन विकास पथ' के विकास में बिहार राज्य की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों पर भी जोर दिया है।
- विद्युत उत्पादन के लिये भारत ने निर्धारित समय से कुछ समय पूर्व (मूल रूप से वर्ष 2023 तक लक्षित) ही गैर-जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता 40% तक कम कर लेने की क्षमता हासिल करके संयुक्त राष्ट्र की पार्टियों का सम्मेलन (COP) 21 पेरिस शिखर सम्मेलन में की गई अपनी प्रतिबद्धता को पार कर लिया है।
- देश नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता (बड़ी जलविद्युत उत्पादन संयंत्र सहित) में विश्व स्तर पर चौथे स्थान, पवन ऊर्जा क्षमता में भी चौथे स्थान और सौर ऊर्जा क्षमता में पाँचवें स्थान पर है (REN21 नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक स्थिति-2023 रिपोर्ट के अनुसार)।
- कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में भारत के सक्रिय कदमों पर जोर दिया गया, जिसमें वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता, वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता शामिल है।
- बिहार ने राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है।
- बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (BREDA) नवीकरणीय ऊर्जा नीति-2024 विकसित कर रही है।
- बिहार देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिये जलवायु सहनीय और निम्न कार्बन विकास पथ विकसित किया है।
- राज्य जलवायु परिवर्तन पर बिहार राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप दे रहा है। ये नीतियाँ राज्य में ऊर्जा परिवर्तन का भी समर्थन करती हैं।
- सचिव ने देशों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढाँचे को सुदृढ़ करने, विकासशील देशों के लिये समर्थन बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ऊर्जा परिवर्तन प्रभावित श्रमिकों एवं समुदायों की जरूरतों को पूरा करता है।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री का निधन

हाल ही में वरिष्ठ राजनेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। वह कैंसर से पीड़ित थे।

मुख्य बिंदु:

- वह वर्ष 2005 से 2013 और वर्ष 2017 से 2020 तक बिहार के उपमुख्यमंत्री के साथ-साथ बिहार के वित्त मंत्री भी रहे।
- वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन सदस्य रहे।

- उन्हें जुलाई वर्ष 2011 में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के लिये राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

उपमुख्यमंत्री:

- भारत में उपमुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि किसी पार्टी के भीतर सहयोगियों या गुटों को खुश करने के लिये एक राजनीतिक व्यवस्था है।
- वह रैंक और भत्तों के मामले में एक कैबिनेट मंत्री के समतुल्य होता है लेकिन उसके पास कोई विशिष्ट वित्तीय या प्रशासनिक शक्तियाँ नहीं होती हैं।
- उपमुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना होता है और अपने पोर्टफोलियो से संबंधित किसी भी निर्णय के लिये उसकी स्वीकृति लेनी होती है।
- उपमुख्यमंत्री के पास उन फाइलों या मामलों तक पहुँच नहीं है जो मुख्यमंत्री के लिये हैं।
- अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164(1) में स्पष्ट रूप से उप मुख्यमंत्री की स्थिति का उल्लेख नहीं है।
- अनुच्छेद 163(1) राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद की स्थापना का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 164(1) नियुक्ति प्रक्रिया की रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।

छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स

SAIL-भिलाई द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना

राज्य संचालित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की छत्तीसगढ़ स्थित शाखा, भिलाई स्टील प्लांट (BSP), अपने कार्बन में सुधार के लिए राज्य की पहली 15-मेगावाट (MW) फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित करेगी।

मुख्य बिंदु:

- यह परियोजना NTPC-SAIL पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (NSPCL) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) और SAIL की एक 50:50 साझेदारी वाली संयुक्त उद्यम कंपनी है। सोलर प्लांट दुर्ग जिले में स्थापित किया जाएगा।
- मरोदा जलाशय का क्षेत्रफल 2.1 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जल भंडारण क्षमता 19 घन मिलीमीटर (MM3) है।
- मरोदा-I जलाशय में संग्रहीत जल न केवल संयंत्र को बल्कि टाउनशिप को भी जल आपूर्ति करता है।
- इस संयंत्र से अनुमानित कुल हरित विद्युत ऊर्जा उत्पादन लगभग 34.26 मिलियन यूनिट सालाना होने की संभावना है।
- इस परियोजना से भिलाई स्टील प्लांट के CO_2 उत्सर्जन में सालाना 28,330 टन की कमी आने की उम्मीद है।

कार्बन फुटप्रिंट:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) के अनुसार, कार्बन फुटप्रिंट जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की मात्रा पर लोगों की गतिविधियों के प्रभाव का एक माप है और इसे कई टन में उत्पादित CO_2 उत्सर्जन के भार के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- इसे आमतौर पर प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले कई टन CO_2 के रूप में एक संख्या में (जिसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों सहित कई टन CO_2-समतुल्य गैसों द्वारा पूरक किया जा सकता है) मापा जाता है।
- यह एक व्यापक उपाय हो सकता है या किसी व्यक्ति, परिवार, घटना, संगठन या यहाँ तक कि पूरे देश के कार्यों पर लागू किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के कार्यकर्त्ता को मिलेगा ग्रीन नोबेल

हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसे "ग्रीन नोबेल पुरस्कार" के रूप में भी जाना जाता है, यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियन का सम्मान करता है।

मुख्य बिंदु:

- उन्हें पर्यावरण की रक्षा के लिये उनके संघर्षों और पहलों के लिये चुना गया है, जिसमें मध्य भारत के सबसे सघन वनों में से एक हसदेव अरण्य भी शामिल है, जो 170,000 हेक्टेयर तक फैला हुआ है, जिसमें 23 कोयला ब्लॉक हैं। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मानित किया जाएगा।
- उन्होंने आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में 21 नियोजित कोयला खदानों से 445,000 एकड़ जैवविविधता से समृद्ध वनों को बचाने के लिये अडानी खनन के खिलाफ अभियान चलाने के लिये स्वदेशी समुदायों और कोयला खनन से प्रभावित लोगों को सफलतापूर्वक अभियान चलाया तथा संगठित किया।
- वर्ष 2009 में, पर्यावरण मंत्रालय ने हसदेव अरण्य को उसके समृद्ध वन क्षेत्र के कारण खनन के लिये 'नो-गो' क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया, लेकिन इसे खनन हेतु फिर से खोल दिया। हसदेव अरण्य को खनन मुक्त बनाने के लिये CBA ने लगातार

संघर्ष किया।

हसदेव अरण्य वन:

- छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में फैला हुआ हसदेव अरण्य वन क्षेत्र अपनी जैवविविधता और कोयला भंडार के लिये जाना जाता है।
- यह वन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण आदिवासी आबादी वाले जिलों कोरबा, सुजापुर और सरगुजा के अंतर्गत आता है।
- महानदी की सहायक नदी हसदेव यहाँ से प्रवाहित होती है।
- हसदेव अरण्य मध्य भारत का सबसे बड़ा अखंडित वन है जिसमें प्राचीन साल (शोरिया रोबस्टा) और सागौन के वन शामिल हैं।
- यह एक प्रसिद्ध प्रवासी गलियारा है, जिसमें हाथियों की महत्त्वपूर्ण उपस्थिति है।

ग्रीन नोबेल पुरस्कार:

- गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार (जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है) अक्सर बड़े व्यक्तिगत जोखिम पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्द्धन हेतु निरंतर तथा महत्त्वपूर्ण प्रयासों के लिये व्यक्तियों को मान्यता देता है।
- यह वर्ष 1990 से गोल्डमैन एनवायर्नमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- यह विश्व के छह महाद्वीपीय क्षेत्रों के लोगों का सम्मान करता है: अफ्रीका, एशिया, यूरोप, द्वीप एवं द्वीप राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण एवं मध्य अमेरिका।
- गोल्डमैन पुरस्कार 'जमीनी स्तर' के नेताओं को स्थानीय प्रयासों में शामिल लोगों के रूप में देखता है, जहाँ उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों में समुदाय या नागरिक की भागीदारी के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन किया जाता है।
- गोल्डमैन पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता सामान्यत: पृथक् गाँवों या सुदूर शहरों के लोग होते हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिये बड़े व्यक्तिगत जोखिम उठाना चुनते हैं।
- विजेताओं की घोषणा पृथ्वी दिवस पर की जाती है जो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है।

CCI ने लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दी

हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के पूर्ण अधिग्रहण के लिए अदानी समूह की सहायक कंपनी अदानी पावर लिमिटेड को मंजूरी दे दी। इस अधिग्रहण में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड की 100% इक्विटी शेयर पूंजी का अदानी पावर लिमिटेड को हस्तांतरण शामिल है।

मुख्य बिंदु:

- अडानी पावर लिमिटेड (अधिग्रहणकर्त्ता), अडानी समूह का एक हिस्सा जो भारत के कानूनों के तहत निगमित कंपनी है।
- यह भारत में ताप विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है।
- यह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश सहित भारत के कई राज्यों में ताप विद्युत संयंत्र संचालित करती है।
- अडानी समूह एक वैश्विक एकीकृत बुनियादी ढाँचा कंपनी है, जो प्रमुख उद्योग क्षेत्रों संसाधनों, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा में कारोबार करती है।
- लैंको समूह का एक हिस्सा लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड (लक्ष्य) भारत में ताप विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है।
- यह वर्तमान में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) से गुजर रहा है।
- प्रस्तावित संयोजन अधिग्रहणकर्त्ता द्वारा लक्ष्य की 100% इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण से संबंधित है।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI):

- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिये उत्तरदायी है। इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था।
- राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP Act), 1969 को निरस्त कर इसे प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016:

- इसे भारत के आर्थिक इतिहास में सबसे बड़े शोधन अक्षमता सुधारों में से एक माना जाता है।
- इसे ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिये समयबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन तथा शोधन अक्षमता समाधान के लिये अधि नियमित किया गया था।

कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP):

- भारत में CIRP, IBC द्वारा शासित एक समयबद्ध प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अपनी संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करते हुए कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय संकट को हल करना है।
- इस प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय रूप से संकटग्रस्त कंपनी का पुनरुद्धार सुनिश्चित करना है और ऐसे मामलों में जहाँ कंपनी का पुनरुद्धार संभव नहीं है, यह संकटग्रस्त कंपनी की संपत्ति का व्यवस्थित परिसमापन सुनिश्चित करता है जिसे कॉर्पोरेट देनदार घोषित किया गया है।

राजस्थान राज्य करेंट अफेयर्स

सरिस्का टाइगर रिजर्व

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट क्षेत्रों में की जा रही सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (CTH) के एक किलोमीटर के दायरे में किसी

भी खनन गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

प्रमुख बिंदु:

- न्यायालय ने राजस्थान सरकार से गतिविधियों को बंद करने की योजना बनाने या उसके आदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है।
- न्यायालय के अनुसार, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 38XA से पता चलता है कि व्याघ्र अभयारण्य पर वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में अधिक ध्यान दिया जाता है।

सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में:

- सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली पर्वतमाला में स्थित है जो राजस्थान के अलवर जिले का एक हिस्सा है।
- सरिस्का को वर्ष 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में वर्ष 1978 में इसे व्याघ्र अभयारण्य घोषित किया गया, जिससे यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया।
- इस रिजर्व में खंडहर हो चुके मंदिर, किले, मंडप और एक महल हैं।

वनस्पति और जीव:

- यह रिजर्व वनस्पतियों और जीवों में बेहद समृद्ध है तथा रॉयल बंगाल टाइगर के लिये प्रसिद्ध है।
- पार्क में तेंदुए, नीलगाय, साँभर, चीतल आदि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं।

राजस्थान की डिजिटल हेल्थकेयर एक्सेस प्रणाली

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करने के लिये डिजिटलीकरण के साथ एक नई एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिये तैयार है।

मुख्य बिंदु:

- नई ऑनलाइन प्रणाली स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड एवं एकल खिड़की प्रक्रियाओं की सुविधाएँ तैयार करेगी।
- परियोजना को जल्द-से-जल्द पूरा किया जाएगा और इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिये संबंधित विभाग एवं एजेंसियाँ पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करेंगी।
- ऑनलाइन प्रणाली के एक हिस्से के रूप में, आम लोगों और स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुँचने वाले मरीजों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड की सुविधा, डिजी-स्वास्थ्य लॉकर, कतार के झंझट से मुक्ति, एकीकृत डिजिटल सर्वेक्षण, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) आधारित डैशबोर्ड, टेली-मेडिसिन गहन देखभाल इकाई, जियोटैगिंग आधारित अस्पताल मानचित्र, स्वास्थ्य संबंधी लाइसेंस और नॉ-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिये एकल खिड़की प्रक्रियाओं की सुविधा मिलेगी।
- नई प्रणाली के कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेंसी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग शामिल हैं।

डिजिटल जल वितरण प्रणाली

हाल ही में सिंचाई जल की आपूर्ति की सुविधा के लिये राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में कृषि क्षेत्रों के लिये एक अनूठी डिजिटल जल वितरण प्रणाली शुरू की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) जयपुर द्वारा विकसित नई प्रणाली किसानों को उनके खेतों तक पहुँचने वाले जल की स्थिति के बारे में जानने में सक्षम बनाएगी और मैन्युअल प्रणाली में अक्सर रिपोर्ट की जाने वाली मानवीय त्रुटि की गुंजाइश को कम करेगी।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म जिले के सभी किसानों को जल की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर से जल वितरित करने में पारदर्शिता बढ़ाएगा।
- जल संसाधन विभाग के अनुसार जल उपयोक्ता संघों के प्रमुख अपने-अपने क्षेत्र के किसानों की जानकारी पोर्टल पर केवल एक बार दर्ज करेंगे। इसके बाद किसानों को सिंचाई बारी की पर्चियाँ स्वत: ऑनलाइन मिल जाएंगी।
- ऑनलाइन 'बाराबंदी' (निश्चित बारी) का विस्तार किया जा सकता है और राज्य के अन्य जिलों में भी किसानों के लाभ के लिये एक समान जल वितरण प्रणाली के रूप में कार्यान्वित किया जा सकता है।

राजस्थान में बाल विवाह

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य में कोई भी बाल विवाह न हो और यदि ऐसे विवाह होते हैं तो ग्राम प्रधान एवं पंचायत सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- न्यायालय का आदेश 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया त्योहार से पहले आया, क्योंकि राजस्थान में अक्षय तृतीया पर कई बाल विवाह संपन्न होते हैं।
- न्यायालय ने बाल विवाह को रोकने के लिये न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करने वाली जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस की जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के बावजूद राज्य में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं।
- यदि सरपंच और पंच लापरवाही से बाल विवाह को रोकने में विफल रहते हैं तो उन्हें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 11 के तहत जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अनुसार बाल विवाह को प्रतिबंधित करने का दायित्व सरपंच को दिया गया हैं।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006:

- इस अधिनियम ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 का स्थान लिया जो ब्रिटिश काल के दौरान लागू किया गया था।
- बाल विवाह में बच्चे का तात्पर्य 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष और 18 वर्ष से कम उम्र की महिला से है।

उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स

पीलीभीत टाइगर रिजर्व

हाल ही में वन अधिकारियों ने एक तेंदुए को पकड़ा जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से भटककर अलीगंज गाँव में आ गया था।

प्रमुख बिंदु:

- पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के तीन जिलों-पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराईच में फैला हुआ है।
- इसका क्षेत्रफल 700 वर्ग किमी. से अधिक है और यह तेंदुओं व बाघों सहित विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का निवास स्थल है।
- यह ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है।
- रिजर्व का उत्तरी किनारा भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है जबकि दक्षिणी सीमा शारदा और खकरा नदी द्वारा चिह्नित है।

तेंदुए के बारे में:

- यह एक रात्रिचर जानवर है जो जंगली सूअर, हॉग हिरण एवं चीतल सहित अपने क्षेत्र में छोटे शाकाहारी जानवरों को खाता है।
- तेंदुओं में मेलेनिज्म एक आम घटना है, जिसमें जानवर की पूरी त्वचा काले रंग की होती है, जिसमें उसके धब्बे भी शामिल हैं।
- मेलेनिस्टिक तेंदुए को प्राय: ब्लैक पैंथर कहा जाता है।

प्राकृतिक आवास:

- यह उप-सहारा अफ्रीका में पश्चिमी और मध्य एशिया के छोटे हिस्सों एवं भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिण-पूर्व तथा पूर्वी एशिया तक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है।
- भारतीय तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस फुस्का) भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाने वाला तेंदुआ है।

खतरा:

- खाल एवं शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के लिये अवैध शिकार।
- पर्यावास हानि एवं विखंडन
- मानव-तेंदुआ संघर्ष

संरक्षण की स्थिति:

- IUCN रेड लिस्ट: संवेदनशील
- CITES: परिशिष्ट-I
- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

सीडीएस

हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने प्रयागराज स्थित भारतीय वायु सेना के मध्य वायु कमान के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्हें मध्य वायु कमान के परिचालनात्मक पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। मध्य वायु कमान भारतीय वायु सेना की पाँच परिचालन कमानों में से एक है। इसका मुख्यालय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। इसका गठन 19 मार्च 1962 को रानी कुठी, कलकत्ता में हुआ था।

सीडीएस के बारे में:

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सशस्त्र बलों का प्रमुख और सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है।
- रक्षा प्रमुख सेना का मुख्य कार्यकारी होता है जिसके पास रक्षा बलों पर परिचालन और रणनीतिक अधिकार होता है
- वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) हैं जिन्हें 28 सितंबर, 2022 को नियुक्त किया गया था।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारियां:

- थल सेना, वायु सेना और नौसेना का संयुक्त अभियान।
- हथियार खरीद प्रक्रियाओं का मानकीकरण।
- संयुक्त कमांडरों और स्टाफ समिति के कमांडिंग ऑफिसर और अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।
- तीनों सेनाओं में बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।

अयोध्या के जिलाधिकारी नितीश कुमार का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज

अयोध्या के जिलाधिकारी नितीश कुमार का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। यह सम्मान उन्हें सरयू नदी में सबसे बड़ा तैरता हुआ स्वीप मतदाता जागरूकता लोगो स्थापित कराने के लिए दिया गया।

अवध विश्वविद्यालय के विवेकानंद प्रेक्षागृह में आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह में जिलाधिकारी को मैडल एवं प्रमाण पत्र सौंपकर सम्मानित किया।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चित्रकला प्रदर्शनी

हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय (Faculty of Visual Arts) द्वारा चार दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी 'योगसूत्र' का आयोजन किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- प्रदर्शनी में पेंटिंग विभाग के चार छात्रों- जयदेव दास, नॉडी ज्यूडिथ गोम्ज, फराज इमरान और निहारिका अहोना बरसात की कलात्मक

प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें लगभग 25 पेंटिंग प्रदर्शित की गई हैं।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में:

- इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में डॉ. एनी बेसेंट जैसी महान हस्तियों के सहयोग से की थी, जिन्होंने भारत के विश्वविद्यालय के रूप में इसकी कल्पना की थी।
- यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित शिक्षा का मंदिर है, जो पवित्र शहर वाराणसी में स्थित है।
- विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित संग्रहालय-भारत कला भवन, दुर्लभ संग्रहों का खजाना है।
- विश्वविद्यालय का 927 बिस्तरों वाला अस्पताल सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।

यमुना ई-वे से दूर के क्षेत्रों में भवन निर्माण योजनाएँ

हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम (BPMS) नामक एक प्रणाली शुरू की है, जो 34,000 से अधिक आवासीय भू-खंड मालिकों को अनुमोदन के लिये अपनी भवन योजना ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाती है।

प्रमुख बिंदु:

- प्राधिकरण के अनुसार, बिल्डिंग परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम (BPMS) का उद्देश्य प्रसंस्करण अनुप्रयोगों के लिये तेज, पारदर्शी और कुशल समाधान प्रदान करके भवन मानचित्रों के लिये अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण:

- इसे उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के तहत दिल्ली के निकटवर्ती उनके संबंधित अधिसूचित क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास के लिये बनाया गया है, जो अगर योजनाबद्ध नहीं होते, तो अनधिकृत शहरी विकास का खतरा होता।

प्रयागराज में बनेगी दूसरी SSH लैब

हाल ही में प्रयागराज में जल्द ही दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब (SSH लैब) स्थापित किया जाने वाला है, जो डेंगू वायरस के निदान के लिये एक महत्त्वपूर्ण सुविधा केंद्र होगा।

मुख्य बिंदु:

- वर्तमान में, प्रयागराज जिले में केवल मोती लाल नेहरू (MLN) मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थित एक SSH लैब है।
- राष्ट्रीय डेंगू दिवस (16 मई 2024) मनाने के लिये मोती लाल नेहरू कॉलेज में आयोजित एक कार्यशाला में इस बात पर चर्चा की गई कि वर्ष 2024 के अंत से पहले तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, जिसे बेली अस्पताल भी कहा जाता है, में एक विशेष डेंगू परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है।
- डेंगू दिवस- 2024 की थीम 'Connect with the community and control dengue-' अर्थात् समुदाय से जुड़ना और डेंगू को नियंत्रित करना था।

डेंगू के बारे:

- डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस (जीनस फ्लेवीवायरस) के कारण होती है, इसका प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडीज (Genus Aedes) प्रजातियों, मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी (Aedes Aegypti) द्वारा होता है
- यह मच्छर चिकनगुनिया, पीला बुखार (Yellow fever) और जीका संक्रमण भी फैलाता है।
- डेंगू को उत्पन्न करने वाले चार अलग-अलग परंतु आपस में संबंधित सीरोटाइप (सूक्ष्मजीवों की एक प्रजाति के भीतर अलग-अलग समूह जिनमें एक समान विशेषता पाई जाती है) DEN-1, DEN-2, DEN-3 और DEN-4 हैं।

लक्षण:

- अचानक तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आँखों में दर्द, हड्डी, जोड़ और मांसपेशियों में तेज दर्द आदि।

निदान और उपचार:

- डेंगू संक्रमण का निदान रक्त परीक्षण से किया जाता है।
- डेंगू संक्रमण के उपचार के लिये कोई विशिष्ट दवा नहीं है।

झारखंड करेंट अफेयर्स

NGT ने झारखंड में थर्मल पावर प्लांट को नोटिस जारी किया

हॉल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) ने अप्रैल 2024 में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक यूनिट में लगी भीषण आग के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

प्रमुख बिंदु:

- यह संयंत्र, देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC की कोयला आधारित 660X3 मेगावाट इकाई जाँच के दायरे में थी।
- अधिकरण या ट्रिब्यूनल ने इस मुद्दे के लिये संयंत्र के प्रशासनिक प्रमुख, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) के सदस्य सचिवों के साथ-साथ विभिन्न अधिकारियों को शामिल किया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT):

- यह पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं शीघ्र निपटान के लिये

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम (2010) के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है।

- NGT की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण (Specialised Environmental Tribunal) स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा (और पहला विकासशील) देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी।
- NGT को आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटान करने का आदेश दिया गया है।
- NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं।

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC):

- NTPC 68,961.68 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है और वर्ष 2032 तक 130 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करने की योजना है।
- कंपनी नवोन्मेषी पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के साथ कई ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को अनुकूलित करके एक सतत् तरीके से प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर विश्वसनीय विद्युत का उत्पादन करने के लिये प्रतिबद्ध है, इस प्रकार NTPC राष्ट्र के आर्थिक विकास और समाज के उत्थान में योगदान दे रहा है।

पहाड़िया जनजाति

झारखंड में पहाड़िया समुदाय के लोगों को अब खेती करने के लिए बीज खरीदने की जरूरत नहीं होती है। वे अपने पारंपरिक बीजों से ही अच्छी उपज हासिल कर रहे हैं और इससे उनके पैसों की बचत भी हो रही है। झारखंड की पहाड़िया जनजाति का लक्ष्य समुदाय के नेतृत्व वाले बैंकों में देशी किस्मों को जमा करके बीज स्वतंत्रता प्राप्त करना है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2019 में, पाकुड़ और गोड्डा के पहाड़ी जिलों में चार समुदाय-आधारित बीज बैंक स्थापित किये गए थे। बैंक 90 गाँवों में 1,350 से अधिक परिवारों को सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- वे चार पंचायतों के अंतर्गत संचालित होते हैं: बारा पकतरी, बारा सिंदरी, कुंजबोना और कर्मा तरन तथा महिला नेतृत्व वाली समितियों द्वारा प्रबंधित किये जाते हैं।
- बीज बैंकों में पंजीकरण कराने के लिये सदस्यों को 2.5 किलोग्राम देशी बीज जमा करना होगा। राज्य सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से भी बीज उपलब्ध कराये जाते हैं।
- बुआई के मौसम के दौरान, समितियाँ मामले-दर-मामले के आधार पर वितरण का निर्णय लेती हैं। अब तक वे 3,679 किलोग्राम बीज वितरित कर चुके हैं।
- सदस्य वर्तमान में स्टॉक को फिर से भरने के लिये प्रत्येक फसल के बाद 0.5 किलोग्राम बीज प्रदान करते हैं।

पहाड़िया जनजाति के बारे में:

- वे मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में रहते हैं। वे राजमहल पहाड़ियों के मूल निवासी हैं, जिन्हें आज झारखंड के संताल परगना डिवीजन के रूप में जाना जाता है।
- उन्हें पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड की सरकारों द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- वे माल्टो बोलते हैं, जो एक द्रविड़ भाषा है।
- वे झूम कृषि करते हैं जिसमें कुछ वर्षों तक कृषि के लिये वनस्पति जलाकर भूमि साफ करना शामिल है।

उत्तराखंड करेंट अफेयर्स

कुमाऊँ फैन पाम संरक्षणाधीन

कुमाऊं पाम, जिसे कुमाऊं फैन पाम के नाम से भी जाना जाता है, को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के प्रयास में उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग ने पातालथौड़ नर्सरी, पिथौरागढ़ में इस स्थानिक पौधे के 300 पौधों की खेती करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मुख्य बिंदु:

- यह शून्य से भी कम तापमान में जीवित रहने वाली एकमात्र ताड़ की प्रजाति है और इसे दुनिया की सबसे कठोर ताड़ कहा जाता है।
- वन अनुसंधान विंग के अनुसार, पौधों की प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) और उत्तराखंड जैवविविधता बोर्ड दोनों द्वारा 'संकटग्रस्त' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कुमाऊँ फैन पाम:

- ताड़ का पेड़ उत्तर-पश्चिमी भारत में उत्तराखंड प्रांत के कुमाऊँ मंडल और निकटवर्ती पश्चिमी नेपाल में पाया जाता है।
- ताड़ 1,800-2,700 मीटर (5,900-8,900 फीट) की ऊँचाई पर उगता है और यह अपने मूल स्थान में नियमित आधार पर बर्फ तथा ठंड प्राप्त करता है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेचीकार्पस टाकिल (Trachycarpus takil) है।

शंभू नदी

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कुँवारी गाँव में शंभू नदी पर एक बार फिर लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है, जिससे स्थानीय लोग निकट आने वाली त्रासदी को लेकर चिंतित हैं।

मुख्य बिंदु:

- झील का यह पुनरुद्धार वर्ष 2022 और 2023 की पिछली घटनाओं की याद दिलाता है जब भू-स्खलन के कारण नदी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली तुलनीय संरचनाओं के कारण बहाव में संभावित बाढ़ को रोकने के लिये त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी।
- शंभू नदी बागेश्वर से निकलती है और चमोली जिले में पिंडर नदी

में मिल जाती है।

भीमताल झील के जलस्तर में कमी

हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित भीमताल झील का जल स्तर 22 मीटर से घटकर 17 मीटर हो गया है।

भीमताल झील के बारे में:

- भीमताल झील नैनीताल जिले की सबसे बड़ी झील है। यह कुमाऊँ क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसे ष्भारत का झील जिलाष कहा जाता है।
- यह एक प्राकृतिक झील है और इसकी उत्पत्ति का श्रेय भू-पर्पटी के खिसकने के कारण उत्पन्न हुए कई भ्रंश को दिया जाता है।
- इस झील का निर्माण वर्ष 1883 में ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था और इस पर चिनाई-बाँध (Masonry Dam) बनाया गया है।
- झील के चारों ओर समृद्ध वनस्पति और जैव पारिस्थितिकी तंत्र हैं साथ ही पहाड़ी ढलानों पर देवदार एवं ओक के घने वन हैं।
- सर्दियों के महीनों के दौरान यह कई प्रवासी पक्षियों का आवास होता है।
- क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रसिद्ध प्रजातियों में बुलबुल, वॉल क्रीपर, एमराल्ड डव, ब्लैक ईगल और टॉनी फिश आउल शामिल हैं।

मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स

भोपाल में पहला सिटी म्यूजियम

केंद्र सरकार ने भोपाल में पहले सिटी म्यूजियम की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड मोती महल के बाएं विंग में भोपाल सिटी संग्रहालय की स्थापना कर रहा है। यह परियोजना अद्वितीय है और इसका उद्देश्य विरासत और संस्कृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक पर्यटक व्याख्या केंद्र/नागरिक सहभागिता केंद्र बनाना है।

मुख्य बिंदु:

- 11 दीर्घाओं वाला प्रस्तावित संग्रहालय भोपाल और मध्य प्रदेश के समृद्ध इतिहास पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक संदर्भ तथा विशेष रूप से भोपाल के गठन को शामिल किया जाएगा।
- प्रागैतिहासिक शैल चित्रों, पत्थर के औजारों, पुरातात्त्विक खोजों, टिकटों, भोपाल तथा आसपास के क्षेत्रों के राजाओं एवं रानियों की पोशाक, प्राचीन मूर्तियाँ, मंदिर के अवशेष और भोपाल नवाब काल की उत्कृष्ट कला का संग्रह प्रदर्शित किया जाएगा।
- सभी आयु समूहों हेतु एक आकर्षक और जानकारीपूर्ण अनुभव बनाने के लिये आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय भोपाल के मोती महल के दाहिने हिस्से में परमार राजा भोज, उनके जीवन और कार्यों पर एक समर्पित तथा व्यापक संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- जनजातीय समुदाय की जीवनशैली को करीब से समझने तथा देखने के लिये भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में प्रदेश की सात प्रमुख जनजातियों गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, सहरिया और कोल के सात घर बनाए गए हैं।
- इस पहल का मकसद आदिवासी समाज से जुड़े मिथकों और मान्यताओं को खत्म करना है।

मोती महल के बारे में:

- मोती महल का निर्माण गढ़ मंडला के गोंड राजा हृदय शाह ने वर्ष 1651 से 1667 के बीच कराया था।
- महल भूलभुलैया, गुप्त सुरंगों और भूमिगत मार्गों से भरा है।

ओरछा वन्य जीव अभयारण्य में अवैध खनन

हाल ही में ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन में अवैध खनन के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित की गयी है। ओरछा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। जहां इन इकाइयों के संचालन से वहां की समृद्ध वनस्पतियों और जैवविविधता के लिए खतरा पैदा हो गया है।

मुख्य बिंदु:

- NGT के अनुसार, 337 टन रासायनिक अपशिष्ट के निपटान, भूजल प्रदूषण, पाइप से पानी की कमी और अनुमेय सीमा से अधिक लौह, मैंगनीज तथा नाइट्रेट सांद्रता की निगरानी के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी और यह एक बड़े वन क्षेत्र के भीतर स्थित है।
- यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा क्षेत्र में बेतवा नदी (यमुना की एक सहायक नदी) के पास स्थित है, जो इस अभयारण्य के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा जैवविविधता में योगदान देती है।

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) के तहत निर्धारित किया कि राज्य सरकारों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किमी. के भीतर आने वाली भूमि को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZs) अथवा पर्यावरण नाजुक क्षेत्र के रूप में घोषित करना चाहिये।

पावर पैक्ड न्यूज

हसदेव अरण्य आंदोलन

हाल ही में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक सदस्य आलोक शुक्ला को हसदेव अरण्य आंदोलन के लिए एशिया के 2024 गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

हसदेव अरण्य आंदोलन के बारे में:

- ❖ हसदेव अरण्य आंदोलन छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य क्षेत्र के आसपास के कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में एक जमीनी स्तर का पर्यावरण अभियान है।
- ❖ इस आंदोलन का उद्देश्य प्रस्तावित कोयला खनन परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों से हसदेव अरण्य के जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को बचाना था।
- ❖ सामुदायिक अभियानों और प्रयासों के माध्यम से, आंदोलन ने क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों की स्थापना को सफलतापूर्वक रोका, जिससे लगभग 445,000 एकड़ वनों का संरक्षण हुआ।
- ❖ जंगल महानदी की सहायक नदी हसदेव के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं, जो 741,000 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। यह क्षेत्र लगभग 15,000 आदिवासियों का आवास है जो अपनी आजीविका, सांस्कृतिक पहचान और जीविका के लिए हसदेव अरण्य वनों पर निर्भर हैं।
- ❖ हसदेव अरण्य कोयला भंडार से भी समृद्ध है, जिसके कारण सरकारों द्वारा खनन कार्य शुरू करने के प्रयास किए गए हैं।

गोल्डमैन पुरस्कार:

- ❖ पुरस्कार की स्थापना 1989 में रिचर्ड और रोंडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी।
- ❖ इस पुरस्कार का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए दुनिया भर के जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को पहचानना और सम्मानित करना है।
- ❖ यह छह क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण और मध्य अमेरिका और द्वीप और द्वीप राष्ट्र।
- ❖ गोल्डमैन पुरस्कार के प्रत्येक विजेता को उनके चल रहे पर्यावरणीय कार्यों और पहलों का समर्थन करने के लिए $200,000 का पुरस्कार मिलता है।

हैंगर क्लास पनडुब्बी

हाल ही में 26 अप्रैल को चीन के वुहान शिपयार्ड में पहली हैंगर क्लास पनडुब्बी लॉन्च की गई।

हैंगर क्लास पनडुब्बी के बारे में:

- ❖ हैंगर क्लास सबमरीन एक डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है जो चीन टाइप 039A युआन क्लास के निर्यात संस्करण का प्रतिनिधित्व करती है।
- ❖ इसे पाकिस्तान के लिए बनाया गया है जो 2028 तक इस श्रेणी की कुल आठ पनडुब्बियों को शामिल करने की पाकिस्तानी नौसेना की योजना की शुरुआत का प्रतीक है।
- ❖ इस पनडुब्बी का नाम पीएनएस हंगोर के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय युद्धपोत आईएनएस खुकरी को डुबाने के लिए प्रसिद्धि हासिल की थी।
- ❖ पनडुब्बी सतह या स्नॉर्कलिंग संचालन के लिए डीजल इंजन का उपयोग करती है, जबकि यह जलमग्न संचालन के लिए बैटरी चालित प्रणाली पर निर्भर करती है।
- ❖ एआईपी प्रणाली से सुसज्जित, पनडुब्बी पानी के भीतर अपनी शक्ति और अपनी गुप्त क्षमताओं को बढ़ा सकती है।
- ❖ यह 21 इंच के 6 टारपीडो ट्यूबों से युक्त है और 450 किमी की रेंज के साथ एंटी-शिप मिसाइलों और बाबर-3 सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता रखता है।
- ❖ भारत की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की तुलना में, हैंगर श्रेणी का आकार बड़ा है और इसमें एआईपी सिस्टम शामिल है, जो संभावित रूप से इसे पानी के भीतर शक्ति और छिपने की क्षमता के मामले में लाभ प्रदान करता है।

ईशान पहल

हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ISHAN (इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट) पहल पर काम शुरू किया है।

ईशान पहल के बारे में:

- ISHAN पहल भारत के खंडित हवाई क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है।
- ISHAN का उद्देश्य देश के चार उड़ान सूचना क्षेत्रों (FIR) दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई और उप-उड़ान सूचना क्षेत्रों को नागपुर स्थित एक इकाई में विलय करना है।
- ISHAN नागपुर में एक ही प्राधिकरण के तहत इन एफआईआर को एकीकृत करना चाहता है।
- इस समेकन का उद्देश्य भारतीय हवाई क्षेत्र में समन्वय को सुव्यवस्थित करके, भीड़भाड़ को कम करके और क्षमता में वृद्धि करके हवाई यातायात संचालन में दक्षता, सुरक्षा और निर्बाधता को बढ़ाना है।
- इस पहल का उद्देश्य परिचालन को सुव्यवस्थित करना, क्षमता बढ़ाना और भारतीय हवाई क्षेत्र में भीड़भाड़ को कम करना है, जिससे एयरलाइंस और यात्रियों दोनों को लाभ होगा।

शेनझोउ 17

हाल ही में, शेनझोउ-17 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का कैप्सूल तीन अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर छह महीने के मिशन को पूरा करने के बाद, उत्तरी चीन में डोंगफेंग लैंडिंग स्थल पर सुरक्षित रूप से उतरा।

शेनझोउ 17 के बारे में:

- शेनझोउ 17 एक चीन अंतरिक्ष यान है जो 26 अक्टूबर, 2023 को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया गया था।
- अंतरिक्ष यान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स (पीएलएएसी) के तीन अंतरिक्ष यात्रियों (तांग होंगबो, तांग शेंगजी और जियांग शिनलिन) को शेनझोउ अंतरिक्ष यान पर ले गया।
- चालक दल के प्राथमिक कार्यों में अंतरिक्ष चिकित्सा और प्रौद्योगिकी में प्रयोग करना, स्टेशन के अंदर एवं बाहर उपकरण स्थापित करना और रखरखाव करना शामिल है।
- चालक दल की औसत आयु 38 वर्ष है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे कम उम्र की टीम है।
- शेनझोउ 17 अंतरिक्ष यान लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट पर लॉन्च होने के लगभग 6.5 घंटे बाद तियांगोंग पहुंचा।

लाल कोलोबस बंदर

हाल ही में, एक अध्ययन से अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में लाल कोलोबस बंदरों के संरक्षण के महत्व का पता चला है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि उनका संरक्षण पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

लाल कोलोबस बंदर के बारे में:

- लाल कोलोबस बंदर (पिलियोकोलोबस एसपीपी) पुरानी दुनिया के बंदरों का एक समूह है जो भूमध्यरेखीय अफ्रीका के स्थानिक हैं।
- वे लाल नारंगी से लाल भूरे, काले या काले और सफेद रंग के होते हैं।
- उनके पास कोई अंगूठा नहीं होता है या केवल अवशेषी अंगूठा है और वे काले और सफेद कोलोबस बंदरों (जीनस कोलोबस) से निकटता से संबंधित हैं।
- वे अफ्रीकी बंदरों का सबसे खतरनाक समूह हैं, जिनकी प्रत्येक प्रजाति को 2020 में विलुप्त होने के खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- वे अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता में गिरावट के प्राथमिक संकेतक के रूप में कार्य करते हैं।
- बड़े शरीर वाले लाल कोलोबस बंदर के मांस की मांग अत्यधिक होने के कारण इनका शिकार होता है, जिससे अफ्रीकी जंगलों में तेजी से जनसंख्या में गिरावट आ रही है।

POCSO अधिनियम से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के उद्देश्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, भले ही बाल विवाह हो या पीड़ित नाबालिग अपने अपराधकर्ता से शादी करके अभियोजन से बचने की कोशिश करे।

POCSO अधिनियम के बारे में:

- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न और बाल अश्लीलता से बचाने के लिए संसद द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 पारित किया गया था।
- इसका संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- यह अधिनियम इन अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें भी स्थापित करता है।
- POCSO अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को 'व्यक्ति' के रूप में परिभाषित करता है, जो बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए लैंगिक-तटस्थ कानूनी ढांचा स्थापित करता है।
- यह विभिन्न प्रकार के यौन शोषण को परिभाषित करता है, जैसे प्रवेशक और अप्रवेशक हमला, साथ ही यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य।
- यह अधिनियम उन लोगों के लिए भी सजा का प्रावधान करता है जो यौन उद्देश्यों के लिए बच्चों की तस्करी करते हैं।
- 2019 में, गंभीर प्रवेशक यौन उत्पीड़न के लिए न्यूनतम सजा को सात साल से बढ़ाकर दस साल करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था।

THOTA, 1994

हाल ही में, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट (THOTA), 1994 के तहत एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

THOTA, 1994 के बारे में:

- ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट (THOTA) 1994 चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों और ऊतकों के निष्कासन, भंडारण और प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है।
- यह अधिनियम 4 फरवरी 1994 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था।
- इस अधिनियम का उद्देश्य मानव अंगों और ऊतकों में व्यावसायिक लेन-देन को रोकना है।
- यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अस्पतालों को नियंत्रित करने वाले नियमों को निर्धारित करता है और उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है।
- अधिकांश स्थितियों में, यह अधिनियम निकट संबंधियों जैसे भाई-बहनों, माता-पिता, बच्चों, जीवनसाथी, दादा-दादी और नाना-नानी और नाती-पोतियों से जीवित दान को अधिकृत करता है।
- अधिनियम मस्तिष्क स्टेम मृत्यु के बाद लगभग 37 विभिन्न अंगों और ऊतकों के दान की भी अनुमति देता है, जिसमें महत्वपूर्ण अंग जैसे कि गुर्दे, हृदय, यकृत और फेफड़े शामिल हैं।
- 2022 में, भारत में कुल 16,041 अंगों का दान किया गया, जिनमें गुर्दे सबसे अधिक दान किए जाने वाले अंग थे।
- दिल्ली में सबसे अधिक दान दर्ज किए गए, जहां 3,818 अंग दान किए गए।

साहित्य अकादमी फेलोशिप

हाल ही में प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड को उनके मसूरी स्थित आवास पर साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है।

साहित्य अकादमी फेलोशिप के बारे में:

- साहित्य अकादमी फेलोशिप जीवित लेखकों के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो साहित्य अकादमी, भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी द्वारा दिया जाता है।
- फेलोशिप में 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक तांबे की पट्टिका और एक शॉल शामिल है।
- यह फेलोशिप 1968 में स्थापित की गई थी, जिसमें डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले निर्वाचित फेलो थे।
- साहित्य अकादमी एक पुरस्कार भी देती है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है।
- पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए, एक लेखक को भारतीय होना चाहिए और उनका काम उनकी भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए।

PS4 इंजन

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरि में न्यूलिक्विड रॉकेट इंजन (PS4 इंजन) का सफल परीक्षण

किया है।

PS4 इंजन के बारे में:

- PS4 इंजन भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- यह चौथे चरण की प्रणोदन प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो उपग्रहों को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह एक बाइप्रोपेलेंट संयोजन पर काम करता है जिसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड (N_2O_4) और ईंधन के रूप में मोनोमिथाइल हाइड्राजीन शामिल होता है।
- भागों की संख्या 14 से घटाकर एक भाग में कर दी गई है, जिससे 19 वेल्ड जोड़ समाप्त हो गए हैं।
- PS4 इंजन का निर्माण एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का उपयोग करके किया जाता है, जिसे 3D प्रिंटिंग के रूप में भी जाना जाता है।
- PS4 चरण में अपने प्राथमिक कार्य के अलावा, इंजन PSLV के पहले चरण (PSI) के रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम (RCS) को भी शक्ति प्रदान करता है।
- मेटल पाउडर की खपत 565 किलोग्राम से घटाकर 13.7 किलोग्राम प्रति इंजन कर दी गई है।
- उत्पादन समय में 60% की कमी की गई है, जो विनिर्माण दक्षता में वृद्धि का संकेत है।

आर्मर्ड सेलफिन कैटफिश

हाल ही में सीएसआईआर-सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) के वैज्ञानिकों ने पाया है कि आक्रामक आर्मर्ड सेलफिन कैटफिश की पूर्वी घाट के जल निकायों में 60% विस्तार हुआ है।

आर्मर्ड सेलफिन कैटफिश के बारे में:

- आर्मर्ड सेलफिन कैटफिश, जिसे सेलफिन प्लेक या जेनिटर मछली के रूप में भी जाना जाता है, एक दक्षिण अमेरिकी उष्णकटिबंधीय मछली है, जो विशेष रूप से अमेजन नदी बेसिन में पाई जाती है।
- मछली का नाम उसके पाल जैसे पृष्ठीय पंख के चलते रखा गया है और इसका वैज्ञानिक नाम, टेरीगोप्लिचथिस मल्टीरेडियाटस, का अर्थ है 'कई किरणों वाला'।
- इसे इसकी अनूठी उपस्थिति और टैंकों तथा एक्वैरियम में शैवाल को साफ करने की क्षमता के लिए उपयोग किया गया था।
- यह 20 इंच से अधिक तक बढ़ सकता है और इसका वजन 3 पाउंड तक हो सकता है।
- आर्मर्ड सेलफिन कैटफिश की कुछ प्रजातियों में ओरिनोको सेलफिन कैटफिश, अमेजन सेलफिन कैटफिश (जिसे सामान्य प्लीको या 'तेंदुए प्लीको' के रूप में भी जाना जाता है) और वर्मीक्यूलेटेड सेलफिन कैटफिश शामिल हैं।

भीष्म क्यूब

हाल ही में, भारतीय वायु सेना ने उत्तर प्रदेश के आगरा में एयरड्रॉप ऑपरेशन के लिए भीष्म क्यूब का परीक्षण किया।

भीष्म क्यूब के बारे में:

- भीष्म क्यूब भारत द्वारा विकसित एक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है।
- यह प्रोजेक्ट भीष्म (सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल) का एक घटक है।
- इसका उद्देश्य देश में कहीं भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करना है।
- यह आपात्कालीन स्थिति के दौरान सुदूर या दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती की इसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- इसे 200 हताहतों के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे बड़े पैमाने पर हताहतों से निपटने के लिए उपयुक्त बनाता है।
- यह मजबूत, जलरोधक और हल्का है, जो स्थायित्व और तैनाती में आसानी सुनिश्चित करता है।

एलिस मुनरो

हाल ही में 13 मई 2024 को कनाडा की एक प्रसिद्ध लेखिका एलिस मुनरो जिन्हें लघुकथा विधा में दक्षता प्राप्त करने के लिए जाना जाता था, निधन हो गया है। उनका जन्म कनाडा के ओंटारियो प्रांत के विंगहैम में हुआ था।

- एलिस मुनरो ने युवा अवस्था में लिखना शुरू कर दिया और 1968 में अपना पहला कहानी संग्रह, 'डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स' प्रकाशित किया। तब से, उन्होंने कई प्रशंसित लघु कहानी संग्रह लिखे हैं, जिनमें 'द मून्स ऑफ ज्यूपिटर, द प्रोग्रेस ऑफ लव और द रन वे' शामिल हैं।

- ❖ उनकी कहानियाँ अक्सर कनाडा के ग्रामीण जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम, हानि, स्मृति और समय बीतने जैसे विषयों का पता लगाती हैं।
- ❖ एलिस मुनरो को 2013 में साहित्य के लिए नोवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली पहली कनाडाई महिला बनीं।
- ❖ उन्हें 2009 में उनके समग्र लेखन के लिए बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।

कंवर झील

हाल ही में, बिहार में राज्य की एकमात्र रामसर साइट कांवर झील, अतिक्रमण और सूखने के कारण अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है।

कंवर झील के बारे में:

- ❖ कांवर झील, जिसे स्थानीय रूप से कंवर झील के नाम से भी जाना जाता है, भारत में बिहार के बेगुसराय जिले की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है।
- ❖ इसे 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया, जिससे यह रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला बिहार का पहला आर्द्रभूमि बन गया।
- ❖ कांवर झील बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है।
- ❖ यह आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को दर्शा रहा है।
- ❖ यह मीठे पानी की झील है, जो इसे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण बनाती है।
- ❖ कांवर झील एक अवशिष्ट ऑक्सबो झील है जो गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंडक नदी के भूवैज्ञानिक घुमाव के कारण बनी है।
- ❖ 1984 में, कंवर झील 6,786 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करती थी।
- ❖ हालाँकि, 2004 तक यह घटकर 6,044 हेक्टेयर रह गया था।
- ❖ 1986 में राज्य सरकार ने इसे संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया। बाद में केंद्र सरकार ने पक्षियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए इसे अभयारण्य घोषित कर दिया।

कोर्टालम फॉल्स

हाल ही में, अचानक भारी बारिश के बीच ओल्ड कोर्टालम झरने में पानी बढ़ गया, जिससे तमिलनाडु में अचानक बाढ़ आ गई।

कोर्टालम फॉल्स के बारे में:

- ❖ कोर्टालम तमिलनाडु के तेनकासी जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित है।
- ❖ इन झरनों के पानी में नहाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के कारण इन्हें 'दक्षिण भारत का स्पा' भी कहा जाता है।
- ❖ इस झरने की ऊंचाई लगभग 60 मीटर (लगभग 200 फीट) है।
- ❖ कुट्रालम के जलप्रपातों का औषधीय महत्व है क्योंकि वे अपने अस्तित्व से पहले जंगल और जड़ी-बूटियों से होकर गुजरते हैं।
- ❖ झरनों को चित्तर नदी से पानी मिलता है, जो तमिरापरानी नदी की एक सहायक नदी है।

डेड़ा विधि

हाल ही में, एक मुरिया जनजाति, जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ की है और अब गोदावरी घाटी के घने जंगलों में रहती है, को खेती की 'डेडा' पद्धति का अभ्यास करते हुए देखा गया है।

डेड़ा विधि के बारे में:

- ❖ डेडा विधि छत्तीसगढ़ की मुरिया जनजातियों द्वारा उपयोग की जाने वाली बीजों को संरक्षित करने की एक पारंपरिक, पर्यावरण-अनुकूल विधि है, जिसे गुट्टी कोया भी कहा जाता है।
- ❖ इस विधि में बीजों को पत्तियों में संरक्षित करना और उन्हें लगभग वायुरोधी पैक करना शामिल है ताकि वे दूर से बोल्डर की तरह दिखें।
- ❖ फिर पैक किए गए बीजों को सियाली की पत्तियों से बुना जाता है, जिन्हें 'अड्डाकुलु' भी कहा जाता है, ताकि डेडा बनाया जा सके, जिसमें तीन परतें होती हैं।
- ❖ पहली परत में सियाली की पत्तियों के अंदर लकड़ी की राख फैलाई जाती है।
- ❖ बाद में, राख को एक आवरण बनाने के लिए नींबू के पत्तों से ढक दिया जाता है और अंत में, बीजों को आवरण के अंदर संरक्षित किया जाता है और बंद कर दिया जाता है।

- डेडा विधि कीटों और कीड़ों से बीज की सुरक्षा में उपयोगी है।
- इस विधि में संग्रहित बीजों का उपयोग पांच साल तक खेती के लिए किया जा सकता है।

मारिजुआना

हाल ही में, गुरुवार (16 मई) को एक ऐतिहासिक कदम में, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने मारिजुआना को अनुसूची 1 से अनुसूची III में दवा में पुनः वर्गीकृत करने की योजना की घोषणा की।

मारिजुआना के बारे में:

- मारिजुआना, जिसे कैनबिस या खरपतवार के रूप में जाना जाता है, एक मनो-सक्रिय दवा है जो कैनबिस पौधे से आती है, जो मध्य या दक्षिण एशिया का मूल निवासी है।
- इसका उपयोग सदियों से पारंपरिक दवाओं और मनोरंजन और एन्थोजेनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है।
- इसमें 483 ज्ञात यौगिक शामिल हैं, जिनमें कम से कम 65 कैनबिनोइड्स और टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (टीएचसी), मुख्य मनो-सक्रिय घटक शामिल हैं।
- इसका उपयोग धूम्रपान, वाष्पीकरण, भोजन में या अर्क के रूप में किया जा सकता है।
- उत्तराखंड में इसकी खेती को वैध कर दिया गया है और मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी भांग की नियंत्रित खेती की जा रही है।
- भारत में कैनबिस (खरपतवार या मारिजुआना) से संबंधित केंद्रीय कानून, 1985 का नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है।

अर्तारा' 24

हाल ही में, अर्तारा '24 ने दुबई में देश की उभरती कलात्मक प्रतिभाओं को खोजने और पोषित करने के लिए एक मंच के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

अर्तारा' 24 के बारे में:

- अर्तारा' 24 दुबई में अल जलीला सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता है, जिसे जज़्ॉकर्स द्वारा आयोजित किया गया था।
- अर्तारा 24 का प्राथमिक उद्देश्य दुबई में रहने वाली उभरती कलात्मक भारतीय प्रतिभाओं को खोजने और पोषित करने पर था।
- इसका उद्देश्य कम ज्ञात कलाकारों, छात्रों और कला प्रेमियों को अपनी असाधारण क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रतिष्ठित मंच प्रदान करना था।
- इसमें 250 से अधिक कला कृतियों का एक प्रभावशाली संग्रह था, जिनमें से प्रत्येक अपनी अनूठी कहानी बताती है और प्रतिभागियों की विविध पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है।
- मुख्य प्रदर्शनी के अलावा, अर्तारा' 24 में बच्चों के लिए एक ललित कला प्रतियोगिता 'एक्सप्रेशंस' 24' भी शामिल थी।

पिग बुचरिंग घोटाला

हाल ही में, अमेरिकी न्याय विभाग ने दो चीनी नागरिकों पर पिग बूचरिंग घोटाला चलाने का आरोप लगाया, जिसमें शेल कंपनियों के माध्यम से 73 मिलियन डॉलर से अधिक का धन शोधन किया गया था।

पिग बुचरिंग घोटाला के बारे में:

- पिग बूचरिंग घोटाला, जिसे शा झू पैन घोटाला के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी है जिसमें घोटालेबाज समय के साथ पीड़ितों का विश्वास हासिल करते हैं और फिर उनके पैसे चुरा लेते हैं।
- यह शब्द वध से पहले सुअर को 'मोटा करने' की प्रथा से आया है और घोटालेबाज इस विचार का उपयोग पीड़ितों को एक धोखाधड़ी योजना में अधिक पैसा निवेश करने के लिए मनाने के लिए करते हैं।
- पिग बूचरिंग घोटाले में, घोटालेबाज एक नकली ऑनलाइन व्यक्तित्व बनाता है और ऑनलाइन संचार के माध्यम से पीड़ित के साथ विश्वास बनाता है।
- घोटालेबाज फिर पीड़ित को धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी योजना में निवेश करने के लिए मना लेता है।

रेन्जलैंड

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से पता चला है कि विश्व के रेन्जलैंड का 50% तक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो पिछले अनुमान के 20-35% की तुलना में लगभग दोगुना है।

रेन्जलैंड के बारे में:

- रेन्जलैंड उन विशाल भूमि क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से मवेशियों के चराई के लिए उपयोग किए जाते हैं, जहां प्राकृतिक वनस्पति जैसे घास, झाड़ियाँ और जड़ी-बूटियाँ मुख्य चारे के स्रोत के रूप में काम करती हैं।
- ये परिदृश्य आमतौर पर खुले स्थानों, न्यूनतम वृक्षावरण और गहन कृषि के लिए अनुपयुक्त होते हैं।
- ये 80 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जो स्थलीय सतह के 54% से अधिक का निर्माण करते हैं।
- ये व्यापक मवेशी उत्पादन प्रणालियों का समर्थन करते हैं, जो वैश्विक भूमि सतह के 45% को कवर करते हैं।
- भारत की कुल भूमि सतह का लगभग 40% चराई के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें घास के मैदान (17%) और वन (23%) शामिल हैं।
- पशुपालन सबसे पुराने और सबसे टिकाऊ खाद्य प्रणालियों में से एक है, जो विश्व भर में 500 मिलियन लोगों का समर्थन करता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय रेन्जलैंड और पशुपालक वर्ष घोषित किया है ताकि स्वस्थ रेन्जलैंड और टिकाऊ पशुपालन की वकालत की जा सके।
- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने भारत में पशुपालकों, जानवरों और पशुपालक अर्थव्यवस्था की संख्या का अनुमान लगाने के लिए पहली जनगणना शुरू की।
- वर्तमान में लगभग 20 मिलियन पशुपालक भारत के वनों और घास के मैदानों में चराई करते हैं।

जोस राउल मुलिनो

- हाल ही में 64 वर्षीय पूर्व सुरक्षा मंत्री जोस राउल मुलिनो ने पनामा के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। निवर्तमान राष्ट्रपति लॉरेंटिनो कॉर्टिजो ने जोस राउल मुलिनो को उनकी जीत पर बधाई दी। आगामी 1 जुलाई 2024 को वे अपना पदभार ग्रहण करेंगे।
- जोस राउल मुलिनो को शुरू में पूर्व राष्ट्रपति रिकार्डो मार्टिनेली द्वारा उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था और वे स्वयं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे।
- मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराए जाने और 10 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद रिकार्डो मार्टिनेली को राष्ट्रपति पद की दौड़ छोड़नी पड़ी थी। रिकार्डो मार्टिनेली ने भाग कर पनामा स्थित निकारागुआ दूतावास में राजनीतिक शरण लिया।
- पनामा में एक व्यक्ति केवल एक कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है।

यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत

- हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 2014 से यूनिसेफ इंडिया से जुड़ी रही है।
- राष्ट्रीय राजदूत के रूप में वह बच्चों के बचपन के विकास, स्वास्थ्य शिक्षा और लैंगिक समानता के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए इस संगठन का समर्थन करेंगी। उन्होंने यूनिसेफ इंडिया के लिए एक सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में काम किया था।
- यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो विश्व में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गयी थी।
- इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क (यूएसए) में स्थित है। वर्तमान में इसकी कार्यकारी निदेशक कैथरीन एम. रसेल हैं। यह संगठन प्रत्येक बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है।

शेख अहमद अब्दुला अल-अहमद अल-सबा

- हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद अलसबा को कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंनें शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल- सबा का स्थान लिया है।
- अहमद अल-अब्दुल्ला अल-अहमद अल-सबा (जन्म 5 सितंबर 1952) एक कुवैती अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और शासक परिवार अल सबा

के वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने 2009 से 2011 के बीच तेल मंत्री के रूप में कार्य किया। 15 अप्रैल 2024 को उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया और उनका प्रीमियर 15 मई 2024 को शुरू हुआ।

- कुवैत पश्चिम एशिया में स्थित एक संप्रभु देश है। इसकी राजधानी कुवैत सिटी है। इसकी मुद्रा कुवैती दीनार है। वर्तमान में कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) के नए सीएमडी

- डॉ. सुभ्रांशु शेखर आचार्य ने 2 मई, 2024 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- NSIC सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय के तहत एक आईएसओ 9001-2015 प्रमाणित भारत सरकार का उद्यम है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने और सहायता करने के लिए काम कर रहा है।

जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष

- हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक होगा ।
- जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना जीएसटी से संबंधित विवादों को संभालने के लिए विशेष निकाय के रूप में की गई है। सितंबर, 2023 में केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रधान पीठ के साथ 31 जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पीठ स्थापित करने की अधिसूचना जारी की थी।

ओपन एआई द्वारा भारत में पहली नियुक्ति

- प्रज्ञा मिश्रा को अप्रैल, 2024 में चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी 'ओपन एआई' द्वारा भारत में पहली इम्प्लाई (Employee) नियुक्त किया गया। वे ओपन एआई के लिए भारत में पब्लिक पॉलिसी अफेयर्स हेड की जिम्मेदारी संभालेगी। वह वर्तमान में ट्रूकॉलर में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक अफेयर्स की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।
- ओपन एआई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में है। वर्तमान में इसके सीईओ सैम आल्टमैन है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) के प्रबंध निदेशक

- हाल ही में संजय शुक्ला को वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो (FSIB) द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) के नए प्रबंध निदेशक नामित किया गया है।
- एनएचबी (NHB) को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत 9 जुलाई, 1988 को स्थापित किया गया। यह आरबीआई के संपूर्ण स्वामित्व में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ पर्सनल (COP)

- वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने 10 मई, 2024 को भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ पर्सनल (COP) का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वे पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टॉफ के पद पर कार्यरत थे।

जेरेमिया मानेले

- हाल ही में जेरेमिया मानेले ने सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया।

- उन्होंने नवनिर्वाचित 50 सीटों वाली संसद में विपक्षी नेता मैथ्यू वाले को 31 के मुकाबले 18 वोटों से हराया।
- सोलोमन द्वीप ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में स्थित ओशीनिया के उपक्षेत्र मेलानेशिया में 6 प्रमुख द्वीपों और 900 से अधिक छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक देश है। सोलोमन द्वीप की राजधानी होनियारा है।

9वां ऑक्सफोर्ड बुक कवर प्राइज 2024

- 9वां ऑक्सफोर्ड वुक कवर प्राइज मई, 2024 में ऑक्सफोर्ड बुकस्टोर्स द्वारा भावी मेहता को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।
- यह पुरस्कार उन्हें चैट इंडिया द्वारा प्रकाशित और प्रदीप सेबेस्टियन द्वारा लिखित 'द बुक ब्यूटीफुल' के लिए प्रदान किया गया।
- इस पुरस्कार के तहत राशि के रूप में 1 लाख रुपये प्रदान किये जाते हैं।

पुलित्जर पुरस्कार 2024

- पत्रकारिता के क्षेत्र में लोक सेवा (Public Service) के लिए प्रो. पब्लिका, जोशुआ कपलान, जस्टिन इलियट, ब्रेट मर्फी, एलेक्स मिरजेस्की और कर्स्टन बर्ग के को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है।
- इसकी घोषणा मई, 2024 में हुई थी।
- पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में हुई थी।

शील नागू मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस नियुक्त हुए

- हाल ही में जस्टिस शील नागू ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने चीफ जस्टिस रवि विजयकुमार मलिमठ की जगह ली, जो 24 मई को रिटायर्ड हुए थे।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

हाल ही में स्पेन 99वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर-सरकारी संगठन और सहयोगात्मक मंच है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाना है।
- इसकी स्थापना पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) और फ्रांस के राष्ट्रपति (फ्रांस्वा ओलांद) द्वारा की गई थी।
- इसके लक्ष्यों में ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और सदस्य देशों में ऊर्जा परिवर्तन को गति देना शामिल है।
- इसका लक्ष्य 1000 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना और सालाना 1000 मिलियन टन CO_2 का शमन करना है।
- इसकी अवधारणा 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के लिए पार्टियों के 21वें सम्मेलन (COP21) के दौरान की गई थी।
- इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है।

ड्रिप मूल्य निर्धारण

हाल ही में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग ने 'ड्रिप मूल्य निर्धारण' के संबंध में ग्राहकों को चेतावनी जारी की है।

ड्रिप प्राइसिंग क्या है:

- अमेरिका का संघीय व्यापार आयोग ड्रिप प्राइसिंग को एक मूल्य निर्धारण तकनीक के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें फर्म किसी उत्पाद की कीमत का केवल एक हिस्सा विज्ञापित करती हैं और ग्राहक द्वारा खरीद प्रक्रिया से गुजरने के बाद, अन्य शुल्कों का खुलासा करती हैं।
- प्रिंट, ईमेल या वेबसाइट पर किसी उत्पाद का विज्ञापित मूल्य, जिसे 'हेडलाइन मूल्य' कहा जाता है, उपभोक्ता के लिए अंतिम लागत या सही मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। अतिरिक्त शुल्क अनिवार्य शुल्क हो सकते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म शुल्क, होटल रिसॉर्ट शुल्क या

वैकल्पिक अपग्रेड और ऐड-ऑन के लिए शुल्क आदि।

- ड्रिप मूल्य निर्धारण तुलनात्मक खरीदारी को जटिल बनाता है और उन विक्रेताओं के लिए नुकसानदेह है जो अधिक पारदर्शी मूल्य निर्धारण संरचना प्रदान करते हैं।
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ड्रिप मूल्य निर्धारण, प्रच्छन्न विज्ञापन और झूठी तात्कालिकता जैसी प्रथाओं से निपटने के लिए दिसंबर में 'डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023' जारी किए थे।

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीप्ति जीवनजी ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

- हाल ही में 20 मई को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने टी-20 की 400 मीटर दौड़ में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
- दीप्ति ने यह दौड़ 55.07 सेकंड में पूरी की। उन्होंने अमेरिकी एथलीट ब्रेना क्लार्क का 55.12 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ा।
- तुर्की की आयसेल ओन्डर दूसरे स्थान पर और इक्वाडोर की लिजानशेला तीसरे स्थान रहीं।
- दीप्ति जीवनजी ने 2023 में एशियाई पैरा गेम्स में भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था।
- टी-20 कैटेगरी में मानसिक रूप से कमजोर एथलीट भाग लेते हैं।

ज्योति रात्रे बनी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला

- हाल ही में 19 मई को भोपाल की ज्योति रात्रे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का नया रिकॉर्ड बनाया। उनकी उम्र 55 वर्ष है।
- उन्होंने 53 वर्षीय संगीता बहल का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है।
- ज्योति ने 8848.86 मीटर की ऊंचाई पर जाकर यह उपलब्धि हासिल की।
- यह उनका दूसरा प्रयास था। 2023 में खराब मौसम के कारण उन्हें 8160 मीटर की ऊंचाई से वापस लौटना पड़ा था।
- वह बोलीविया के पर्वतारोही डेविड ह्यूगो अयाविरी क्विस्पे के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा थीं।
- ज्योति पहले भी एल्ब्रस, किलिमंजारो, आइलैंड पीक और कोसियुज्को जैसी कई चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी हैं।

अफ्रीकी देशों को 'R21/Matrix-M' मलेरिया वैक्सीन का निर्यात

- हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने अफ्रीकी देशों में मलेरिया से लड़ने में मदद करने के लिए 'R21/Matrix-M' मलेरिया वैक्सीन का निर्यात शुरू किया।
- यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और नोवावैक्स द्वारा विकसित मैट्रिक्स-एम एडजुवेंट के साथ मिलकर बनाई गई है।
- पहली खेप में 43,200 वैक्सीन डोज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भेजे गए हैं। इस देश को कुल 1,63,000 वैक्सीन डोज मिलेंगे।
- इसके बाद वैक्सीन दक्षिण सूडान, कांगो और मलेरिया से ग्रस्त अन्य देशों को भेजी जाएगी।
- 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, अफ्रीका में मलेरिया के 233 मिलियन मामले सामने आए थे।
- यह वैक्सीन मलेरिया से होने वाली बीमारी और मौतों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- यह पहल भारत सरकार और एसआईआई की मलेरिया को खत्म करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

ताइवान के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ली शपथ

- हाल ही में 20 मई को ताइवान की राजधानी ताइपे में लाई चिंग-ते ने नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
- उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति साई इंग-वेन की जगह ली, जिन्होंने 8 साल तक ताइवान का नेतृत्व किया।
- लाई चिंग-ते 2020 में ताइवान के उपराष्ट्रपति बने थे।
- इसके साथ ही चो जंग ताई (Cho Jung-tai) ताइवान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। उन्हें ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते द्वारा नियुक्त किया गया।

❖ ताइवान चीनी गणराज्य के अंतर्गत एक पूर्वी एशियाई देश है। इसकी राजधानी ताइपे एवं मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है।

ब्राजील करेगा 2027 फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी

❖ 17 मई को थाईलैंड में FIFA की 74वीं कांग्रेस मीटिंग में घोषणा की गई कि 2027 फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी ब्राजील करेगा।
❖ यह पहला वुमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा जो साउथ अमेरिका में आयोजित होगा।
❖ ब्राजील ने नीदरलैंड्स, बेल्जियम और जर्मनी को मेजबानी की दौड़ में हराया।
❖ अप्रैल 2024 में अमेरिका और मैक्सिको ने मेजबानी की दौड़ से खुद को बाहर कर लिया था।
❖ ब्राजील ने पहले 1950 और 2014 में मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी।
❖ फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप के अब तक 9 संस्करण खेले जा चुके हैं, जो 1991 में शुरू हुए थे।
❖ 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी।

भारत–फ्रांस का 'शक्ति' अभ्यास

❖ हाल ही में मेघालय के उमरोई में 13 मई से 26 मई 2024 तक भारत और फ्रांस के बीच 7वां 'शक्ति' सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ।
❖ इसमें भारत की तरफ से 90 सैनिकों की टुकड़ी (राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन सहित), नौसेना और भारतीय वायु सेना के जवान और फ्रांस की तरफ से 90 सैनिक (13वीं फॉरेन हाफ-ब्रिगेड) ने भाग लिया।
❖ यह अभ्यास हर दो साल में भारत और फ्रांस में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
❖ इस बार का अभ्यास अर्ध-शहरी और पहाड़ी इलाकों में सैन्य अभियानों पर केंद्रित था।
❖ शक्ति अभ्यास 2019 में शुरू हुआ था।
❖ पिछला अभ्यास 2021 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था।
❖ यह अभ्यास भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण है।
❖ यह दोनों सेनाओं को विभिन्न प्रकार के इलाकों में एक साथ काम करने और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है।

असम की डॉ. पूर्णिमा देवी बर्मन को 'ग्रीन ऑस्कर' से सम्मानित किया गया

❖ असम की डॉ. पूर्णिमा देवी बर्मन को ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। व्हिटली अवॉर्ड को 'ग्रीन ऑस्कर' भी कहा जाता है। इसका आयोजन लंदन में हुआ।
❖ उन्हें व्हिटली फंड फॉर नेचर (WFN) से 100,000 ब्रिटिश पाउंड का व्हिटली गोल्ड अवॉर्ड मिला।
❖ यह अवॉर्ड उन्हें विलुप्त हो रहे ग्रेटर एजुटैंट स्टोर्क (हरगिला पक्षी) और उसके वेटलैंड निवास के संरक्षण के लिए दिया गया।
❖ डॉ. पूर्णिमा को 2017 में भी व्हिटली अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।
❖ व्हिटली अवॉर्ड हर साल WFN द्वारा आयोजित किया जाता है, जो दुनियाभर में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए काम करता है।
❖ ग्रेटर एजुटैंट को असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, जिसका मतलब 'हड्डी निगलने वाला' होता है।

सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग

❖ हाल ही में 13 मई को सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 2024 की दुनिया के 2000 सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थानों की सूची जारी की।
❖ इस सूची में हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बेहतरीन संस्थान माना गया है।
❖ IIM अहमदाबाद को भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना गया है।
❖ दुनिया में IIM अहमदाबाद की रैंक 410वीं है।
❖ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IIS) 7 रैंक गिरकर 501वें स्थान पर है।
❖ IIT बॉम्बे 568वें स्थान पर, IIT मद्रास 582वें स्थान पर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 606वें स्थान पर हैं।
❖ इस लिस्ट में भारत के कुल 64 संस्थान शामिल हैं।
❖ 32 भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जबकि 33 की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले गिरी है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. आरईसी लिमिटेड ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए 3 मई, 2024 को आरबीआई से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किया। आरईसी लिमिटेड, भारत में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी है।
2. भारत 2022 में 111 बिलियन डॉलर से अधिक प्रेषण प्राप्त करके वैश्विक स्तर पर प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया। प्रेषण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश के भुगतान संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
3. भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया। यह विकास स्वच्छ ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को दर्शाता है।
4. भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधी ट्रस्ट फंड में $500,000 का योगदान दिया। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और 2017 में इसे संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय (यूएनओसीटी) को हस्तांतरित कर दिया गया।
5. राहत शिविरों में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए मणिपुर में 'स्कूल ऑन व्हील्स' शुरू किया गया। यह मोबाइल स्कूल कार्यक्रम विस्थापित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पहुँच और समावेशिता को बढ़ावा देता है।
6. केरल में वेस्ट नाइल बुखार के मामले सामने आए हैं। वेस्ट नाइल बुखार मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है और केरल में इसका प्रकोप इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए निरंतर वेक्टर नियंत्रण प्रयासों और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
7. चक्रवात रेमल ने 26 मई को बंगाल में दस्तक दी। चक्रवात रेमल का नाम ओमान द्वारा रखा गया।
8. भारतीय हज यात्रियों ने पहली बार हाई-स्पीड ट्रेन से जेद्दा से मक्का की यात्रा की।
9. उत्तराखंड सरकार ने जंगल की आग पर काबू पाने के लिए 'पिरूल लाओ पैसे पाओ' अभियान शुरू किया। अभियान का नाम, जिसका अनुवाद 'चीड़ की सुइयां लाओ, पैसे पाओ' है, उन व्यक्तियों को इनाम देता है जो चीड़ के पत्ते इकट्ठा करते हैं और उनकी सूचना देते हैं। चीड़ के पत्ते जंगल में आग लगने का एक प्रमुख कारण बनते हैं।
10. भारत और घाना अपनी भुगतान प्रणालियों, यूपीआई और जीएचआईपीएसएस को एकीकृत करने पर सहमत हुए। इस एकीकरण का उद्देश्य भारत और घाना के बीच निर्बाध लेनदेन को सुविधाजनक बनाना और डिजिटल कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ाना है।
11. भारत और नाइजीरिया स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को अंतिम रूप देने की योजना बना रहे हैं। यह उनकी स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेनदेन को सुविधाजनक बनाएगा, जिससे अमेरिकी डॉलर जैसी तीसरे पक्ष की मुद्राओं पर निर्भरता कम होगी।
12. यूक्रेन ने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए एआई-जनरेटेड प्रवक्ता विक्टोरिया शि को पेश किया। यह अभिनव दृष्टिकोण सूचना को अधिक आकर्षक और आधुनिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है, जो संभावित रूप से मंत्रालय के संचार प्रयासों को बढ़ाता है।
13. दुबई ने खुद को गेमिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए दीर्घकालिक गेमिंग वीजा लॉन्च किया।
14. रूस ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में विशाल तेल और गैस भंडार की खोज की घोषणा की है।
15. श्रीलंका ने मन्नार और पूनेरिन में पवन ऊर्जा स्टेशन बनाने के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ एक समझौते को मंजूरी दी। इस सहयोग का उद्देश्य श्रीलंका की अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना और जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करना है।
16. पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 मिला।
17. भावी मेहता ने 'द बुक ब्यूटीफुल' के लिए ऑक्सफोर्ड बुकस्टोर बुक कवर पुरस्कार जीता।
18. भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 6 मई, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर रवाना हुई। नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, विलियम्स बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान का संचालन कर रही हैं, जो कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उनके मिशन का उद्देश्य स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की एंड-टू-एंड क्षमताओं का परीक्षण करना है।
19. डॉ. सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
20. मैकलारेन के लैंडो नोरिस ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत हासिल की।

21. तेजस्विन शंकर टक्सन, एरिजोना में यूएसएटीएफ फेस्टिवल में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में विजयी हुए।
22. चीन ने चेंग्दू में 2024 बीडब्ल्यूएफ थॉमस एंड उबेर कप फाइनल में अपना दबदबा बनाया, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते।
23. जापान ने उद्घाटन सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी का खिताब जीता।
24. गेल (Gail) ने 24 मई, 2024 को मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपना पहला 10 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया। यह परियोजना भारत के हरित हाइड्रोजन उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह 2030 तक देश के 5 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता के लक्ष्य में योगदान दे सकती है।
25. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन उत्पादन में नए ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए नॉर्वे की नेल एएसए के साथ भागीदारी की।
26. टीसीएस और आईआईटी-बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की।
27. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) ने ओमान में प्रवासी अभिलेखों का अपना पहला विदेशी डिजिटलीकरण पूरा किया।
28. क्रेडिट एग्रीकोल और सोसाइटी जेनरल सहित चार यूरोपीय बैंकों ने तीसरे पक्ष के लेनदेन मॉडल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मंजूरी प्राप्त की। यह मॉडल बैंकों को अक्टूबर 2022 में यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ESMA) द्वारा क्लियरिंग कॉर्प ऑफ इंडिया (CCIL) की मान्यता रद्द करने के बावजूद भारतीय सरकारी बॉन्ड और डेरिवेटिव में व्यापार जारी रखने में सक्षम बनाएगा।
29. RBI ने अनुचित टर्म लोन मंजूर करने के लिए ICICI बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना RBI के विवेकपूर्ण ऋण प्रथाओं पर जोर देने और भारतीय बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
30. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने भारत सरकार को 3,662 करोड़ रुपये का लाभांश दिया।
31. दक्षिण कोरिया के येचेओन में तीरंदाजी विश्व कप 2024, स्टेज 2 इवेंट में, भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता।
32. महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 28 मई को मनाया गया। इस दिन की स्थापना 1987 में दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के लिए महिला वैश्विक नेटवर्क (WGNRR) द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने और उनके यौन और प्रजनन अधिकारों की वकालत करने के लिए की गई थी।
33. विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2024 28 मई को "एक साथ #पीरियडफ्रेंडली वर्ल्ड" थीम के साथ मनाया गया। 'एक साथ #पीरियडफ्रेंडलीवर्ल्ड' थीम एक ऐसा समाज बनाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देती है जो मासिक धर्म से पीड़ित महिलाओं का समर्थन और सशक्तिकरण करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने मासिक धर्म को सुरक्षित, सम्मानजनक और कलंक या भेदभाव के डर के बिना प्रबंधित कर सकें।
34. मुंबई सिटी एफसी ने कोलकाता में इंडियन सुपर लीग फाइनल में मोहन बागान को 3-1 से हराया।
35. राकेश सिंह को पेटीएम मनी लिमिटेड का नया सीईओ नियुक्त किया गया।
36. संजीव नौटियाल को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया।
37. सुजय रैना को वीजा द्वारा भारत का नया कंट्री मैनेजर नामित किया गया।
38. नागेश कपूर ने भारतीय वायु सेना में प्रशिक्षण कमान (टीसी) के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (एओसी-इन-सी) के रूप में कार्यभार संभाला।
39. दिलीप संघानी को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (इफको) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
40. भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों के लिए IOCL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में करती है, जिसे विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से बिजली में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें जल वाष्प एकमात्र उपोत्पाद होता है।
41. डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में डॉ. समीर वी. कामत का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। डॉ. कामत को अगस्त 2022 में डीआरडीओ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 31 मई, 2025 तक बढ़ा दिया गया।

42. विश्व भूख दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है और विश्व भूख दिवस 2024 का विषय 'समृद्ध माताएँ, समृद्ध विश्व' है।
43. कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता।
44. तेलंगाना राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
45. हाल ही में 20 से 24 मई, 2024 तक वियना में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
46. संजीव पुरी ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला।
47. इगा स्वितेक ने टेनिस में इटैलियन ओपन का खिताब जीता। यह चार वर्षों में उनका तीसरा इटैलियन ओपन खिताब है तथा आगामी फ्रेंच ओपन में उनके प्रबल दावेदार होने की उम्मीद है।
48. वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख का पदभार संभाला।
49. भारत ने अंटार्कटिका में मैत्री-II नामक एक नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की घोषणा की। नया स्टेशन, जिसके 2029 तक चालू होने की उम्मीद है, मौजूदा मैत्री स्टेशन के पास स्थित होगा तथा इसमें 90 शोधकर्ताओं को समायोजित करने की क्षमता होगी।
50. केकी मिस्त्री को एचडीएफसी लाइफ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति दीपक पारेख द्वारा 18 अप्रैल, 2024 को एचडीएफसी लाइफ के अध्यक्ष और गैर-कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा देने के बाद की गई है।
51. भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कुश्ती की वैश्विक शासी संस्था, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने कथित डोपिंग उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
52. श्रीलंका ने भारतीयों के वीजा-मुक्त प्रवेश की समय सीमा को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।
53. TCS और IIT-बॉम्बे ने 28 मई, 2024 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए सहयोग किया। इस उन्नत सेंसिंग टूल का उद्देश्य सेमीकंडक्टर चिप्स की जांच को बढ़ाना, चिप विफलताओं को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। यह सहयोग सरकार के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ संरेखित है, जो भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है।
54. भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने 27 मई, 2024 को दक्षिण कोरिया में तीरंदाजी विश्व कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता।
55. फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने 26 मई, 2024 को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। यह मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में उनकी पहली जीत और सीजन की पहली जीत थी।
56. वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए भारत की जीडीपी विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत वृद्धि से प्रेरित होकर 7.8% रही। वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 2023-24 में 7.2% की दर से बढ़ा, जबकि 2022-23 में 6.7% की वृद्धि देखी गई।
57. अल्लामाये हलीना चाड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। सक्सेस मासरा के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
58. भारत ने एंटी-रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-II का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे इसकी प्रणोदन प्रणाली और नियंत्रण और मार्गदर्शन एल्गोरिदम की पुष्टि हुई है।
59. भारत ने 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है, जो इसकी स्थापना के बाद पहली बार है। कोलंबो प्रक्रिया दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है।
60. डॉ. मोनिक एलोइट की जगह 28 मई, 2024 को इमैनुएल सौबेरन को WOAH का नया महानिदेशक चुना गया।
61. महामत इदरीस डेवी मई, 2024 में चाड के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इससे पूर्व वे इस देश के अंतरिम राष्ट्रपति थे। चाड मध्य अफ्रीकी स्थलरुद्ध देश है। इसकी राजधानी नदजामेना (N'Djamena) एवं मुद्रा सीएफए फ्रांक है।
62. हाल ही में शू फेइहोंग (Xu Feihong) को भारत में चीन के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। भारत में चीन के राजदूत का पद 18 माह से खाली था, जो चार दशकों में सबसे लंबा अंतराल है। इन्होंने सुन वेइदोंग का स्थान लिया है।
63. हाल ही में रिचर्ड 'रिक' स्लेमैन, संशोधित सुअर किडनी प्रत्यारोपण के पहले प्राप्तकर्ता थे, जिनका मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में सर्जरी के लगभग दो महीने बाद निधन हो गया।

प्री स्पेशल

भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया पहल

1. घर्षण रहित ऋण (Frictionless Credits):

- घर्षण रहित ऋण एक उधार लेने का दृष्टिकोण है जो उपभोक्ताओं के लिए ऋण देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहता है।
- पारंपरिक क्रेडिट प्रणालियों के विपरीत, जहां व्यक्तियों को व्यापक कागजी कार्रवाई, क्रेडिट जांच और लंबी अनुमोदन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, घर्षण रहित क्रेडिट एक सहज और त्वरित प्रक्रिया का वादा करता है।

2. आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम:

- आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में आसानी से निवेश करने की अनुमति देती है।
- निवेशक अब सीधे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने में सक्षम हो गए हैं।

3. आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना:

- आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाना है।

4. सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी):

- भारत ने डिजिटल रुपया (e₹) नामक एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) लॉन्च की। डिजिटल रुपया दो संस्करणों में उपलब्ध है:
  - » **थोक के लिए डिजिटल रुपया (e₹-W):** 1 नवंबर, 2022 को लॉन्च किया गया, यह संस्करण वित्तीय संस्थानों के लिए डिजाइन किया गया है और सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के निपटान तक सीमित है।
  - » **रिटेल के लिए डिजिटल रुपया (e₹-R):** 1 दिसंबर, 2022 को लॉन्च किया गया, यह संस्करण उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए डिजाइन किया गया है और इसका उपयोग व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) लेनदेन के लिए किया जा सकता है।
- **उद्देश्य:** व्यवसायों और उपभोक्ताओं को गोपनीयता, हस्तांतरणीयता, सुविधा, पहुंच और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- **प्रकार:** वित्तीय संस्थानों के लिए थोक सीबीडीसी और उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए खुदरा सीबीडीसी।
- **लाभ:** वित्तीय समावेशन, कम लेनदेन लागत और मौद्रिक नीति नियंत्रण।
- **विशेषताएँ:** फिएट मनी का डिजिटल समकक्ष, केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाता है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की हालिया पहल

1. **लाइट टैंक जोरावर का परीक्षण:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने लाइट टैंक जोरावर का विकास परीक्षण शुरू कर दिया है। सेना ने लद्दाख सेक्टर में गतिशीलता और युद्धाभ्यास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से निर्मित 59 जोरावर लाइट टैंक का ऑर्डर दिया है।
2. **सागर मैत्री मिशन-4:** डीआरडीओ के समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत, आईएनएस सागरध्वनि ने 'महासागर अनुसंधान एवं विकास' में हिंद महासागर रिम देशों के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी स्थापित करने के लिए दो महीने की अवधि वाले सागर मैत्री मिशन-4 की शुरुआत की।

इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मिशन

1. **XPoSat:** 1 जनवरी, 2024 को लॉन्च किया गया, XPoSat ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष वेधशाला है। इसे पीएसएलवी रॉकेट पर लॉन्च किया गया था और इसकी अनुमानित परिचालन अवधि कम से कम पांच साल है।

मिशन विवरण:

- 1 जनवरी, 2024 को लॉन्च किया गया
- भारत में पहला समर्पित पोलारिमेट्री मिशन
- दुनिया में दूसरा पोलारिमेट्री मिशन
- इसरो और आरआरआई द्वारा विकसित

पेलोड:

- एक्स-रे में पोलारिमीटर उपकरण (POLIX)
- एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और समय (XSPECT)

उद्देश्य:

- ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करना
- विभिन्न खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं को समझना
- बहुमूल्य समय और स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी प्रदान करना

- खगोलीय उत्सर्जन प्रक्रियाओं की वर्तमान समझ की सीमाओं पर काबू पाना

2. आदित्य – एल 1:

- 2 सितम्बर, 2023 को लॉन्च किया गया, आदित्य-एल1 भारत का पहला सौर मिशन है और इसने पहले सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु के आसपास अपनी अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है।
- आदित्य-एल1 के मुख्य उद्देश्य हैं: सूर्य के क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिशीलता का निरीक्षण करना, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) और उनकी उत्पत्ति का अध्ययन करना।

3. चंद्रयान – 3 :

- 14 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया गया, चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने के लिए एक मिशन है और इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल हैं।

अंतरिक्ष यान के घटक:

- लैंडर मॉड्यूल (विक्रम): 1726 किग्रा (3806 पाउंड)
- रोवर (प्रज्ञान): 26 किग्रा (57 पाउंड)
- प्रणोदन मॉड्यूल: 3 से 6 महीने (योजनाबद्ध)

लैंडर पेलोड:

- तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए ChaSTE
- लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए ILSA
- प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंडर पेलोड
- चंद्र लेजर रेंजिंग अध्ययन के लिए नासा से लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर ऐरे

रोवर पेलोड

- लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (एपीएक्सएस) और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (एलआईबीएस)

4. इन्सैट – 3DS:

- 26 जनवरी, 2024 को लॉन्च किया गया, INSAT-3DS एक संचार उपग्रह है जो मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और संबंधित गतिविधियों के लिए मौसम संबंधी इमेजिंग और डेटा रिले सेवाएं प्रदान करता है।
- उपग्रह के पेलोड में शामिल हैं:
  - » **डीआरटी:** डेटा रिले ट्रांसपोंडर
  - » **एसएएस एंड आर:** उन्नत सहायता प्राप्त खोज एवं बचाव
  - » **इमेजर:** 6 चैनल इमेजर
  - » **साउंडर:** 19 चैनल साउंडर
- INSAT-3DS उपग्रह भूस्थिर कक्षा से तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है। मिशन पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) द्वारा वित्त पोषित है। इसे मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधी अवलोकन और भूमि और महासागर सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। यह उपग्रह वर्तमान में संचालित INSAT-3D और INSAT-3DR उपग्रहों के साथ-साथ मौसम संबंधी सेवाओं को भी बढ़ाएगा।

5 .निसार:

- नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (एनआईएसएआर) मिशन पृथ्वी अवलोकन मिशन है जो दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक एपर्चर रडार को सह-विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- 5 से 10 मीटर के रेजोल्यूशन पर महीने में चार से छह बार पृथ्वी की भूमि और बर्फ के द्रव्यमान की ऊंचाई का मानचित्र बनाना।
- 12 दिनों में संपूर्ण विश्व का मानचित्रण करने के लिए उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करना।
- पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ द्रव्यमान, वनस्पति बायोमास, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूजल और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन सहित प्राकृतिक खतरों में परिवर्तन को समझने के लिए स्थानिक और अस्थायी रूप से सुसंगत डेटा प्रदान करना।

पेलोड

- एल-बैंड (1.25 गीगाहर्ट्ज, 24 सेमी तरंग दैर्ध्य) पोलारिमेट्रिक एसएआर, नासा द्वारा निर्मित किया जाएगा
- एस-बैंड (3.20 गीगाहर्ट्ज, 9.3 सेमी तरंग दैर्ध्य) पोलारिमेट्रिक एसएआर, इसरो द्वारा निर्मित किया जाएगा

हाल ही में चर्चा में रही प्रमुख जनजातियाँ

1. **हट्टी जनजाति:** हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरि क्षेत्र में हट्टी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा गया था। हट्टी जनजाति को शामिल करने की मांग लगभग 50 वर्षों से लंबित थी।
2. **नारिकोरावन और कुरीविक्करन पहाड़ी जनजातियाँ:** तमिलनाडु की नारिकोरावन और कुरीविक्करन पहाड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ा गया।
3. **बिंझिया:** छत्तीसगढ़ में बिंझिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा गया। बिंझिया जनजाति को शामिल करने की मांग लगभग 15 वर्षों से लंबित थी।

4. **पीवीटीजी समुदाय:** ओडिशा में भुइयां जनजाति के पर्यायवाची शब्द के रूप में पौरी भुइयां और पौडी भुइयां शामिल हैं; भुंजिया जनजाति के पर्याय के रूप में चुक्तिया भुंजिया; बोंडो पोराजा जनजाति की एक उप-जनजाति के रूप में बोंडो और मैनकिडिया, मैनकिर्डिया जनजाति के पर्याय के रूप में को अनुसूचित जनजाति की सूचि में जोड़ा गया है। आंध्र प्रदेश में, पीवीटीजी समुदायों में पोरजा जनजाति के पर्याय के रूप में बोंडो पोरजा और खोंड पोरजा और सावरस जनजाति के पर्याय के रूप में कोंडा सावरस को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा गया है
5. **गोंड समुदाय:** उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा गया। इसमें गोंड समुदाय की पांच उपश्रेणियां (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड) शामिल हैं।
6. ओडिशा की एसटी सूची में संशोधन करने वाले विधेयक ने दो प्रविष्टियों तमाडिया और तमुडिया को अनुसूचित जाति की सूची से अनुसूचित जनजाति सूची में स्थानांतरित कर दिया।

जहाजरानी मंत्रालय की हालिया पहल

1. **समुद्री अमृत काल विजन 2047:** ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के दौरान लॉन्च किए गए एक व्यापक रोडमैप के साथ भारत का समुद्री क्षेत्र बदलने के लिए तैयार है, जिसमें 80,000 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार अमृत काल विजन 2047, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पर आधारित है और इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय बंदरगाहों को विकसित करना और अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय शिपिंग और एक सतत समुद्री क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है। इसमें भारत की 'ब्लू इकोनॉमी' के समर्थन में लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा और पोत परिवहन में आकांक्षाएं शामिल हैं।

2. **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (समुद्री):** यह एक वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो सभी लॉजिस्टिक्स हितधारकों को आईटी के माध्यम से जोड़ता है, जिसका लक्ष्य दक्षता, पारदर्शिता बढ़ाना और लागत और समय की देरी को कम करना है।
3. **सागर मंथन:** यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें मंत्रालय से संबंधित व्यापक डेटा शामिल है। यह वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड परियोजनाओं, KPI और वित्तीय मापदंडों की निगरानी में सहायता करता है।
4. **सागर-सेतु:** यह मोबाइल ऐप वास्तविक समय पर बंदरगाह संचालन और निगरानी सेवाएं प्रदान करके व्यापार करने में आसानी को बढ़ाता है।
5. **हरित सागर:** यह शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के बड़े दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देश है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की हालिया पहल

1. **ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम संस्थाओं को वृक्षारोपण और खराब वन भूमि की बहाली के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसका उद्देश्य जलवायु कार्रवाई पहल को और मजबूत करना है।
2. **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी):** जनवरी 2019 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक पीएम10 और पीएम2.5 सांद्रता में 20 से 30 प्रतिशत की कमी हासिल करने के लक्ष्य के साथ व्यापक तरीके से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना है।
3. **अमृत धरोहर:** यह योजना आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करती है और स्थानीय समुदायों के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण-पर्यटन के अवसरों और आय सृजन को बढ़ाती है।
4. **मिष्टी पहल**

- मिष्टी (तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल) 2022 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा शुरू की गई एक योजना है।

मिष्टी पहल के उद्देश्य:

- मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और बहाली।
- कार्बन पृथक्करण में वृद्धि।
- तटरेखा की सुरक्षा एवं कटाव की रोकथाम।
- स्थानीय समुदायों के लिए पर्यावरण-पर्यटन और आय सृजन को बढ़ावा देना।
- टिकाऊ आजीविका विकल्पों के माध्यम से तटीय समुदायों की आजीविका में सुधार।

2011 में भारत की जनगणना से संबंधित मुख्य तथ्य

जनसंख्या:

- भारत की जनसंख्या 1.21 अरब है, जो पिछले दशक की तुलना में 17.7% अधिक है
- महिलाओं की वृद्धि दर 18.3% थी जो पुरुषों (17.1%) की तुलना में अधिक है।

- 2001-11 के दौरान भारत की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले दशक में यह 21.5% थी।

ग्रामीण और शहरी जनसंख्या:

- कुल मिलाकर, 2011 की जनगणना के अनुसार 833.5 मिलियन व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का दो-तिहाई से अधिक था, जबकि 377.1 मिलियन व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।
- शहरी अनुपात 1951 में 17.3% से बढ़कर 2011 में 31.2% हो गया है

साक्षरता:

- देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है, पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46 है।

घनत्व:

- देश में जनसंख्या का घनत्व भी 2001 में 325 से बढ़कर 2011 में 382 प्रति वर्ग किमी हो गया है।
- प्रमुख राज्यों में, बिहार 1106 के घनत्व के साथ पहले स्थान पर है, जिसने पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 2001 के दौरान पहला स्थान हासिल किया था।

लिंग अनुपात:

- 2011 में देश में जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 पुरुषों के मुकाबले 943 महिलाओं का है, जो पिछली जनगणना से 10% अधिक है जब प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 थी।
- हरियाणा को सभी राज्यों में सबसे खराब पुरुष-महिला अनुपात होने का संदिग्ध गौरव प्राप्त है, जबकि केरल का प्रदर्शन सबसे अच्छा है।

बाल जनसंख्या

- 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या 2001 में 163.8 मिलियन से 0.4% की वृद्धि के साथ 2011 में 164.5 मिलियन हो गई है।
- बाल जनसंख्या (0-6) लगभग स्थिर है। 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 2001 की तुलना में 2011 में बाल जनसंख्या में गिरावट आई है

कृषि जनगणना

- कृषि जनगणना 2021-22 28 जुलाई, 2022 को शुरू की गई थी और चरण-I प्रगति पर है, जिसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह भारत में 11वीं कृषि जनगणना है।

उद्देश्य:

- कृषि जनगणना का उद्देश्य देश में कृषि की संरचनात्मक विशेषताओं के बारे में डेटा एकत्र करना और मात्रात्मक जानकारी प्राप्त करना है।

आवृत्ति:

- भारत में कृषि जनगणना हर पांच साल में आयोजित की जाती है।

चरण:

- कृषि जनगणना का क्षेत्रीय कार्य तीन चरणों में किया जाता है, प्रत्येक चरण एक वर्ष की अवधि का होता है।

संदर्भ वर्ष:

- संदर्भ वर्ष 2021-22 के साथ वर्तमान जनगणना शृंखला में 11वीं होगी।

10वीं कृषि जनगणना

मुख्य निष्कर्ष:

- महिला परिचालन भूमि धारकों की संख्या 2010-11 में 12.79% से बढ़कर 2015-16 में 13.87% हो गई।
- 2010-11 में 159.59 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में कुल संचालित क्षेत्र 1.53% घटकर 157.14 मिलियन हेक्टेयर रह गया।
- परिचालन जोत की संख्या 2010-11 में 138 मिलियन से 5.33% बढ़कर 146 मिलियन हेक्टेयर से अधिक हो गई।
- परिचालन जोत की संख्या में वृद्धि के मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, मेघालय, कर्नाटक और नागालैंड हैं।
- गोवा में सबसे तेज गिरावट देखी गई और मणिपुर में परिचालन होल्डिंग्स की संख्या सबसे कम थी।
- 14 राज्यों में 91.03% परिचालन हिस्सेदारी है जिसमें पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और केरल शामिल हैं।
- भारत की लगभग 86.21% खेती योग्य और अकृषित भूमि 2 हेक्टेयर से कम भूमि रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों के अधीन है।
- कृषि भूमि का औसत आकार 2010-11 में 1.15 हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर हो गया।
- 2015-16 में अर्ध-मध्यम और मध्यम परिचालन जोत (2-10 हेक्टेयर) 13.22% थी, जिसमें 43.61% संचालित क्षेत्र था।
- कृषि जोत का औसत आकार नागालैंड में सबसे अधिक 5.06 हेक्टेयर और केरल में सबसे कम 0.18 हेक्टेयर था।
- भूमि जोतने वाले लोगों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, उसके बाद बिहार और महाराष्ट्र हैं।

- राजस्थान में कुल संचालित क्षेत्र सबसे बड़ा था, इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक थे।

एशियाई शेरों की जनगणना–2020

प्रमुख बिंदु:

- 2020 की जनगणना में 674 शेर दर्ज किए गए।
- 2015 में आखिरी गणना से शेरों की आबादी लगभग 29% बढ़ गई है।
- गुजरात राज्य में शेरों की आबादी 2001 से दोगुनी हो गई है।
- गुजरात राज्य में शेरों की आबादी 2015 में 22,000 वर्ग किमी से बढ़कर 2020 में 30,000 वर्ग किमी. हो गई है।
- गिर के जंगलों के शेरों के लिए भौगोलिक वितरण क्षेत्र में 36% की वृद्धि की गई है।

जनसंख्या वितरण:

- एशियाई शेरों की आबादी गिर राष्ट्रीय उद्यान और भारतीय राज्य गुजरात के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित है।
- एशियाई शेरों की सुरक्षा के लिए वर्तमान में पांच संरक्षित क्षेत्र मौजूद हैं: गिर अभयारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्यान, पनिया अभयारण्य, मितियाला अभयारण्य और गिरनार अभयारण्य।

2022 में बाघ जनगणना

जनसंख्या:

- भारत में वर्तमान बाघों की आबादी 3,167 है, जो 2018 में 2,967 थी।
- 785 बाघों की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटक (563) और उत्तराखंड (560), और महाराष्ट्र (444) हैं।

विकास दर:

- 2018 से 2022 के चार वर्षों में विकास दर धीमी होकर 6.7% हो गई, जो 2014-2018 के दौरान लगभग 33% थी।
- 2018 से 2022 तक बाघों की आबादी 200 बढ़ गई है।

वृद्धि:

- शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है।
- उत्तर-पूर्व की पहाड़ियों और मैदानों में 194 बाघों को कैमरा ट्रैप द्वारा कैद किया गया था और क्षेत्र का ब्रह्मपुत्र नीलगिरि समूह दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है, जो पड़ोसी क्षेत्रों में बाघों के उपनिवेशण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

गिरावट:

- नवीनतम विश्लेषण से पता चला है कि पश्चिमी घाट में बाघों की संख्या में गिरावट आई है। वायनाड परिदृश्य क्षेत्र और बिलिगिरिरंगा पहाड़ियों में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई।

उच्च संरक्षण प्राथमिकता:

- सिमलीपाल में बाघों की आनुवंशिक रूप से अद्वितीय और छोटी आबादी को भी उच्च संरक्षण प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया है।

सतत विकास लक्ष्य

- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का एक सार्वभौमिक आह्वान हैं।
- **कोई गरीबी नहीं (एसडीजी 1):** गरीबी कम करना और सुनिश्चित करना कि सभी लोगों को भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों तक पहुंच हो।
- **शून्य भूख (एसडीजी 2):** भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना।
- **अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण (एसडीजी 3):** स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य देखभाल और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तक पहुंच सहित सभी लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देना।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (एसडीजी 4):** समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना।
- **लैंगिक समानता (एसडीजी 5):** लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना।
- **स्वच्छ जल और स्वच्छता (एसडीजी 6):** सुरक्षित और किफायती पानी और स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
- **सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (एसडीजी 7):** सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- **अच्छे कार्य और आर्थिक विकास (एसडीजी 8):** निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास और सभी के लिए अच्छे कार्य को बढ़ावा देना।
- **उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा (एसडीजी 9):** लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना।

- **असमानताओं में कमी (एसडीजी 10):** देशों व देश के बीच आय और सामाजिक असमानताओं को कम करना।
- **टिकाऊ शहर और समुदाय (एसडीजी 11):** शहरों और समुदायों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना।
- **जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन (एसडीजी 12):** टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना और प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग हासिल करना।
- **जलवायु कार्रवाई (एसडीजी 13):** जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।
- **जल के नीचे जीवन (एसडीजी 14):** महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और स्थायी उपयोग करना।
- **भूमि पर जीवन (एसडीजी 15):** स्थलीय और वन पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना।
- **शांति, न्याय और मजबूत संस्थान (एसडीजी 16):** शांतिपूर्ण और समावेशी समाज, न्याय तक पहुंच और प्रभावी और जवाबदेह संस्थानों को बढ़ावा देना।
- **लक्ष्यों के लिए साझेदारी (एसडीजी 17):** कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना।
- ये एसडीजी आपस में जुड़े हुए हैं और इनका लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत दुनिया बनाना है।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से संबंधित मुख्य तथ्य:

- **17 लक्ष्य:** 17 एसडीजी हैं, जो एकीकृत और परस्पर जुड़े हुए हैं।
- **169 लक्ष्य:** 17 लक्ष्यों में 169 लक्ष्य हैं।
- **232 संकेतक:** लक्ष्यों की ओर प्रगति को मापने के लिए 232 संकेतक हैं।
- **वैश्विक एजेंडा:** एसडीजी एक वैश्विक एजेंडा है, जो अमीर और गरीब सभी देशों पर लागू होता है।
- **सार्वभौमिक:** एसडीजी सार्वभौमिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे हर जगह, सभी लोगों पर लागू होते हैं।
- **एकीकृत:** एसडीजी एकीकृत हैं, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित करते हैं।

भारत में प्राकृतिक संसाधन

ऊर्जा संसाधन:

- **कोयला:** भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है और कोयला खनन 1774 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में शुरू हुआ था। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों के साथ, देश विश्व स्तर पर कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- **तेल:** भारत के पास एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है, अधिकांश भंडार पश्चिमी तट (मुंबई हाई) और देश के दक्षिणपूर्वी हिस्सों में स्थित हैं। राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है।
- **प्राकृतिक गैस:** भारत में 1,437 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस भंडार है, जिसमें पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र प्रमुख उत्पादक हैं।

खनिज स्रोत

प्रमुख खनिज:

भारत एक खनिज समृद्ध देश है और कई प्रमुख खनिजों का घर है, जिनमें शामिल हैं:

- **लौह अयस्क:** ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा
- **बॉक्साइट:** ओडिशा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र
- **कोयला:** झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना
- **लीड:** राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार
- **जिंक:** राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात
- **तांबा:** मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, झारखंड का सिंहभूम जिला
- **जिप्सम:** राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, गुजरात
- **क्रोमाइट:** ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
- **चूना पत्थर:** आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु
- **मैंगनीज:** ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश
- **चांदी:** राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात
- **निकेल:** ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश
- **हीरा:** मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा
- **सोना:** कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु

भारत में लघु खनिज

लघु खनिज क्या हैं?

- गौण खनिज वे खनिज हैं जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 में निर्दिष्ट नहीं हैं।
- वे ऐसे खनिज हैं जिनका उपयोग भवन निर्माण उद्देश्यों के लिए

किया जाता है, जैसे बजरी, साधारण मिट्टी, साधारण रेत और अन्य खनिज जिन्हें केंद्र सरकार गौण खनिजों के रूप में घोषित कर सकती है।

लघु खनिजों के उदाहरण:

- गेंद मिट्टी
- बैराइट्स
- कैलकेरियस रेत
- कैल्साइट
- चाक
- चीनी मिट्टी
- मिट्टी (अन्य)
- कोरंडम
- डायस्पोर
- डोलोमाइट
- ड्यूनाइट/पाइरोक्सेनाइट
- फेलसाइट
- फेल्सपार
- फायरक्ले
- फ्यूशाइट क्वार्टजाइट
- जिप्सम
- जैस्पर
- काओलिन
- लेटराइट
- लाइमकंकर
- अभ्रक
- गेरू
- पायरोफिलाइट
- क्वार्ट्ज
- क्वार्टजाइट
- रेत (अन्य)
- शेल
- सिलिका की रेत
- स्लेट
- स्टीटाइट/टैल्क/सोपस्टोन

गौण खनिजों का विनियमन:

- लघु खनिजों से संबंधित नीति और कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकारों को सौंपी गई है, जबकि प्रमुख खनिजों से संबंधित नीति और कानून संघ/केंद्र सरकार के तहत खान मंत्रालय द्वारा निपटाए जाते हैं।
- विभिन्न राज्य सरकारों ने वास्तव में एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत लघु खनिजों के रूप में वर्गीकृत खनिजों के संबंध में खनिज रियायतें देने के लिए नियम निर्धारित किए हैं।

भारत में कृषि

- भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्रों में से एक है और यह भारत की 55% आबादी के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है।
- भारत में दुनिया का सबसे बड़ा पशुधन है, गेहूं, चावल और कपास के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है, और दुनिया में दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- यह फल, सब्जियां, चाय, खेती की गई मछली, कपास, गन्ना, गेहूं, चावल, कपास और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत में कृषि क्षेत्र देश की लगभग आधी आबादी के लिए रोजगार पैदा करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि भूमि का रिकॉर्ड रखता है।
- 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) में प्रमुख वस्तुओं का निर्यात निम्नलिखित था:
  - » **समुद्री उत्पाद:** 5.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर
  - » **बासमती और गैर-बासमती चावल:** 7.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर
  - » **मसाले:** 2.91 अरब अमेरिकी डॉलर
  - » **भैंस का मांस:** 2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर
  - » **चीनी:** 1.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर
  - » **विविध प्रसंस्कृत वस्तुएँ:** 1.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर
  - » **ऑयल मील:** 1.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर

प्रमुख योजनायें

- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना:** यह किसान कल्याण योजना देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती है।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई):** इस फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई):** इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **आयुष्मान सहकार योजना:** यह योजना भारत में सहकारी समितियों को उनके स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM):** यह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल

कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा APMC (कृषि उपज विपणन समिति) मंडियों को नेटवर्क बनाता है।

- **प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई):** यह भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
- **कृषि कल्याण अभियान (केकेए):** इस केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य भारत के आकांक्षी जिलों में किसानों की आय और आजीविका में सुधार करना है।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना:** इस सरकारी पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक सामग्री का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करके भारत में कृषि भूमि के मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना है।
- **राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम):** इस योजना का उद्देश्य भारत में बांस की खेती और उपयोग को बढ़ावा देना है।
- **कृष्णोन्नति योजना:** इस प्रमुख पहल में कृषि क्षेत्र के समग्र उत्थान के लिए एक छतरी के नीचे 11 विशिष्ट योजनाएं शामिल हैं।
- **युवा सहकार-सहकारी उद्यम सहायता और नवाचार योजना (युवा सहकार):** इस योजना का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा):** इस केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करना है।
- **परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई):** इस योजना का उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम):** इस योजना का लक्ष्य भारत में चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाना है।
- **पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना (पीडीडीयूयूकेएसवाई):** इस योजना का उद्देश्य पर्यावरणीय जीविका और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और गाय आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम):** इस योजना का उद्देश्य भारत में स्वदेशी मवेशी नस्लों का संरक्षण और विकास करना है।

भारत में प्रमुख कृषि फसलें

चावल:
- तापमान: 22-32°C
- वर्षा: 150-300 सेमी
- मिट्टी: गहरी चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी

गेहूं:
- तापमान: 10-15°C (बुवाई), 21-26°C (पकने और कटाई)
- वर्षा: 75-100 सेमी
- मिट्टी: अच्छी जल निकास वाली उपजाऊ दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी

बाजरा (पोषक अनाज):
- तापमान: 27-32°C
- वर्षा: 50-100 सेमी
- मिट्टी: निम्न जलोढ़ या दोमट मिट्टी

मक्का:
- तापमान: 21-27°C
- वर्षा: अधिक
- मिट्टी: पुरानी जलोढ़ मिट्टी

दालें:
- तापमान: 20-27°C
- वर्षा: 25-60 सेमी
- मिट्टी: बलुई-दोमट मिट्टी

कपास:
- तापमान: 21-27°C
- वर्षा: 60-100 सेमी
- मिट्टी: अच्छी जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी

गन्ना:
- तापमान: 21-27°C
- वर्षा: 150-200 सेमी
- मिट्टी: अच्छी जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी

चाय:
- तापमान: 15-25°C
- वर्षा: 150-200 सेमी
- मिट्टी: अम्लीय मिट्टी

कॉफी:
- तापमान: 15-25°C
- वर्षा: 150-200 सेमी
- मिट्टी: अम्लीय मिट्टी

मसाले:
- तापमान: मसाले के आधार पर भिन्न होता है (उदाहरण के लिए, मिर्च - 20-25°C, हल्दी - 20-25°C)
- वर्षा: मसाले के आधार पर भिन्न होती है (उदाहरण के लिए, मिर्च

– 50–100 सेमी, हल्दी – 100–150 सेमी)

- मिट्टी: मसाले के आधार पर अलग-अलग होती है (उदाहरण के लिए, मिर्च -अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी, हल्दी – थोड़ी अम्लीय मिट्टी)

वर्ष 2023 में विज्ञान क्षेत्र की प्रमुख पहलें

1. जनरेटिव ए.आई

जेनरेटेड एआई से तात्पर्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है जो विभिन्न तकनीकों के माध्यम से बनाई या उत्पन्न की जाती है, जैसे:

- **मशीन लर्निंग:** एल्गोरिदम जो मशीनों को डेटा से सीखने और समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करने में सक्षम बनाते हैं।
- **डीप लर्निंग:** मशीन लर्निंग का एक उपसमूह जो डेटा का विश्लेषण करने के लिए तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है।
- **प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी):** कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने, उत्पन्न करने और संसाधित करने में सक्षम बनाता है।
- **जेनरेटिव एडवरसैरियल नेटवर्क (जीएएन):** एल्गोरिदम जो किसी दिए गए डेटासेट के समान नया डेटा उत्पन्न करते हैं।
- **विकासवादी एल्गोरिदम:** प्राकृतिक विकास से प्रेरित, ये एल्गोरिदम पुनरावृत्ति चयन और उत्परिवर्तन के माध्यम से एआई उत्पन्न करते हैं।
- जेनरेटेड AI के कई अनुप्रयोग हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - » छवि और वीडियो निर्माण
  - » प्राकृतिक भाषा निर्माण (पाठ, चैटबॉट)
  - » संगीत और ऑडियो निर्माण
  - » रोबोटिक्स और नियंत्रण प्रणाली
  - » पूर्वानुमानित मॉडलिंग और पूर्वानुमान

➢ उत्पन्न AI के उदाहरणों में शामिल हैं:

  - » एआई-जनित कलाकृति
  - » चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट
  - » एआई-जनित संगीत और संगीत रचना
  - » स्व-चालित कारें और स्वायत्त प्रणालियाँ
  - » वित्त, स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु पूर्वानुमान के लिए पूर्वानुमानित मॉडल

2. सिकल सेल रोग और बीटा थैलेसीमिया के लिए नई क्रिस्पर थेरेपी कैसगेवी

- कैसगेवी (एक्सगैमग्लोजीन ऑटोटेमसेल), जिसे पहले CTX001 या एक्सा-सीएल के नाम से जाना जाता था, एक अनुमोदित जीन-संपादन थेरेपी है जिसका उपयोग सिकल सेल रोग (एससीडी) वाले लोगों के लिए किया जाता है जो बार-बार वासो-ओक्लूसिव संकट (वीओसी) का अनुभव करते हैं।
- इसे इन दर्दनाक संकटों की आवृत्ति और गंभीरता को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।एक बार अंत:शिरा या शिरा में जलसेक के माध्यम से प्रशासित थेरेपी, सीआरआईएसपीआर थेरेप्यूटिक्स और वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित की गई थी।
- एससीडी के अलावा, कैसगेवी को ट्रांसफ्यूजन-डिपेंडेंट बीटा थैलेसीमिया (टीडीटी) नामक संबंधित स्थिति के इलाज के लिए भी मंजूरी दी गई है।

3. ड्रग वेगोवी

- वेगोवी एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है जिसका उपयोग कुछ लोगों में वजन घटाने में मदद के लिए किया जाता है। इसे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है।

वेगोवी का उपयोग किस लिए किया जाता है?

- लंबे समय तक वजन घटाने के लिए व्यायाम और कम कैलोरी वाले आहार के साथ वेगोवी की सिफारिश की जाती है:
  - » 30 या उससे अधिक बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले वयस्क (मोटापा) के लिए।
  - » 27 या उससे अधिक बीएमआई (जिसे अधिक वजन माना जाता है) और वजन से संबंधित स्वास्थ्य स्थिति वाले वयस्क के लिए।
  - » 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चे जिनका बीएमआई 95 प्रतिशत या उससे अधिक है (जिसे मोटापा माना जाता है) के लिए।

4. एलके–99

- हाल ही में दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक ऐसी सामग्री की खोज का दावा किया है जिसे उन्होंने LK-99 नाम दिया है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार, LK-99 कमरे के तापमान और दबाव पर एक सुपरकंडक्टर है।
- सुपरकंडक्टर्स ऐसी सामग्रियां हैं जो बेहद कम तापमान पर ठंडा होने पर शून्य विद्युत प्रतिरोध प्रदर्शित करती हैं।
- यह गुण उन्हें बिना ऊर्जा हानि के बिजली संचालित करने की अनुमति देता है। उदाहरण: लैंथेनम-बेरियम-कॉपर ऑक्साइड, येट्रियम-बेरियम-कॉपर ऑक्साइड, नाइओबियम-टिन आदि।

5. एनटीएलए–2001

- इंटेलिया थेरेप्यूटिक्स ने कार्डियोमायोपैथी के साथ ट्रान्सथायरेटिन (एटीटीआर) अमाइलॉइडोसिस के उपचार के लिए एनटीएलए-2001 के एक महत्वपूर्ण चरण 3 परीक्षण को शुरू करने के लिए इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग (आईएनडी) एप्लिकेशन को एफडीए की मंजूरी की घोषणा की है।

- एनटीएलए-2001 एक सीआरआईएसपीआर-आधारित जीन संपादन थेरेपी है जो संभावित रूप से एटीटीआर अमाइलॉइडोसिस के लिए पहला एकल-खुराक उपचार हो सकता है।
- **उपचार:** एनटीएलए-2001 मानव शरीर के अंदर जीन को संपादित करने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रशासित किया जाने वाला पहला जांचात्मक सीआरआईएसपीआर थेरेपी उम्मीदवार है।
- **जीन संपादन:** NTLA-2001 TTR जीन को संपादित करने के लिए CRISPR/Cas9 तकनीक का उपयोग करता है, जो ATTR अमाइलॉइडोसिस का कारण बनता है।
- **डिलिवरी:** NTLA-2001 लीवर तक CRISPR/Cas9 प्रणाली पहुंचाने के लिए लिपिड नैनोकणों का उपयोग करता है।
- **प्रभावकारिता:** मजबूत प्रीक्लिनिकल और क्लिनिकल डेटा लक्ष्य जीन के विवो निष्क्रियता के बाद गहरी और लंबे समय तक चलने वाली ट्रांसथायरेटिन (टीटीआर) में कमी दिखाते हैं।
- **क्षमता:** एनटीएलए-2001 में एटीटीआर अमाइलॉइडोसिस के लिए एकल-प्रशासन चिकित्सीय होने की क्षमता है।

6. न्यूट्रिनो:

- **न्यूट्रिनो द्रव्यमान:** न्यूट्रिनो द्रव्यमान का सबसे हालिया और सटीक माप जर्मनी में कार्लजूए ट्रिटियम न्यूट्रिनो प्रयोग (कैट्रिन) द्वारा किया गया था, जिसने 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट (ईवी) से कम पर न्यूट्रिनो के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा स्थापित की गयी।
- **न्यूट्रिनो भौतिकी:** 2024 में, न्यूट्रिनो भौतिकी और खगोल भौतिकी पर XXXI अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 16 से 22 जून तक मिलान, इटली में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन वैज्ञानिकों के लिए न्यूट्रिनो में नवीनतम परिणामों, विचारों और भविष्य के दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए एक मंच होगा।

7. ग्राफीन से बना सेमीकंडक्टर:

- ग्राफीन से बना पहला कार्यात्मक सेमीकंडक्टर 3 जनवरी, 2024 को जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा बनाया गया।
- ग्राफीन सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन की तुलना में 10 गुना अधिक गतिशीलता होती है, जिसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन बहुत कम प्रतिरोध के साथ इसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। इससे कंप्यूटिंग गति में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- सेमीकंडक्टर कार्बन परमाणुओं की एक परत से बना होता है, जो इसे पारंपरिक सिलिकॉन अर्धचालकों की तुलना में बहुत पतला बनाता है। इससे छोटे, अधिक शक्तिशाली उपकरणों का विकास हो सकता है।

8. लाइट-मैटर हाइब्रिड:

- शोधकर्ताओं ने पदार्थ के एक नए चरण की खोज की है, जिसे 'लाइट-मैटर हाइब्रिड' नाम दिया गया है, जो इस बात की समझ को नया आकार दे सकता है कि प्रकाश पदार्थ के साथ कैसे संपर्क करता है।
- लाइट-मैटर हाइब्रिड एक चरण है जो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन शक्तिशाली विकिरण के साथ संपर्क करते हैं।
- शोधकर्ताओं ने एटोसेकंड टाइमस्केल पर प्रकाश-कण इंटरैक्शन का अध्ययन करने के लिए एटोसेकंड एक्स-रे अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग किया। अध्ययन से पता चला कि अवरक्त प्रकाश की तीव्रता अलग-अलग होने से विकिरण की शक्ति के साथ संबंध में इलेक्ट्रॉन के गुण बदल जाते हैं।
- लाइट-मैटर हाइब्रिड चरण में अतिचालकता के समान, मूल अवस्था की तुलना में कम प्रतिरोध होता है। अध्ययन के निष्कर्ष सौर कोशिकाओं और ऑप्टिकल कंप्यूटिंग के विकास में मूल्यवान साबित हो सकते हैं।

9. गिगेंटोपिथेकस ब्लैकी:

- वैज्ञानिकों ने पाया कि सबसे बड़ा ज्ञात प्राइमेट, गिगेंटोपिथेकस ब्लैकी संभवत: 295,000 से 215,000 साल पहले मर गया था, क्योंकि यह लगभग 700,000 साल पहले शुरू हुए पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुसार अपने आहार या व्यवहार को अनुकूलित करने में विफल रहा था।

10. स्लिम अंतरिक्ष यान

- स्लिम एक जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) मिशन, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून का संक्षिप्त रूप है।
- स्लिम 6 सितंबर, 2023 को लॉन्च हुआ और 19 जनवरी, 2024 को चंद्रमा पर उतरा।

स्लिम का उद्देश्य क्या है?

- एसएलआईएम को सटीक चंद्र लैंडिंग तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य हल्के अन्वेषण प्रणालियों का उपयोग करके चंद्रमा और ग्रहों के अध्ययन में तेजी लाना है। इस मिशन द्वारा प्रदर्शित तकनीकें भविष्य के चंद्र नमूना वापसी मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगी।

11. एलआईएसए मिशन

- एलआईएसए मिशन या लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, पहली अंतरिक्ष-आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला होगी।
- एलआईएसए में त्रिकोणीय संरचना में 2.5 मिलियन किमी की दूरी पर तीन अंतरिक्ष यान शामिल होंगे, जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी का अनुसरण करेंगे।

मिशन के उद्देश्य:

- मिशन का लक्ष्य पूरे ब्रह्मांड में, आकाशगंगाओं के केंद्रों पर विशाल ब्लैक होल के टकराने से उत्पन्न होने वाली अंतरिक्ष-समय की

तरंगों का पता लगाना है।

- इससे वैज्ञानिकों को इन पिंडों की उत्पत्ति का पता लगाने, यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि वे सूर्य से लाखों गुना अधिक विशाल कैसे हो गए, और आकाशगंगाओं के विकास में उनकी भूमिका स्थापित करने में सक्षम होंगे।
- मिशन हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों से अनुमानित गुरुत्वाकर्षण 'रिंगिंग' को पता लगाने के लिए तैयार है।

लॉन्च और टाइमलाइन:

- 2035 में लॉन्च की उम्मीद है।
- मिशन अभी विकास चरण में है।

सहयोग:

- एलआईएसए मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए), नासा और वैज्ञानिकों के एक अंतरराष्ट्रीय संघ के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।

12. न्यूरालिंक द्वारा अपना पहला माइक्रोचिप मानव मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया

- एलन मस्क की न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक ने अपना पहला ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (बीसीआई) पहली बार किसी इंसान में प्रत्यारोपित किया है। प्राप्तकर्ता ठीक है और प्रारंभिक परिणामों में आशाजनक न्यूरॉन स्पाइक का पता चला है।
- चिप अल्ट्रा-फाइन 'थ्रेड्स' से जुड़ा एक ट्रांसमीटर है जो तंत्रिका गतिविधि को रिकॉर्ड करता है और थ्रेड्स द्वारा उठाए गए विद्युत संकेतों को वायरलेस तरीके से न्यूरालिंक एप्लिकेशन तक पहुंचाता है।
- इसे टेलीपैथी कहा जाएगा और यह उपयोगकर्ताओं को केवल विचारों से अपने फोन या कंप्यूटर को नियंत्रित करने में सक्षम करेगा।

13. सुपर अर्थ – टीओआई–715 बी:

- TOI-715 b एक सुपर-अर्थ एक्सोप्लैनेट है जो M-प्रकार के तारे की परिक्रमा करता है।
- **स्थान:** ग्रह पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और एक छोटे, लाल तारे की परिक्रमा करता है।
- **आकार:** यह ग्रह पृथ्वी से लगभग डेढ़ गुना चौड़ा है।
- **कक्षा:** ग्रह अपने मूल तारे के चारों ओर रूढ़िवादी रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करता है।
- **वर्ष:** इस ग्रह पर एक वर्ष 19.3 दिन लंबा होता है।
- **तापमान:** ग्रह का संतुलन तापमान 234 K (-39°C) है।
- **वातावरण:** ग्रह का वातावरण जीवन की संभावित उपस्थिति का सुराग दे सकता है।
- **खोज:** इस ग्रह की खोज 2023 में ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) द्वारा की गई थी।

14. जूजवे:

- शुक्र के अर्ध-चंद्रमा 2002 VE के लिए जूजवे नाम को आधिकारिक तौर पर 5 फरवरी, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के कार्य समूह लघु निकाय नामकरण (WGSBN) द्वारा अनुमोदित और घोषित किया गया था।
- जूजवे शुक्र का एक अर्ध-चंद्रमा है, जिसका अर्थ है कि यह ग्रह की परिक्रमा करता प्रतीत होता है लेकिन गुरुत्वाकर्षण से बंधा नहीं है। यह वास्तव में एक जटिल कक्षा में शुक्र और सूर्य दोनों का चक्कर लगाता है।

15. कैल्शियम आयन बैटरी:

- शोधकर्ताओं ने ऑक्साइड संरचनाओं और नए इलेक्ट्रोलाइट्स के उपयोग सहित उच्च प्रदर्शन के साथ कैल्शियम-आयन बैटरी विकसित करने में प्रगति की है।
- कैल्शियम-आयन बैटरियां संभावित रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों, ग्रिड स्टोरेज और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में लिथियम-आयन बैटरियों की जगह ले सकती हैं।
- कैल्शियम प्रचुर मात्रा में, पर्यावरण के अनुकूल, गैर विषैला और सस्ता है, जो इसे बैटरी के लिए लिथियम का एक आशाजनक विकल्प बनाता है।

16. कैल्शियम–आयन बैटरी बनाम लिथियम–आयन बैटरी प्रदर्शन:

- कैल्शियम-आयन बैटरियों में लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में अधिक ऊर्जा घनत्व होता है।
- कैल्शियम-आयन बैटरियों में लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में अधिक सेल वोल्टेज होता है।
- कैल्शियम-आयन बैटरियों की क्षमता लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में अधिक होती है।
- कैल्शियम-आयन बैटरियां लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में कम कुशल होती हैं।

17. क्षुद्रग्रहों की सतह पर पानी के अणु:

- हाल ही में इन्फ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए स्ट्रैटोस्फेरिक वेधशाला के डेटा का उपयोग करके दो क्षुद्रग्रहों, आइरिस और मैसालिया की सतह पर पहली बार पानी के अणुओं का पता लगाया गया।
- **वर्णक्रमीय विश्लेषण:** क्षुद्रग्रहों के वर्णक्रमीय हस्ताक्षरों का विश्लेषण करके पता लगाया गया, जिससे पानी के अणुओं की उपस्थिति का पता चला।
- **क्षुद्रग्रह संरचना:** क्षुद्रग्रह मुख्य रूप से सिलिकेट्स से बने होते हैं, जो आंतरिक सौर मंडल में आम हैं।

- **जल वितरण:** इन क्षुद्रग्रहों पर पानी का पता लगाने से जानकारी प्राप्त होती है कि सौर मंडल में पानी अधिक व्यापक रूप से वितरित हो सकता है।
- **जीवन पर प्रभाव:** क्षुद्रग्रहों पर पानी की उपस्थिति का पृथ्वी से परे जीवन की खोज पर संभावना बढ़ती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए एक आवश्यक घटक है।

18. क्यूएसओ जे0529–43 51 क्वासर:

- **चमक:** QSO श्र0529-4351 अब तक ज्ञात सबसे चमकदार वस्तु है, जो सूर्य से 500 ट्रिलियन गुना अधिक चमकती है।
- **स्थान:** क्वासर 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर पिक्टर तारामंडल में स्थित है।
- **ब्लैक होल:** क्वासर अपने केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होता है, जिसका द्रव्यमान 17 बिलियन सूर्य है और प्रति दिन एक सौर द्रव्यमान से अधिक का उपभोग करता है।
- **अभिवृद्धि डिस्क:** क्वासर की अभिवृद्धि डिस्क सबसे बड़ी ज्ञात डिस्क है, जिसका व्यास सात प्रकाश वर्ष है, और यह सूर्य और नेपच्यून के बीच की दूरी का 15,000 गुना है।
- **विकास दर:** क्वासर में ब्लैक होल का द्रव्यमान प्रति दिन एक सूर्य के बराबर बढ़ रहा है, जिससे यह अब तक ज्ञात सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्लैक होल बन गया है।

19. एमआरएनए–4157/वी940 वैक्सीन:

- एमआरएनए-4157/वी940 एक नवीन जांच संदेशवाहक राइबो न्यूक्लिक एसिड (एमआरएनए)-आधारित वैयक्तिकृत कैंसर वैक्सीन है जो वर्तमान में अंतिम चरण के तीसरे चरण के परीक्षण में है।
- **वैयक्तिकृत कैंसर वैक्सीन:** एमआरएनए-4157/वी940 को प्रत्येक रोगी के ट्यूमर उत्परिवर्तन हस्ताक्षर के लिए विशिष्ट अनुरूप एंटीट्यूमर प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- **एमआरएनए-आधारित:** वैक्सीन में 34 नियोएंटीजन के लिए एक एकल सिंथेटिक एमआरएनए कोडिंग होती है, जिसे रोगी के ट्यूमर के अद्वितीय उत्परिवर्तन हस्ताक्षर के आधार पर डिजाइन और उत्पादित किया जाता है।
- **संयोजन थेरेपी:** mRNA-4157/V940 को KEYTRUDA (पेम्ब्रोलिजुमैब) के संयोजन में विकसित किया जा रहा है, जो एक इम्यूनोथेरेपी है जो ट्यूमर कोशिकाओं का पता लगाने और उनसे लड़ने में मदद करने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता को बढ़ाकर काम करती है।

20. रिकॉर्ड में सबसे गर्म साल

- वैश्विक रिकॉर्ड 1850 में शुरू होने के बाद से वर्ष 2023 सबसे गर्म वर्ष था, 20वीं सदी के औसत 13.9 डिग्री सेल्सियस (57.0 डिग्री फारेनहाइट) से 1.18 डिग्री सेल्सियस (2.12 डिग्री फारेनहाइट) ऊपर। यह मान 2016 में बनाए गए पिछले रिकॉर्ड से 0.15°C (0.27°F) अधिक है। 174 साल के रिकॉर्ड में 10 सबसे गर्म वर्ष पिछले दशक (2014-2023) के दौरान हुए हैं।

2023 में जलवायु टिपिंग बिंदु

जलवायु टिपिंग बिंदु उन महत्वपूर्ण सीमाओं को संदर्भित करते हैं जिनके परे एक प्रणाली या प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण और अक्सर अपरिवर्तनीय परिवर्तन से गुजरती है। 2023 में, पर्यावरण और मानव समाज पर उनके संभावित प्रभावों के कारण कई जलवायु टिपिंग बिंदुओं की बारीकी से निगरानी की जा रही है उनमे शामिल हैं:

- **आर्कटिक की बर्फ का पिघलना:** आर्कटिक की बर्फ की टोपी खतरनाक दर से पिघल रही है, कुछ अनुमानों से पता चलता है कि यह 2040 तक गर्मियों के महीनों के दौरान पूरी तरह से गायब हो सकती है।
- **पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की चादर का ढहना:** पश्चिमी अंटार्कटिक की बर्फ की चादर को अस्थिर माना जाता है और इसके ढहने का खतरा है, जिससे वैश्विक समुद्र का स्तर कई मीटर तक बढ़ सकता है।
- **कोरल रीफ का खत्म होना:** समुद्र के बढ़ते तापमान और अम्लीकरण से दुनिया की कोरल रीफ को खतरा है, जिसके समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और तटीय समुदायों के लिए संभावित विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
- **अमेजॅन रेनफॉरेस्ट डाई-बैक:** वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने अमेजॅन वर्षावन को एक चरम बिंदु तक पहुंचने के खतरे में डाल दिया है, जिसके आगे यह एक हरे-भरे जंगल से सूखे सवाना में बदल सकता है।
- **पर्माफ्रॉस्ट से मीथेन का उत्सर्जन:** पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से भारी मात्रा में मीथेन निकल सकता है, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है।
- **ग्रीनलैंड में बर्फ की चादर का ढहना:** ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का द्रव्यमान बढ़ती दर से घट रहा है, जिसके संभावित परिणाम समुद्र स्तर में वृद्धि और वैश्विक महासागरीय धाराएं हो सकते हैं।
- **मानसून पैटर्न में व्यवधान:** मानसून पैटर्न में बदलाव से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं

ग्रीन केमेस्ट्री

- हरित रसायन विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग का एक क्षेत्र है जो उत्पादों और प्रक्रियाओं के डिजाइन पर केंद्रित है जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग और उत्पादन को कम या समाप्त करता है।

विटामिन

- विटामिन आवश्यक पोषक तत्व हैं जो इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वसा में घुलनशील विटामिन:

- **विटामिन ए (रेटिनॉल):** दृष्टि, प्रतिरक्षा कार्य और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण।
- **विटामिन डी (कोलेकल्सीफेरोल):** हड्डियों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा कार्य और मूड विनियमन के लिए महत्वपूर्ण है।
- **विटामिन ई (टोकोफेरॉल):** एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, कोशिकाओं को क्षति से बचाता है।
- **विटामिन के (फाइलोक्विनोन):** रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

जल में घुलनशील विटामिन:

- **विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड):** प्रतिरक्षा कार्य, कोलेजन उत्पादन और लौह अवशोषण के लिए आवश्यक।
- **थायमिन (विटामिन बी1):** ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका कार्य के लिए आवश्यक।
- **राइबोफ्लेविन (विटामिन बी2):** ऊर्जा उत्पादन और दृष्टि स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण।
- **नियासिन (विटामिन बी3):** ऊर्जा उत्पादन और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण।
- **पैंटोथेनिक एसिड (विटामिन बी5):** ऊर्जा उत्पादन और हार्मोन उत्पादन के लिए आवश्यक।
- **विटामिन बी6 (पाइरिडोक्सिन):** ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका कार्य सहित कई शारीरिक प्रक्रियाओं में शामिल होता है।
- **बायोटिन:** ऊर्जा उत्पादन, तंत्रिका कार्य और स्वस्थ त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए महत्वपूर्ण है।
- **फोलेट (विटामिन बी9):** गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास और ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक।
- **विटामिन बी12 (कोबालामिन):** ऊर्जा उत्पादन, तंत्रिका कार्य और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।

विटामिन के लिए खाद्य स्रोत:

- **विटामिन ए:** शकरकंद, गाजर, पालक, फोर्टिफाइड अनाज।
- **विटामिन बी1 (थियामिन):** साबुत अनाज, पौष्टिक उत्पाद जैसे ब्रेड और अनाज।
- **विटामिन बी2 (राइबोफ्लेविन):** दूध, ब्रेड उत्पाद, फोर्टिफाइड अनाज।
- **विटामिन बी3 (नियासिन):** मांस, मछली, मुर्गी, समृद्ध और साबुत अनाज वाली ब्रेड, फोर्टिफाइड अनाज।
- **विटामिन बी5 (पैंटोथेनिक एसिड):** चिकन, बीफ, आलू, जई, अनाज, टमाटर।
- **विटामिन बी6:** फोर्टिफाइड अनाज, फोर्टिफाइड सोया उत्पाद, छोले, आलू, ऑर्गन मीट।
- **विटामिन बी7 (बायोटिन):** लीवर, फल, मांस।
- **विटामिन बी12:** मछली, मुर्गी, मांस, डेयरी उत्पाद।
- **विटामिन सी:** लाल और हरी मिर्च, कीवी, संतरे और अन्य खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकोली, टमाटर।
- **विटामिन डी:** फिश लीवर ऑयल, वसायुक्त मछली, फोर्टिफाइड दूध उत्पाद, फोर्टिफाइड अनाज।
- **विटामिन ई:** फोर्टिफाइड अनाज, सूरजमुखी के बीज, बादाम, मूंगफली का मक्खन, वनस्पति तेल।
- **विटामिन के:** पालक, कोलार्ड और ब्रोकोली जैसी हरी सब्जियाँ; ब्रसल स्प्राउट; पत्ता गोभी।

रक्त

रक्त के घटक:

- **प्लाज्मा:** प्लाज्मा का 90 प्रतिशत से अधिक भाग पानी है। शेष भाग (मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजेन) ज्यादातर प्लाज्मा प्रोटीन है और अन्य घुले हुए पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट्स और घुली हुई गैसें।
- **लाल रक्त कोशिकाएं (आरबीसी):** फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाती हैं।
- **श्वेत रक्त कोशिकाएं (डब्ल्यूबीसी):** प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा, संक्रमण और बीमारी से लड़ती हैं।
- **प्लेटलेट्स:** रक्त का थक्का जमने और रक्तस्राव रोकने में मदद करता है।

रक्त के प्रकार:

एबीओ ग्रुप:

- ए
- बी
- एबी
- ओ

आरएच प्रकार:

- आरएच पॉजिटिव
- आरएच नकारात्मक

रक्त कार्य:

- **ऑक्सीजन परिवहन:** आरबीसी फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं।

- **कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन:** आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के ऊतकों से फेफड़ों तक ले जाते हैं।
- **पोषक तत्व परिवहन:** प्लाज्मा पाचन तंत्र से शरीर के ऊतकों तक पोषक तत्वों को पहुंचाता है।
- **अपशिष्ट निष्कासन:** प्लाज्मा शरीर के ऊतकों से अपशिष्ट उत्पादों को उत्सर्जन अंगों तक ले जाता है।
- **पीएच का विनियमन:** रक्त शरीर के एसिड-बेस संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है।
- **शरीर के तापमान का नियमन:** रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- **प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य:** डब्ल्यूबीसी संक्रमण और बीमारी से लड़ते हैं।
- **रक्त का थक्का जमना:** प्लेटलेट्स रक्तस्राव को रोकने में मदद करते हैं।

भारत में विनियामक निकाय

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी):

सेबी की स्थापना:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन 12 अप्रैल, 1988 को एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था।
- सेबी की स्थापना 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधान 30 जनवरी 1992 को लागू हुए।

बोर्ड की शक्तियाँ और कार्य:

सेबी को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं:

- प्रतिभूति विनिमय के उपनियमों को मंजूरी देना।
- खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करना और मान्यता प्राप्त प्रतिभूति एक्सचेंजों से समय-समय पर रिटर्न मंगवाना।
- वित्तीय मध्यस्थों के खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करना।
- कुछ कंपनियों को अपने शेयरों को एक या अधिक प्रतिभूति एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने के लिए बाध्य करना।
- दलालों और उप-दलालों का पंजीकरण।
- सुरक्षा बाजार में व्याप्त गड़बड़ियों को दूर करना।

उद्देश्य:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की प्रस्तावना में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बुनियादी कार्यों का वर्णन इस प्रकार किया गया है प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और विकास को बढ़ावा देना, और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना।

भारतीय रिजर्व बैंक:

- **भूमिका:** आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विनियमन के लिए जिम्मेदार है।
- **कार्य:** आरबीआई बैंक नोटों के मुद्दे को नियंत्रित करता है और भारत में मौद्रिक स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए रिजर्व रखता है। यह देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को भी अपने लाभ के लिए संचालित करता है।
- **इतिहास:** आरबीआई की स्थापना 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत की गई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था।
- **स्वामित्व:** आरबीआई का स्वामित्व भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास है।
- **शासन:** आरबीआई की समग्र दिशा 21 सदस्यीय केंद्रीय निदेशक मंडल पर निर्भर करती है, जिसमें गवर्नर, चार डिप्टी गवर्नर, दो वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, दस सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले चार निदेशक शामिल होते हैं।

उद्देश्य:

- आरबीआई का लक्ष्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना और तेजी से जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करने के लिए एक आधुनिक मौद्रिक नीति ढांचा बनाना है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण:

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है।
- **गठन:** आईआरडीएआई का गठन 1999 में हुआ था।
- **कार्य:** आईआरडीएआई को भारत में बीमा को विनियमित करने और लाइसेंस देने का काम सौंपा गया है।
- **उद्देश्य:** आईआरडीएआई के उद्देश्यों में बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता की पसंद में वृद्धि और कम प्रीमियम के साथ ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल है।
- **संरचना:** आईआरडीएआई भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्यों सहित 10 सदस्यीय निकाय है।
- **कार्य:** आईआरडीएआई के कार्यों में पंजीकरण जारी करना, नवीनीकरण करना, संशोधित करना, वापस लेना, निलंबित करना या रद्द करना, पॉलिसीधारक हितों की रक्षा करना, योग्यता निर्दिष्ट करना, मध्यस्थों और एजेंटों के लिए आचार संहिता और प्रशिक्षण, और बहुत कुछ शामिल हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई):

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का गठन 14 अक्टूबर, 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत किया गया था।
- सीसीआई को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने और भारत में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए बनाया गया था। सीसीआई मई 2009 में धनेंद्र कुमार पहले अध्यक्ष के साथ पूरी तरह कार्यात्मक हो गया।
- **संरचना:** सीसीआई में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं।
- **कार्य:** सीसीआई प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और भारत में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार है।
- **उद्देश्य:** सीसीआई का मुख्य उद्देश्य आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
- **शक्तियां:** सीसीआई के पास प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए जांच करने, जुर्माना लगाने और आदेश जारी करने की शक्ति है।
- **क्षेत्राधिकार:** सीसीआई का क्षेत्राधिकार पूरे भारत पर है और यह किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी):

- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) का गठन 24 जुलाई 1998 को विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के तहत किया गया था।

शक्ति:

- जांच और पूछताछ करना
- जुर्माना लगाना
- लाइसेंस देना या रद्द करना
- टैरिफ और शुल्क निर्धारित करना
- विवादों और अपीलों का समाधान करना

संघटन:

- सीईआरसी में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई):

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय है। यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है।

ट्राई के उद्देश्य:

- ट्राई का मिशन भारत में दूरसंचार के विकास के लिए परिस्थितियों का निर्माण और पोषण करना है ताकि देश को उभरते वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाया जा सके।
- ट्राई का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए और साथ ही देश में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी परिस्थितियों का पोषण किया जाए जिससे भारत उभरते वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभा सके।
- ट्राई का मिशन एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीति वातावरण प्रदान करना है जो समान अवसर को बढ़ावा देता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की सुविधा प्रदान करता है।

ट्राई का इतिहास:

- भारत में दूरसंचार सेवाओं और टैरिफ को विनियमित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा 20 फरवरी 1997 को ट्राई की स्थापना की गई थी।

ट्राई की संरचना:

- ट्राई में एक अध्यक्ष और दो से अधिक पूर्णकालिक सदस्य और दो से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होते हैं। ट्राई अधिनियम को 24 जनवरी 2000 से प्रभावी एक अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें ट्राई से न्यायिक और विवाद कार्यों को संभालने के लिए एक दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी।

ट्राई के कार्य:

- ट्राई नियमित रूप से टैरिफ, इंटरकनेक्शन, सेवा की गुणवत्ता, डायरेक्ट टू होम सेवाओं और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जैसे विभिन्न विषयों पर आदेश और निर्देश जारी करता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण:

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासन के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- **उद्देश्य:** FSSAI खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करता है, साथ ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक भी स्थापित करता है।
- **इतिहास:** FSSAI की स्थापना 5 सितंबर 2008 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई थी।
- **कार्य:** FSSAI के विभिन्न कार्य हैं, जिनमें खाद्य सुरक्षा मानकों को निर्धारित करने के लिए नियम बनाना, खाद्य परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए दिशानिर्देश बनाना, केंद्र सरकार को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करना, भोजन में अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान देना शामिल

है।

- **स्थान:** FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं

भारत के औषधि महानियंत्रक:

- भारत का औषधि महानियंत्रक (DCGI) भारत में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) का प्रमुख है जिसकी स्थापना 1940 में हुई थी। सीडीएससीओ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की नियामक संस्था है और यह संस्था कुछ श्रेणियों की दवाओं के लिए लाइसेंस को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।
- सीडीएससीओ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है।
- सीडीएससीओ के नियंत्रण में नौ क्षेत्रीय कार्यालय, सात उप-क्षेत्रीय कार्यालय, 18 बंदरगाह कार्यालय, सात केंद्रीय प्रयोगशालाएं और छह मिनी प्रयोगशालाएं हैं।
- सीडीएससीओ भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (एनआरए) है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए):

- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की स्थापना 29 अगस्त, 1997 को रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग (अब फार्मास्यूटिकल्स विभाग) के एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी।

कार्य:

- एनपीपीए दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र नियामक है।
- एनपीपीए दवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करता है।
- एनपीपीए नियंत्रित थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन की कीमतें तय/संशोधित करता है।
- एनपीपीए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के तहत देश में दवाओं की कीमतों और उपलब्धता को लागू करता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी):

कार्य:

- जल एवं वायु गुणवत्ता की निगरानी।
- विभिन्न पर्यावरण कानूनों के तहत राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखना।
- पर्यावरण मूल्यांकन और अनुसंधान का संचालन करना।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के बीच विवादों का समाधान करना।
- पर्यावरण नियमों का प्रवर्तन।
- उद्योगों और व्यक्तियों को निर्देश और आदेश जारी करना।
- निरीक्षण एवं जांच करना।
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना।
- जन जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रम बनाना।

संगठन संरचना:

- मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- इसमें छह जोनल कार्यालय और 14 उप-जोनल कार्यालय है।

कानून और विनियम:

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट) नियम, 2016
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण:

- **उद्देश्य:** हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए शुल्कों को विनियमित करना।

कार्य:

- वैमानिक सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित करना।
- हवाईअड्डे की सुविधाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना।
- प्रमुख हवाई अड्डों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
- **स्थापित:** AERA अधिनियम, 2008 के अनुसार

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण:

- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए नियामक निकाय है।

स्थापना:

- 23 अगस्त 2003 को भारत में पेंशन क्षेत्र को बढ़ावा देने, विकसित करने और विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से अंतरिम पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की स्थापना की गई थी।

कार्य:

- पीएफआरडीए सरकार के कर्मचारियों द्वारा सदस्यता प्राप्त एनपीएस को नियंत्रित करता है।
- पीएफआरडीए पेंशन बाजार की व्यवस्थित वृद्धि और विकास सुनिश्चित करता है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संदर्भ में सैचेटाइजेशन क्या है?

A. वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को छोटे, अधिक प्रबंधनीय पैकेट में उपलब्ध कराना।
B. वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को बड़े, अधिक जटिल पैकेट में उपलब्ध कराना।
C. वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को सीमित ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराना।
D. वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों के लिए अनुपलब्ध बनाना।

2. वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है?

A. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
B. व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
C. विश्व आर्थिक मंच
D. विश्व बैंक

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. TAK-003 टेकेडा फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित एक डेंगू वैक्सीन है।
2. यह एक टेट्रावेलेंट वैक्सीन है, जिसका अर्थ है कि यह डेंगू वायरस के सभी चार सीरोटाइप (DEN-1, DEN-2, DEN-3 और DEN-4) को लक्षित करता है।
3. यह चरण III नैदानिक परीक्षणों से डेंगू बुखार को रोकने में प्रभावकारिता दिखा चुका है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने अपनी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में कहा कि भारत का प्रेषण 2022 में बढ़कर 111 बिलियन डॉलर हो गया।
2. भारत इस मामले में सबसे आगे है, उसके बाद मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस का स्थान है।
3. भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या भी सबसे अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. शामलात देह भूमि भारत के हरियाणा में एक प्रकार की आम भूमि या समुदाय के स्वामित्व वाली भूमि है।
2. इसे कई भूस्वामियों द्वारा गाँव के लोगों के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी व्यक्तिगत भूमि जोत के बराबर हिस्से को देकर बनाया जाता है।
3. हरियाणा में शामलात देह भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसमें भूस्वामियों ने पंजाब ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में 1992 के संशोधन को चुनौती दी है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

6. वेनेजुएला देश के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है।
2. यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है।
3. वेनेजुएला में मराकाइबो झील स्थित है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 1 और 2
D. केवल 1 और 3

7. व्यक्तित्व अधिकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के निजता या संपत्ति के अधिकार के तहत अपने व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार को संदर्भित करता है।
2. व्यक्तित्व अधिकार प्रचार अधिकारों के समान हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मानव-प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय बर्फ के पिघलने और उसके बाद भूमध्य रेखा की ओर पानी की गति के कारण पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो गई है।
2. ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर पानी की गति के कारण, पृथ्वी थोड़ी कम गोलाकार और अधिक चपटी हो गई है, जिससे घूर्णन धीमा हो गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लक्षद्वीप समूह के द्वीपों पर ICAR-नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (NBFGR) के वैज्ञानिकों ने अगत्ती द्वीप के पास बड़े पैमाने पर एनीमोन ब्लीचिंग पाया है।
2. लक्षद्वीप में कोरल ब्लीचिंग कोई नई घटना नहीं है, लेकिन द्वीप समूह में पहली बार समुद्री एनीमोन ब्लीचिंग देखी गई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

10. उर्वरक पर नैरोबी घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. नैरोबी घोषणा का उद्देश्य 2034 तक घरेलू उर्वरक उत्पादन को तीन गुना करना है, जिसमें स्थानीय उत्पादन पर जोर दिया जाएगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
2. घोषणा 10 साल की कार्य योजना अफ्रीका के लिए मृदा पहल (एसआईए) का हिस्सा है जिसमें वित्तपोषित करने का तंत्र शामिल है।
3. मई 2024 में केन्या में आयोजित दूसरे अफ्रीका उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी राष्ट्रपतियों द्वारा घोषणा का समर्थन किया गया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

11. गैंडे, हाथी, पैंगोलिन, देवदार, शीशम और अगरवुड अवैध वन्यजीव व्यापार से सबसे अधिक प्रभावित हैं। यह निष्कर्ष विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट में आया है। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा दी गई है?

A. यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC)
B. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)
C. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF)
D. जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)

12. इबेरियन लिंक्स के वर्तमान IUCN स्थिति क्या है?

A. गंभीर रूप से संकटग्रस्त
B. संकटग्रस्त
C. कमजोर
D. विलुप्त

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है।
2. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19, प्रवर्तन निदेशालय (ED) को धन शोधन के अपराध को अंजाम देने के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

14. खेत के पेड़ों के नुकसान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. महाराष्ट्र और तेलंगाना को खेत के पेड़ों का महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, कुछ क्षेत्रों में प्रति वर्ग किलोमीटर 50% तक पेड़ कम हुए।
2. भारत ने 2010 और 2018 के बीच खेत के पेड़ों में 11% की गिरावट का अनुभव किया, जिसमें अनुमानित 5.3 मिलियन पेड़ कम हुए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, यूएनओडीसी द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी की गई थी।
2. रिपोर्ट 2015 और 2021 के बीच हुए अवैध वन्यजीव व्यापार की जानकारी प्रदान करती है।
3. रिपोर्ट में पाया गया कि राइनो और पैंगोलिन सबसे अधिक प्रभावित पशु प्रजातियाँ थीं

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात पिछले 18 वर्षों में दोगुना से अधिक हो गया है, जो 2023 में 340 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है और 2030 तक 800 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
2. 2005 और 2023 के बीच सेवा निर्यात वैश्विक सेवा निर्यात के 2% से बढ़कर 4.6% हो गया है, जबकि इसी अवधि में माल निर्यात 1% से बढ़कर केवल 1.8% हुआ।
3. भारत का सेवा निर्यात 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद का 11% होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में IMF ने भारत के विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.8% कर दिया है, जो वित्त वर्ष 2025 के लिए जनवरी के पूर्वानुमान में 6.5% था।
2. IMF ने भारत के वित्त वर्ष 24 के विकास के पूर्वानुमान को भी संशोधित कर 7.8% कर दिया है, जो सरकार के 7.6% के अनुमान से अधिक है।
3. IMF के अनुसार मार्च में भारत की मुद्रास्फीति 10 महीने के निचले स्तर 4.9% पर आ गई।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

18. हाल ही में अक्रा में आयोजित भारत-घाना संयुक्त व्यापार समिति के चौथे सत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था?

A. डिजिटल परिवर्तन समाधान पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) की संभावनाओं पर चर्चा करना।
B. भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा करना।
C. द्विपक्षीय व्यापार और पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश को बढ़ाने के लिए फोकस के क्षेत्रों की पहचान करना।
D. उपरोक्त सभी।

19. हाल ही में चर्चा में रहा कंवर झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह बिहार के बेगूसराय जिले में दूसरी सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है।
2. इसे 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था।
3. यह मीठे पानी की झील है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

20. हाल ही में खबरों में आए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ऑस्ट्रेलिया और भारत ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) पर हस्ताक्षर किए, जो 29 दिसंबर, 2022 को प्रभावी हुआ।
2. यह समझौता ऑस्ट्रेलिया को भारत के 96% निर्यात और भारत को ऑस्ट्रेलिया के 85% निर्यात पर टैरिफ हटाता है।
3. दोनों देश वर्तमान में एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर बातचीत कर रहे हैं, जो ECTA परिणामों पर आधारित होगा

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

21. PS4 इंजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का एक महत्वपूर्ण घटक है।
2. यह नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड (N_2O_4) युक्त द्वि-प्रणोदक संयोजन पर संचालित होता है।
3. इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

22. निम्न में से कौन नाइजीरिया का पड़ोसी देश नहीं है?

A. बेनिन
B. कैमरून
C. चाड

D. दक्षिण अफ्रीका

23. भारत और मंगोलिया संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और ऐसा करने वाला सोवियत ब्लॉक के बाहर पहला देश था।
2. उलानबटार में भारतीय प्रवास मिशन 1971 में खोला गया था।
3. 2015 में दोनों देशों ने रिश्ते को 'रणनीतिक साझेदारी' में बदला।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

24. आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कौन सा क्षेत्र विवादित है?

A. दक्षिण काकेशस
B. नागोर्नो-करबाख
C. आट्र्सख
D. उपरोक्त सभी

25. इग्ला-एस एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक बहुत ही कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जो पोर्टेबल, कंधे से दागी जाने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के रूप में कार्य करती है।
2. इसे आपातकालीन खरीद के तहत रूस से अनुबंधित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

26. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. केरल के स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में तीन जिलों में वेस्ट नाइल बुखार के मामलों की सूचना दी है।
2. यह वेस्ट नाइल वायरस (WNV) के कारण होने वाली बीमारी है।
3. WNV फ्लेविवायरस जीनस का सदस्य है और फ्लेविविरिडे परिवार के जापानी इंसेफेलाइटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित है।
4. पक्षी WNV के प्राकृतिक होस्ट हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. सभी चार

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. हाल ही में, इसरो द्वारा 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट (ISSAR) जारी की गई है।
2. रिपोर्ट बाहरी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की विभिन्न पर्यावरणीय खतरों के प्रति भेद्यता का आकलन करती है।
3. इस दौरान यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस कमांड (USSPACECOM) से लगभग 1,37,565 अलर्ट प्राप्त हुए।
4. भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए 2023 के दौरान इसरो द्वारा कुल 23 CAM किए गए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. सभी चार

28. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों 2024 पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की।
2. रिपोर्ट उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों 2021-2030 के लिए रोड मैप के कार्यान्वयन की दिशा में 2023 में की गई प्रगति का लेखा-जोखा प्रदान करती है।
3. रिपोर्ट को चार खंडों में विभाजित किया गया है और यह वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 20 बीमारियों और रोग समूहों के नियंत्रण, उन्मूलन और उन्मूलन की दिशा में की गई प्रगति का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

29. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) एक काल्पनिक AI सिस्टम है जो कार्यों और डोमेन की एक विस्तृत श्रृंखला में ज्ञान को समझने, सीखने और लागू करने की क्षमता रखता है।
2. AGI AI का एक उन्नत रूप है जो किसी भी बौद्धिक कार्य को कर सकता है जो मनुष्य कर सकता है और इसे बेहतर तरीके से कर सकता है

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है/हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

30. जानवरों में ऑक्सीटोसिन के उपयोग पर दिल्ली उच्च न्यायालय का हालिया रुख क्या है?
A. यह तब तक स्वीकार्य है जब तक इसका उपयोग उचित ढंग से किया जाए।
B. यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत एक संज्ञेय अपराध है।
C. यह केवल मवेशियों की कुछ नस्लों के लिए स्वीकार्य है।
D. यह केवल कुछ डेयरी फार्मों के लिए स्वीकार्य है।

31. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक अंतर-सरकारी संगठन है।
2. इसकी स्थापना पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत फ्रांस द्वारा की गई थी।
3. इसका मुख्यालय राजस्थान के बाड़मेर में है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

32. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. हाल ही में, वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के नेतृत्व में भारत के सात सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने नाइजीरिया का दौरा किया और अबुजा में अपने नाइजीरियाई समकक्षों के साथ एक संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की बैठक की।
2. बैठक के दौरान भारत और नाइजीरिया ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग बढ़ाने के क्षेत्रों की पहचान की है।
3. भारत और नाइजीरिया ने 2017 में भारतीय पक्ष से वाणिज्य सचिव और नाइजीरियाई पक्ष से स्थायी सचिव (व्यापार) के स्तर पर चल रहे द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों की समीक्षा के लिए एक संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की स्थापना की थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

33. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दो प्रमुख संशोधनों को पेश करके किशोर न्याय अधिनियम को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड या बाल न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सख्त 30-दिवसीय समय सीमा तय की है।
3. इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना और न्याय देने में देरी को रोकना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

34. राज्यपाल के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल को अपने आधिकारिक कार्यों के लिए कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होती है।
2. राज्यपाल को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलायी जाती है।
3. संविधान स्पष्ट रूप से उन आधारों को निर्धारित करता है जिनके आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

35. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?
1. सोहराई पेंटिंग में मुख्य रूप से देवताओं और पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाता है
2. सोहराई पेंटिंग में मजबूत मातृसत्तात्मक जड़ें हैं और यह माताओं से बेटियों को विरासत में मिली है।
3. पेंटिंग पारंपरिक रूप से मिट्टी की दीवारों पर बनाई जाती हैं और फसल उत्सवों और विवाह अनुष्ठानों से जुड़ी होती हैं।

सही कथन चुनें
A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 3
C. केवल 2
D. केवल 1 और 2

36. भारत-बांग्लादेश संबंधों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी और दिसंबर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश के साथ राजनयिक

संबंध स्थापित किए।
2. बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
3. भारत ने 2011 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के तहत तम्बाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को शुल्क मुक्त कोटा मुक्त पहुँच प्रदान की है।

सही कथन चुनें
A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 3
C. केवल 2
D. सभी

37. हूती विद्रोही के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. हूती एक शिया राजनीतिक और सैन्य संगठन है जो 1990 के दशक में यमन में यमनी सरकार के विरोध के रूप में उभरा।
2. यह समूह मध्य पूर्व में फैल रही अमेरिकी विरोधी और इजरायल विरोधी भावनाओं से प्रेरित था।
3. 2011 में, हौथियों ने अरब स्प्रिंग के रूप में जानी जाने वाली यमनी क्रांति को भड़काने में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

सही कथन चुनें
A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 3
C. केवल 2
D. सभी

38. वितरित खाता प्रौद्योगिकी (डीएलटी) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वितरित खाता प्रौद्योगिकी (डीएलटी) परिसंपत्ति लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिजिटल प्रणाली है जिसमें एक ही समय में कई स्थानों पर विवरण दर्ज किए जाते हैं।
2. ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी एक विशिष्ट प्रकार की वितरित खाता प्रौद्योगिकी है।
3. पारंपरिक डेटाबेस के विपरीत, वितरित खाताधारकों में केंद्रीय डेटा स्टोर या प्रशासन कार्यक्षमता होती है

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की हैं।
2. SCBA को अपनी कार्यकारी समिति के चुनावों के लिए आरक्षण और दिशा-निर्देश स्थापित करने हैं।
3. कोषाध्यक्ष सहित विभिन्न समिति पदों में एक तिहाई सीटें महिला सदस्यों के लिए आरक्षित की जानी हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

40. एगशेल स्कल नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. कथन-I: यह एक कानूनी सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि अपराधी सभी क्षति/घाव के लिए उत्तरदायी है, भले ही पीड़ित की पहले से कोई ऐसी स्थिति हो जो चोट को और भी बदतर बना दे।
2. कथन-II: यह नियम उस क्षति के लिए बढ़े हुए मुआवजे का दावा करने के लिए लागू किया जाता है जो प्रतिवादी द्वारा होने वाली सामान्य रूप से अनुमानित क्षति से अधिक हो।

सही कोड का चयन करें।
A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही स्पष्टीकरण है
B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही स्पष्टीकरण नहीं है
C. कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है
D. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है

41. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 लॉन्च की।
2. रिपोर्ट में वैश्विक प्रवासन पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलावों का खुलासा किया गया है, जिसमें विस्थापित लोगों की रिकॉर्ड संख्या और अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण में वृद्धि शामिल है।
3. रिपोर्ट में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन मानव विकास और आर्थिक विकास का एक चालक बना हुआ है जिसे 2000 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण में 650 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि से 128 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

42. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. हाल ही में TAK-003 WHO द्वारा प्रीक्वालीफाई किया जाने वाला दूसरा डेंगू वैक्सीन बन गया है।
2. यह एक जीवित-क्षीणित वैक्सीन है जिसमें डेंगू पैदा करने

वाले वायरस के चार सीरोटाइप के कमजोर संस्करण शामिल हैं।

3. WHO उच्च डेंगू बोझ और संचरण तीव्रता वाले सेटिंग्स में 6-16 वर्ष की आयु के बच्चों में TAK-003 के उपयोग की सिफारिश करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

43. विश्व मधुमक्खी दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस दिन को आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीकों के 18वीं सदी के स्लोवेनियाई अग्रणी एंटोन जानसा के जन्मदिन का सम्मान करने के लिए चुना गया था।
2. इस दिन को 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था।
3. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM) 2020 में शुरू किया गया था।
4. पश्चिम बंगाल शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. सभी चार

44. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आर्टारा 24 दुबई में जैजरॉकर्स द्वारा आयोजित एक ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता है।
2. आर्टारा 24 का प्राथमिक उद्देश्य उभरती हुई कलात्मक प्रतिभाओं को उजागर करना और उनका पोषण करना था, विशेष रूप से दुबई में रहने वाली भारतीय प्रतिभाओं पर ध्यान केंद्रित करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

45. AK-203 असॉल्ट राइफल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह AK-100 शृंखला राइफलों का एक प्रकार है।
2. इसका उद्देश्य स्वदेशी INSAS राइफल को प्रतिस्थापित करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

46. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कथन-I: कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसमें कैल्शियम धनायन और कार्बाइड ऋणायन होता है।
2. कथन-II: इसका उपयोग कैल्शियम साइनामाइड बनाने और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है/हैं?

A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।
B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
C. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
D. कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

47. हाल ही में समाचारों में आए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति 36.62 से घटकर 31.28 हो गई।
2. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रतिवर्ष संकलित किया जाता है, जो पत्रकारों की स्वतंत्र रूप से काम करने और रिपोर्ट करने की क्षमता का आकलन करता है।
3. भारत की रैंक 2023 में 161 से बढ़कर 2024 में 159 हो गई।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

48. हाल ही में समाचारों में आए मणिपुरी टट्टू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मणिपुरी टट्टू भारत की सात मान्यता प्राप्त घोड़ा और टट्टू नस्लों में से एक है।
2. इसे मूल पोलो टट्टू माना जाता है, क्योंकि मणिपुर के पारंपरिक सागोल कांगजेई खेल ने आधुनिक पोलो को जन्म दिया।
3. नस्ल के संरक्षण के लिए 2016 में मणिपुरी टट्टू संरक्षण और विकास नीति (एमपीसीडीपी) तैयार की गई थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो

C. सभी तीन
D. कोई नहीं

49. आईसीएमआर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन के लिए सर्वोच्च निकाय है।
2. इसकी स्थापना 1911 में भारतीय अनुसंधान निधि संघ (आईआरएफए) के रूप में की गई थी।
3. इसका नाम बदलकर 1950 में आईसीएमआर कर दिया गया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

50. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. हाल ही में, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के लिए अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी ट्रस्ट फंड में $5,00,000 का योगदान दिया।
2. संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी ट्रस्ट फंड की स्थापना 2009 में की गई थी और इसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी कार्यालय (यूएनओसीटी) को हस्तांतरित कर दिया गया था।
3. यह फंड सरकारों, अंतर-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, निजी संस्थानों और व्यक्तियों सहित विभिन्न संस्थाओं से योगदान स्वीकार करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

51. हाल ही में समाचारों में देखी गई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत सरकार ने 2026 तक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना शुरू करने की योजना की घोषणा की है।
2. इस योजना का उद्देश्य उत्सर्जन में कमी के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।
3. इस योजना के तहत, संस्थाएँ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए खुद को 'पंजीकृत संस्थाओं' के रूप में पंजीकृत कर सकती हैं।
4. कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र केंद्र सरकार या अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किए जाएंगे।
5. यह योजना अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने और अपने जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों को पूरा करने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल चार
D. सभी पाँच

52. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुसंधान और विकास (R-D) प्रयासों का मार्गदर्शन करने, रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से निपटने के लिए अपनी जीवाणु प्राथमिकता रोगजनक सूची (BPPL) को अपडेट किया है।
2. सूची का उद्देश्य एंटीबायोटिक प्रतिरोध की उभरती चुनौतियों का समाधान करना है जो एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर

1.	(A)	19.	(C)	37.	(D)
2.	(C)	20.	(C)	38.	(B)
3.	(C)	21.	(C)	39.	(C)
4.	(C)	22.	(D)	40.	(A)
5.	(C)	23.	(C)	41.	(C)
6.	(D)	24.	(D)	42.	(C)
7.	(C)	25.	(D)	43.	(C)
8.	(C)	26.	(D)	44.	(C)
9.	(C)	27.	(D)	45.	(C)
10.	(C)	28.	(C)	46.	(A)
11.	(A)	29.	(C)	47.	(C)
12.	(B)	30.	(B)	48.	(C)
13.	(C)	31.	(B)	48.	(C)
14.	(C)	32.	(C)	49.	(B)
15.	(C)	33.	(C)	50.	(B)
16.	(C)	34.	(B)	51.	(D)
17.	(C)	35.	(B)	52.	(C)
18.	(D)	36.	(D)		

प्रीलिम्स आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वायुमंडलीय अमोनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वायुमंडलीय अमोनिया (NH_3) नाइट्रोजन चक्र का एक प्रमुख घटक है और वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित क्षारीय गैस है।
2. इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक और मानवजनित दोनों स्रोतों से होती है।
3. औद्योगिक प्रदूषण मानवजनित अमोनिया उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने **गलत** हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

2. SWATI Portal के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह STEMM में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक एकल ऑनलाइन पोर्टल है।
2. इसका विकास और रखरखाव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च (NIPGR) द्वारा किया जाता है।
3. यह लैंगिक-अंतराल की चुनौतियों का समाधान करने वाला भारत का पहला पोर्टल है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

3. HAPS प्रौद्योगिकी अपनी क्षमता के कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है:

(a) विशाल सीमा क्षेत्रों में वास्तविक समय की इमेजरी और डेटा अधिग्रहण प्रदान करना।
(b) उग्रवाद की आशंका वाले दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर संचार बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराना।
(c) दुश्मन की पहचान सीमा से परे अत्यधिक ऊंचाई वाले टोही मिशनों का संचालन करना।
(d) उपर्युक्त सभी

4. भारत की बंजर भूमि को हरा-भरा करने की कृषि वानिकी (GROW) रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रिपोर्ट हरियाली और बहाली परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों और उद्योगों का समर्थन करने के लिए राज्य-वार और जिला-वार विश्लेषण प्रदान करती है।
2. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. फ्लोर टेस्ट 1954 में प्रारंभ की गई संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है।
2. अनुच्छेद 163 के तहत, किसी राज्य का राज्यपाल उस समय शक्ति परीक्षण करा सकता है जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो।
3. जब सदन का सत्र चल रहा हो तो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विश्वास मत का आह्वान किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

6. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	संरक्षित क्षेत्र	**राज्य**
1.	गुप्तेश्वर वन	– झारखण्ड
2.	थानथाई पेरियार अभयारण्य	– केरल
3.	वेदानथंगल पक्षी अभयारण्य	– तमिलनाडु

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

7. e-Jagriti के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक एकीकृत पोर्टल है जो सभी स्तरों पर सरल, तीव्र और लागत प्रभावी उपभोक्ता विवाद निवारण सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है।
2. यह विवाद समाधान परिदृश्य में दक्षता और नवीनता को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग

का उपयोग करता है।
3. इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित, डिजाइन और संरक्षित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

8. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. बेल्ट एंड रोड पहल
2. लिविंग इंडस पहल
3. महान हरित दीवार पहल
4. एक्सियन एंडिना सामाजिक आंदोलन

उपर्युक्त में से कौन सी परियोजनाएँ विश्व पुनर्स्थापना फ्लैगशिप का हिस्सा हैं?
(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

9. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. वांडेरू
2. भारतीय हाथी
3. नीलगिरि तहर
4. ग्रेटर एक सींग वाला गैंडा
5. एशियाई शेर

उपर्युक्त में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है?
(a) केवल 3, 4 और 5
(b) केवल 1, 3 और 5
(c) केवल 2, 3, 4 और 5
(d) केवल 1, 3, 4 और 5

10. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	जीव		**सहजीवी संबंध**
1.	बार्नाकल और तैरने वाले केकड़े	–	परजीविता
2.	क्लाउनफिश और समुद्री एनीमोन्स	–	सहभोजिता
3.	बार्नाकल और हंपबैक व्हेल	–	पारस्परिकता
4.	मूंगे और स्पंज	–	प्रतिस्पर्धा

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

11. गल्फ स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक गर्म समुद्री धारा है जो मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है।
2. यह एक महत्वपूर्ण कन्वेयर बेल्ट के रूप में कार्य करता है और दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है।
3. यह अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) का हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

12. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	मार्शल आर्ट		**उद्गम राज्य**
1.	क्राव मागा	–	असम
2.	कलारीपयट्टू	–	केरल
3.	गतका	–	पंजाब
4.	खुकुरी नृत्य	–	नागालैंड

उपर्युक्त कितने युग्म सही सुमेलित हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

13. प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे बॉन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में एक पर्यावरण संधि है।
2. यह एकमात्र वैश्विक और संयुक्त राष्ट्र-आधारित अंतरसरकारी संगठन है जो विशेष रूप से स्थलीय, जलीय और प्रवासी पक्षी के प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है।
3. जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (COP-14) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक ब्राजील सरकार द्वारा आयोजित की गई है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

14. चुनावी बांड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चुनावी बांड ब्याज मुक्त वाहक बांड या धन उपकरण हैं

जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता है।
2. ये बांड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में उपलब्ध हैं।
3. चुनावी बांड केवल 15 दिनों के लिए वैध हैं और इसका उपयोग राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

15. माइसेलर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. माइसेलर जल उत्पादों में मिसेल्स होते हैं, जो अणुओं के समूह होते हैं और चिकने संदूषकों को समाप्त करने में बेहद प्रभावी होते हैं।
2. यह आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला त्वचा देखभाल करने वाला उत्पाद है जो आपकी त्वचा से अशुद्धियाँ और मेकअप हटाने में मदद करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

16. कैसिनी अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कैसिनी-ह्यूजेंस शनि पर नासा, ईएसए और इसरो का एक सहयोगी मिशन था।
2. यह 2015 में लॉन्च किए गए सबसे बड़े अंतरग्रहीय अंतरिक्षयान में से एक था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

17. यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह वर्ष 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
2. इसका उद्देश्य यूरोप और वैश्विक स्तर पर अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

18. निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए:
यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। यह सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी में बसा है, जो भारत का हृदय है और मध्य भारतीय उच्चभूमि का निर्माण करता है। रुडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध उपन्यास, द जंगल बुक में चित्रित जंगल को कुछ लोग जंगलों पर आधारित मानते हैं, जिसमें यह अभ्यारण्य भी शामिल है। यह आधिकारिक तौर पर शुभंकर, "भूरसिंह द बारासिंघा" आरम्भ करने वाला भारत का पहला बाघ अभयारण्य भी है। पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, स्लॉथ भालू और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण/सार्थक आबादी है।
उपर्युक्त अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य से संबंधित है?
(a) पन्ना टाइगर रिजर्व
(b) पेंच टाइगर रिजर्व
(c) बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
(d) कान्हा टाइगर रिजर्व

19. कार्यक्रम (YUVIKA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. YUVIKA, शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने वाले युवा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए इसरो का एक शिक्षण और जागरूकता उत्पन्न करने वाला कार्यक्रम है।
2. जिन छात्रों ने 10वीं कक्षा पूरी कर ली है और वर्तमान में 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, वे कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
3. प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से दो छात्र हर साल इस कार्यक्रम में भाग लेंगे , जिसमें CBSE, ICSE और राज्य-बोर्ड पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

20. एंटी-सैटेलाइट हथियार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे उन उपग्रहों को निष्क्रिय करने या नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है जो पहले से ही कक्षा में हैं और सक्रिय हैं।
2. ये सभी हमले हवाई, निचली कक्षा या यहां तक कि जमीनी प्रतिष्ठानों से भी शुरू किए जा सकते हैं।
3. 'मिशन शक्ति' भारत का पहला एंटी-सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

21. इंडिया स्टैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का एक सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने की अनुमति देता है।
2. चूंकि इस परियोजना के नाम में इंडिया शब्द है, इसलिए इंडिया स्टैक का दृष्टिकोण केवल भारत तक ही सीमित है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

22. म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर संवाद के लिए विश्व का अग्रणी मंच है।
2. इसका आयोजन यूरोपीय संघ द्वारा किया जाता है।
3. इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के तहत निरंतर, क्यूरेटेड और अनौपचारिक बातचीत को बनाए रखते हुए विश्वास का निर्माण करना और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान में योगदान देना है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

23. मध्य एशियाई फ्लाईवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह आर्कटिक और हिंद महासागरों तथा संबंधित द्वीप श्रृंखलाओं के मध्य यूरेशिया के एक बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र को कवर करता है।
2. फ्लाईवे एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें प्रवासी प्रजातियों का समूह अपना वार्षिक चक्र-प्रजनन, मॉलिंग, स्टेजिंग और गैर-प्रजनन को पूरा करता है।
3. विश्व में कुल पांच फ्लाईवे हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

24. रबर बोर्ड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह रबर अधिनियम, 1947 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है।
2. इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

25. क्वासर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. क्वासर एक अत्यंत सक्रिय और चमकदार प्रकार का सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस है।
2. ऐसा माना जाता है कि क्वासर ब्रह्मांड के उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां पदार्थ का बड़े पैमाने पर घनत्व औसत से बहुत अधिक है।
3. ये ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे चमकदार, शक्तिशाली और जीवंत वस्तुओं में से हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

26. रोडामाइन-बी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक पानी में घुलनशील रासायनिक यौगिक है।
2. यह आमतौर पर कपड़ा, कागज, चमड़ा और पेंट उद्योग में रंगाई के लिए एक रंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाने वाला रसायन है जो लाल और गुलाबी रंग प्राप्त करने में मदद करता है।
3. यह विशेष रूप से खतरनाक हो जाता है जब इसे खाद्य उत्पादों के साथ मिलाया जाता है, जिससे समय के साथ कैंसर और ट्यूमर होता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

27. रायसीना डायलॉग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है।
2. यह 2015 से प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
3. 2024 संस्करण का विषय "चतुरंग: संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण" है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

28. निएंडरथल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I:
निएंडरथल पुरातन मानवों की एक विलुप्त प्रजाति है जो लगभग 40,000 साल पहले तक उत्तरी अमेरिका में रहते थे।
कथन II:
निएंडरथल अंतत: विलुप्त होने से पहले लंबे समय तक आधुनिक मनुष्यों के साथ सह-अस्तित्व में थे।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I के लिए सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है।
(d) कथन-I गलत है किन्तु कथन-II सही है।

29. ग्रीन एनाकोंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वजन और लंबाई के आधार पर यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्प है।
2. इनका मूल स्थान उत्तरी अमेरिका है, तथा यह आम तौर पर पर्णपाती वनों में पाये जाते हैं।
3. यह कंस्ट्रिक्टर्स परिवार का सदस्य है, जो बहुत जहरीले सांप होते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

30. तुअर-दाल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक महत्वपूर्ण फलीदार फसल और प्रोटीन युक्त भोजन है जिसे भारत में मुख्य रूप से दाल के रूप में उपभोग किया जाता है।
2. यह मुख्यत: उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है, जिसकी खेती मुख्य रूप से भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

31. उचित एवं लाभकारी मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह सरकार द्वारा घोषित मूल्य है, जिसे मिलें किसानों को उनसे खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
2. एफआरपी कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा तय किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

32. सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कैबिनेट समितियाँ संविधानेतर होती हैं।
2. सीसीएस का नेतृत्व लोक सभा अध्यक्ष करता है।
3. सीसीएस भारत की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का निस्तारण करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

33. पॉजिट्रोनियम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पॉजिट्रोनियम एक अल्पकालिक हाइड्रोजन जैसा परमाणु है,

जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और उसके समकक्ष एंटीमैटर, एक पॉजिट्रॉन होता है।
2. इसका जीवन बहुत छोटा होने के कारण यह 142 नैनो-सेकंड के आधे जीवन में नष्ट हो जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

34. चित्तीदार हिरण (चीतल) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चित्तीदार हिरण या चीतल भारतीय उपमहाद्वीप की मूल स्थानीय हिरण प्रजाति है।
2. यह एशिया में व्यापक रूप से पायी जाती है, विशेष रूप से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान के एक छोटे समूह में।
3. इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

35. ब्लैनेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ब्लैनेट अन्य ग्रहों के समान हैं, लेकिन वे किसी तारे या भूरे बौने के बजाय एक ब्लैक होल की परिक्रमा करते हैं।
2. उनके पास अपने गुरुत्वाकर्षण द्वारा गोल होने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान है, लेकिन थर्मोन्यूक्लियर संलयन शुरू करने और तारे बनने के लिए पर्याप्त नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

36. एडवर्ड्स सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह क्रोमोसोम 18 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होने वाला एक ऑटोसोमल क्रोमोसोमल विकार है।
2. यह एक बहुत ही गंभीर आनुवंशिक स्थिति है जो बच्चे के शरीर के विकास और वृद्धि को प्रभावित करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

37. G-33 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. G-33 (कृषि क्षेत्र में विशेष उत्पादों के मित्र) विकसित और विकासशील देशों का एक गठबंधन है।
2. भारत इस समूह का सदस्य नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

38. गर्भिनी-GA2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह दूसरी और तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला में भ्रूण की समयावधि का सटीक निर्धारण करने वाला पहला भारत-विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल है।
2. इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (टीएचएसटीआई), फरीदाबाद के शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

39. एरोसोल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वे हवा या गैस में निलंबित छोटे ठोस या तरल कण हैं।
2. एरोसोल प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे कोहरा या ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैस या कृत्रिम जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से निकलने वाला धुआं।
3. एरोसोल कण या तो सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं (प्राथमिक एरोसोल) या वायुमंडल में पूर्ववर्ती गैसों (द्वितीयक एरोसोल) से उत्पन्न होते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

40. अतिरिक्त टियर-1 (AT-1) बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. AT-1 बांड स्थायी बांड हैं जिनकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं है।
2. इन बांड्स में निवेशकों को उनका मूलधन वापस मिल

जाता है।
3. AT-1 बांड पर अन्य बांड की तुलना में कम ब्याज दर होती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

41. जनरल डायरी (GD) और प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रत्येक एफआईआर की एक प्रति वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है जबकि जीडी की प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी जाती है, हालांकि इसकी प्रति एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भेजी जाती है।
2. जनरल डायरी एक आंतरिक पुलिस रिकॉर्ड है, जबकि एफआईआर के मामले में, इनकी एक प्रति शिकायतकर्ता को प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

42. निम्नलिखित देशों को नाममात्र जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. भारत
2. चीन
3. यूएसए
4. जर्मनी
5. जापान

सही उत्तर चुनिए:
(a) 3-2-4-1-5
(b) 3-2-5-1-4
(c) 3-2-4-5-1
(d) 3-2-5-4-1

43. राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह मूल्य सूचकांक है जो सभी बिक्री चैनलों से कीमतों को शामिल करता है और कोयला ब्लॉकों के वाणिज्यिक खनन में नीलामी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है।
3. सूचकांक की अवधारणा और डिजाइन केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान (CMPDI) द्वारा विकसित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

44. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति *(SIDE)* रिपोर्ट, 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे नीति आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष दो बार जारी किया जाता है।
2. अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटलीकृत देश है।
3. रैंकिंग कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट और सस्टेन (CHIPS) ढांचे के 5 स्तंभों पर आधारित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

45. वैभव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका उद्देश्य भारतीय STEMM प्रवासी भारतीयों को भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से जोड़ना है।
2. यह योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
3. यह फेलोशिप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में काम करने वाले सभी वैज्ञानिकों के लिए है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

46. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे 1974 में तेल की आपूर्ति में बड़े व्यवधानों पर सामूहिक प्रतिक्रिया के समन्वय में मदद करने के लिए बनाया गया था।
2. IEA में पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की सदस्यता एक शर्त है।
3. उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट IEA की एक पहल है।

उपर्युक्त कितने कथन गलत हैं?
(a) केवल एक

(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

47. इंडियन स्कीमर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक प्रवासी प्रजाति है जो रूस और पूर्वी एशिया में प्रजनन करती है।
2. वे अपना अधिकांश जीवन चक्र वृक्षरेखा के ऊपर बिताते हैं।
3. यह प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन (सीएमएस) के तहत सूचीबद्ध है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

48. अनुच्छेद 142 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह उन स्थितियों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को असाधारण अधिकार प्रदान करता है जहां मौजूदा कानूनों या कानूनों में पर्याप्त उपचार की कमी हो सकती है।
2. अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए आदेशों या डिक्री को संसद द्वारा स्थापित मौजूदा कानूनों का पालन करना होगा।
3. अनुच्छेद 142 सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं है और इसे प्रत्येक मामले में लागू नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

49 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत या विदेश में पारस्परिक लाभ के लिए सहकारी विपणन के विकास के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के साथ सहयोग करना।
2. वेयरहाउसिंग अधिनियम के तहत वेयरहाउस के रूप में कार्य करना।
3. सहकारी संस्थाओं की विपणन और व्यापारिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना, समन्वय करना और बढ़ावा देना।
4. कृषि उपज और अन्य वस्तुओं की ग्रेडिंग, पैकिंग, मानकीकरण, वैज्ञानिक उपचार और प्रक्रिया के अंतर्गत आता है।

उपर्युक्त में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ *(NAFED)* के उद्देश्य हैं?
(a) केवल 1, 3 और 4
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

50. आउटकम बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा धन के परिव्यय को उनके अपेक्षित परिणामों से जोड़ता है।
2. आउटकम बजटिंग की अवधारणा भारत में 2005 में शुरू की गई थी।
3. सभी राज्य विधानसभाओं के लिए आउटकम बजटिंग का पालन करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

51. यू-रिपोर्ट, युवा लोगों के लिए एक डिजिटल समुदाय, पहल है:
(a) क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (CAN)
(b) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)
(c) संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)
(d) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)

52. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह 1987 में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। ।
2. यह संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है।
3. यह एक सांस्कृतिक संग्राहक और प्राचीन ग्रंथों का संरक्षक है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

53. *INSAT-3DS* मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) का उपयोग करके लॉन्च किया गया था।
2. यह मिशन पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)

द्वारा वित्त पोषित है।
3. यह मिशन पर्यावरण निगरानी, मौसम पूर्वानुमान और आपदा राहत कार्यों में सहायता करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

54. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड *(NBWL)* के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है जिसमें सेना प्रमुख और रक्षा सचिव सहित अन्य सदस्य होते हैं।
2. इसका गठन भारतीय वन्यजीव बोर्ड के स्थान पर वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया था।
3. बोर्ड को वर्ष में कम से कम दो बार बैठके करना होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

55. बलीन व्हेल दांतेदार व्हेल से किस प्रकार भिन्न हैं?
1. दांतेदार व्हेल समुद्री जल से शिकार को छानती हैं जबकि बलीन व्हेल सक्रिय रूप से मछली, स्क्विड और अन्य समुद्री जीवों का शिकार करती हैं।
2. ब्लू व्हेल एक बलीन व्हेल है जबकि डॉल्फिन और पोर्पोइज दांतेदार व्हेल से संबंधित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

56. हाल ही में समाचारों में देखा जाने वाला मोरोधारो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
(a) धोलावीरा के पास हाल ही में खोजा गया हड़प्पा स्थल
(b) यह कॉटन कैंडी में पाया जाने वाला एक कैंसर जनित पदार्थ है।
(c) हाल ही में रूसी सेना द्वारा यूक्रेन में कब्जा किया गया एक शहर है।
(d) अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी में स्थित एक सबसे बड़ा बौद्ध मठ

57. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. AWBI पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत स्थापित एक वैधानिक सलाहकार निकाय है।
2. AWBI पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तत्वावधान में काम करता है।
3. राजकुमारी अमृत कौर ने बोर्ड की स्थापना का नेतृत्व किया, जिसका मुख्यालय चेन्नई में था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने **गलत** हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

58. समाचारों में रहे निम्नलिखित शहर और उनसे सम्बन्धित देशों पर विचार कीजिए:

	शहर	–	देश
1.	राफा	–	सीरिया
2.	सिनाई	–	सऊदी अरब
3.	बेलगोरोड	–	बेल्जियम
4.	एंगोस्टूरा	–	टर्की

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

59. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. मीथेन
2. ब्लैक कार्बन
3. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन
4. ग्राउण्ड लेवल ओजोन

उपर्युक्त में से किसे सुपर प्रदूषक के रूप में जाना जाता है?
(a) केवल 1, 3 और 4
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

60. घड़ियाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अनुसूची । की प्रजाति है और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है।
2. गंडक घड़ियाल रिकवरी परियोजना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की एक पहल है।
3. वे खारे पानी में रहते हैं और भोजन के लिए विशेष रूप से मछलियों पर निर्भर रहते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

61. एलोरा गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एलोरा की गुफाएँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं।
2. गुफाओं को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
3. क्षेत्र की स्थलाकृति अर्धवृत्त के आकार में एक चट्टानी पठार से बनी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

62. राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है।
2. संविधान ने राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किया है।
3. राष्ट्रपति कला, विज्ञान, खेल और समाज सेवा में अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

63. व्हिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. व्हिप शब्द का उल्लेख न तो भारत के संविधान में, न सदन के नियमों में और न ही संसदीय कानून में किया गया है।
2. भारत में सभी दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

64. अवरोधन आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. गृह सचिव, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सूचना को रोकने, निगरानी करने और डिक्रिप्ट करने के आदेशों को निष्पादित करने वाली नोडल एजेंसी है।
2. निगरानी डेटा को छह माह के अन्दर हटाना होता है।
3. आईटी नियम, 2009 उस प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करते हैं जिनका सरकार को सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन का पालन करना होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

65. बढ़ते समुद्र और भीषण तूफान धीरे-धीरे तुवालु द्वीप को डुबो रहे हैं। तुवालु स्थित है?
(a) आर्कटिक महासागर
(b) प्रशांत महासागर
(c) हिंद महासागर
(d) दक्षिणी महासागर

66. बौद्ध और जैन साहित्य के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बौद्ध कथाएँ और साहित्य चरित्र में उपदेशात्मक हैं, जबकि जैन कथाएँ नहीं हैं।
2. प्राचीन/मध्यकालीन बौद्ध साहित्य संस्कृत में उपलब्ध है, जबकि प्राचीन/मध्यकालीन जैन साहित्य की रचना संस्कृत में नहीं की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

67. भक्ति साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ज्ञानेश्वर एक मराठी भक्ति कवि थे।
2. तुकाराम, ज्ञानेश्वर के समकालीन थे जिन्होंने गुजराती में भक्ति गद्य लिखा था।
3. एकनाथ ने काव्यात्मक आख्यान और भक्तिपूर्ण अभंग लिखे।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

68. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संगीत से संबंधित गंधर्व वेद अथर्ववेद का उपवेद है।
2. जैमिनी ब्राह्मण सामूहिक रूप से नृत्य और संगीत की बात करता है।
3. ऐतरेय आरण्यक संगीत वाद्ययंत्रों की चर्चा करता है।
4. संगीत सिद्धांत का पहला उल्लेख भरत के नाट्यशास्त्र में किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

69. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नाट्य शास्त्र मुखौटों और रंगमंच में उनके उपयोग के बारे में बताता है।
2. सिन्धु घाटी सभ्यता में मुखौटों के प्रयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।
3. पूर्वी भारत में चौथी शताब्दी के टेराकोटा मुखौटे की खुदाई के दौरान खोज की गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

70. तीन सिरों वाले रॉककट शिवा, महेश-मूर्ति, किस गुफा में पायी जा सकती है?

(a) अजंता
(b) एलोरा
(c) एलीफेंटा
(d) मालोवा

71. पेट्राड्यूरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें गुंबद जैसी संरचनाओं को सहारा देने के लिए लंबे स्तंभों की एक श्रृंखला होती है।
2. शाहजहाँ द्वारा इसका विस्तृत उपयोग ताज महल में किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने **गलत** हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

72. तिरुमलाईपुरम पेंटिंग को संरक्षण दिया गया:

(a) विजयनगर साम्राज्य
(b) पांड्य
(c) चोल
(d) पल्लव

73. "मसीतखानी" शैली किससे सम्बंधित है:

(a) दारा सिकोह
(b) जहांगीर
(c) इब्राहीम लोदी
(d) तानसेन

74. भारत में 19वीं सदी के दौरान राजनीतिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बंगभाषा प्रकाशिका सभा का गठन राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा किया गया था।
2. बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना सिसिर कुमार घोष ने लंदन में की थी।
3. इंडियन लीग की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में की थी।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

75. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अठारहवीं सदी के अंत और उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में जोतदारों के नाम से जाने जाने वाले धनी किसानों के एक वर्ग ने गांवों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली और भूमि के विशाल क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया।
2. जोतदार जमींदारों के प्रति वफादार थे और उन्हें रैयतों से राजस्व इकट्ठा करने में मदद करते थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा **असत्य** हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

76. मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा अनुपस्थित थी।
2. मौर्य शासन का अपने साम्राज्य के सभी क्षेत्रों पर समान नियंत्रण था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

77. संविधान के अनुच्छेद 87 में निहित भारत की संसद में राष्ट्रपति के संबोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रपति का अभिभाषण पूर्व वर्ष की सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है और आने वाले वर्ष के लिए व्यापक शासन एजेंडा निर्धारित करता है।
2. राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, दोनों सदन राष्ट्रपति को उनके भाषण के लिए धन्यवाद देने के लिए एक प्रस्ताव पेश करते हैं।
3. अब तक संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन पारित होने का कोई उदाहरण नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

78. राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत का संविधान राज्य सभा के मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई योग्यता निर्दिष्ट नहीं करता है।
2. राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को वे सभी शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जिनके लिए निर्वाचित सांसद हकदार होते हैं।
3. उन्हें भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

79. भारत के उपराष्ट्रपति पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान कहता है कि उपराष्ट्रपति लोक सभा का पदेन अध्यक्ष होगा।
2. भारत के उपराष्ट्रपति का पद वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद आता है।
3. उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

80. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भूमि सुधारों को जांच से छूट दी गई
2. संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा प्रदान की गई।
3. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया गया।

भारत के संविधान के पहले संशोधन में उपर्युक्त में से कौन सा प्रावधान शामिल था?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 1, 2 और 3
(d) कोई भी नहीं

81. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो संविधान केंद्र सरकार को कानून बनाने की अनुमति देता है।
2. किसी राज्य का राज्यपाल केवल राष्ट्रपति की मंजूरी से ही अध्यादेश जारी कर सकता है।
3. किसी अध्यादेश को केवल एक बार ही पुनः प्रख्यापित किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से **गलत** है/हैं?

(a) केवल 3
(b) केवल 2
(c) 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

82. राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राज्यसभा का सभापति सदस्यों में से उपाध्यक्षों का एक पैनल नामित करता है।
2. राज्यसभा के सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में पैनल का कोई भी सदस्य सदन की अध्यक्षता कर सकता है।
3. राज्यसभा के नियमों के अनुसार, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य पैनल के सदस्य बनने के पात्र नहीं होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

83. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख है, और सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है।

2. जबकि राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वह केवल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही किसी मंत्री की नियुक्ति कर सकता है।
3. त्रिशंकु विधानसभा में राज्यपाल यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी पार्टी को अपना बहुमत साबित करने के लिए कितना समय चाहिए या ऐसा करने के लिए किस पार्टी को पहले आमंत्रित करना चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

84. भारतीय रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका उद्देश्य कमजोर बैंकों के संचालन की अधिक बारीकी से निगरानी करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है पूंजी बचाएं और जोखिम से बचें।
2. यह वित्तीय रूप से कमजोर बैंकों द्वारा लाभांश वितरण और शाखाओं के विस्तार पर कुछ प्रतिबंध लगाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा **गलत** है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

85. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संबंध में अदालतों द्वारा अक्सर "अनिवार्यता का सिद्धांत" का उपयोग किया जाता है?
(a) अनुच्छेद 14
(b) अनुच्छेद 19
(c) अनुच्छेद 21
(d) अनुच्छेद 25

86. सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ), जिसे अक्सर बजट और आर्थिक सर्वेक्षणों में देखा जाता है, अनिवार्य रूप से संदर्भित करता है:
(a) जनता के हाथों में धन का संचलन
(b) बैंकिंग क्षेत्र का पूंजीकरण
(c) उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में प्रत्यक्ष खुदरा निवेश
(d) बुनियादी ढांचे या टिकाऊ आर्थिक संपत्तियों का निर्माण

87. लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संबंधित है:
(a) अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से
(b) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से
(c) संसद सदस्य की अयोग्यता से
(d) भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार से।

88. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सरकार के विभिन्न स्तर समान नागरिकों पर शासन करते हैं, लेकिन प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है।
2. सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की आम तौर पर संवैधानिक गारंटी है।
3. सरकार के प्रत्येक स्तर को अपने सभी वित्तीय संसाधन दूसरे स्तर से स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन सी संघवाद की विशेषताएं हैं?
(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

89. संघीय सरकार का तात्पर्य ऐसी सरकार से है:
(a) केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और संघीय और राज्य न्यायपालिकाओं के बीच भी
(b) सभी शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं और क्षेत्रीय सरकारें अपना अधिकार राष्ट्रीय सरकार से प्राप्त करती हैं।
(c) बड़ी संख्या में शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं और क्षेत्रीय सरकारें, कुछ स्वतंत्र शक्तियों के साथ, राष्ट्रीय सरकार से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं।
(d) संविधान द्वारा शक्तियों को राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य विभाजित किया जाता है और दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

90. भारत के संविधान के भाग *IX* में इसके संदर्भ में प्रावधान हैं
1. पंचायतें
2. नगर पालिकाएँ
3. सहकारी समितियाँ

सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

91. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत जारी किए जाते हैं।
2. भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के पास राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने और यह

सुनिश्चित करने की वैधानिक शक्ति है कि उनका नेतृत्व प्रत्येक पांच वर्ष में नवीनीकृत, परिवर्तित या पुन: निर्वाचित हो सके।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा **गलत** है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

92. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धार्मिक आस्था वाले संगठनों को राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकृत होने से रोकता है।
2. भारत का संविधान भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति प्रदान करता है।
3. चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 राजनीतिक दलों को धार्मिक या सांप्रदायिक आस्था वाले प्रतीक रखने से रोकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

93. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक *(CAG)* के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CAG एक संवैधानिक निकाय है, जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है।
2. CAG का कर्तव्य वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है।
3. CAG सार्वजनिक धन का संरक्षक है और देश की वित्तीय प्रणाली को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नियंत्रित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

94. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सभी सदस्यों का चुनाव सदन द्वारा किया जाना चाहिए।
2. यह अपनी रिपोर्ट सदन के अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करता है।
3. इसे केंद्र के किसी भी मंत्रालय के साथ एक सलाहकार समिति का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।

उपर्युक्त से कौन सी संसदीय समितियों की कुछ सामान्य विशेषताएँ हैं/हैं?

(a) केवल 2
(b) 1 और 2
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

95. शीतोष्ण वर्षावनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. समशीतोष्ण वर्षावन अधिकतर तटीय, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
2. ठंडा तापमान और अधिक स्थिर जलवायु अपघटन को धीमा कर देती है, जिससे अधिक सामग्री जमा हो जाती है।
3. समशीतोष्ण वर्षावन विश्व में सबसे अधिक जैविक रूप से विविधतापूर्ण स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

96. निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र का हिस्सा नहीं है?

(a) ओन्टारियो झील
(b) ग्रेट स्लेव लेक
(c) मिशिगन झील
(d) एरी झील

97. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'डोलड्रम्स' का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(a) पृथ्वी का ठंडा क्षेत्र जहां वायुमंडलीय परिसंचरण बहुत कम है।
(b) भूमध्यरेखीय क्षेत्र में शांत क्षेत्र की बेल्ट जहां विद्यमान व्यापारिक पवनें मिलती हैं।
(c) हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां अक्सर चक्रवात उत्पन्न होते हैं।
(d) उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च दबाव क्षेत्र जहां पछुआ पवनें उत्पन्न होती हैं।

98. वलित पर्वतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वलित पर्वत तब बनते हैं जब बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं और लंबवत विस्थापित हो जाते हैं।
2. उनमें शंक्वाकार चोटियाँ होने की संभावना सबसे कम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन **गलत** है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

99. थर्मोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. थर्मोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेजी से घटता है।
2. पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं।
3. अंतरिक्ष शटल और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन दोनों थर्मोस्फीयर में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

100. उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ हैं?
1. क्षोभमंडल के माध्यम से अस्थिर स्थिति
2. मजबूत कोरिओलिस बल
3. तीव्र ऊर्ध्वाधर पवन
4. गर्म और आर्द्र राशि की निरंतर आपूर्ति।

सही उत्तर चुनिए:
(a) 1, 2 और 3
(b) 1, 2 और 4
(c) 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर

1	a	21	a	41	c	61	d	81	c
2	c	22	c	42	c	62	b	82	b
3	d	23	b	43	a	63	c	83	b
4	a	24	a	44	b	64	c	84	d
5	b	25	c	45	b	65	b	85	d
6	a	26	c	46	a	66	d	86	d
7	c	27	b	47	d	67	b	87	c
8	b	28	d	48	c	68	c	88	b
9	b	29	a	49	d	69	b	89	d
10	b	30	c	50	b	70	c	90	d
11	b	31	a	51	c	71	a	91	b
12	b	32	b	52	b	72	b	92	b
13	b	33	c	53	c	73	d	93	b
14	c	34	c	54	c	74	a	94	a
15	c	35	c	55	b	75	b	95	b
16	d	36	c	56	a	76	d	96	b
17	c	37	d	57	b	77	b	97	b
18	d	38	c	58	d	78	a	98	c
19	d	39	c	59	d	79	a	99	b
20	c	40	a	60	a	80	c	100	b

ध्येय LAW®
The legal essence of success

MAJESTIC CLAT
POWERED BY DHYEYA

HEY CLATIANS!!

GEAR UP FOR

CLAT 2025

WITH

MAJESTIC DCLAT

BOOTCAMP
– FOR CLAT 2025 –

16TH JUNE

STUDY | STRATEGIZE | APPLY | DESIRED RESULT

CLAT AUDITION TEST
(ALL INDIA SCHOLARSHIP TEST)

23RD JUNE

CLEAR CLAT THE DHYEYA LAW WAY!!

LIVE STREAMING OF **FREE CLASSES** FOR CLAT
ON OUR OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL @ DHYEYA LAW

17TH MAY

MONDAY TO FRIDAY
12:00 NOON

9319991061
7800001572

A-12, SECTOR J RD,ALIGANJ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH 226024

CP1, JEEVAN PLAZA, NEAR, SHAHEED CHANDRASHEKHAR AZAD CHOWK, VIRAM KHAND 5, GOMTI NAGAR, LUCKNOW UTTAR PRADESH 226010

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

The UPSC ROADMAP

by Vinay Sir

Vinay Sir
(Founder & CEO)
Dhyeya IAS

Book Your Slot
Admission Open

JUNE
21
2024

Time: 5:30 PM

ALIGANJ, LUCKNOW

9506256789